INTERMEDIATE

अर्थशास्त्र

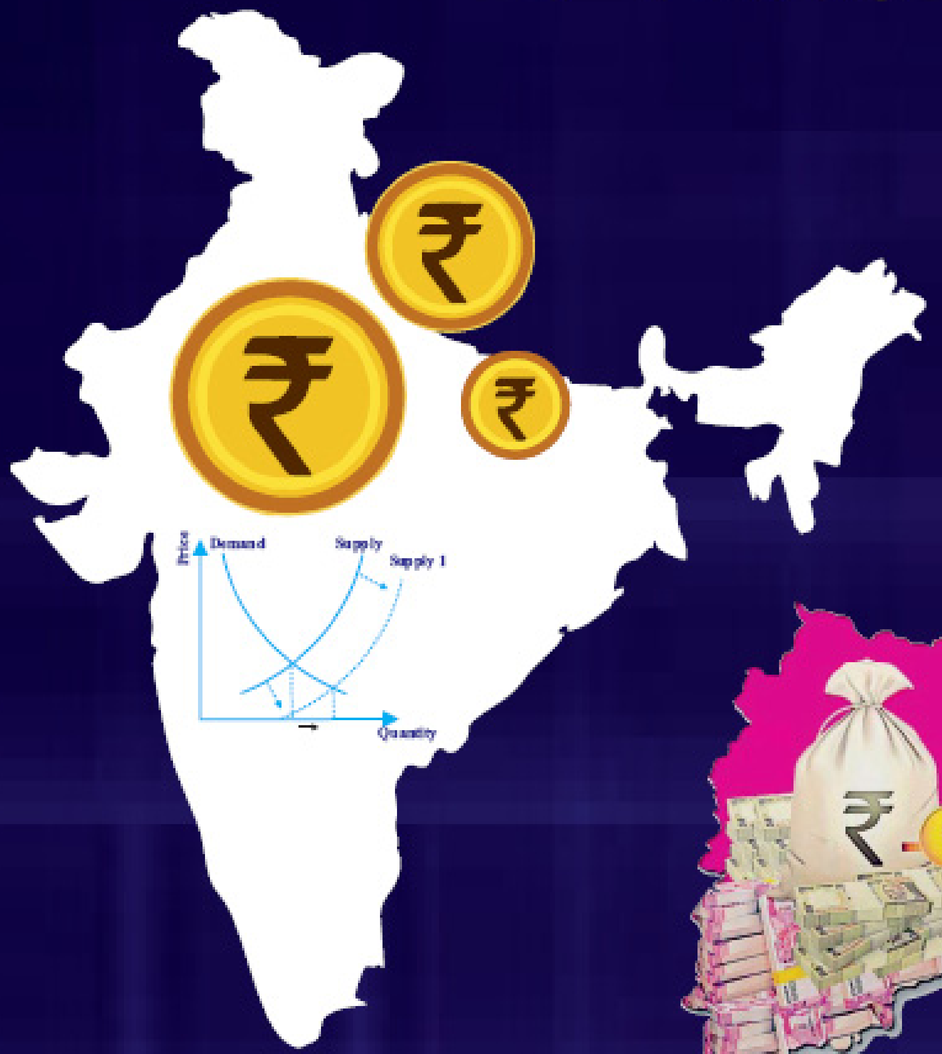

Government of Telangana

तेलंगाना ओपनस्कूल सोसयटी, हैदराबाद

Government of Telangana

INTERMEDIATE

अर्थशास्त्र

तेलंगाना ओपनस्कूल सोसयटी, हैदराबाद

318

अर्थशास्त्र

प्रधान सलाहकार

श्रीमती वाकटि करुणा, आई.ए.एस.,
विशेष प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, तेलंगाणा राज्य

संपादक

प्रो.एस.लिंबा गौड़
प्रोफेसर अर्थशास्त्र (सेवानिवृत्त)
पूर्व डीन, सामाजिक विज्ञान संकाय, तेलंगाना विश्वविद्यालय एवं प्राचार्य,
गिरिराज राजकीय महाविद्यालय (स्वायत्त)
निज़ामाबोद

पाठ्यपुस्तक विकास एवं प्रकाशन समिति

श्रीमती ए. श्रीदेवसेना आई.ए.एस.,
निदेशक, स्कूली शिक्षा, तेलंगाणा राज्य

श्री पी.वी. श्रीहरी
निदेशक, तेलंगाणा ओपन स्कूल
सोसायटी, तेलंगाणा राज्य

श्री एस. श्रीनिवास चारी
निदेशक, पाठ्यपुस्तक प्रेस, तेलंगाणा,
हैदराबाद

प्रधान समन्वयक

श्री मारासानि सोमी रेड्डी
संयुक्त निदेशक, तेलंगाणा ओपन स्कूल
सोसायटी, तेलंगाणा, हैदराबाद

श्री बी. वेंकटेश्वर राव
राज्य समन्वयक, तेलंगाणा ओपन स्कूल
सोसायटी, तेलंगाणा, हैदराबाद

तेलंगाणा ओपन स्कूल सोसायटी, तेलंगाणा राज्य, हैदराबाद
एससीआरटी कैंपस,
बशीरबाग, हैदराबाद - 500 001
Phone: 040-23299568, Website: telanganaopenschool.org,
E-mail: dintoshyd@gmail.com

© TELANGANA OPEN SCHOOL SOCIETY

GOVERNMENT OF TELANGANA, HYDERABAD

First Published : 2023

No. of Copies : 1021

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means without the prior permission, in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover.

This Study Material is Prepared on the basis of Original Economics (Telugu Version) of TOSS, Hyderabad.

Published by:

Telangana Open School Society (TOSS), Hyderabad.

Foreword

Providing education to children is a fundamental right, and it's essential for the overall development of society. The government of Telangana plays a crucial role in ensuring that education is accessible to all, and they often establish institutions like the Telangana Open School Society (TOSS) to cater to children who may be unable to access formal education due to various reasons.

To provide quality education to learners studying Intermediate Education in Telangana Open School Society starting from the 2023 academic year, the textbooks have been revised to align with the changing social situations and incorporate the fundamental principles of the National Education Policy 2020. The guidelines set forth in the policy aim to enhance the overall learning experience and cater to the diverse needs of the learners. Earlier Textbooks were just guides with questions and answers. TOSS has designed the textbook with a student-centric approach, considering the different learning styles and needs of learners. This approach encourages active engagement and participation in the learning process. The textbooks include supplementary teaching materials and resources to support educators in delivering effective and engaging lessons.

This textbook of economics is broadly divided into four areas: introduction to Economics, Microeconomics, Macroeconomics, the Indian Economy, and the Telangana Economy. Inflation, unemployment, economic growth, Demand Analysis, National Income Analysis, Economic Development in India, and human resources are some of the topics of this textbook. Understanding all these chapters is essential for a comprehensive grasp of the subject.

We are indeed very grateful to the Government of Telangana and the Telangana State Board of Intermediate Education. Special thanks to the editor, co-coordinator, teachers, lecturers, and DTP operators who participated and contributed their services tirelessly to write this text book.

Date: .08.2023,
Place: Hyderabad.

Director, TOSS,
Hyderabad.

Coordinator

Sri Gaddameedi Rathangapani Reddy,
ZPHS, Janampet, Musapet (M),
Mahabubnagar.

Textbook Development Committee

Dr. D. Adeppa,
Asst. Professor, Economics,
Giriraj Govt. College (A), Nizamabad.

Dr. Yalavathi Venu Prasad,
Asst. Professor, Economics,
Giriraj Govt. College (A), Nizamabad.

Dr. S. Ramesh,
Asst. Professor, Economics,
Govt. Degree College, Malkajgiri.

Dr. M. Mallikarjun,
Asst. Professor, Economics,
MVS Govt. Arts & Science College (A), Mahabubnagar.

Tungaturti Subba Rao, SA,
ZPHS, Kamanchikal, Khammam.

Dr. Padegela Dasharath, PGT,
TS Model School, Navipet, Nizamabad.

Mohareer Rajendra Kumar, PGT,
TS Model School, Kethepally, Nalgonda.

G. Sreedevi, PGT,
TSMS, Mirdoddi, Siddipet.

Gaddameedi Rathangapani Reddy, SA,
ZPHS, Janampet, Musapet (M), Mahabubnagar.

A. Srinivas Goud, SA,
ZPHS, Nasrullabad, Jadcherla, Mahabubnagar.

M. Prasoon Kumar, SA,
ZPHS, Dongli, Kamareddy.

Bakaram Lalitha, SA,
ZPHS (Grils), Manchal, Rangareddy.

G. Venkateshwarlu, SA,
ZPHS, Champapet, Rangareddy.

Dr. Yellaiah Jangati, PGT,
TS Model School, Vallala, Shaligouraram, Nalgonda.

Nuthipally Balaraj, SA,
ZPHS, Tadgur Big, Madnoor, Kamareddy.

Thatipamula Ramesh, SA,
ZPHS, Wardhannapet, Warangal.

Dr. Sushila Aleme, PGT,
TSMS, Boodhan Pochampally, Yadadri Bhuvanagiri.

K. Gopi Krishna, Retd. Lecturer,
MJPTBCWR Junior College, Pragnapur, Siddipet.

Translation Committee

Cover page designing

K. Sudhakara Chary,
MPPS Mylaram, Mdl: Rayaparthy, Warangal

Layout Design

Smt. Arifa Sultana, SCERT, Hyderabad.

INDEX

क्र.सं.	पाठ का नाम	पृ.सं.
	I. अर्थशास्त्र का परिचय	
1.	अर्थव्यवस्था की प्रकृति और क्षेत्र	1-14
2.	आर्थिक विकास और आर्थिक विकास	15-24
	II. व्यष्टि अर्थशास्त्र	
3.	उपयोगिता विश्लेषण	25-34
4.	मांग विश्लेषण	35-47
5.	उत्पादन विश्लेषण	48-65
6.	आपूर्ति, लागत और राजस्व विश्लेषण	66-78
7.	बाज़ार विश्लेषण	79-91
8.	वितरण के सिद्धांत	92-104
	III. समष्टि अर्थशास्त्र	
9.	राष्ट्रीय आय विश्लेषण	105-116
10.	रोज़गार का सिद्धांत	117-129
11.	सार्वजनिक वित्त और बजट	130-145
12.	धन	146-156
13.	बैंकिंग	157-168
14.	मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र	169-177
	IV. भारतीय अर्थशास्त्र	
15.	भारत में आर्थिक विकास	178-190
16.	जनसांख्यिकि	191-204
17.	मानव संसाधन विकास	205-215
18.	राष्ट्रीय आय रूझान और क्षेतीय योगदान	216-223
19.	गरीबी और बेरोजगारी	224-240
20.	योजना एवं नीति आयोग	241-253
21.	कृषि क्षेत्र	254-269
22.	औद्योगिक क्षेत्र	270-282
23.	तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)	283-297
24.	विदेशी क्षेत्र	298-313
25.	पर्यावरण आर्थिक विकास	314-327
	V. तेलंगाना अर्थशास्त्र	
26.	गठन के बाद तेलंगाना अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास	328-338
27.	मानव संसाधन	339-349
28.	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र - तेलंगाना	350-360
29.	तेलंगाना बजट	361-367
30.	तेलंगाना राज्य में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, निर्माण एवं कल्याण कार्यक्रम	368-382

अध्याय
1

अर्थशास्त्र का परिचय

1.0. उद्देश्य
1.1. परिचय
1.2. अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ : अर्थशास्त्र की परिभाषा व विकास
 1.2.1: संपत्ति की परिभाषा (1776)
 1.2. 2. कल्याण की परिभाषा (1890)
 1.2. 3: कमी की परिभाषा (1932)
 1.2. 4: वृद्धि की परिभाषा (1948)
 1.2. 5: आधुनिक परिभाषा (2011)
1.3. अर्थव्यवस्था की समस्याएँ
 1.3.1. आर्थिक समस्या
1.4. अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र
 1.4.1 अर्थशास्त्र का क्षेत्र
1.5 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र
 1.5.1 व्यष्टि अर्थशास्त्र
 1.5.2 समष्टि अर्थशास्त्र
1.6 सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र
 1.6.1 सकारात्मक अर्थशास्त्र
 1.6.2 मूलभूत अवधारणाएँ
1.7 आदर्शात्मक अर्थशास्त्र
 1.7.1 वस्तुएँ
 1.7.2 माँगें
1.8 आय का वृत्तीय प्रवाह
1.9 सारांश
1.10 नमूना परीक्षा प्रश्न
1.11. शब्दकोश
1.12. संदर्भ

1.0. उद्देश्य

- अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ
- अर्थशास्त्र की समस्याएँ
- अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र
- सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर बताएँ

1.1. परिचय

अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि मनुष्य अभाव की स्थिति में कैसे निर्णय लेता है। यह हो सकता हैं कि व्यक्तिगत निर्णय, पारिवारिक निर्णय, व्यावसायिक निर्णय या सामाजिक निर्णय। अगर आप चारों ओर ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि अभाव जीवन का एक तथ्य है। दृष्टिकोण से विषय को बेहतर ढंग से समझना और समस्या का समाधान ढूँढ़ना ज़रूरी है। अध्यानाधीन आर्थिक मुद्दे की प्रकृति और उस क्षेत्र या शाखा को जानें जिसके अंतर्गत यह मुद्दे निपटे गए हैं। इस अध्याय में हम इसकी परिभाषा, प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधाराणाएँ।

1.2. अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ : अर्थशास्त्र की परिभाषा व विकास

- धन की परिभाषा (1776) : एडम स्मिथ
- कल्याण परिभाषा (1890) : अल्फ्रेड मार्शल
- कमी की परिभाषा (1932) : लियोनेल रॉबिंस
- विकास की परिभाषा (1948) : P.A. सैमुएलन
- आधुनिक परिभाषा (2011) : A.C. धास

1.2.1 संपत्ति की परिभाषा (1776)

- एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उन्होंने ''राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति और कारणों की जाँच'' नामक एक पुस्तक 1776 प्रकाशित की जिसमें कोई देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कैसे धन अर्जित करता है। उल्लेख किया है।

- उन्होंने अर्थशास्त्र को ''एक विज्ञान जो प्रकृति और कारणों की जाँच करता है।'' के रूप में परिभाषित किया।
- उन्होंने विषय वस्तु के रूप में धन के उत्पादन और अर्थशास्त्र के वृद्धि पर जोर दिया।

संपत्ति की परिभाषा विशेषताएँ

विशेषताएँ:

- इसमें केवल भौतिक वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए धन पर जोर दिया गया है।
- यह धन सृजन के पीछे के कारणों की जाँच करता है।

आलोचनाएँ:

- यह अर्थशास्त्र को एक निराशजनक या स्वार्थी विज्ञान मानता था।
- इसने धन को बहुत ही संकीर्ण और प्रतिबंधित अर्थ में परिभाषित किया।
- यह केवल भौतिक और मूर्त वस्तुओं पर विचार करता था।
- इसने केवल धन पर जोर दिया और मनुष्य को गौण स्थान पर ला दिया।

1.2.2. कल्याण की परिभाषा (1890)

- 1890 में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स' में कहा था कि ''अर्थ शास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है, यह जाँच करता है व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया का वह भाग जो सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है। प्राप्ति और कल्याण की भौतिक आवश्यकताओं के उपयोग के साथ।
- यह एक तरफ संपत्ति का अध्ययन है और दूसर ओर, मानव कल्याण का अध्ययन संपत्ति पर आधारित।

कल्याण परिभाषा की विशेषताएँ

विशेषताएँ:

- यह मुख्य रूप से मानव जाति का अध्ययन है।
- यह एक तरफ संपत्ति का अध्ययन है और दूसरी तरफ मनुष्य का अध्ययन।
- यह जीवन के सामान्य व्यवसाय को ध्यान में रखता है। इसका सामाजिक, धार्मिक और मनुष्य के जीवन के राजनीतिक पहलू से कोई सरोकार नहीं है।
- यह भौतिक कल्याण अर्थात मानव कल्याण पर जोर देता है जो धन से संबंधित है।
- यह पैसे के संदर्भ में मापने योग्य गतिविधियों के क्षेत्र को सीमित करता है।

आलोचनाएँ:

- इसने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान के बजाय एक सामाजिक विज्ञान माना।
- यह समुदाय केवल अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संगठित रूप से रहने वाले व्यक्तियों के अध्ययन तक सीमित करता है। कल्याण का अपने आप में एक व्यापक अर्थ है जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है।

1.2.3. कमी की परिभाषा (1932)

- लियोनेल रॉबिंस के अनुसार, ''अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन लक्ष्य और वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के बीच संबंध के रूप में करता है।''
- उन्होंने 'कमी के तहत विकल्प' पर जोर दिया। उनके अपने शब्दों में, ''अर्थशास्त्र व्यवहार के उस पहलू से संबंधित है जो दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों की कमी से उत्पन्न होता है।

कल्याण परिभाषा की विशेषताएँ

विशेषताएँ:

अर्थशास्त्र एक सकारात्मक विज्ञान है-

- नई अवधारणाएँ : असीमित साध्य, दुर्लभ साधन और साधनों का वैकल्पिक उपोयग।
- यह विकल्प पर जोर देता है - मानव व्यवहार का अध्ययन।
- इसने सामाजिक विज्ञान आर्थिक समस्या को सामने लाने का प्रयास किया जो अर्थशास्त्र की नींव बनाती है।
- यह सभी मानवीय गतिविधियों को ध्यान में रखता है।

आलोचनाएँ:

- यह चक्रवाती अस्थिरता के कई महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बेरोजगारी, आय निर्धारण और आर्थिक वृद्धि और विकास।
- इसमें समय के साथ संसाधनों में वृद्धि की संभावना को ध्यान में नहीं रखा गया।
- इसने अर्थशास्त्र को केवल अभाव का विज्ञान माना है।

1.2.4. वृद्धि की परिभाषा (1948)

- प्रोफेसर पी.ए. सैमुएलसन के अनुसार, ''अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि कैसे पुरुष और समाज वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ उत्पादक संसाधनों को नियोजित करने के लिए धन के उपयोग के साथ या उसके बिना, समाज के विभिन्न लोगों और समूहों के बीच भविष्य के साथ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें अभी और उपभोग के लिए विपरित करते हैं।
- यह संसाधन आवंटन के पैटर्न में सुधार की लागत और लाभों का विश्लेषण करता है। इस परिभाषा ने आपदा की स्थिति में विकास के आयाम को प्रस्तुत किया।

विकास परिभाषा की विशेषताएँ

विशेषताएँ

- परिभाषा केवल दिए गए संसाधनों के आवंटन से संबंधित नहीं है बल्कि संसाधनों के विस्तार के साथ-साथ विस्तार और विकास कैसे हो इसका विश्लेषण करने का प्रयास करता है। बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं से निपटने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- अधिक गतिशील दृष्टिकोण।
- इस परिभाषा के अनुसार एख बेहतर अर्थव्यवस्था या विनिमय अर्थव्यवस्था का संसाधन आवंटन, वह एक सार्वभौतिक समस्या है।
- परिभाषा प्रकृति में व्यापक है क्योंकि यह विकास के साथ-साथ भविष्योन्मुखी भी है।

1.2.5. आधुनिक परिभाषा (2011)

- प्रोफेसर A.C. धस के अनुसार, "अर्थशास्त्र विकल्प निर्माण का अध्ययन है। अभाव की स्थिति में व्यक्ति, संस्थाएँ, समाज, राष्ट्र विश्व और अधिशेष वर्तमान और भविष्य के लाभ को अधिकतम करने और उनकी असीमित ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है।"
- संक्षेप में, अर्थशास्त्र को ''दुलर्भ दिए गए संसाधनों के साथ उत्पादन और उपभोग लाभ को अधिकतम करना और वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों के लिए अधिशेष के विकल्पों का अध्ययन'' के रूप में परिभाषित किया गया है।

आधुनिक परिभाषा की विशेषताएँ

- यह पूर्व सभी परिभाषाएँ - धन, कल्याण, अभाव और विकास को ध्यान में रखता है।
- यह अर्थशास्त्र के सूक्ष्म और स्थूल दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है।
- यह उत्पादन और उपभोग दोनों गतिविधियों पर विचार करता है।
- यह अर्थशास्त्र में विकल्प निर्माण के आयाम को महत्वपूर्ण मानकर जोर देता है।
- इसका लक्ष्य दिए गए संसाधनों के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करना है।
- यह कमी और अधिशेष दोनों स्थितियों में उपयुक्त है।
- यह वर्तमान और भविष्य-समय के आयामों - विकास आयाम और सतत विकास को ध्यान में रखता है।

1.3. अर्थव्यवस्था की समस्याएँ

मूलभूत आर्थिक समस्याएँ:

- क्या उत्पादन करें?
    - किस प्रकार के उत्पादों का उत्पादन किया जाना है?
    - कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए?
- उत्पादन कैसे करें?
    - किस उत्पादन विधि का उपयोग किया जाए?
- किसके लिए उत्पादन करें ?
    - परिमाण का वितरण कैसे करें?
    - कौन से मापदंड चुने जाना चाहिए?

1.3.1. आर्थिक समस्या

वैकल्पिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधनों के आवंटन के संबंध में आर्थिक समस्या सेवाएँ, इसलिए आर्थिक समस्या पसंद की समस्या है। आर्थिक समस्या निहित है। अर्थव्यवस्था की सभी समस्याओं में सापेक्ष की कमी मूलभूत समस्या है।

आर्थिक समस्या :

उत्पादन के सभी कारकों को वैकल्पिक उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ज़मीन के एक टुकडें का उपयोग खेती करने, फैक्ट्री बनाने, स्कूल विकसित करने या अस्पताल बनाने के लिए किया जा सकता है। एक श्रमिक का उपयोग खेत की जुताई करने, टोकरियाँ बनाने या सब्जियाँ बेचने के लिए किया जा सकता है, इसलिए, हम देखते हैं कि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है।

आर्थिक या विकल्प संबंधी समस्या

इच्छाएँ असीमित हैं लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के संसाधन सीमित हैं। इसलिए, सभी अर्थशास्त्रियों के सामने आने वाली मूलभूत आर्थिक समस्या यह है कि इच्छाएँ असीमित है। लेकिन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन सीमित हैं। हमने यह भी चर्चा की है कि संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। संसाधनों की कमी भी विकल्प की ओर ले जाती है।

सीमित स्त्रोत

मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन सीमित हैं। लोगों की आय अधिक या कम हो सकती है लेकिन असीमित आय नहीं। इसलिए, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। संसाधन उत्पादन के कारक हैं जिनका उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए किया जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इन संसाधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल हैं।

संसाधनों की कमी

कमी का अर्थ है कि संसाधनों की मांग उनकी उपलब्धता से अधिक है। आवश्यकताओं की पूर्ति के संसाधन सीमित हैं। लोगों की आय अधिक या कम हो सकती है लेकिन असीमित आय नहीं। इन संसाधनों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्‌यामिता शामिल हैं।

1.4. अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र

- अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उत्पादन के आदान-प्रदान और आर्थिक प्रणालियों में विभिन्न वस्तुएँ उपभोग से संबंधित है।
- यह दर्शाता है कि संपत्ति और मानव कल्याण को बढ़ाने के लिए दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है।
- अर्थशास्त्र का केंद्रीय ध्यान संसाधनों की कमी और उनके वैकल्पिक उपयोगों के बीच विकल्पों पर है।
- वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध संसाधन या इनपुट सीमित या दुलर्भ हैं। यह कमी लोगों को विकल्पों में से चुनाव करने के लिए प्रेरित करती है और अर्थशास्त्र के ज्ञान का उपयोग उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने के लिए विकल्पों की तुलना करने के लिए किया जाता है।

1.4.1 अर्थशास्त्र का क्षेत्र

अर्थशास्त्र का दायरा व्यापक है और इसमें मानव व्यवहार के विभिन्न पहलू शामिल हैं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो व्यक्तियों, सरकारों और समाजों की जाँच करता है। उनकी असीमित चाहतों और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का आवंटन करें।

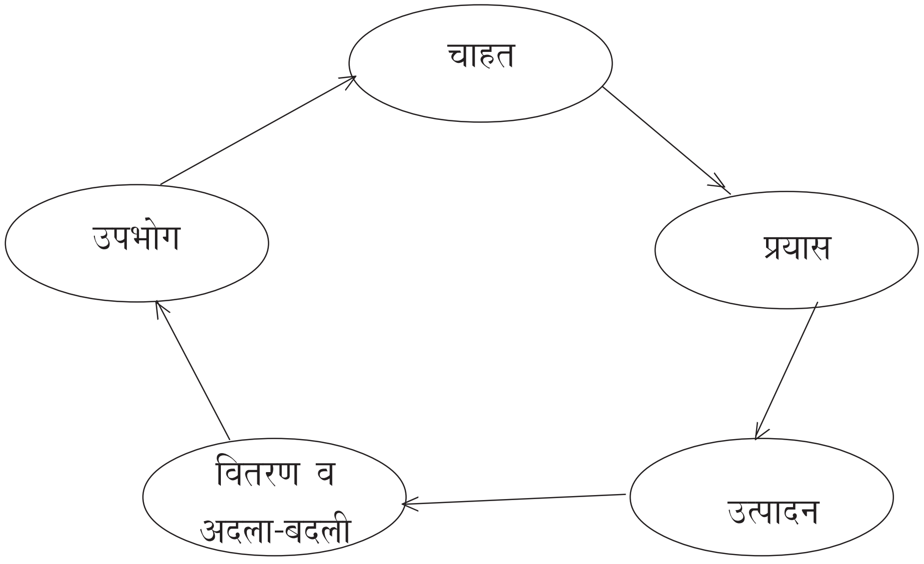

1.5 व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र

व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र की दो मूलभात शाखाएँ हैं। एकत्रीकरण के विभिन्न स्तरों पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करें। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और व्यापक आर्थिक विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माने जाते हैं। अर्थशास्त्र में 'माइक्रो' और 'मॉक्रो' शब्द का प्रयोग पहली बार 1933 में नॉर्वोजियन अर्थशास्त्री रेंजर फ्रिस्क द्वारा किया गया था। ये शब्द ग्रीक शब्द 'माइक्रोस' और मैक्रोस' से बने हैं जिनका अर्थ क्रमशः छोटा और बड़ा होता है।

1.5.1 व्यष्टि (सूक्ष्म) अर्थशास्त्र

व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो व्यक्तिगत एजेंटों के अध्ययन पर बाज़ार के भीतर उनकी आर्थिक बातचीत केंद्रित है। यह जाँच करता है कि कैसे व्यक्ति, घर और कंपनियाँ संसाधनों के आवंटन, उत्पादन आदि के संबंध में निर्णय लेती हैं। वस्तुओं और सेवाओं की खपत और ये निर्णय कीमतों, मात्राओं आदि को बाज़ार के नतीजे कैसे प्रभावित करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र 'पूर्ण रोज़गार' और 'सीमांत विश्लेषण' की धारणाओं पर आधारित है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन सिद्धांत शामिल हैं। 1) उत्पाद मूल्य निर्धारण का सिद्धांत 2) कारक मूल्य निर्धारण का सिद्धांत 3) आर्थिक कल्याण का सिद्धांत

व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व

- संसाधन के आवंटन: व्यष्टि अर्थशास्त्र यह निर्धारित करने में मदद करता है कि श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों जैसे उद्योग संसाधनों को विभिन्न उपयोगों के बीच कैसे आवंटित किया जाता है।
- मूल्य निर्धारण निर्णय : व्यष्टि अर्थशास्त्र बाज़ार में निर्धारित कीमतों का विश्लेषण कने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- नीति निर्धारण : व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण जैसे- कराधान, सब्सिडी, विनिमय और अविश्वास कानूनों के डिजाइन करने के लिए आधार प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में व्यक्तिगत कंपनियों और उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यवहार भी प्रासंगिक है।
- उपभोक्ता व्यवहार : व्यष्टि अर्थशास्त्र उपभोक्ता की पसंद, प्राथमिकताओं और खरीदारी पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित है।

1.5.2 समष्टि अर्थशास्त्र

दूसरी ओर, समष्टि अर्थशास्त्र समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित है और व्यापक समुच्चय पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि उत्पादन का समग्र स्तर पर, रोजगार, मुद्रास्फीति और आर्थिक वीकास।

विकास। यह संपूर्ण आर्थिक प्रणाली को देखता है और इसका उद्देश्य उन कारकों को समझना है
इसके समग्र प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक्स को आय और के रूप में भी जाना जाता है
रोजगार सिद्धांत या समग्र अर्थशास्त्र। यह मैक्रो के सिद्धांत से भी संबंधित है
वितरण, व्यापार चक्र का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति का सिद्धांत।

समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व:

स्थिरता और विकास: मैक्रोइकॉनॉमिक्स नीति निर्माताओं और सरकारों को स्थिर और टिकाऊ आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता: मैक्रोइकॉनॉमिक्स मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रोज़गार और बेरोज़गारी: व्यापक आर्थिक विश्लेषण इसमें सहायक है
बेरोजगारी के मुद्दों को संबोधित करना। सरकारें राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों का उपयोग कर सकती हैं
रोजगार के स्तर को प्रभावित करना और नौकरी की वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाना।

सरकारी नीति निर्माण: सरकारें व्यापक आर्थिक डेटा और सिद्धांतों का उपयोग करती हैं
प्रभावी आर्थिक नीतियां बनाना। राजकोषीय नीतियां (सरकारी व्यय और
कराधान) और मौद्रिक नीतियां (धन आपूर्ति और ब्याज दरों का नियंत्रण)

व्यापार और भुगतान संतुलन: समष्टि अर्थशास्त्र प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करता है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जैसे विनिमय दरें, व्यापार घाटा और अधिशेष।

सूक्ष्मअर्थशास्त्र और समष्टिअर्थशास्त्र के बीच अंतर

व्यष्टि अर्थशास्त्र	समष्टि अर्थशास्त्र
यह अर्थव्यवस्था के विशेष खंड का अध्ययन करता है, यानी एक व्यक्ति, घर, फर्म या उद्योग।	यह समग्र रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित है; यह समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल्य स्तर, कुल खपत, आदि। यह व्यापक आर्थिक मुद्दों से संबंधित है।
यह मांग, आपूर्ति, जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। कारक मूल्य निर्धारण, उत्पाद मूल्य निर्धारण, आर्थिक कल्याण, उत्पादन, खपत, और बहुत कुछ।	यह राष्ट्रीय आय, वितरण, रोजगार, सामान्य मूल्य स्तर, धन और बहुत कुछ जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित है।
इसे 'मूल्य सिद्धांत' के नाम से जाना जाता है	इसे 'आय एवं रोजगार सिद्धांत' के नाम से जाना जाता है
सूक्ष्मअर्थशास्त्र किसी विशेष की कीमत निर्धारित करता है पूरक की कीमतों के साथ-साथ वस्तु और स्थानापन्न सामान.	समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य मूल्य स्तर को बनाए रखने में सहायक है।

1.6 सकारात्मक एवं मानक अर्थशास्त्र

सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं जो अलग-अलग सेवा प्रदान करती हैं

उद्देश्य और आर्थिक विश्लेषण के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक अर्थशास्त्र स्थापित करता है आर्थिक घटनाओं को समझने की नींव, जबकि मानक अर्थशास्त्र प्रदान करता है नीति विकल्पों का मूल्यांकन करने और मूल्य-आधारित निर्णय लेने की रूपरेखा।

1.6.1 सकारात्मक अर्थशास्त्र

सकारात्मक अर्थशास्त्र आर्थिक तथ्यों और घटनाओं के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण से संबंधित है। यह इसका उद्देश्य आर्थिक व्यवहार और घटनाओं को बिना बताए, जैसी वे हैं, वैसे ही वर्णित और समझाना है निर्णय या राय को महत्व दें कि वे अच्छे हैं या बुरे। ध्यान प्रदान करने पर है डेटा, गणितीय मॉडल का उपयोग करके आर्थिक मुद्दों का वैज्ञानिक और अनुभवजन्य विश्लेषण, और आर्थिक विश्लेषण के अन्य उपकरण।

1.6.2 मानक अर्थशास्त्र

दूसरी ओर, मानक अर्थशास्त्र, आर्थिक के व्यक्तिपरक विश्लेषण से संबंधित है मुद्दे और क्या होना चाहिए इसके बारे में मूल्य निर्णय लेने का प्रयास करता है। इसमें बनाना शामिल है आर्थिक नीतियों या कार्यों के आधार पर सिफ़ारिशें और राय पेश करना विशिष्ट मूल्य प्रणालियाँ या नैतिक ढाँचे।

1.7 बुनियादी अवधारणाएँ

1.7.1 माल

वस्तुएँ बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के कामकाज में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। उत्पादन, वस्तुओं का वितरण और उपभोग आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं और इसमें योगदान करते हैं व्यक्तियों और समाजों का समग्र कल्याण। विभिन्न प्रकार के सामानों को समझना और उनकी विशेषताएँ आर्थिक व्यवहार के विश्लेषण के लिए आवश्यक हैं

सामान के प्रकार:

मुफ़्त वस्तुएँ: मुफ़्त वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जो प्रचुर मात्रा में होती हैं और जिनमें प्रत्यक्ष लागत नहीं जुड़ी होती है उनके साथ। उदाहरण के लिए, हवा और सूरज की रोशनी को आम तौर पर मुफ़्त सामान माना जाता है।

आर्थिक वस्तुएँ: आर्थिक वस्तुएँ दुर्लभ वस्तुएँ हैं जिनके साथ लागत जुड़ी होती है उत्पादन, वितरण, या अधिग्रहण। ये वे सामान हैं जिनकी आर्थिक आवश्यकता है उनकी सीमित उपलब्धता के कारण विकल्प और व्यापार-बंद।

उपभोक्ता वस्तुओं:

टिकाऊ सामान: ये लंबे जीवनकाल वाले उत्पाद हैं और इनका अधिक उपयोग होने की उम्मीद है एक विस्तारित अवधि, आमतौर पर तीन साल से अधिक समय तक चलने वाली। उदाहरणों में कार, फर्नीचर, और उपकरण.

गैर-टिकाऊ सामान: इन सामानों का जीवनकाल छोटा होता है और इनका उपयोग जल्दी हो जाता है। उदाहरण भोजन, पेय पदार्थ और प्रसाधन सामग्री शामिल करें।

पूँजीगत वस्तुएँ: पूँजीगत वस्तुएँ, जिन्हें उत्पादक वस्तुएँ भी कहा जाता है, का उपयोग व्यवसायों द्वारा किया जाता है अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करें। वे सीधे तौर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपभोग नहीं किए जाते हैं लेकिन हैं उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। उदाहरणों में मशीनरी, उपकरण और कारखाने शामिल हैं।

मध्यवर्ती वस्तुएँ: मध्यवर्ती वस्तुएँ वे सामग्रियाँ और घटक हैं जिनका उपयोग किया जाता है अन्य वस्तुओं का उत्पादन. वे उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले अंतिम उत्पाद नहीं हैं बल्कि हिस्सा हैं उत्पादन प्रक्रिया का.

अमूर्त वस्तुएं: इन्हें सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है, ये गैर-भौतिक उत्पाद हैं जो नहीं हैं मूर्त लेकिन उपभोक्ताओं को मूल्य प्रदान करते हैं। उदाहरणों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, बैंकिंग और मनोरंजन सेवाएँ।

1.7.2 चाहता है

चाहत किसी वस्तु को पाने की इच्छा है। सभी में चाहतों और उनकी संतुष्टि की प्रमुख भूमिका होती है आर्थिक गतिविधियाँ। वे मानव व्यवहार और निर्णय को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं-बनाना। आवश्यकताओं की विशेषताओं को समझना व्यक्तियों, व्यवसायों के लिए आवश्यक है। और नीति निर्माताओं को सूचित विकल्प बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने और संसाधनों का प्रबंधन करने में प्रभावी रूप से।

चाहतों के लक्षण:

इच्छाएँ असीमित हैं: इच्छाएँ अनेक हैं। वे कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं. वे फिर से उभर आते हैं और फिर। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। चाहत बढ़ती जाती है.

प्रकृति में इच्छाएँ बार-बार होती हैं: कुछ मनुष्य बार-बार इच्छाएँ चाहते हैं। एक बार संतुष्ट होने पर भी वे उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम एक निश्चित समय अंतराल के बाद भोजन करते हैं भूख मिटाने के लिए.

आवश्यकताएँ पूरक होती हैं: कई बार समूह की एक भी वस्तु संतुष्ट नहीं हो पाती

मानव स्वयं चाहता है। इसका उपयोग पूरा करने के लिए अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, ए

मोटर कार को चालू रखने के लिए पेट्रोल और इंजन तेल दोनों की आवश्यकता होती है।

एक विशेष इच्छा पूरी की जा सकती है: हालाँकि मानव की इच्छाएँ असीमित हैं और सभी की पूर्ति संभव नहीं है

एक समय में संतुष्ट, लेकिन एक विशेष इच्छा पूरी की जा सकती है। इसे जल्दी संतुष्ट किया जा सकता है या

बाद में, यदि कोई इसके लिए प्रयास करता है और उसके पास इसे संतुष्ट करने के लिए संसाधन हैं।

इच्छाएँ प्रतिस्पर्धी होती हैं: कुछ इच्छाएँ एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती हैं। प्रतिस्पर्धा करना चाहता है

क्योंकि उन सभी को एक समय में संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसलिए, एक विकल्प चुनना होगा

उनके बीच बना.

1.8 आय का चक्रीय प्रवाह

आय का चक्रीय प्रवाह एक आर्थिक अवधारणा है जो धन के प्रवाह को दर्शाती है

एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच माल। यह दिखाता है कि कैसे घर, व्यवसाय,

सरकारें और विदेशी क्षेत्र आपस में बातचीत करते हैं और आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। गोलाकार

प्रवाह मॉडल उन जटिल अंत:क्रियाओं का सरलीकृत प्रतिनिधित्व प्रदान करता है जो घटित होती हैं

एक अर्थव्यवस्था.

आय का चक्रीय प्रवाह दो मुख्य चैनलों के माध्यम से संचालित होता है:

उत्पाद बाज़ार: यह वह जगह है जहाँ व्यवसाय घरों को सामान और सेवाएँ बेचते हैं, और घरवाले, बदले में, इन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते हैं।

कारक बाजार: यह वह जगह है जहां परिवार उत्पादन के कारक (श्रम, भूमि, और) प्रदान करते हैं

पूंजी) व्यवसायों को वेतन, किराया, ब्याज और लाभ के बदले में।

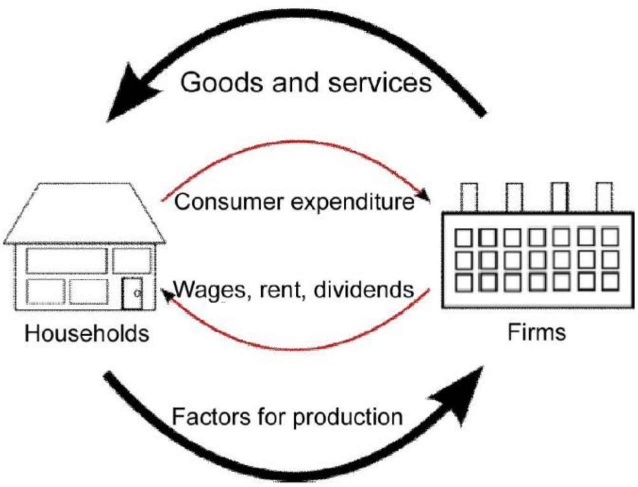

1.9 सारांश

अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि लोग किस प्रकार दुर्लभता के साथ विकल्प और निर्णय लेते हैं संसाधन। हमारी दुनिया में अधिकांश संसाधन सीमित हैं, चाहे वह समय हो, पैसा हो या प्राकृतिक संसाधन। इस प्रकार, व्यक्ति निरंतर निर्णय लेते हैं कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसका उत्पादन करें और क्या उपभोग करें। सूक्ष्मअर्थशास्त्र और व्यापकअर्थशास्त्र दो हैं अर्थशास्त्र की मौलिक शाखाएँ जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं का अलग-अलग अध्ययन करती हैं एकत्रीकरण के स्तर। सकारात्मक और मानक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं जो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और आर्थिक विश्लेषण के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

1.10 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. पसंद की समस्या
2. वैकल्पिक उपयोग
3. सीमित संसाधन
4. कमी की परिभाषा
5. वस्तुओं का वर्गीकरण करें.

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. अर्थव्यवस्था की समस्याओं की व्याख्या करें
2. सूक्ष्मअर्थशास्त्र और समष्टिअर्थशास्त्र में अंतर बताएं।
3. आवश्यकताओं की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए।
4. सकारात्मक एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का वर्णन करें

तृतीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दीजिए।

1. अर्थशास्त्र की (4) परिभाषाएँ स्पष्ट कीजिए।
2. अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं कार्यक्षेत्र की व्याख्या करें।
3. अर्थशास्त्र के चक्राकार प्रवाह का वर्णन करें।
4. सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र और उनके महत्व की व्याख्या करें।

1.11. शब्दकोष

एडम स्मिथ (1723:1790) को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। के लेखक

राष्ट्रों का धन।

माइक्रोइकॉनॉमिक्स: माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द 'माइक्रो' से लिया गया है

मतलब छोटा.

आर्थिक वस्तुएँ: ये वस्तुएँ मानव निर्मित वस्तुएँ हैं। इन वस्तुओं की कीमत होती है.

इन वस्तुओं की आपूर्ति हमेशा उनकी मांग से कम होती है।

कीमत: वस्तु के मूल्य को मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे कीमत कहा जाता है।

अमूर्त वस्तुएँ: सेवाएँ अमूर्त वस्तुओं की एक विस्तृत श्रेणी है जिसमें व्यक्तियों द्वारा प्रदान की जाने वाली गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है।

1.12. संदर्भ

1. अर्थशास्त्र का परिचय - डेविड विलियम्स
2. बुनियादी अर्थशास्त्र - थॉमस सोवेल
3. अर्थशास्त्र का परिचय-फ्रीकॉनॉमिक्स
4. इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यपुस्तक - TSBIE
5. बीए अर्थशास्त्र

आर्थिक विकास और आर्थिक विकास

अध्याय

2

2.0 उद्देश्य 2.1
परिचय

2.2 आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाएँ 2.2.1 आर्थिक विकास की
अवधारणा 2.2.2 आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के
बीच अंतर 2.2.3 विकास के उद्देश्य 2.3 आर्थिक विकास के संकेतक 2.3.1 वास्तविक राष्ट्रीय आय

2.3.2 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद 2.3.3 कल्याण

2.3.4 सामाजिक संकेतक या बुनियादी जरूरतें

2.3.5 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं 2.4 भारत के
विशेष संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं 2.4.1 कम प्रति व्यक्ति आय 2.4.2 कृषि की
प्रधानता 2.4.3 पूंजी की कमी 2.4.4
तकनीकी पिछड़ापन 2.4.5 अपर्याप्त बुनियादी
सुविधाएं 2.4.6 जनसांख्यिकीय
विशेषताएं 2.4.7 निरक्षरता की उच्च दर 2.4.8
एक द्वैतवादी अर्थव्यवस्था 2.4.9 अविकसित प्राकृतिक
संसाधन 2.4.10 उद्यमिता का अभाव
2.4.11 काम और जीवन के प्रति
परंपरा से बंधे दृष्टिकोण

2.5 सारांश 2.6
मॉडल परीक्षा प्रश्न 2.7 शब्दावली 2.8 संदर्भ

2.0. उद्देश्य

- आर्थिक विकास को परिभाषित करें.
- आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर बताएं.
- विकसित और विकासशील अर्थशास्त्र की पहचान करें।
- विकसित और विकासशील अर्थशास्त्र की विशेषताओं को समझें।
- भारत के विशेष संदर्भ में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का विश्लेषण करें।

2.1. परिचय

इस पाठ में आप आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के उद्देश्य तथा आर्थिक विकास के संकेतकों के बारे में अध्ययन करेंगे।

2.2 आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाएँ

किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा में वृद्धि होती है
आर्थिक विकास कहा जाता है।

माइकल पी. टोडारो के अनुसार, "आर्थिक विकास एक स्थिर प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जाती है।"
राष्ट्रीय उत्पादन और आय का स्तर"।

आर्थिक विकास की अनिवार्यताएँ:

- आर्थिक विकास वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की तुलना में वृद्धि की उच्च दर को दर्शाता है
  जनसंख्या वृद्धि दर.
- आर्थिक विकास हमेशा उत्पादन क्षमता में बड़ी वृद्धि से जुड़ा होता है
  अर्थव्यवस्था।

आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य देश में वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि से है
सेवाएँ (या) प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि।

2.2.1 आर्थिक विकास की अवधारणा

आर्थिक विकास अवधारणा की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि "आर्थिक विकास" विकास में न केवल आर्थिक विकास बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में कुछ अन्य सकारात्मक बदलाव भी शामिल हैं। वस्तुतः इसमें सभी क्षेत्रों का विकास शामिल है।

माइकल पी. टोडारो के अनुसार "विकास की कल्पना बहु-स्तरीय के रूप में की जानी चाहिए।" आयामी प्रक्रिया जिसमें सामाजिक संरचनाओं, लोकप्रिय दृष्टिकोण और में बड़े बदलाव शामिल हैं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ-साथ आर्थिक विकास में तेजी, की कमी असमानता और गरीबी का उन्मूलन ”।

2.2.2 आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर

आर्थिक विकास	आर्थिक विकास
परिभाषा: इसका तात्पर्य धन में वृद्धि से है किसी विशेष काल में किसी राष्ट्र का विकास। अवधारणा का विस्तार: की तुलना में यह एक संकीर्ण अवधारणा है आर्थिक विकास। दायरा: यह एक आयामी दृष्टिकोण है किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। अवधि: अल्पकालिक प्रक्रिया माप: मात्रात्मक लागू: विकसित अर्थशास्त्र सरकारी सहायता: यह एक स्वचालित प्रक्रिया है जो या हो सकती है के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो सकती है सरकार। पूर्व: जीडीपी, जीएनपी	इसका तात्पर्य समग्र विकास से है किसी राष्ट्र में जीवन की गुणवत्ता जिसमें शामिल है आर्थिक विकास। की तुलना में यह एक व्यापक अवधारणा है आर्थिक विकास। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है आय के साथ-साथ आय पर भी ध्यान देता है किसी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता. दीर्घकालिक प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अर्थशास्त्र का विकास करना इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है सरकार क्योंकि सभी विकासात्मक नीतियां सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। पूर्व: एचडीआई, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक विकास।

2.2.3 आर्थिक विकास के उद्देश्य

आर्थिक विकास का उद्देश्य जीवन के भौतिक मानकों में सुधार करना है
प्रति व्यक्ति आय का पूर्ण स्तर बढ़ाकर।

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना भी सभी विकासशील देशों की सरकार की नीति का एक घोषित उद्देश्य है।

- विकास की उच्च दर: योजना के पहले तीन दशकों के दौरान, की दर
  हमारे देश में आर्थिक विकास उतना उत्साहवर्धक नहीं था। लेकिन छठी योजना के बाद से,
  भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आया है.

  छठी योजना - 5.4%

  7वीं योजना - 5.8%

  8वीं योजना - 6.8%

  9वीं योजना - 7% (लक्षित)

  10वीं योजना - 7.6%

  11वीं योजना - 8% (लक्षित)

- आर्थिक आत्मनिर्भरता: आत्मनिर्भरता का तात्पर्य यह है कि एक देश अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करता है। इसके लिए यह अन्य देशों पर निर्भर नहीं है
  उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन के संसाधन।

- आधुनिकीकरण: आधुनिकीकरण का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है
  लोग पारंपरिक तकनीक को हटाकर उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक अपना रहे हैं
  पिछड़े तरीकों और ग्रामीण संरचना और संस्थानों में बदलाव लाकर
  समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण, पारंपरिक ग्रामीण कृषक से परिवर्तन
  एक धर्मनिरपेक्ष शहरी औद्योगिक समाज के लिए समाज।

- आर्थिक स्थिरता: आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना आर्थिक और वित्तीय संकटों से बचने का मामला है। आर्थिक स्थिरता अत्यधिक का अभाव है
  वृहत अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव. काफी स्थिर उत्पादन वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था
  और निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति को आर्थिक रूप से स्थिर माना जाएगा।

  आर्थिक स्थिरता लोगों को वित्तीय संसाधनों, गुणवत्तापूर्ण आवास और भोजन और नौकरी प्रदान करने सहित जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने की क्षमता प्रदान करती है
  स्थिर जीवनयापन वेतन.

- सतत विकास: वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को बिना पूरा किये
  भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता करना।

सतत विकास मानव से मिलन का एक संगठित सिद्धांत है

विकासात्मक लक्ष्य प्रदान करने के साथ-साथ प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को भी बनाए रखना

प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ जिन पर अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करता है

निर्भर करना।

- समावेशी विकास: समावेशी विकास का अर्थ है आर्थिक विकास जो रोजगार के अवसर पैदा करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है। इसका मतलब गरीबों तक स्वास्थ्य और शिक्षा की आवश्यक सेवाओं तक पहुंच होना है। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना शामिल है।

2.3 आर्थिक विकास के संकेतक

2.3.1 वास्तविक राष्ट्रीय आय

राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से है

इस प्रकार, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यह किसी भी देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का शुद्ध परिणाम है

एक वर्ष की अवधि के दौरान और पैसे के संदर्भ में इसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय है

स्थिर कीमतों पर मापा जाता है, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है।

2.3.2 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद

इसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और विदेश से शुद्ध कारक आय शामिल है

जो सेवाओं के लिए प्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली आय है। उन्होंने इसमें योगदान दिया है

घरेलू अर्थव्यवस्था।

2.3.3 कल्याण

यह इस बात का अध्ययन है कि संसाधनों और वस्तुओं का आवंटन सामाजिक कल्याण को कैसे प्रभावित करता है।

इसका सीधा संबंध आर्थिक दक्षता और आय वितरण की छाया से भी है

जैसे कि ये दोनों कारक अर्थव्यवस्था में लोगों की समग्र भलाई को कैसे प्रभावित करते हैं।

2.3.4 सामाजिक संकेतक

विकास के मुख्य सामाजिक संकेतकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार शामिल हैं

और बेरोजगारी दर और लैंगिक समानता। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के संकेतक

इन मापों का उपयोग करें कि कोई देश कितना "विकसित" है, और मुख्य सूचकांक आर्थिक हैं,

जनसांख्यिकीय और नागरिक, सामाजिक आर्थिक, स्वास्थ्य सुरक्षा और सुरक्षा और पर्यावरण और

ऊर्जा।

2.3.5 विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएँ

प्रति व्यक्ति जीएनआई के आधार पर, देशों को निम्न आय मध्यम आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उच्च आय वाले देश, विश्व बैंक की रिपोर्ट (2014) के अनुसार "जोखिम और"। अवसर, विकास के लिए जोखिम का प्रबंधन”।

- सेवा एवं औद्योगिक क्षेत्र का महत्व: वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र

  फैक्टर कास्ट पर देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अधिकतम हिस्सेदारी का योगदान देता है (राष्ट्रीय आय)। 2000-01 के अनुसार राष्ट्रीय आय का 48.5% हिस्सा आता है सेवा क्षेत्र से और इसके अलावा, कुल कामकाजी आबादी का 22.9% कार्यरत है इस क्षेत्र में.

- पूंजी निर्माण की उच्च दर: किसी देश में पूंजी निर्माण की उच्च दर

  मतलब आर्थिक विकास की उच्च दर। सामान्यतः पूंजी निर्माण की दर या उन्नत देशों की तुलना में संचयन बहुत कम है। आम तौर पर, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण जितना अधिक होगा, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ सकती है कुल आय।

- आधुनिक उत्पादन तकनीकों और कौशलों का उपयोग: आधुनिक उत्पादन तकनीकें

  और कौशल आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं विकसित देशों। के लिए नई एवं उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया गया है भौतिक मानव संसाधनों का शोषण।

  विकासशील देशों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने का गहरा प्रभाव पड़ा है उनकी अर्थव्यवस्थाएँ, जैसे उत्पादन की राष्ट्रीय लागत को कम करना, स्थापित करना गुणवत्ता के मानक और व्यक्तियों को दूर से संचार की अनुमति देना।

- जनसंख्या की कम वृद्धि: धीमी जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि महिलाएं औसत हैं

  बुखार वाले बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिससे लड़कियों और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है शिक्षा और करियर और स्कूली शिक्षा, स्वायत्तता आदि का एक सकारात्मक चक्र जारी रखें बराबरी का दर्जा। धीमी जनसंख्या वृद्धि से आप्रवासन पर भी अधिक प्रभाव पड़ेगा।

2.4 भारत की विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएँ

सामान्य रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएँ और भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से इस प्रकार हैं:

2.4.1 कम प्रति व्यक्ति आय

गरीबी प्रति व्यक्ति कम जीएनपी में परिलक्षित होती है। हालाँकि, यह सापेक्षिक गरीबी नहीं है इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पूर्ण गरीबी का आकलन करना अधिक महत्वपूर्ण है।

पहले अग्रिम के अनुसार, 2020-21 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 8.7% गिरकर 99,155/- रुपये हो गया, जो एक साल पहले 1,08,620/- रुपये था।

राष्ट्रीय आय का अनुमान.

2.4.2 कृषि की प्रधानता

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है और 60% से अधिक आबादी को रोजगार प्रदान करता है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कृषि ने प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है।

भारत के कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में कुछ लोग नियोजित प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में वे नहीं हैं।

2.4.3 पूंजी की कमी

राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय पूंजी का मूल कारण है विकासशील देशों में कमी वास्तविक राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर है जो बचत निवेश के उद्देश्यों तक सीमित है। वांछित निवेश की कमी के कारण, पूंजी निर्माण में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

2.4.4 तकनीकी पिछड़ापन

भारत प्रौद्योगिकी में पिछड़ा है क्योंकि हमारे पास धन बहुत सीमित और अपर्याप्त है उच्च तकनीक वाले उत्पादों के लिए अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचा और कम कुशल भी मानव संसाधन जो घर में काम कर रहे हैं। 2001 में भारत आविष्कारों में 46वें स्थान पर था सूचक.

2.4.5 अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं

बुनियादी ढांचे की कमी से जीवन स्तर खराब होता है, आर्थिक घाटा होता है और सुधार होता है गरीबी। उदाहरण के लिए: जब किसी समुदाय में भार जैसे परिवहन बुनियादी ढांचे का अभाव होता है, तो इसका मतलब है कि उस समुदाय के लोग शहरों या नौकरी वाली जगहों पर यात्रा करने में असमर्थ हैं सोशल नेटवर्किंग के अवसर, साथ ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

2.4.6 जनसांख्यिकीय विशेषताएं

जनसंख्या सांख्यिकी में ऐसे संकेतक शामिल होते हैं जो जनसंख्या आकार, लिंग अनुपात, घनत्व और निर्भरता राशन को मापते हैं जबकि महत्वपूर्ण आंकड़ों में जन्म दर जैसे संकेतक शामिल होते हैं।

मृत्यु दर, और प्राकृतिक विकास दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, नैतिकता और प्रजनन दर।

2.4.7 निरक्षरता की उच्च दर

एक समूह के रूप में निरक्षरता दर उन सदस्यों के अनुपात को संदर्भित करती है जो निरक्षर आबादी का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत की औसत साक्षरता दर 77.70% है। भारत स्तर पर पुरुष साक्षरता 2021 है

84.70% और महिला साक्षरता 70.30% है।

2.4.8 एक द्वैतवादी अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था को द्वैतवादी विशेषता वाला माना जाता है क्योंकि इसमें अविकसित और प्रगतिशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं शामिल हैं। अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो अविकसित हैं और अविकसित हैं

पिछड़ा वर्ग.

2.4.9 प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

अविकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का या तो उपयोग नहीं किया जाता है या कम उपयोग किया जाता है या दुरुपयोग किया जाता है। किसी देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन नहीं
पूर्ण अर्थ में ऐसा हो।

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है
आज विकासशील देश. गैर-नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जिसमें शामिल हैं
तेल, गैस, खनिज और लकड़ी को अक्सर ट्रिगर करने वाले, बढ़ने वाले प्रमुख कारक के रूप में उद्धृत किया गया है
या दुनिया भर में हिंसक संघर्षों को कायम रखना।

2.4.10 उद्यमिता का अभाव

अविकसित देशों की एक अन्य विशेषता उद्यमशीलता क्षमता का अभाव है।
उद्यमिता उस सामाजिक व्यवस्था द्वारा बाधित होती है जो रचनात्मक अवसरों से इनकार करती है
शिक्षा संकाय। बाज़ार का छोटा आकार, पूंजी की कमी, बुनियादी सुविधाओं की कमी,
तकनीकी पिछड़ापन, और निजी संपत्ति का अभाव, स्वतंत्रता का अभाव
अनुबंध एवं कानून एवं व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने वाले उद्यम एवं पहल इन सभी संगठनों द्वारा किये गये
बहुत कठिन।

2.4.11 कार्य और जीवन के प्रति परंपरा से बंधा दृष्टिकोण

भारतीय समाज कई जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ है जिसके परिणामस्वरूप झगड़े होते हैं समाज में. उनके काम के प्रति समाज का रवैया अनुकूल नहीं है। का रवैया पुरुष परंपरा से बंधा हुआ है और उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाता है।

2.5 सारांश

हालाँकि, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास अलग-अलग अवधारणाएँ हैं परस्पर संबंधित और परस्पर समावेशी हैं। आर्थिक विकास की संकल्पना में आर्थिक और गैर-आर्थिक कारकों के बीच संबंधों को प्रतिबिंबित किया है आर्थिक विकास। विकसित और विकासशील देशों की विशेषताएं नहीं हैं विकास के विभिन्न स्तरों पर देशों के साथ बिल्कुल भिन्न लेकिन समान विशेषताएं।

2.6 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. आर्थिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. आत्मनिर्भरता

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर.
2. आर्थिक विकास के उद्देश्यों की व्याख्या करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या करें
2. विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताओं का परीक्षण करें

2.7 शब्दावली

1. आर्थिक विकास: एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि।
2. आर्थिक विकास: सामाजिक, तकनीकी एवं समग्र विकास में परिवर्तन विकास के साथ-साथ.

3. संरचनात्मक परिवर्तन: ये परिवर्तन भिन्न-भिन्न के सापेक्ष योगदान को दर्शाते हैं
क्षेत्र - सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र।

4. आत्मनिर्भरता: आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है कि एक देश अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करता है। इन्हें हासिल करने के लिए आवश्यक धन के संसाधनों के लिए यह अन्य देशों पर निर्भर नहीं है। आत्मनिर्भरता आयात की अनुमति देती है।

5. सतत विकास: वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को बिना पूरा किये
भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता करना।

6. समावेशी विकास: इसका अर्थ है अब तक बहिष्कृत जनसंख्या की समावेशिता
विकास प्रक्रिया में.

2.8 सन्दर्भ

1. आर्थिक वृद्धि विकास - सिबाब्रेट दास, एलेक्स मौरमौरेस।

2. हेंड्रिक वान डेन बर्ग द्वारा आर्थिक विकास विकास।

अध्याय

3

उपयोगिता विश्लेषण

3.0 उद्देश्य

3.1 परिचय

3.2 उपयोगिता का अर्थ

3.2.1 उपयोगिता का मापन

3.2.2 उपयोगिता के प्रकार

3.3 सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम

3.4 सम-सीमांत उपयोगिता का नियम

3.5 सारांश

3.6 मॉडल परीक्षा प्रश्न

3.7 शब्दावली

3.8 सन्दर्भ

3.0. उद्देश्य

उपयोगिता का अर्थ समझें

सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को समझें

कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझें

कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को समझें

सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम समझाइये

3.1. परिचय

उपयोगिता विश्लेषण आमतौर पर अर्थशास्त्र में उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा है। उपयोगिता विश्लेषण का उपयोग मांग सिद्धांत में, तर्कसंगत निर्णय लेने में, उनके आधार पर विकल्पों के मूल्यांकन में किया जाता है उपयोगिता और उपभोक्ता की संतुष्टि को मापने के लिए।

3.2. उपयोगिता का अर्थ

उपयोगिता की अवधारणा 1871 में विलियम स्टेनली जेवन्स द्वारा प्रस्तुत की गई थी। लोग वस्तुओं की मांग करें क्योंकि वे आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। उपयोगिता का अर्थ है एक की संतुष्टिदायक शक्ति चाहिए माल। आत्मनिरीक्षण से उपभोक्ता को संतुष्टि मिलती है। इसे परिभाषित भी किया जा सकता है वस्तु की संपत्ति के रूप में जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। उपयोगिता एक है व्यक्तिपरक, यह अलग-अलग व्यक्तियों के साथ भिन्न होता है। अर्थात अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग राशि प्राप्त होती है किसी दी गई वस्तु से उपयोगिता की.

3.2.1 उपयोगिता माप

उपयोगिता को मापने के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं।

(ए) कार्डिनल उपयोगिता

अल्फ्रेड मार्शल उपयोगिता के अनुसार, हम कार्डिनल संख्याओं के संदर्भ में माप सकते हैं। उपभोक्ता संतुष्टि को मात्रात्मक रूप से 1, 2, 3, 4, 5 अंकों में व्यक्त किया जाता है। यह दृष्टिकोण को कार्डिनल उपयोगिता के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण: एक सेब 25 यूनिट संतुष्टि देता है। यहां 25 का माप है कार्डिनल उपयोगिता.

(बी) साधारण उपयोगिता

जेआर हिक्स और राजद एलन ने क्रमिक उपयोगिता का पालन किया है। उपभोक्ता संतुष्टि को संख्याओं के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है, लेकिन हम तुलना यानी संतुष्टि की तुलना करते हैं दूसरे के साथ गुणात्मक रूप से मापा जाता है।

उदाहरणार्थ: चाय की तुलना में कॉफ़ी अधिक संतुष्टि देती है। I, II, III, IV की प्राथमिकता आदि का उपयोग सामान्य उपयोगिता के लिए किया जाता है।

3.2.2. उपयोगिता के प्रकार

उपयोगिताएँ चार प्रकार की होती हैं।

क) प्रपत्र उपयोगिता

कुछ वस्तुएँ अपने आकार द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, उन्हें रूप उपयोगिता के रूप में जाना जाता है। उदाहरणार्थ: लकड़ी के लट्ठे को मेज और कुर्सी में बदलना।

बी) स्थान उपयोगिता

सामान को जहां लोग चाहते हैं वहां स्थानांतरित करना प्लेस यूटिलिटी कहलाता है। उदाहरणार्थ: कच्चा माल उद्योग, तैयार माल उपभोक्ता बाजार में पहुँचते हैं, उन्हें उपयोगिता मिलती है।

ग) समय उपयोगिता

कुछ वस्तुओं को निश्चित समय पर ही उपयोगिता मिलेगी। उदाहरणार्थ: गर्मियों में शीतल पेय; चाय, सर्दियों में कॉफ़ी, स्वैटर; बरसात आदि में छाता।

घ) सेवा उपयोगिता

कुछ सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होती है। उदाहरणार्थ: एक अच्छे डॉक्टर की सेवाएँ, शिक्षक की उपयोगिता है.

3.3 सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम

परिचय: सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम मूल रूप से एचएच द्वारा समझाया गया था गोसेन ने 1854 में बनाया, इसलिए इसे गोसेन का पहला नियम कहा जाता है। अल्फ्रेड मार्शल, अपने प्रसिद्ध में पुस्तक "प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890" ने इसे वैज्ञानिक रूप से विकसित किया और लोकप्रिय बनाया लिखित।

परिभाषा:

“वह अतिरिक्त लाभ जो किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के स्टॉक में दी गई वृद्धि से प्राप्त होता है

उसके पास पहले से मौजूद स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ कमी आती है" (अल्फ्रेड मार्शल)।

अर्थ: इसमें बताया गया है कि यदि कोई उपभोक्ता वस्तु का स्टॉक बढ़ाता है,

उस अतिरिक्त स्टॉक की सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी।

धारणाएँ:

कानून निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है।

1. तर्कसंगतता: उपभोक्ता तर्कसंगत है। उसका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है।

2. कार्डिनल उपयोगिता: उपभोक्ता उपयोगिता को संख्याओं में मापा जा सकता है। उदाहरण: 1,2,3,4...

3. स्वतंत्र उपयोगिता: किसी भी वस्तु की उपयोगिता स्वतंत्र होती है।

4. धन की सीमान्त उपयोगिता स्थिर रहती है: यह धारणा आवश्यक है। सीमांत

धन की उपयोगिता स्थिर है. आय स्तर में कोई परिवर्तन नहीं.

5. सजातीय वस्तुएँ: वस्तुएँ सजातीय होती हैं।

6. सामान का आकार एक समान है।

7. वस्तुओं की खपत के बीच कोई समय अंतराल नहीं है।

8. वस्तु विभाज्य है

9. उपभोक्ता की रुचि, आदतें और प्राथमिकताएँ स्थिर रहती हैं।

10. उपभोक्ता को बाजार की पूरी जानकारी होती है।

कानून के उदाहरण:

कुल उपयोगिता (टीयू)

कुल उपयोगिता सभी संभव उपभोग से प्राप्त कुल संतुष्टि है

किसी वस्तु की इकाइयाँ.

ट्यून = एफ (क्यूएन)

जहां, 'एन' वस्तु की कुल उपयोगिता; एफ = कार्यात्मक संबंध; Qn = 'n' वस्तु की मात्रा

सीमांत उपयोगिता (एमयू)

सीमांत उपयोगिता किसी के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता का योग है

किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई।

एमयू = टीयू / क्यू

$$\text{सीमान्त उपयोगिता} = \frac{\text{कुल उपयोगिता में परिवर्तन}}{\text{माल की मात्रा में परिवर्तन}}$$

एमयूएन = ट्यून - ट्यून-1

सीमांत उपयोगिता = वर्तमान उपयोगिता - पिछली उपयोगिता

ऊपर दी गई धारणा ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम पर आधारित है।

कानून का चित्रण:

ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम मानव व्यवहार का एक सामान्य अवलोकन है। जैसे-जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करता है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त होने लगती है घट रही है और अंततः शून्य हो जाती है, और यदि वस्तु का उपयोग आगे भी जारी रखा जाता है इस चरण में, सीमांत उपयोगिता अंततः नकारात्मक हो जाती है।

तालिका नंबर एक

कमोडिटी की इकाइयाँ (सेब) प्र	कुल उपयोगिता (यूआईटीएलएस) टीयू	सीमांत उपयोगिता (यूआईटीएलएस) एमयू
1	30	-
2	80	50
3	110	30
4	120	10
5	120	0
6	110	-10

तालिका-1 बताती है कि कुल उपयोगिता और के बीच कार्यात्मक संबंध सीमांत उपयोगिता। उपभोक्ता अच्छा यानि सेब खा रहा है। जैसे उपभोक्ता उपभोग कर रहा है एक्स गुड से अधिक से अधिक प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस अतिरिक्त गुड से कम हो रही है।

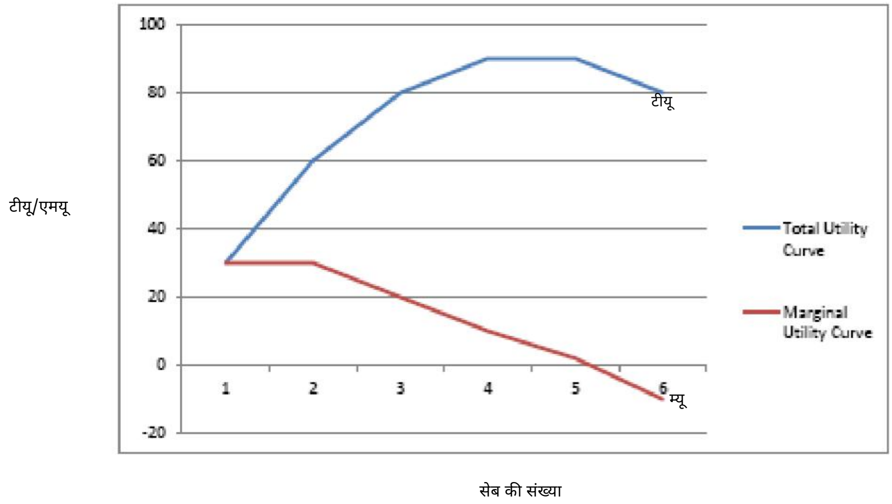

एक्स-अच्छे सेब का उपभोग करने वाले उपभोक्ता पहले से चौथे सेब का टीयू बढ़ रहा है लेकिन एमयू घट रहा है। जब 5thApple का उपभोग किया जाता है तो TU स्थिरांक MU शून्य हो जाता है

उपभोक्ता छठा सेब खाता है तो टीयू कम हो रहा है और एमयू नकारात्मक (-10) हो जाता है।

ए) जब टीयू घटती दर से बढ़ रहा है, तो एमयू घट रहा है।

बी) जब टीयू अधिकतम होता है, तो एमयू शून्य होता है।

सी) जब टीयू कम होने लगता है तो एमयू नकारात्मक हो जाता है।

कानून की सीमाएँ:

ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की कुछ सीमाएँ हैं। वे हैं

1. कानून अवास्तविक धारणाओं पर आधारित है।
2. उपभोक्ता का व्यवहार हर समय तर्कसंगत नहीं हो सकता है।
3. यदि सामान सजातीय (समान) नहीं है तो यह कानून लागू नहीं होगा।
4. उपभोक्ता की आय, स्वाद, आदतें बदलने पर यह कानून लागू नहीं होगा।
5. कानून अविभाज्य वस्तुओं और टिकाऊ वस्तुओं पर लागू नहीं किया जा सकता है।
6. उपभोक्ता शौक जैसे टिकट और सिक्का संग्रह इस कानून के अपवाद हैं।
7. कंजूस पर कानून लागू नहीं होगा.

कानून का महत्व:

1. यह कानून उत्पादकों को सामान के डिजाइन, पैटर्न और पैकिंग में बदलाव में मददगार है।
2. यह कानून वस्तुओं की कीमत के मूल्य सिद्धांत की व्याख्या करता है।
3. इस कानून के आधार पर सरकार टैक्स बना सकती है.
4. इस नियम के आधार पर उपयोग में मूल्य और विनिमय में मूल्य के बीच अंतर। पूर्व:
   हीरा - जल विरोधाभास।

3.4 समसीमांत उपयोगिता का नियम

परिचय: सम-सीमांत उपयोगिता का नियम उपभोग का एक महत्वपूर्ण नियम है।

इस नियम को एचएच गोसेन का द्वितीय नियम और अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है

प्रतिस्थापन का नियम.

कानून की परिभाषा:

मार्शल के अनुसार, “यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे कई उपयोगों में लाया जा सकता है, तो वह वितरित करेगा इसे वहां के उपयोगों के बीच वितरित किया जाएगा, वह इसे इन उपयोगों के बीच इस तरह वितरित करेगा कि इसमें समान हो सभी में सीमांत उपयोगिता.

कानून का कथन:

उपभोक्ता की एक निश्चित आय होती है। यदि वह सामान पर पैसा खर्च करता है, तो उसे अधिकतम मिलेगा
संतुष्टि। पैसा खर्च करने वाले उपभोक्ता को हर तरह से सिद्धांतों का पालन करना चाहिए
विभिन्न वस्तुओं से समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापन।

उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि और संतुलन के लिए मूलभूत शर्त

उपभोक्ता इस प्रकार हो सकता है:

MUX/Px = MUY / Py = MUz/Pz = MUn/ Pn

वहाँ, MUX , MUY , MUZ और MUN वस्तुओं x, y, z और कई की सीमांत उपयोगिताएँ हैं, और
Px, Py और Pz x, y, z वस्तुओं की कीमतें हैं।

कानून की मान्यताएँ:

1. उपयोगिता मापी जा सकती है।
2. अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता का व्यवहार तर्कसंगत हो।
3. धन की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है।
4. वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं।

तालिका 2

धन की इकाइयाँ (रुपये में)	व्यय की सीमांत उपयोगिता एक पर	की सीमांत उपयोगिता बी पर व्यय
1	20 (प्रथम)	18 (तीसरा)
2	18 (दूसरा)	16 (5वाँ)
3	16 (चौथा)	14
4	14	12
5	12	10
कुल उपयोगिता	80	70

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता वस्तु A तथा पर तीन रुपये खर्च करता है
बी पर दो रुपये, ताकि वह अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम कर सके। रुपये खर्च करके. ए पर 3, वह है
कुल उपयोगिता 54 प्राप्त हो रही है, और बी से कुल उपयोगिता 34 है। इसलिए 5 रुपये खर्च करके

ए और बी दोनों से वह 88 की कुल उपयोगिता प्राप्त करने में सक्षम है। (54+34)। इस प्रकार उपभोक्ता को मिलता है रुपये खर्च करके ए और बी की सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करके अधिकतम संतुष्टि। ए पर 3 और बी पर 2 रु.

कानून की सीमाएँ:

इस कानून की कुछ सीमाएँ हैं

1. यह अविभाज्य वस्तुओं के मामले में लागू नहीं है।
2. यह कानून कुछ अवास्तविक धारणा पर आधारित है।
3. अज्ञानी उपभोक्ता के मामले में सम-सीमांत उपयोगिता का नियम लागू नहीं होता है।
4. वास्तव में धन की सीमान्त उपयोगिता स्थिर नहीं रहती।
5. यह माना जाता है कि उपभोक्ता को पूर्ण ज्ञान है। लेकिन ये सही नहीं है.

कानून के महत्वपूर्ण:

1. उपभोक्ता का व्यय इस नियम पर निर्भर करता है।

1. यह नियम उत्पादन के सिद्धांत में उपयोगी है।
2. यह नियम वितरण के सिद्धांत में उपयोगी है।
3. यह कानून सरकार को बजट बनाने में सहायक है।

3.5 सारांश

उपयोगिता विश्लेषण में उपयोगिता अवधारणा, उपयोगिता के प्रकार और उपयोगिता के माप को समझाया गया है दृष्टिकोण. उपयोगिता का विश्लेषण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम और के नियम के आधार पर किया जाता है सम-सीमांत उपयोगिता।

3.6 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. उपयोगिता क्या है?
2. कार्डिनल यूटिलिटी क्या है?
3. साधारण उपयोगिता से आप क्या समझते हैं?
4. कुल उपयोगिता समझाइये।

5. सीमांत उपयोगिता के बारे में लिखें।

6. ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को परिभाषित करें।

7. सम-सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें।

8. उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता के बीच अंतर लिखिए।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. उपयोगिता विश्लेषण की अवधारणा को समझाइये।

2. कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच अंतर स्पष्ट करें।

3. कार्डिनल उपयोगिता, क्रमसूचक उपयोगिता की अवधारणा को समझाइये।

4. ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की परिभाषा एवं मान्यताएँ लिखिए।

5. ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम की सीमाओं और महत्व पर चर्चा करें।

6. सम-सीमांत उपयोगिता के कानून की अवधारणा और मान्यताओं की व्याख्या करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दीजिए।

1. ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम, इसकी सीमाएँ और महत्व की व्याख्या करें।

2. सम-सीमांत उपयोगिता के नियम का वर्णन करें।

3.8 शब्दावली

उपयोगिता: किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति या क्षमता को उपयोगिता कहते हैं

एक उपयोगिता के रूप में.

कार्डिनल उपयोगिता: उपभोक्ता संतुष्टि को संख्याओं अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 में व्यक्त किया जाता है

मात्रात्मक रूप से. इसे कार्डिनल यूटिलिटी कहा जाता है।

सामान्य उपयोगिता: उपभोक्ता संतुष्टि को इसके संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है

संख्याएँ, लेकिन हम तुलना में संतुष्टि को गुणात्मक रूप से माप सकते हैं

अन्य एक।

कुल उपयोगिता: एक व्यक्ति को मिलने वाली मनोवैज्ञानिक (महसूस) संतुष्टि की कुल मात्रा, वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहा जाता है।

सीमांत उपयोगिता: सीमांत उपयोगिता से प्राप्त उपयोगिता का योग है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की खपत

3.9 सन्दर्भ

1. तेलुगु अकादमी से इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक।
2. वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र (318), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।
3. तेलुगु अकादमी से बीए प्रथम वर्ष माइक्रो इकोनॉमिक्स।
4. सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत - एम.एल. झिंगन।

अध्याय

4

मांग विश्लेषण

4.0. उद्देश्य

4.1. परिचय

4.2. मांग समारोह

4.2.1. मांग के निर्धारक

4.3. मांग का नियम

4.3.1. मांग के नियम की विशेषताएँ

4.3.2. मांग के नियम की मान्यताएं

4.4. मांग के प्रकार

4.4.1. कीमत की मांग

4.4.2. आय की मांग

4.4.3. क्रॉस डिमांड

4.5. सारांश

4.6. मॉडल परीक्षा प्रश्न

4.7. शब्दकोष

4.8. संदर्भ

4.0. उद्देश्य

- मांग का अर्थ स्पष्ट करें
- मांग के प्रकारों को वर्गीकृत करें
- बाजार मांग अनुसूची का विश्लेषण करें
- मांग पर आय के प्रभाव का वर्णन करें
- क्रॉस डिमांड को समझाइये

4.1. परिचय

अर्थशास्त्र में मांग प्राथमिक अवधारणा है। इसलिए, अवधारणा को सीखना आवश्यक है मांग का. इस अध्याय में आप मांग का अर्थ सीखेंगे। मांग फलन, निर्धारक मांग की प्रकृति, मांग के प्रकार आदि।

मांग का अर्थ : सामान्यतः मांग और इच्छा अथवा एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है सामान और सेवाएँ खरीदें। लेकिन अर्थशास्त्र में, मांग का अर्थ है इच्छुक और सक्षम होना वह सामान या सेवाएँ खरीदें जो उपभोक्ता चाहता है।

उदाहरण के लिए, एक गरीब व्यक्ति की कार खरीदने की इच्छा कोई मांग नहीं है। भले ही कोई अमीर व्यक्ति हो कार खरीदना चाहता है, यदि वह कार की कीमत चुकाने में रुचि नहीं रखता है, तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता है एक मांग। इसका मतलब यह है कि अगर अमीर व्यक्ति कार की कीमत चुकाने को तैयार है, तभी इसे एक मांग माना जाता है। यानी, जब किसी के पास कार खरीदने की इच्छा हो, उसके पास वित्तीय साधन हों और वह उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो, तो इसे मांग माना जा सकता है।

मांग में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए।

- उत्पाद खरीदने की इच्छा.
- उन इच्छाओं को पूरा करने की वित्तीय क्षमता होनी चाहिए।
- उपभोक्ता को किसी वस्तु की कीमत चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए।

एक उपभोक्ता बाजार में मांग तभी पैदा कर सकता है जब उसके पास उपरोक्त तीनों हों विशेषणिक विशेषताएं।

परिभाषा:

मांग वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित समय पर और किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होते हैं दी गई कीमत. 36

4.2. मांग समारोह

यह एक गणितीय अभिव्यक्ति है, जो किसी वस्तु की मांग की मात्रा और उसे निर्धारित करने वाले कारक के बीच संबंध दर्शाती है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

$D_x = f(P_x, P_1, ..., P_n, Y, T)$

P_x = वस्तु की कीमत

$P_1, ..., P_n$ = अन्य वस्तुओं की कीमतें

Y = घर की आय;

एफ = कार्यात्मक संबंध

टी = घर का स्वाद और प्राथमिकताएँ।

मांग एक आश्रित चर है, जबकि $P_1, P_2, ... P_n, Y, T$ स्वतंत्र चर हैं।

4.2.1. मांग के निर्धारक:

ऐसे कई कारक हैं जो किसी वस्तु की मांग निर्धारित करते हैं। मांग समारोह
मांग और मांग निर्धारित करने वाले कारकों के बीच संबंध को दर्शाता है
एक अच्छा।

मांग के निर्धारक निम्नलिखित हैं।

किसी वस्तु की कीमत: किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत पर निर्भर करती है। में परिवर्तन
मांग तब होती है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है
विपरीतता से। जब मांग निर्धारित करने वाले अन्य कारक स्थिर होते हैं और उनमें परिवर्तन होता है
केवल अच्छे की कीमत. किसी वस्तु की मांग का उसकी कीमत से विपरीत संबंध होता है।

पीएक्स ---> डीएक्स

विकल्प और पूरकों की कीमत: किसी वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है
प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन से। कॉफी, चाय और स्कूटर, मोटरसाइकिल स्थानापन्न वस्तुओं के उदाहरण हैं।

इसमें किसी एक में वृद्धि से दूसरे विकल्प की मांग में वृद्धि होगी
माल। इसलिए, स्थानापन्न के मामले में, के बीच एक सकारात्मक संबंध मौजूद है
कीमत और मांग की गई मात्रा।

पूरक वस्तुओं के मामले में, इनके बीच एक नकारात्मक संबंध मौजूद है
वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा। गश्त, कार और चाय, चीनी हैं
पूरक वस्तुओं के उदाहरण. पूरक वस्तुओं के लिए संयुक्त मांग मौजूद है।

उपभोक्ता की आय:

उपभोक्ता की आय क्रय शक्ति को प्रभावित करती है। अन्य बातें स्थिर रहने के कारण जब भी किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, लेकिन घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। उदाहरण: जब उपभोक्ता की आय

बढ़ती है, वह सामान्य कारों से प्रीमियम कारों की ओर बेहतर वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।

उपभोक्ता की पसंद और प्राथमिकताएँ:

समाज में स्वाद और प्राथमिकताएँ या तो एक जैसी नहीं होती हैं और यह व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न हो सकती हैं।
स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं रहता. उदाहरण के लिए, फैशन में बदलाव, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रभावित करता है।

जनसंख्या:

किसी देश की जनसंख्या का आकार कुछ वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जितनी अधिक जनसंख्या होगी, खाद्यान्न, कपड़े आदि वस्तुओं की मांग उतनी ही अधिक होगी।

तकनीकी परिवर्तन:

तकनीकी प्रगति के कारण नई-नई खोजें बाजार में आती हैं। परिणामस्वरूप पुराने माल के स्थान पर नया माल आ जाता है। इसलिए पुरानी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, तकनीक में बदलाव के कारण लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल फोन ने ले ली है।

मौसम में बदलाव:

जलवायु की समान परिस्थितियों में बदलाव के कारण किसी वस्तु की मांग बदल सकती है। उदाहरण के लिए, सर्दियों में ऊनी कपड़े और गर्मियों में सूती कपड़ों की मांग अधिक हो जाती है।

4.3. मांग का नियम

कानून मांग, कीमत और मांग की मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। आम तौर पर कीमत कम होने पर उपभोक्ता अधिक या अधिक मात्रा में सामान खरीदता है और कीमत अधिक होने पर कम मात्रा की मांग की जाती है।

मार्शल के अनुसार, जब अन्य चीजें समान रहती हैं, तो राशि
कीमत में गिरावट के साथ मांग बढ़ती है और कीमत में वृद्धि के साथ मांग कम हो जाती है।

4.3.1. मांग के नियम की विशेषताएँ

मांग के नियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

विपरीत रिश्ते:

जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है और इसके विपरीत। कीमतें स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह कीमत की मात्रा में परिवर्तन के कारण होती है, मांग में परिवर्तन होता है। किसी के कारण नहीं
अन्य कारक।

समयावधि: उपभोक्ता की मांग एक विशेष समयावधि से जुड़ी होती है। कीमतें नहीं हैं वे समय के साथ निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे दैनिक मासिक साप्ताहिक आदि।

अन्य चीजें समान हैं:

यह कानून के रूप में एक धारणा है कि कीमत के अलावा अन्य चीजें जैसे आय, कीमत स्थानापन्न वस्तुओं और पूरक वस्तुओं आदि की स्थिति समान रहती है।

4.3.2. मांग के नियम की मान्यताएं

मांग के नियम की कुछ मुख्य धारणाएँ निम्नलिखित हैं:

i) उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं।

ii) उपभोक्ता की पसंद और पसंद में कोई बदलाव नहीं।

iii) विकल्प और पूरक की कीमत में कोई बदलाव नहीं।

iv) कोई नया विकल्प नहीं खोजा गया है।

v) भविष्य में कीमत में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं।

मांग के नियम के अपवाद निम्नलिखित हैं:

मांग के नियम के अनुसार, किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है।
लेकिन, कुछ परिस्थितियों में कीमत और मांग का सीधा आनुपातिक संबंध होता है।
इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता अधिक खरीदते हैं और जब कीमत गिरती है, तो वे कम खरीदते हैं।

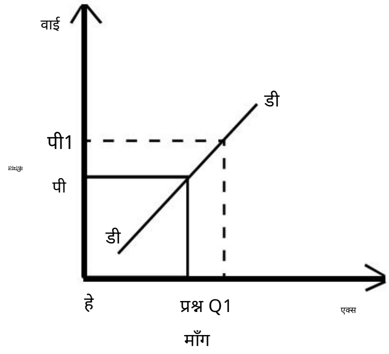

मात्रा की मांग

चित्र.1: असाधारण मांग वक्र

माँगी गई मात्राएँ OX अक्ष पर दिखाई गई हैं और कीमतें चित्र में OY अक्ष पर दिखाई गई हैं। डीडी असाधारण मांग वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर की ओर ढलता है। जब कीमत OP से OP तक बढ़ती है, तो मांग की गई मात्रा भी OQ से OQ तक बढ़ जाती है। यह है ?? मांग के नियम के विपरीत.

1) अटकलें:

यदि भविष्य में वस्तुओं की कीमतें और भी बढ़ने की उम्मीद है
उपभोक्ता अब इसे और अधिक खरीदेंगे। इसलिए, कीमत में वृद्धि से कमी नहीं हो सकती है
मांग जो मांग के नियम के विपरीत है।

2) गिफेन का विरोधाभास:

19वीं सदी में सर रॉबर्ट गिफेन ने देखा कि जब रोटी की कीमत बढ़ गई, तो इंग्लैंड में श्रमिकों ने मांस की खपत कम करके अधिक रोटी खरीदी क्योंकि रोटी उनकी भूख को संतुष्ट करने के लिए मुख्य भोजन है। इस प्रकार की स्थिति को 'गिफेन्स पैराडॉक्स' के नाम से जाना जाता है। कीमतें गिरने पर भी कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं और घटिया वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इस मामले में, मांग वक्र अपवाद दर्शाते हुए बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुकता है

मांग का नियम.

3) वेब्लेन प्रभाव:

वेब्लेन के अनुसार, उपभोक्ता किसी उत्पाद को उसके मूल्य के बजाय उसके मूल्य के आधार पर खरीदना चाहते हैं
उपयोगिता। वेब्लेन ने बताया कि हीरे, कीमती पत्थर जैसे कुछ सामान महंगे हैं
फर्नीचर आदि जिनकी मांग बहुत अमीर लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। यदि
इन वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं, गरीब लोग भी खरीद सकते हैं और इसलिए अमीर लोग खरीदना बंद कर देते हैं
इन वस्तुओं को क्योंकि इन वस्तुओं को कोई विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है।

4)भ्रम:

कभी-कभी, उपभोक्ताओं के मन में यह गलत धारणा विकसित हो जाती है कि ऊंची कीमत वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
यदि वस्तुओं की कीमत कम हो जाती है तो उन्हें लगता है कि साथ ही उनकी गुणवत्ता भी कम हो गई है
मध्यम वर्ग के लोग इन वस्तुओं को पसंद कर सकते हैं।

5) आवश्यक सामान:

टीवी, वॉशिंग मशीन, रसोई गैस, पेट्रोलियम जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग
मूल्य वृद्धि होने पर भी उत्पाद आदि बरकरार रहते हैं। लोग इसे खरीदना बंद नहीं कर सकते
नियमित आवश्यकताओं के उत्पाद.

6) कमी का डर:

जब निकट भविष्य में किसी वस्तु की कमी होने की आशंका हो
युद्ध की संभावना या अकाल या आर्थिक मंदी जैसी प्राकृतिक आपदा, उपभोक्ता प्रारंभ
उपलब्ध कीमत पर वस्तु खरीदना, यहां तक कि अधिक कीमत पर भी।

4.4. मांग के प्रकार

अर्थशास्त्र में मांग को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:

1) कीमत की मांग

2) आय मांग

3) क्रॉस डिमांड

4.4.1. कीमत की मांग

मूल्य मांग उस राशि से संबंधित है जो उपभोक्ता किसी दिए गए मूल्य पर किसी उत्पाद पर खर्च करने को तैयार है। मांग और कीमत का विपरीत संबंध है। इसका मतलब यह है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो मांग कम हो जाती है।

संतरे की कीमत (रुपये)	मांग की गई मात्रा (इकाइयाँ)
50	5
40	10
30	15
20	20
10	25

बाज़ार मांग अनुसूची

बाजार मांग अनुसूची एक वस्तु की मात्रा का एक सारणीबद्ध रूप है जो सभी उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त की जाती है
बाजार एक निश्चित कीमत पर खरीदारी करेगा। किसी भी कीमत पर, संबंधित मूल्य
मांग अनुसूची उस कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई सभी मात्राओं का योग है। यह है एक
व्यक्तिगत मांग अनुसूचियों का योग और विभिन्न की मांग को दर्शाता है
किसी वस्तु के लिए ग्राहक उसकी कीमत के संबंध में।

Market Demand Schedule

Price of Oranges Rs..	Quantity Demanded			Market Demand for Oranges (A+B+C)
	Consumer A	Consumer B	Consumer C	
25	4	5	6	15
24	6	8	10	24
23	8	11	14	33
22	10	14	18	42
21	12	17	22	51

व्यक्तिगत माँग वक्र और बाज़ार माँग वक्र

व्यक्तिगत मांग वक्र

बाज़ार मांग वक्र

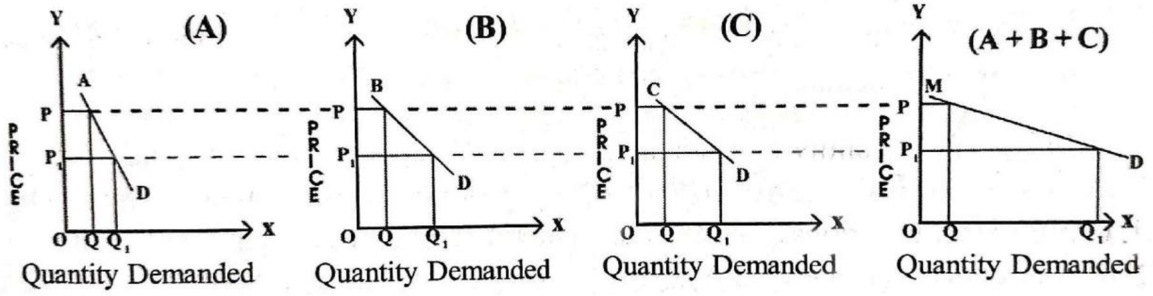

चित्र-2: व्यक्तिगत माँग वक्र और बाज़ार माँग वक्र

4.4.2. आय की मांग

आय की मांग आय और उसकी मात्रा के बीच संबंध को इंगित करती है वस्तु की मांग की गई। यह किसी वस्तु या सेवा की विभिन्न मात्राओं से संबंधित है उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित अवधि में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदा जाएगा, अन्य चीजें बराबर होना.

जैसे-जैसे आय बढ़ती है, बेहतर वस्तुओं या सामान्य वस्तुओं की माँग बढ़ती है। इन वस्तुओं के मामले में, आय के बीच सीधा आनुपातिक संबंध होगा और मांग. इसका मतलब है कि अगर आय बढ़ेगी तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। जैसा आय कम हो जाती है, घटिया वस्तुओं की मांग आय से विपरीत रूप से संबंधित होती है। इसका मतलब है, जब उपभोक्ता की आय गिरती है, तो घटिया वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता के रूप में आय बढ़ती है, घटिया वस्तुओं की माँग घटती है और सामान्य वस्तुओं की माँग घटती है। श्रेष्ठ वस्तुओं में वृद्धि होती है।

आय और मांग के बीच कार्यात्मक संबंध इस प्रकार है

डीएक्स= एफ(वाई)

जहां Dx = वस्तु X की मांग, Y= उपभोक्ता की आय और f = कार्य

तालिका-1: आय मांग अनुसूची

आय (रु.)	मांग (किग्रा)	
	अति उत्तम	इन्फीरियर गुड
2000	4	12
4000	6	10
6000	8	8
8000	10	6
10000	12	4

उपरोक्त तालिका बताती है कि जब भी आय बढ़ती है, तो बेहतर वस्तुओं की मांग की मात्रा बढ़ जाती है बढ़ती है और घटिया वस्तुओं की मांग की मात्रा घट जाती है।

सामान्य/उत्कृष्ट वस्तुओं के लिए आय की मांग

जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो सामान्य वस्तुओं या बेहतर प्रकार की वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है सामान बढ़ता है यानी सामान्य/बेहतर सामान की मांग के मामले में सकारात्मकता होती है मांग और आय के बीच संबंध. मांग वक्र का ऊपर की ओर सकारात्मक ढलान है बाएं से दाएं।

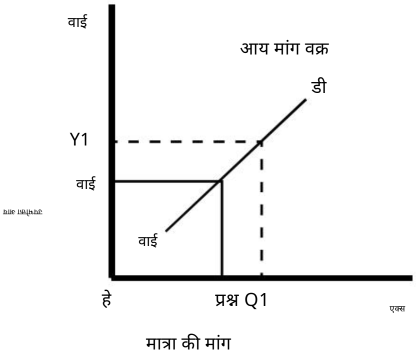

चित्र-3: बेहतर वस्तुओं के लिए आय की मांग

चित्र में, OX-अक्ष बेहतर वस्तुओं के लिए मांग की गई मात्रा को दर्शाता है और OY-अक्ष दर्शाता है उपभोक्ता की आय. YD आय मांग वक्र को सकारात्मक दर्शाता है ढलान। जब भी आय ओए से ओए तक बढ़ती है, तो बेहतर या की मांग की जाने वाली मात्रा सामान्य वस्तुएँ OQ से OQ तक बढ़ती हैं। वेब्लेन माल के मामले में आय मांग वक्र ऊपर की ओर ढलान

घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग:

घटिया वस्तुओं के मामले में, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है, तो मांग कम हो जाती है। इन वस्तुओं के मामले में, आय का मांग से विपरीत संबंध है।

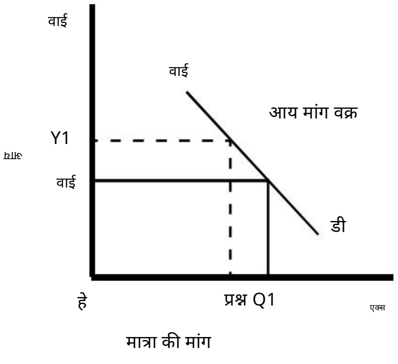

चित्र-4: आय घटिया वस्तुओं की मांग

चित्र में, OX-अक्ष मांग की गई मात्रा को दर्शाता है और OY-अक्ष मांग की मात्रा को दर्शाता है

उपभोक्ता की आय. जब उपभोक्ता की आय OY से OY तक बढ़ जाती है, तो

वस्तु की मांग की मात्रा OQ से OQ तक घट जाती है। YD आय मांग है

घटिया वस्तुओं के लिए वक्र. घटिया वस्तुओं की स्थिति में आय मांग वक्र नीचे की ओर झुक जाता है

बाएँ से दाएँ वार्ड। वक्र का ढलान ऋणात्मक है।

4.4.3. क्रॉस डिमांड

क्रॉस डिमांड: क्रॉस डिमांड उन वस्तुओं की मांग में बदलाव को इंगित करती है जब स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव होता है। क्रॉस-डिमांड विश्लेषण मानता है कि अन्य कारक, यानी, उत्पाद की कीमत, उपभोक्ता आय और प्राथमिकताएँ, स्थिर हैं.

क्रॉस-डिमांड का तात्पर्य स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव और उनकी मांग में बदलाव के बीच पारस्परिक संबंध से है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है:

डीएक्स= एफ(पाइ)

जहां Dx = वस्तु X की मांग, Py = वस्तु Y की कीमत, f = कार्यात्मक संबंध

स्थानापन्न वस्तुएँ: विभिन्न वस्तुएँ जो एक ही आवश्यकता को पूरा करती हैं, स्थानापन्न वस्तुएँ कहलाती हैं।

उदाहरण के लिए: चाय और कॉफ़ी, कोलगेट और क्लोज़-अप, पेप्सी और टम्सअप।

तालिका 2

कॉफी		चाय	
कीमत (रु.)	मांग (कप)	कीमत (रु.)	मांग (कप)
10	500	10	500
9	600	10	400

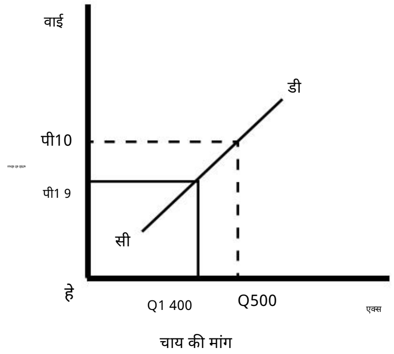

चित्र-5 :

चित्र में, OY-अक्ष कॉफी की कीमत को दर्शाता है और OX-अक्ष मात्रा को दर्शाता है चाय की मांग की. चाय की कीमत स्थिर रहने से कॉफी की कीमत में कमी आई है ओपी से ओपी तक, ओक्यू से ओक्यू तक चाय की मांग की मात्रा में कमी आती है। इसलिए, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर झुकता है।

संपूरक सामान:

कुछ वस्तुएँ सामूहिक रूप से किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए उपयोगी होती हैं। ऐसे सामान कहलाते हैं संपूरक सामान। उदाहरण के लिए: कार और ईंधन, चाय पाउडर और चीनी।

कार		ईंधन	
कीमत (लाख रूपये में) मांग (एल)		कीमत (रु.)	मांग (एल)
5	1000	75	500
5	2000	50	1000

तालिका के अनुसार, कारों की कीमत के बीच नकारात्मक संबंध है और ईंधन की मांग। यदि ईंधन की कीमत कम हो जाती है, तो कारों की मांग बढ़ जाती है। अगर ईंधन की कीमत बढ़ती है, कारों की मांग घट जाती है।

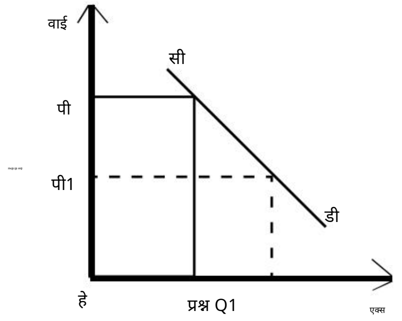

चित्र-6:

कार की मात्रा की मांग

चित्र 9 में, कारों की मांग को OX-अक्ष पर लिया गया है और ईंधन की कीमत को OX-अक्ष पर लिया गया है ओए-अक्ष. यदि ईंधन की कीमत OP से घटकर OP1 हो जाती है, तो कारों की मांग की मात्रा पूरक वस्तुओं के लिए OQ से OQ तक वृद्धि हो सकती है, क्रॉस डिमांड में नकारात्मक ढलान है।

4.5. सारांश

आर्थिक विश्लेषण के अनुसार मांग तब बनती है जब इच्छा साथ हो क्रय शक्ति के साथ. मांग वक्र a की मांग के बीच का संबंध है

वस्तु और उस मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कीमत और मांग में उलटा संबंध है संबंध जब मांग निर्धारित होती है और अन्य कारकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर वहाँ कुछ मामलों में व्युत्क्रम संबंध है। उसी घटिया सामान के मामले में, एक है आय और मांग के बीच नकारात्मक संबंध. क्रॉस-डिमांड मांग का वर्णन करता है वैकल्पिक अचार वाले सामान के लिए.

4.6. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. मांग को परिभाषित करें
2. मांग का नियम समझाइये।
3. कीमत मांग की व्याख्या करें।
4. स्थानापन्न वस्तुएँ क्या हैं? उदाहरण दो।
5. आय मांग क्या है?
6. उपयुक्त उदाहरणों के साथ पूरक वस्तुओं की व्याख्या करें।
7. गिफेन के विरोधाभास को समझाइये।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. माँग के नियम की विशेषताएँ समझाइये।
2. मांग के नियम की धारणाओं को स्पष्ट करें।
3. क्रॉस डिमांड की अवधारणा को स्पष्ट करें।
4. उपयुक्त तालिका एवं ग्राफ द्वारा आय मांग का वर्णन करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. मांग निर्धारित करने वाले कारकों का उल्लेख करें तथा किन्हीं दो की व्याख्या करें।
2. मांग के नियम में छूटों की व्याख्या करें।
3. मांग के प्रकारों का उल्लेख करें और किसी एक को ग्राफ की सहायता से समझाएं।

4.7. शब्दकोष

- मांग: किसी वस्तु या सेवा की कुछ मात्रा के लिए धनराशि का भुगतान करने की इच्छा और क्षमता से समर्थित इच्छा।

• मांग फलन: यह मांग की मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध है

एक अच्छे और सभी मात्रात्मक कारकों के लिए जो मांग निर्धारित करते हैं।

• स्थानापन्न वस्तुएँ: स्थानापन्न वे वस्तुएँ हैं जो समान आवश्यकता को पूरा करती हैं

• पूरक वस्तुएँ: पूरक वे वस्तुएँ हैं जो समान को संतुष्ट करती हैं

संयुक्त रूप से चाहते हैं.

• मूल्य मांग: यह वस्तु की कीमत के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है

और कितनी मात्रा की मांग की गई।

• आय मांग: यह आय के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है

उपभोक्ता और मांग की गई मात्रा।

• क्रॉस डिमांड: यह स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है।

4.8. संदर्भ

1. अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक प्रथम वर्ष TSBIE

2. बीए अर्थशास्त्र

3. एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 12

4. अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक एनआईओएस

अध्याय

5

उत्पादन विश्लेषण

5.0. उद्देश्य

5. 1. परिचय

5.1.1. उत्पादन की अवधारणा

5.2. उत्पादन के कारक

5.3. उत्पादन प्रकार्य

5.4. परिवर्तनशील अनुपात का नियम

5.5. पैमाने पर प्रतिफल का नियम

5.6. पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं

5.7. सारांश

5.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

5.9. शब्दकोष

5.10. संदर्भ

5.0. उद्देश्य

उत्पादन की अवधारणा और अर्थ को समझें

उत्पादन फलन की अवधारणा को समझाइये और उत्पादन फलन के प्रकारों की पहचान कीजिये

उत्पादन के कारकों को समझाइये तथा उनकी विशेषताओं को समझिये

परिवर्तनीय अनुपात के नियम का विश्लेषण करें। जानिए घटते रिटर्न के कारण.
कानून के महत्व को पहचानें.

पैमाने पर रिटर्न की पहचान करें और उनके प्रकारों को वर्गीकृत करें

आंतरिक और बाह्य अर्थव्यवस्थाओं को समझें और उनका विश्लेषण करें

5.1. परिचय

मनुष्य की इच्छाएँ असीमित हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि के साधन सीमित हैं और विकल्प भी हैं
उपयोग करता है. उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं। उत्पादन
इन वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने में मदद करता है। इस अध्याय में हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे
उत्पादन।

5.1.1 उत्पादन की अवधारणा

वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सबसे बुनियादी आर्थिक गतिविधि है और बाकी सभी
आर्थिक गतिविधियाँ यहीं से प्रवाहित होती हैं। उत्पादन उत्पादन अर्थात सामान बनाने की एक क्रिया है
भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे विभिन्न इनपुट का उपयोग करके सेवाएं। इस तरह,
उत्पादन इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है
उत्पादन के कारकों को विभिन्न संयोजनों में जोड़कर या बढ़ाकर या
उनका अनुपात कम हो रहा है।

उत्पादन उत्पादन के चार कारकों के सहयोग का परिणाम है। भूमि, श्रम, पूंजी
और संगठन. यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि किसी एक वस्तु का उत्पादन नहीं किया जा सकता
उत्पादन के इन चार कारकों में से किसी एक की सहायता के बिना। इसलिए, निर्माता
उत्पादन के सभी चार कारकों को तकनीकी अनुपात में जोड़ती है।

5.2. उत्पादन के कारक

वे कारक (इनपुट) जिनका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, के कारक कहलाते हैं उत्पादन। ये कारक प्रकृति में उपलब्ध या मानव निर्मित हो सकते हैं।

परिभाषा:- 'वे सभी वस्तुएँ एवं सेवाएँ जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती हैं, कहलाती हैं उत्पादन के कारक'। - प्रो बेनहम

उत्पादन के कारकों के प्रकार

सामान्य अर्थशास्त्र में, उत्पादन के कारकों को चार प्रकारों में वर्णित किया गया है और वे हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी को भी एक माना जाने लगा है कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा उत्पादन का कारक। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कारकों का वर्णन किया है उत्पादन के रूप में 1. संगठन (श्रम सहित) और 2. पूंजी (भूमि और सहित)। तकनीकी)। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन उत्पादन के कारकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और उनकी गुणवत्ता. आइए उत्पादन के इन कारकों के बारे में और जानें

1. भूमि: 'भूमि' शब्द का तात्पर्य सतह के उस भाग या मिट्टी से है जिसे हम पृथ्वी के रूप में देखते हैं। लेकिन में अर्थशास्त्र में भूमि का व्यापक अर्थ है, इसमें केवल सामान्य अर्थों में भूमि ही शामिल नहीं है शब्द बल्कि संपूर्ण सामग्री और शक्तियां जो प्रकृति मनुष्य को देती है भूमि, जल, वायु, खनिज, वर्षा, प्रकाश और गर्मी आदि जैसी आवश्यकताएँ। इस प्रकार, भूमि में कोई भी शामिल है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। भूमि संसाधन कच्चा माल हैं उत्पादन प्रक्रिया में. ये संसाधन नवीकरणीय हो सकते हैं, जैसे वन, या गैर-नवीकरणीय जैसे तेल या प्राकृतिक गैस।

2. श्रम: श्रम वह प्रयास है जिसके द्वारा लोग वस्तुओं के उत्पादन में योगदान करते हैं सेवाएँ। सामान्य भाषा में श्रम का उपयोग अक्सर श्रम के द्रव्यमान को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है। श्रम का अर्थ है कोई भी कार्य चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक मौद्रिक पुरस्कार के लिए किया गया। इसमें निचले स्तर से लेकर उच्चतम स्तर तक के कार्य शामिल हैं मौद्रिक पुरस्कार के लिए किया गया व्यावसायिक कार्य और इसके लिए किए गए कार्य को शामिल नहीं किया गया है आनंद या प्रेम. श्रम उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

3. पूंजी: अर्थशास्त्र में, पूंजी का तात्पर्य आमतौर पर धन से है। हालाँकि, पैसा कोई कारक नहीं है उत्पादन का क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में शामिल नहीं है। इसके बजाय, यह

उद्यमियों और फर्म मालिकों को सक्षम बनाकर उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाता है कारखाने, मशीनरी, उपकरण, उपकरण, कच्चा माल, धन आदि खरीदें। इस प्रकार, पूंजी इसका मतलब उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मानव निर्मित संसाधन हैं।

पूंजी व्यक्तियों या फर्मों द्वारा अपने वर्तमान के एक हिस्से से बचत के माध्यम से बनाई जाती है भविष्य की संपत्ति के निर्माण में योगदान देने वाली आय। पूंजी को उत्पादित भी कहा जाता है उत्पादन के कारक। पूँजी की उपलब्धता में विभिन्नताएँ एवं परिवर्तन होते रहते हैं। पूंजी गतिशीलता है.

4. संगठन या उद्यमी: संगठन से हमारा तात्पर्य उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है उद्यमी, उद्यमी उत्पादन के अन्य एजेंटों की गतिविधियों का समन्वय करता है जैसे भूमि, श्रम और पूंजी। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के अन्य कारक लाता है एक जगह पर। वह उनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया के लिए करता है। उद्यमिता का सम्बन्ध है नवोन्मेषी विचारों को स्थापित करना और उन्हें योजना और आयोजन द्वारा क्रियान्वित करना उत्पादन। उद्यमी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ही जोखिम उठाते हैं व्यवसाय और संभावित अवसरों की पहचान करना। उद्यमी जो आय अर्जित करते हैं लाभ कहा जाता है.

5.3. उत्पादन प्रकार्य

सरल शब्दों में, उत्पादन फ़ंक्शन इनपुट के बीच कार्यात्मक संबंध को संदर्भित करता है और आउटपुट. उत्पादन फलन किसी वस्तु की अधिकतम मात्रा निर्दिष्ट करता है दी गई मात्रा में इनपुट और प्रौद्योगिकी के साथ एक निश्चित समय में उत्पादन किया जाता है। उत्पादन फ़ंक्शन पूरी तरह से एक तकनीकी संबंध है जो कारक इनपुट और आउटपुट को जोड़ता है।

गणितीय रूप से, इनपुट और आउटपुट के बीच ऐसे बुनियादी संबंध को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है:

क्यू = एफ (एन, के, एल, ओ)

जहां Q = किसी निश्चित अवधि में उत्पादित उत्पाद की मात्रा; के = पूंजी; एल = श्रम; एन = भूमि और ओ = संगठन या उद्यमी।

उत्पादन में बदलाव के लिए उत्पादन के कारकों के अनुपात में बदलाव की आवश्यकता होती है।

उत्पादन फलन को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

1. अल्पावधि उत्पादन फलन: अल्पावधि में उत्पादन में वृद्धि या कमी संभव है

किसी भी एक इनपुट को स्थिर रखते हुए अन्य इनपुट को स्थिर रखें। इसे का नियम कहा जाता है

परिवर्तनशील अनुपात या घटता हुआ रिटर्न। जब कोई निर्माता उत्पादन में बदलाव लाता है

उत्पादन के कारकों में परिवर्तन के फलस्वरूप अनुपात में परिवर्तन होगा

उत्पादन के कारकों का संयोजन. इस प्रकार के आनुपातिक संबंध को कहा जाता है

किसी कारक पर रिटर्न का नियम.

2. दीर्घकालिक उत्पादन कार्य: लंबे समय में, एक फर्म के लिए सब कुछ बदलना संभव है

इसके पैमाने के अनुसार इनपुट। इसे पैमाने पर रिटर्न कहा जाता है। इस स्थिति में एक निर्माता बदल जाता है

उत्पादन के सभी कारक समान अनुपात में। इस प्रकार, के बीच आनुपातिक नेतृत्व

उत्पादन और उत्पादन के कारकों को पैमाने पर प्रतिफल के नियम के रूप में जाना जाता है।

5.4. परिवर्तनीय अनुपात का नियम

परिवर्तनशील अनुपात का नियम आर्थिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह एक लघु है

रन परिघटना जो तब घटित होती है जब किसी एक चर का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है

अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए कारक। अल्पकाल में उत्पादन के कारक होते हैं

दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं: निश्चित कारक और परिवर्तनशील कारक। यह संभव नहीं है

अल्पावधि में उत्पादन में परिवर्तन का एहसास करने के लिए निश्चित कारकों को बढ़ाना या घटाना।

परिवर्तनशील अनुपात के नियम को प्रारंभ में मार्शल ने घटते प्रतिफल का नियम कहा था।

घटते प्रतिफल का नियम बताता है कि लागू पूंजी और श्रम में वृद्धि

सामान्यतः भूमि पर खेती करने से कुल उत्पाद में बढ़ती दर से परिवर्तन होता है

प्रारंभ में, फिर वृद्धि के बाद घटती दर पर और कुछ समय बाद अंततः

गिरावट शुरू हो जाती है.

परिभाषाएँ: “जैसे-जैसे कारकों के संयोजन में कारक का अनुपात बढ़ता है

एक बिंदु, पहले सीमांत और फिर उस कारक का औसत उत्पाद कम हो जाएगा" - बेनहम।

“प्रौद्योगिकी की एक निश्चित स्थिति में अन्य निश्चित इनपुट के सापेक्ष कुछ इनपुट में वृद्धि होगी

आउटपुट में वृद्धि का कारण बनता है, लेकिन एक बिंदु के बाद समान परिवर्धन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आउटपुट होता है

अतिरिक्त इनपुट कम से कम होते जायेंगे।” - सैमुएलसन.

मान्यताएँ: परिवर्तनशील अनुपात का नियम या घटते प्रतिफल का नियम आधारित है
निम्नलिखित धारणाओं पर:

1. स्थिर प्रौद्योगिकी: प्रौद्योगिकी की स्थिति दी गई और स्थिर मानी जाती है।
इस अवधि के दौरान उत्पादन के तरीके और प्रौद्योगिकी अपरिवर्तित रहती है।

2. सजातीय कारक इकाइयाँ: परिवर्तनशील कारक की इकाइयाँ सजातीय होती हैं और प्रत्येक इकाई
गुणवत्ता और मात्रा में हर दूसरी इकाई के समान है।

3. अल्पावधि: कानून अल्पावधि में लागू होता है जहां सभी कारकों को बदलना संभव नहीं है
इनपुट.

4. कारक अनुपात परिवर्तनशील होते हैं। कानून मानता है कि कारक अनुपात परिवर्तनशील हैं। अगर
उत्पादन के कारकों को एक निश्चित अनुपात में संयोजित किया जाना चाहिए, कानून की कोई वैधता नहीं है।

5. उत्पाद को भौतिक इकाइयों में मापा जा सकता है।

इससे पहले कि हम कानून के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करें, आइए पहले अलग-अलग चीजों को समझें
वे शब्द जिनका उपयोग परिवर्तनशील अनुपात के नियम की व्याख्या में किया जाता है।

कुल उत्पाद (टीपी): यह सभी कारकों के प्रयासों से उत्पन्न कुल उत्पादन है
उत्पादन।

औसत उत्पाद (एपी): औसत उत्पाद कुल उत्पाद (टीपी) को कुल से विभाजित करने के बराबर होता है
परिवर्तनीय इनपुट की संख्या. दूसरे शब्दों में, यह चर की प्रति इकाई कुल उत्पाद है
कारक और इस प्रकार:

एपी=टीपी/एन

सीमांत उत्पाद (एमपी): यह किसी के परिणामस्वरूप कुल उत्पाद में किया गया योग है
इनपुट की एक और इकाई की वृद्धि। सीमांत उत्पाद या आउटपुट तब प्राप्त होता है जब उत्पादक
परिवर्तनशील कारकों में इनपुट की अतिरिक्त इकाइयाँ नियोजित करता है।

एमपी = ∆टीपी/∆एन या एमपी = टीपीएन - टीपीएन-1

कानून की व्याख्या:

परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझने के लिए आइए कृषि का उदाहरण लें।

मान लीजिए कि भूमि और श्रम उत्पादन के केवल दो कारक हैं। मान लीजिए कि उत्पादन के लिए 10 एकड़ ज़मीन और श्रम की 1 इकाई है।
इसलिए, भूमि-श्रम अनुपात 10:1 है।

अब, भूमि को स्थिर रखते हुए यदि श्रम की इकाइयों की संख्या 2 तक बढ़ा दी जाये, तो भूमि-
श्रम अनुपात 5:1 हो जाता है।

इसलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कानून कारक अनुपात में परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करता है

की मात्रा और इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। भूमि को अचल मानकर

कारक, परिवर्तनशील कारक अर्थात श्रम का उत्पादन इसकी सहायता से दिखाया जा सकता है

निम्न तालिका:

Table 1.

Units of Land	Units of Labour	Total Production	Average Production	Marginal Production
10 Acres	0	–	–	–
,,	1	20	20	20 } 1st stage MP > AP
,,	2	50	25	30 } 1st stage MP > AP
,,	3	90	30	40 } 1st stage MP > AP
,,	4	120	30	30 } AP = MP
,,	5	140	28	20 } 2nd stage MP=0 and TP Maximum
,,	6	150	25	10 } 2nd stage MP=0 and TP Maximum
,,	7	150	21.3	0 } 2nd stage MP=0 and TP Maximum
,,	8	140	17.5	–10 } 3rd stage MP < 0

तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम के तीन चरण हैं।

चरण I: पहले चरण में अधिक से अधिक खुराक होने पर औसत उत्पादन बढ़ता है

निश्चित कारक (भूमि) पर नियोजित श्रमिकों की संख्या। इस चरण में कुल, औसत और सीमांत

उत्पाद बढ़ रहे हैं तथापि यह देखा जा सकता है कि औसत और सीमांत उत्पाद बढ़ रहे हैं

केवल 4 इकाइयों तक बढ़ रहा है। बाद में श्रमिकों के अनुपात के कारण दोनों कम होने लगते हैं

भूमि पर्याप्त थी और भूमि का उचित उपयोग नहीं किया गया। यह पहले चरण का अंत है.

चरण II: दूसरा चरण वहां से शुरू होता है जहां पहला चरण समाप्त होता है या जहां AP=MP होता है। में

इस अवस्था में औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद गिरने लगते हैं। हमें उस सीमांत पर ध्यान देना चाहिए

उत्पाद औसत उत्पाद की तुलना में तेज़ दर से गिरता है। यहां, कुल उत्पाद बढ़ता है

घटती दर. श्रम की 7 इकाइयों पर यह अधिकतम सीमा पर होता है जहां सीमांत उत्पाद बन जाता है

शून्य जबकि औसत उत्पाद कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता।

चरण III: तीसरा चरण वहीं से शुरू होता है जहां दूसरा चरण समाप्त होता है। इसकी शुरुआत 8वीं यूनिट से होती है.

यहां, सीमांत उत्पाद नकारात्मक है और कुल उत्पाद गिरता है लेकिन औसत उत्पाद अभी भी है

सकारात्मक। इस स्तर पर, श्रम इकाइयों में कोई भी अतिरिक्त वृद्धि नकारात्मक सीमांत की ओर ले जाती है

उत्पाद।

चित्रमय प्रस्तुति:

चित्र 1 में, OX अक्ष पर, हमने मजदूरों की संख्या मापी है जबकि उत्पाद की मात्रा है ओए अक्ष पर दिखाया गया है। टीपी कुल उत्पाद वक्र है। बिंदु 'ई' तक, कुल उत्पाद बढ़ रहा है बढ़ती दर। बिंदु E और F के बीच यह घटती दर से बढ़ रही है। यहाँ सीमांत उत्पाद गिरने लगा है. बिंदु 'M' पर अर्थात, जब मजदूरों की कुल 7 इकाइयाँ कार्यरत हैं उत्पाद अधिकतम है जबकि सीमांत उत्पाद शून्य है। इसके बाद यह कम होने लगता है नकारात्मक सीमांत उत्पाद के अनुरूप। चित्र के निचले हिस्से में एमपी सीमांत है उत्पाद वक्र.

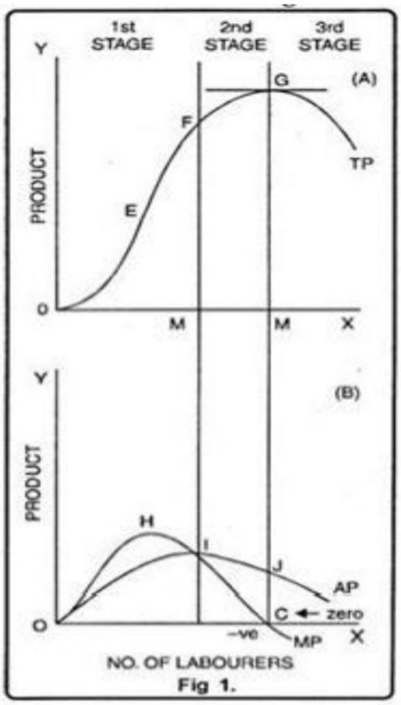

आकृति 1

बिंदु 'H' तक सीमांत उत्पाद बढ़ता है। बिंदु 'H' पर, अर्थात, जब मजदूरों की 3 इकाइयाँ हों नियोजित, यह अधिकतम है। उसके बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। सीमांत बिंदु C पर उत्पाद शून्य हो जाता है और यह ऋणात्मक हो जाता है। एपी वक्र औसत उत्पाद का प्रतिनिधित्व करता है। बिंदु 'I' से पहले, औसत उत्पाद सीमांत उत्पाद से कम है। बिंदु 'I' पर औसत उत्पाद अधिकतम पर है. बिंदु 'I' तक, औसत उत्पाद बढ़ता है लेकिन उसके बाद यह कम होने लगता है।

परिवर्तनीय अनुपात के नियम का महत्व और प्रयोज्यता:

परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन की किसी भी शाखा में सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। यह अर्थशास्त्र में कई सिद्धांतों का आधार बनता है। जनसंख्या का माल्थसियन सिद्धांत

यह इस तथ्य से उपजा है कि जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्य आपूर्ति तेजी से नहीं बढ़ती है कृषि में घटते प्रतिफल के नियम के लागू होने के कारण।

रिकार्डो ने भी अपना लगान सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित किया। उनके अनुसार किराया इसलिये उत्पन्न होता है घटते प्रतिफल के नियम का संचालन अतिरिक्त खुराक के प्रयोग को बाध्य करता है भूमि के एक टुकड़े पर श्रम और पूंजी। इसी प्रकार ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और वितरण के सिद्धांत में घटती सीमांत भौतिक उत्पादकता भी शामिल है इस सिद्धांत पर आधारित.

अविकसितों की समस्याओं को समझने के लिए कानून का मौलिक महत्व है देशों. ऐसी कृषि अर्थव्यवस्थाओं में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है जनसंख्या में वृद्धि के साथ. इससे गिरावट या यहां तक कि शून्य या नकारात्मक सीमांत हो जाता है श्रमिकों की उत्पादकता. यह घटते प्रतिफल के नियम के संचालन की व्याख्या करता है एलडीसी अपने गहन रूप में। रगनार नर्कसे ने इन प्रच्छन्नों का उपयोग करने के तरीके सुझाए हैं बेरोजगार श्रमिकों को निकालकर उन व्यवसायों में लगाना जहां सीमांत उत्पादकता सकारात्मक है.

5.5. पैमाने पर प्रतिफल का नियम

यह एक दीर्घकालिक विश्लेषण है. पैमाने पर प्रतिफल का नियम संबंध की व्याख्या करता है लंबे समय में आउटपुट और इनपुट के पैमाने के बीच जब सभी इनपुट बढ़ जाते हैं समान अनुपात. मांग में दीर्घकालिक बदलाव को पूरा करने के लिए, कंपनी अपने पैमाने को बढ़ाती है कारखाने में अधिक स्थान, अधिक मशीनों तथा मजदूरों का उपयोग करके उत्पादन करना।

मान्यताओं

1. उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील कारक हैं। वे श्रम और भूमि हैं। यहाँ उत्पादन के कारकों जैसे संगठन को श्रम, पूंजी और के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है प्रौद्योगिकी को भूमि के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

2. प्रौद्योगिकी स्थिर है

3. एक पूर्णतः प्रतिस्पर्धी बाज़ार है

4. उत्पाद को भौतिक रूप में मापा जा सकता है

5. उत्पादन के सभी कारक सजातीय हैं।

परिभाषाएँ: रोजर मिलर के अनुसार पैमाने पर रिटर्न का नियम "संबंध" को संदर्भित करता है उत्पादन में परिवर्तन और उत्पादन के सभी कारकों में आनुपातिक परिवर्तन के बीच।

लीबाफस्की के अनुसार पैमाने पर रिटर्न का नियम "कुल आउटपुट के व्यवहार को संदर्भित करता है।" इनपुट विविध हैं और यह एक दीर्घकालिक अवधारणा है"

पैमाने पर प्रतिफल के नियम के प्रकार: पैमाने पर प्रतिफल को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वे हैं: I) पैमाने पर बढ़ता रिटर्न, II) पैमाने पर लगातार रिटर्न और III) पैमाने पर घटता रिटर्न।

आइए पैमाने पर प्रतिफल के नियम के व्यवहार को समझाने के लिए एक संख्यात्मक उदाहरण लें।

तालिका-2: पैमाने पर रिटर्न

उत्पादन का इकाई पैमाना	(श्रम की संख्या+भूमि में वृद्धि) रिटर्न	कुल	सीमांत रिटर्न	को वापस आता है पैमाना
1	1+2	4	4	स्टेज I (की बढ़ती रिटर्न)
2	2 + 4	10	6	
3	3 + 6	18	8	
4	4 + 8	28	10	चरण II (स्थिर रिटर्न)
5	5+10	38	10	
6	6+12	48	10	
7	7+14	56	8	चरण III (घट रहा है रिटर्न)
8	8+16	62	6	

तालिका 1 के डेटा को चित्र-2 के रूप में दर्शाया जा सकता है

चित्र-2 में, OX अक्ष के पैमाने को दर्शाता है जबकि उत्पादन (श्रम और पूंजी में वृद्धि)। ओए अक्ष सीमांत रिटर्न में वृद्धि दर्शाता है (सीमांत आउटपुट)। जब श्रम और भूमि बढ़ती है, आउटपुट भी R से P तक बढ़ता है जो कि अधिक है उत्पादन के कारकों अर्थात श्रम और भूमि की तुलना में।

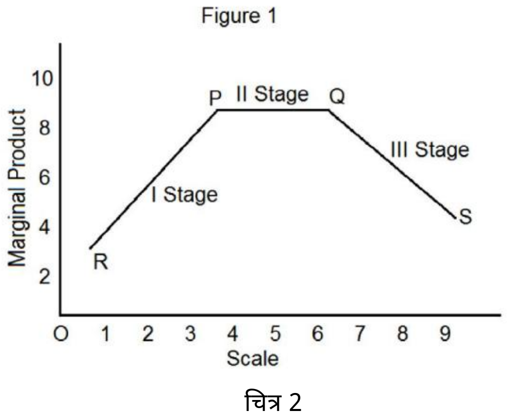

चित्र 2

आरएस = स्केल वक्र पर लौटता है

आरपी = खंड; पैमाने का बढ़ता प्रतिफल

पीक्यू = खंड; पैमाने के अनुसार निरंतर रिटर्न

क्यूएस = खंड; पैमाने पर घटता रिटर्न

I. पैमाने पर बढ़ता रिटर्न: चित्र-2 में, चरण I पैमाने पर बढ़ते रिटर्न को दर्शाता है।

इस चरण के दौरान, फर्म विभिन्न आंतरिक और बाह्य अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लेती है जैसे

आयामी अर्थव्यवस्थाएं, अविभाज्यता से बहने वाली अर्थव्यवस्थाएं, की अर्थव्यवस्थाएं

विशेषज्ञता, तकनीकी अर्थव्यवस्थाएं, प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएं और विपणन अर्थव्यवस्थाएं।

अर्थव्यवस्थाओं का मतलब केवल कंपनी के लिए फायदे से है। इन अर्थव्यवस्थाओं के कारण, फर्म को एहसास होता है

पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। मार्शल बढ़ते रिटर्न को "बढ़े हुए" के रूप में समझाता है

के विस्तार के पैमाने के साथ बेहतर संगठन में श्रम और पूंजी की दक्षता”

उत्पादन और रोजगार कारक इकाई। इसे किसी संगठन की अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है

उत्पादन के प्रारंभिक चरण. बढ़ते रिटर्न के कारण हैं:

1. मशीनों, प्रबंधन, श्रम, वित्त आदि में अविभाज्यताएं हो सकती हैं। उपकरण या कुछ गतिविधियों की एक छोटी सी वस्तु का आकार न्यूनतम होता है

   और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है

   छोटी इकाइयों में.

2. पैमाने पर बढ़ता रिटर्न भी विशेषज्ञता और श्रम विभाजन का परिणाम है,

   जब फर्म का पैमाना बढ़ता है, तो विशेषज्ञता के लिए व्यापक जोखिम होता है

   श्रम विभाजन।

3. जैसे-जैसे फर्म का विस्तार होता है, उसे उत्पादन की आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का आनंद मिलता है। यह करने में सक्षम हो सकता है

   बेहतर मशीनें स्थापित करें, अपने उत्पाद अधिक आसानी से बेचें, सस्ते में पैसा उधार लें, खरीदारी करें

   अधिक कुशल प्रबंधक और श्रमिकों आदि की सेवाएँ।

द्वितीय. स्केल पर निरंतर रिटर्न: चित्र-2 में, चरण II स्केल पर निरंतर रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है।

इस चरण के दौरान, पहले चरण के दौरान अर्जित अर्थव्यवस्थाएं लुप्त होने लगती हैं

विसंगतियाँ उत्पन्न होती हैं। विसंगतियाँ शब्द फर्म के लिए सीमित कारकों को संदर्भित करता है

विस्तार। जब कोई कंपनी अपने दायरे से बाहर विस्तार करती है तो विसंगतियों का उभरना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है

एक निश्चित चरण. चरण II में, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं और विसंगतियां बिल्कुल संतुलन में हैं

आउटपुट की एक विशेष सीमा पर। जब कोई फर्म पैमाने पर निरंतर रिटर्न पर होती है, तो वृद्धि होती है

सभी इनपुट आउटपुट में आनुपातिक वृद्धि की ओर ले जाते हैं लेकिन एक हद तक।

लगातार रिटर्न के कारण हैं:

1. जब किसी फर्म द्वारा आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का आनंद लिया जाता है तो पैमाने पर रिटर्न अपरिवर्तनीय होता है आंतरिक विसंगतियों द्वारा निष्प्रभावी किया गया ताकि उत्पादकता उसी अनुपात में बढ़े।
2. एक अन्य कारण बाहरी अर्थव्यवस्थाओं और बाहरी विसंगतियों का संतुलन है।
3. पैमाने पर अपरिवर्तनीय रिटर्न तब भी होता है जब उत्पादन के कारक पूरी तरह से होते हैं विभाज्य, प्रतिस्थापन योग्य, मानकीकृत और उनकी आपूर्ति किसी भी स्थिति में पूर्णतः लोचदार होती है कीमतें.

इसीलिए पैमाने पर अपरिवर्तनीय रिटर्न के मामले में, उत्पादन कार्य 'सजातीय' होता है डिग्री वन' का.

तृतीय. पैमाने पर घटते रिटर्न: चित्र-2 में, चरण III घटते रिटर्न को दर्शाता है घटता रिटर्न. यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई फर्म इसके बाद भी अपने परिचालन का विस्तार करती है निरंतर रिटर्न का बिंदु. घटते प्रतिफल का अर्थ है कि कुल उत्पादन में वृद्धि नहीं होना इनपुट में वृद्धि के अनुसार आनुपातिक। इस कारण सीमांत उत्पादन घटने लगती है (तालिका-2 देखें)। घटते रिटर्न को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं प्रबंधकीय अक्षमता और तकनीकी बाधाएँ। घटते रिटर्न के कारण हैं:

1. अविभाज्य कारक अक्षम और कम उत्पादक हो सकते हैं।
2. फर्म आंतरिक विसंगतियों का अनुभव करती है। व्यवसाय बोझिल हो सकता है और पर्यवेक्षण और समन्वय की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बड़ा प्रबंधन बनाता है नियंत्रण की जटिलताएँ और कठोरताएँ।
3. इन आंतरिक विसंगतियों में पैमाने की अतिरिक्त बाहरी विसंगतियाँ भी शामिल हैं। इन उच्च कारक मूल्य से या कारकों की घटती उत्पादकता से घटित होता है।

5.6. पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं

पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ फर्मों द्वारा अनुभव किए गए लागत लाभों को संदर्भित करती हैं जैसे वे बढ़ते हैं और बनते हैं अधिक कुशल। पैमाने की अर्थव्यवस्था का एहसास तब होता है जब एक फर्म आकार में बढ़ती है और सक्षम होती है किसी वस्तु की उत्पादन लागत को बड़ी संख्या में इकाइयों तक फैलाना। की अर्थव्यवस्थाएँ मार्शल द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन को आंतरिक अर्थव्यवस्था और बाह्य में वर्गीकृत किया गया है अर्थव्यवस्थाएँ।

(ए) आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ - उनके कारण और प्रकार

किसी फर्म की आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ तब आंतरिक होती हैं जब उसकी उत्पादन लागत कम हो जाती है उत्पादन बढ़ता है. वे "एकल कारखाने या स्वतंत्र रूप से एक एकल फर्म के लिए खुले हैं अन्य फर्मों की कार्रवाई वे फर्म के उत्पादन के पैमाने में वृद्धि के परिणामस्वरूप होते हैं जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता तब तक इसे हासिल नहीं किया जा सकता। वे किसी के आविष्कारों का परिणाम नहीं हैं प्रकार लेकिन उत्पादन के ज्ञात तरीकों के उपयोग के कारण होते हैं जो एक छोटी फर्म नहीं करती है सार्थक खोजें।"

कारण - किसी फर्म के बढ़ने पर आंतरिक अर्थव्यवस्थाएं घटित होंगी और दो कारणों से होती हैं जिन कारकों पर इस प्रकार चर्चा की गई है। वे हैं (1) अविभाज्यताएं, और (2) अटकलें।

1. अविभाज्यताएँ - उत्पादन के कई निश्चित कारक इस अर्थ में अविभाज्य हैं इनका उपयोग एक निश्चित न्यूनतम आकार में किया जाना चाहिए। ऐसे “उत्पादन के कारक हो सकते हैं।” काफी बड़े आउटपुट पर सबसे अधिक कुशलता से नियोजित किया जाता है, लेकिन छोटे पर कम कुशलता से काम किया जाता है आउटपुट क्योंकि उन्हें छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, जिन अविभाज्य कारकों का उपयोग क्षमता से कम किया जा रहा था, उनका उपयोग किया जा सकता है संपूर्ण क्षमता जिससे लागत कम हो जाएगी। श्रम के मामले में ऐसी अविभाज्यताएँ उत्पन्न होती हैं, मशीनें, विपणन वित्त और अनुसंधान।

2. विशेषज्ञता - श्रम का विभाजन जो विशेषज्ञता की ओर ले जाता है वह एक अन्य कारण है आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का. जब कोई फर्म आकार में विस्तार करती है, तो न केवल उसके उत्पादन में बढ़ती है, लेकिन इनपुट की मात्रा और मजदूरों की संख्या भी बढ़ जाती है। श्रम विभाजन की आवश्यकता जिसके तहत प्रत्येक श्रमिक को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है कार्य और अधिक दक्षता के लिए प्रक्रियाओं को उप-प्रक्रियाओं में विभाजित करना।

आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार

1. तकनीकी अर्थव्यवस्थाएँ - ये तब चिंता का विषय बन जाती हैं जब कोई फर्म अच्छा काम करती है उत्पादन के उपकरण और तकनीकें. परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ता है और निर्माण की प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। इसे आगे पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है जैसे कि बेहतर तकनीकों की अर्थव्यवस्थाएं, बढ़े हुए आयाम की अर्थव्यवस्थाएं, जुड़ी हुई प्रक्रियाओं की अर्थव्यवस्थाएं, उप-उत्पादों के उपयोग की अर्थव्यवस्थाएं और अर्थव्यवस्थाएं बढ़ी हुई विशेषज्ञता का.

2. विपणन अर्थव्यवस्थाएँ - एक बड़ी चिंता व्यापार की अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करती है। यह यह विभिन्न कच्चे माल की आवश्यकताओं को एकमुश्त खरीदता है और इसलिए सक्षम है उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले इनपुट के रूप में रचनात्मक शर्तों पर सुरक्षित करने के लिए शीघ्र वितरण, परिवहन रियायतें आदि।

3. प्रबंधकीय अर्थव्यवस्थाएँ - एक बड़ी कंपनी देखरेख के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है और विभिन्न विभागों को नियंत्रित करते हैं। विनिर्माण के लिए एक अलग मद हो सकता है, असेंबलिंग, पैकिंग, मार्केटिंग और सामान्य प्रशासन आदि को निर्देशित करता है कार्यात्मक विशेषज्ञता जो संस्था की उत्पादक दक्षता को बढ़ाती है।

4. वित्तीय अर्थव्यवस्थाएँ - एक बड़ी फर्म सस्ता और समय पर वित्त दोनों प्राप्त कर सकती है बैंकों और बाज़ार से क्योंकि इसके पास बड़ी संपत्ति और साख है। यह भी हो सकता है पूंजी बाजार में शेयर और डिबेंचर जारी करके अतिरिक्त पूंजी लाना।

5. जोखिम वहन करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ - एक बड़ी फर्म एक छोटी फर्म की तुलना में बेहतर स्थिति में होती है अपना ख़तरा फैला रहा है. यह विभिन्न वस्तुएं बना सकता है और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में बेच सकता है। अपने आलेखों के विविधीकरण से विशाल चिंता का पतन करने में सक्षम है एक उत्पाद के नुकसान को दूसरे के लाभ से संतुलित करके जोखिम।

6. अनुसंधान की अर्थव्यवस्थाएँ - एक बड़ी संस्था एक छोटी संस्था की तुलना में बड़े संसाधन रखती है चिंता का विषय है और अपनी स्वयं की अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित कर सकता है और प्रशिक्षित अनुसंधान को नियोजित कर सकता है कर्मी। जब वे नई उत्पादन तकनीकों का आविष्कार करते हैं या बाद की प्रगति करते हैं यह उस फर्म की संपत्ति बन जाती है जो इनका उपयोग अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए करती है लागत कम करना.

(बी) बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ

बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ एक फर्म के लिए बाहरी होती हैं जो उसके उत्पादन के समय उपलब्ध होती हैं उद्योग के विस्तार से ही संपूर्ण उद्योग का विकास होता है। वे "ए द्वारा साझा किए गए हैं।" किसी उद्योग या समूह में उत्पादन का पैमाना होने पर फर्मों या उद्योगों की संख्या या उद्योग बढ़ते हैं. आकार में वृद्धि होने पर उन पर किसी एक फर्म का एकाधिकार नहीं होता बल्कि इसे तब प्रदान किया जाता है जब कुछ अन्य कंपनियां बड़ी हो जाती हैं।

बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ उद्योग के भीतर सभी फर्मों को उद्योग के आकार के अनुसार लाभ देती हैं फैलता है. ऐसी अर्थव्यवस्थाएं चिंता का विषय बन जाती हैं जब उद्योग किसी विशेष क्षेत्र में स्थानीयकृत होता है क्षेत्र नवप्रवर्तन करता है और विशेषज्ञता विकसित करता है।

1. एकाग्रता की अर्थव्यवस्थाएँ - जब कोई उद्योग किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में केंद्रित होता है चिंता के सभी सदस्य कुछ व्यापक अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं। कुशल श्रमिक हैं सभी फर्मों के लिए उपलब्ध है। परिवहन और संचार के साधन काफी हैं सुधार हुआ. उद्योग रेलवे अधिकारियों से अतिरिक्त सुविधाओं की मांग कर सकता है अधिक वैगन, लोडिंग और अनलोडिंग आदि।

2. सूचना की अर्थव्यवस्था - एक उद्योग अनुसंधान स्थापित करने के लिए अच्छी स्थिति में है प्रयोगशालाएँ एक बड़ी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि यह बड़े संसाधनों को एकत्रित करने में सक्षम है। यह रोजगार दे सकता है उच्च वेतनभोगी और अधिक अनुभवी अनुसंधान कर्मी। इनका फल रूप में होता है नवीन नवाचारों की चिंताओं को एक वैज्ञानिक पत्रिका के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

3. कल्याण की अर्थव्यवस्थाएँ - एक उद्योग एक बड़ी चिंता से संबंधित है श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं देने के लिए लाभप्रद स्थिति। उसे यहां जमीन मिल सकती है क्षेत्र के नगर निगम से रियायती दरें और सुविधाएं प्राप्त करें श्रमिकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए आवास कालोनियों की स्थापना के लिए सुविधाएँ।

4. विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाएं - चिंता यह है कि एक उद्योग भी लाभ उठा सकता है विशेषज्ञता की अर्थव्यवस्थाएँ. जब किसी उद्योग का आकार बड़ा हो जाता है तो चिंताएं शुरू हो जाती हैं समग्र रूप से विभिन्न प्रक्रियाओं और उद्योग के लाभों पर विशेषज्ञता।

5. बुनियादी ढांचे की अर्थव्यवस्थाएं: जब किसी उद्योग में सभी कंपनियां केंद्रित होती हैं एक ही स्थान पर सरकार परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। बैंकिंग, बीमा, सूचना, बिजली आदि। कुछ मामलों में निजी संगठन ये बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया करा सकता है. सब कुछ एक ही स्थान पर होना संबंधित फर्मों के लिए इन सुविधाओं से जुड़ी लागत कम कर देता है इस स्थान पर उद्योग.

5.7. सारांश

आगतों को अंतिम वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहा जाता है। का रिश्ता उत्पादन के कारकों और उत्पादन के बीच के अंतर को उत्पादन फलन कहा जाता है। अल्पावधि में, यह अन्य इनपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट को बढ़ाना संभव है। यह कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपात या घटते प्रतिफल के नियम के रूप में। पैमाने पर प्रतिफल का नियम बताता है जब सभी इनपुट होते हैं तो लंबे समय में आउटपुट और इनपुट के पैमाने के बीच संबंध उसी अनुपात में वृद्धि हुई। पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं अनुभव किए गए लागत लाभों को संदर्भित करती हैं फर्मों द्वारा जैसे-जैसे वे बढ़ते हैं और अधिक कुशल हो जाते हैं, उन्हें पैमाने की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन की अर्थव्यवस्थाओं को मार्शल ने आंतरिक और में वर्गीकृत किया है अर्थव्यवस्थाएँ और बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ।

5.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. उत्पादन के कारक क्या हैं?
2. पैमाने पर निरंतर रिटर्न से आपका क्या मतलब है?
3. उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ क्या हैं?
2. भूमि की विशेषताओं के बारे में लिखिए।
3. दीर्घकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. परिवर्तनीय उत्पादन फलन के नियम के बारे में उपयुक्त चित्र सहित लिखिए।
2. पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं पर चर्चा करें।
3. पैमाने पर प्रतिफल के नियम के बारे में विस्तार से बताएं।

5.9. शब्दकोष

1. उत्पादनआयन: कच्चे माल को अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है उत्पादन कहा जाता है.

2. उत्पादन के कारक: वे कारक (इनपुट) जिनका उपयोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है और सेवाओं को उत्पादन के कारक कहा जाता है। ये कारक प्रकृति या मनुष्य में उपलब्ध हो सकते हैं- बनाया।

3. उत्पादन फलन: किसी वस्तु की मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध उत्पादित (आउटपुट) और उत्पादन के कारकों (इनपुट) को उत्पादन फलन कहा जाता है।

4. परिवर्तनीय अनुपात का नियम: यह एक अल्पकालिक घटना है जो घटित होती है जब अन्य सभी को ध्यान में रखते हुए परिवर्तनीय कारकों में से किसी एक का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाया जाता है कारक निश्चित. कानून कहता है कि जब उत्पादन के एक कारक की मात्रा बढ़ जाती है, अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए, इसके परिणामस्वरूप सीमांत उत्पाद में गिरावट आएगी उस कारक का.

5. कुल उत्पादन: किसी दिए गए उत्पादन के सभी कारकों द्वारा उत्पादित कुल उत्पादन अवधि को कुल उत्पादन कहा जाता है।

6. औसत उत्पाद (एपी): औसत उत्पाद कुल उत्पाद (टीपी) को विभाजित करने के बराबर होता है परिवर्तनीय इनपुट की कुल संख्या. दूसरे शब्दों में, यह चर की प्रति इकाई कुल उत्पाद है कारक।

7. सीमांत उत्पाद (एमपी): यह किसी के परिणामस्वरूप कुल उत्पाद में किया गया योग है इनपुट की एक और इकाई की वृद्धि। सीमांत उत्पाद या आउटपुट तब प्राप्त होता है जब उत्पादक परिवर्तनशील कारकों में इनपुट की अतिरिक्त इकाइयाँ नियोजित करता है।

8. पैमाने पर प्रतिफल का नियम: यह एक दीर्घकालिक विश्लेषण है। पैमाने पर रिटर्न का नियम लंबे समय में आउटपुट और इनपुट के पैमाने के बीच संबंध की व्याख्या करता है उसी अनुपात में इनपुट बढ़ाए जाते हैं।

9. आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ: आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ केवल व्यक्तिगत फर्मों में होती हैं। एक फर्म के रूप में अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाता है, फर्म को आंतरिक नामक कई अर्थव्यवस्थाओं का आनंद मिलता है अर्थव्यवस्थाएँ। मूलतः, आंतरिक अर्थव्यवस्थाएँ वे होती हैं जो प्रत्येक फर्म के लिए विशेष होती हैं।

10. बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ: बाहरी अर्थव्यवस्थाएँ एक फर्म के लिए बाहरी होती हैं जो उपलब्ध होती हैं

यह तब होता है जब पूरे उद्योग का उत्पादन उद्योग के विस्तार के साथ बढ़ता है।
जब किसी में उत्पादन का पैमाना होता है तो उन्हें कई फर्मों या उद्योगों द्वारा साझा किया जाता है उद्योग या समूह या उद्योगों में वृद्धि होती है। जब उन पर किसी एक फर्म का एकाधिकार नहीं होता यह आकार में बढ़ता है लेकिन जब कुछ अन्य कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो इसे इसे प्रदान किया जाता है।

5.10. संदर्भ

1. उन्नत आर्थिक सिद्धांत - एचएल आहूजा

2. आधुनिक सूक्ष्म अर्थशास्त्र - एचएल आहूजा

अध्याय आ और राजस्व विश्लेषण

6

6.0 उद्देश्य

6.1 परिचय

6.2 आपूर्ति का अर्थ

6.3 आपूर्ति कार्य

6.3.1 आपूर्ति के निर्धारक

6.3.2 आपूर्ति का नियम

6.3.3 आपूर्ति अनुसूची

6. 3.4 आपूर्ति वक्र

6.3.5 आपूर्ति में वृद्धि और कमी

6. 4. लागत विश्लेषण

6.4.1. लागत के प्रकार

6.4.2 अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागत

6.4.3 अल्पकालीन लागत वक्रों की प्रकृति

6.4. 4 औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध

6.5 राजस्व विश्लेषण

6.5.1 राजस्व अवधारणाएँ

6.5.2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत और सीमांत राजस्व वक्र

6.6 निष्कर्ष

6.7 मॉडल परीक्षा प्रश्न

6.8 शब्दावली

6.9 सन्दर्भ

6.0. उद्देश्य

आपूर्ति के बारे में बताएं.

आपूर्ति निर्धारित करने वाले कारकों को वर्गीकृत किया गया है।

आपूर्ति में वृद्धि और कमी को समझाइये।

खर्चों के प्रकार वर्गीकृत करें.

अल्पकालीन लागत-जलन की प्रकृति की व्याख्या करें।

आय के प्रकारों को वर्गीकृत करें।

6.1 परिचय

आपूर्ति शब्द का उपयोग बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की देय मात्रा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है उत्पादन लागत में परिवर्तन के लिए. माल की वह मात्रा जो बाज़ार में बेचने के लिए तैयार है विभिन्न कीमतों पर तर्कसंगत आपूर्तिकर्ताओं के व्यवहार को दर्शाता है। किसी वस्तु की आपूर्ति का तात्पर्य है बाज़ार में उपलब्ध किसी वस्तु की मात्रा तक। कंपनियां उत्पादन के कारकों का उपयोग करती हैं माल का उत्पादन करें. उत्पादन की लागत उत्पादन के कारकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक है उत्पादन प्रक्रिया जैसे मजदूरी, वेतन आदि में उपयोग किया जाता है।

एक कंपनी द्वारा विभिन्न कीमतों पर एक निश्चित मात्रा में सामान बेचने से अर्जित आय है राजस्व के रूप में माना जाता है। इसलिए उत्पादन की लागत के बारे में भी जानना आवश्यक है फर्मों के रिटर्न. इस इकाई में हम आपूर्ति, लागत और राजस्व विश्लेषण के बारे में सीखेंगे।

6.2 आपूर्ति का अर्थ

किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी उत्पादक द्वारा एक निश्चित कीमत पर बिक्री के लिए तैयार है समय को उस वस्तु की आपूर्ति कहा जाता है। हमें इनके बीच का अंतर याद रखना चाहिए आपूर्ति और स्टॉक. स्टॉक का मतलब कंपनी द्वारा उत्पादित माल को गोदामों में भंडारण करना है। कंपनी स्टॉक का कितना हिस्सा एक निश्चित कीमत पर बाजार में बिक्री के लिए रखती है आपूर्ति कहा जाता है.

6.3 आपूर्ति कार्य

आपूर्ति फ़ंक्शन उन कारकों के बीच संबंध का वर्णन करता है जो आपूर्ति निर्धारित करते हैं एक वस्तु और उस वस्तु की आपूर्ति। किसी वस्तु की आपूर्ति जैसे कारकों द्वारा निर्धारित होती है उस वस्तु की कीमत, स्थानापन्न और पूरक की कीमतें, उत्पादन के कारकों की कीमतें, प्रौद्योगिकी की स्थिति, उत्पादकों के लक्ष्य, सरकारी नीतियां आदि आपूर्ति कार्य हो सकते हैं निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है।

एसएक्स = एफ (पीएक्स, पीटी, पीएफ, टी, जीएफ, जीपी), कहां

Sx =x वस्तु की आपूर्ति; पीएक्स = एक्स वस्तु की कीमत; पीटी = x वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमतें; पीएफ =उत्पादन के कारकों की कीमतें; टी=प्रौद्योगिकी स्तर; जीएफ =फर्म उद्देश्य और जीपी =सरकारी नीतियां

ऊपर दिखाई गई आपूर्ति श्रृंखला में, किसी वस्तु की आपूर्ति परिवर्तनशील है। यह बहुतों पर निर्भर करता है

कारक. Px , Pt , Pf , T, Gf , Gp स्वतंत्र चर हैं। इनमें से किसी एक कारक में बदलाव से आपूर्ति में बदलाव आएगा। आपूर्ति निर्धारित करने में कीमत सबसे महत्वपूर्ण कारक है।

इसलिए, अन्य सभी कारक स्थिर होने पर, आपूर्ति फलन Sx=f(PX) होगा ।

6.3.1 आपूर्ति के निर्धारक

आइए उन कारकों के बारे में जानें जो वस्तुओं की आपूर्ति निर्धारित करते हैं।

1. वस्तु की कीमत: यदि किसी वस्तु की कीमत अन्य कारकों के अनुसार बढ़ती है अपरिवर्तित रहने पर इसकी आपूर्ति बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है आपूर्ति कम हो जायेगी. यानी कीमत और आपूर्ति के बीच सीधा संबंध है.

2. अन्य वस्तुओं की कीमतें (विकल्प और पूरक की कीमतें): की आपूर्ति वस्तु न केवल वस्तु की कीमत पर बल्कि अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर करती है (विकल्प और पूरक की कीमतें)। निर्माता यदि अपने हैं तो अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना पसंद करते हैं कीमतें ऊंची हैं. तो भले ही एक वस्तु की कीमत स्थिर रहे, अगर दूसरे की कीमत वस्तुएँ बदलती हैं, उसकी आपूर्ति भी बदल जायेगी।

3. उत्पादन के कारकों की कीमतें: उत्पादन के कारकों की लागत में भी परिवर्तन होता है माल की आपूर्ति. यदि उत्पादन के कारकों की कीमतें बढ़ती हैं, तो उत्पादन की लागत बढ़ती है। अतः उत्पादन घट जाता है और आपूर्ति घट जाती है। यदि के कारकों की कीमतें उत्पादन गिरता है तो आपूर्ति बढ़ती है।

4. उत्पादकों के लक्ष्य: जब उत्पादक अधिकतम लाभ कमाना चाहता है, तो वह उत्पादन करता है छोटे पैमाने पर माल और लाभ कमाता है। अन्यथा, जब वह बिक्री बढ़ाना चाहता है मुनाफ़े के बजाय वह आपूर्ति बढ़ाता है।

5. प्रौद्योगिकी की स्थिति: प्रौद्योगिकी में वृद्धि से उत्पादन विधियों में परिवर्तन होता है नई मशीनों के निर्माण के कारण. परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत कम हो जायेगी और आपूर्ति बढ़ेगी. इसीलिए परिवर्तनों के कारण वस्तुओं की आपूर्ति में परिवर्तन आता है प्रौद्योगिकी में.

6. सरकारी नीतियाँ: यदि सरकार वस्तुओं पर अधिक कर लगाती है तो यह उत्पादन है माल हतोत्साहित करने वाला। परिणामस्वरूप वस्तुओं की आपूर्ति कम हो जाती है। माल की आपूर्ति होगी यदि सरकार कम कर लगाती है और सब्सिडी देती है तो वृद्धि होगी।

6.3.2 आपूर्ति का नियम

आपूर्ति का नियम कीमत और प्रस्तावित मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध बताता है बिक्री के लिए। आपूर्ति के नियम को इस प्रकार कहा जा सकता है- 'अन्य चीजें समान रहने पर, ए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी आपूर्ति में वृद्धि होगी और इसके विपरीत। वह प्रत्यक्ष है कीमत और आपूर्ति के बीच संबंध.

आपूर्ति के नियम को आपूर्ति अनुसूची और वक्र की सहायता से समझाया जा सकता है।

6.3.3 आपूर्ति अनुसूची

आपूर्ति बिक्री के लिए पेश की गई किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं का विवरण है समय की प्रति इकाई विभिन्न कीमतें।

तालिका-1: विभिन्न कीमतों पर वस्तु की आपूर्ति

वस्तु की कीमत (रुपये में) पी	मात्रा आपूर्ति (इकाइयों में) प्र
10	500
20	600
30	700
40	800
50	900

उपरोक्त तालिका वस्तु की कीमत और आपूर्ति के बीच सीधा संबंध दर्शाती है

वस्तु का. जब वस्तु की कीमत 10 रुपये थी तब आपूर्ति 500 यूनिट थी।

जबकि वस्तु की कीमत 20 रुपये बढ़ गई है, आपूर्ति की मात्रा बढ़ गई है

600 इकाइयाँ। यदि हम तालिका में दी गई जानकारी का अवलोकन करते हैं, तो हम समझते हैं कि जैसे-जैसे कीमत बढ़ती है।

माल की आपूर्ति बढ़ जाती है. कीमत में कमी से आपूर्ति की मात्रा में कमी आएगी।

6.3.4 आपूर्ति वक्र

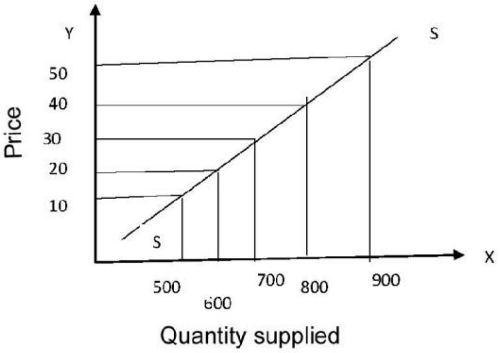

चित्र 6.1 आपूर्ति वक्र

उपरोक्त ग्राफ़ में हम X-अक्ष पर वस्तु की आपूर्ति को मापते हैं

Y-अक्ष पर वस्तु की कीमत। कीमत और के बीच एक सकारात्मक संबंध है

आपूर्ति। अतः आपूर्ति वक्र बाएँ से दाएँ ऊपर की ओर झुका हुआ है। यानी अगर कीमत बढ़ती है.

वे उत्पाद की अधिक मात्रा खरीदते हैं, यदि कीमत कम हो जाती है, तो वे कम मात्रा में खरीदते हैं

उत्पाद। यदि कीमत बढ़ती है, तो आपूर्ति वक्र बाएं से दाएं स्थानांतरित हो जाएगा। की मात्रा

आपूर्ति बढ़ती है. चित्र 6.1 में देखा जा सकता है कि यदि प्रारम्भ में कीमत 10 रूपये है

आपूर्ति की गई मात्रा 500 इकाई है और जब कीमत 50 रुपये बढ़ जाती है तो आपूर्ति की गई मात्रा

900 इकाइयों तक बढ़ जाती है।

6.3.5 आपूर्ति में वृद्धि और कमी

किसी वस्तु की आपूर्ति में परिवर्तन के कारण अन्य स्थितियों में परिवर्तन के बिना

वस्तु की कीमत में परिवर्तन को आपूर्ति में वृद्धि और कमी कहा जाता है।

आपूर्ति को OX-अक्ष पर और कीमत को OY-अक्ष पर दिखाया गया है। एसएस आपूर्ति वक्र है

वह बिंदु मूल्य ओपी है। इसलिए फर्म ओपी मूल्य पर ओक्यू मात्रा में वस्तु की आपूर्ति करती है। जब अन्य

स्थितियाँ बदल रही हैं (उदाहरण के लिए जब उत्पादन के कारकों की लागत गिरती है) बढ़ रही है

आपूर्ति, आपूर्ति वक्र को S1S1 के रूप में दाईं ओर स्थानांतरित कर देगी। तब फर्म अधिक आपूर्ति बेचेगी

पिछली कीमत ओपी पर OQ1 मात्रा। या OQ सप्लाई को OP1 को कम कीमत पर बेचता है। अगर बदलता है

अन्य स्थितियों में आपूर्ति कम हो जाती है, आपूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगा

S2S2, तब आपूर्ति घटकर OQ2 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में फर्म या तो प्रारंभिक बेच देती है

उच्च कीमत OP2 पर मात्रा OQ या प्रारंभिक कीमत OP पर कम मात्रा OQ2।

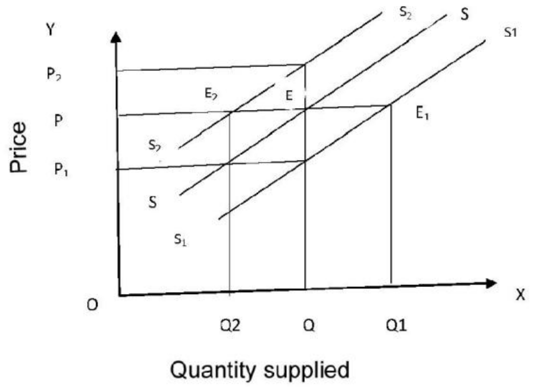

चित्र.6.2 आपूर्ति में वृद्धि और कमी

6.4 लागत विश्लेषण

कंपनियाँ माल का उत्पादन करती हैं। कंपनियाँ माल का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के कारकों का उपयोग करती हैं। की लागत

उत्पादन उत्पादन में प्रयुक्त उत्पादन के कारकों के लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक है

प्रक्रिया जैसे मजदूरी, भवनों का किराया, ब्याज भुगतान आदि। वस्तुओं का उत्पादन

एक फर्म अपनी लागत पर निर्भर करती है। किसी वस्तु की मांग और उसकी आपूर्ति मिलकर निर्धारित करते हैं

इसकी कीमत। लागत विश्लेषण तभी उपयोगी होता है जब विभिन्न लागत अवधारणाएँ ज्ञात हों।

6.4.1 लागत के प्रकार: लागतों को मोटे तौर पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे पैसे हैं

लागत, वास्तविक लागत, अवसर लागत।

1. धन लागत: किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए की गई धन लागत को कहा जाता है

पैसे की लागत. उदाहरण के लिए, मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, उपयोग में आने वाले कच्चे माल पर खर्च

उत्पादन, मशीनरी, ईंधन, मूल्यह्रास, आदि बिजली, विज्ञापन, बीमा प्रीमियम,

कर, परिवहन के लिए किया गया भुगतान आदि मौद्रिक व्यय हैं।

धन लागत को फिर से स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट लागत वे हैं

के उत्पादन के लिए बाहर से खरीदे गए उत्पादन के कारकों का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है

माल । यदि उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया में अपने स्वयं के संसाधनों या सेवाओं का उपयोग करता है,

उनके मूल्य को अंतर्निहित लागत कहा जाता है।

2. वास्तविक लागत: अल्फ्रेड मार्शल ने बताया कि वास्तविक लागत प्रयास और बलिदान हैं
किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए समाज के विभिन्न सदस्यों द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए,
जब जमींदार जमीन दे देता है तो उसकी फसल नष्ट हो जाती है, मजदूर को अवकाश की हानि होती है
काम करते हुए, पूंजीपति पूंजी के निवेश के कारण अपने उपभोग का त्याग करता है। असली
लागत और मौद्रिक लागत एक दूसरे से भिन्न हैं।

3. अवसर लागत: अवसर लागत को वैकल्पिक लागत या स्थानांतरण लागत कहा जाता है।
यदि उत्पादन का कोई कारक बेहतर कार्य में संलग्न होता है तो अवसर लागत वह पुरस्कार है जो प्राप्त होता है
वर्तमान में लगे हुए कार्य का विकल्प। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान इसके स्थान पर गेहूँ उगाता है
उसकी भूमि पर चावल की उपज, गेहूँ उगाने की अवसर लागत उसके द्वारा उगाए गए चावल का मूल्य है
उस भूमि पर उगे हैं.

6.4.2 अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागत

समय तत्व के आधार पर लागतों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक लागतों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
अल्पावधि में कुछ इनपुट स्थिर होते हैं जबकि अन्य परिवर्तनशील होते हैं। लंबे समय में सभी इनपुट
परिवर्तनशील हैं. इसलिए लंबे समय में, सभी लागतें परिवर्तनीय लागतें हैं।

1. निश्चित लागत: निश्चित लागत वे खर्च हैं जो तदनुसार नहीं बदलते हैं
अल्पावधि में उत्पादन में परिवर्तन। इन्हें वहन करना पड़ता है भले ही फर्म बंद कर दे
अस्थायी रूप से उत्पादन. उत्पादकों को निश्चित लागत वहन करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, निश्चित लागत में शामिल हैं
इमारतों पर किराया, मशीनरी पर पूंजी निवेश, स्थायी कर्मचारियों को भुगतान किया गया वेतन, ब्याज
पूंजी, मूल्यह्रास आदि। इन्हें ओवरहेड लागत या पूरक लागत भी कहा जाता है।

2. परिवर्तनीय लागत: लागत उत्पादन के स्तर के साथ बदलती रहती है। उत्पादन बढ़ेगा तो खर्च
वृद्धि होगी। उत्पादन कम होगा तो खर्च भी कम होगा. अगर कंपनी बंद हो जाती है
उत्पादन में कोई परिवर्तनीय लागत नहीं होगी। उदाहरण के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला दैनिक वेतन, भुगतान
कच्चे माल, ईंधन और बिजली के लिए।

6.4.3 अल्पकालीन लागत वक्रों की प्रकृति

किसी फर्म की विभिन्न प्रकार की अल्पकालीन लागतों की प्रकृति और उत्पादन में उनकी प्रकृति
तालिका 6.2 में दिए गए विवरण से प्रक्रिया।

तालिका-2: अल्पकालिक लागत

वर्ष	कुल निश्चित लागत (टीएफसी)	कुल परिवर्तनीय लागत (टीवीसी)	कुल लागत (टीसी)	औसत लागत (एसी)	सीमांत लागत (एमसी)
0	100	-	100	100	-
1	100	20	120	120	0
2	100	38	138	69	18
3	100	52.5	152.5	50.8	14.5
4	100	66	166	41.5	13.5
5	100	80	180	36	14
6	100	99	199	33.2	19
7	100	140	240	34.3	41
8	100	184	284	35.5	44

जैसा कि तालिका 6.2 में दिखाया गया है, एक निर्माता चर को बदलकर अल्पावधि में आउटपुट बदल सकता है निश्चित लागतों को बदले बिना लागतें। इसलिए अल्पावधि में निश्चित लागतें और दोनों होती हैं परिवर्ती कीमते। यदि कोई फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती है, तो कुल परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होगी। कमी उत्पादन कुल परिवर्तनीय लागत को कम करता है। इसका मतलब यह है कि कुल परिवर्तनीय लागतें बदलती रहती हैं उत्पादन की मात्रा. तालिका में कुल निश्चित लागत अपरिवर्तित रहती है। इस का मतलब है कि उत्पादन बढ़ने या घटने पर भी कुल स्थिर लागत 100 रुपये ही रहती है उत्पादन बढ़ता है, परिवर्तनीय लागत बढ़ती है। हालाँकि, शुरुआत में इसमें तेजी से वृद्धि हुई और फिर घटती दर से बढ़ी बढ़ते रिटर्न के नियम के कारण। उसके बाद जिस दर से कुल कानून के कारण परिवर्तनीय लागत बढ़ जाती है घटते रिटर्न का.

टीसी=टीएफसी+टीवीसी। ऊपरोक्त में समीकरण टीसी = कुल लागत, टीएफसी = कुल निश्चित लागत, टीवीसी = कुल परिवर्तनीय लागत।

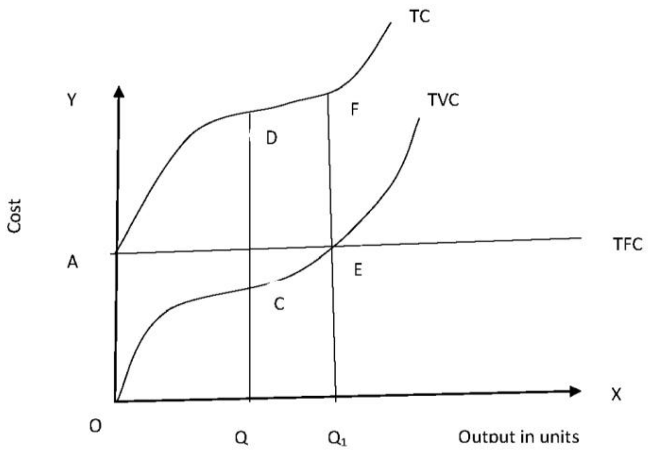

चित्र.6.3 कुल लागत, कुल निश्चित लागत, कुल परिवर्तनीय लागत

उपरोक्त चार्ट में, हम OX-अक्ष पर उत्पादन और OY-अक्ष पर लागत मापते हैं।

टीएफसी लाइन कुल निश्चित लागत दिखाती है टीवीसी लाइन कुल परिवर्तनीय लागत दिखाती है और टीसी लाइन कुल दिखाती है

लागत। टीएफसी लाइन एक्स अक्ष के समानांतर है क्योंकि कुल निश्चित लागत अल्पावधि में स्थिर है। टीवीसी वक्र मूल बिंदु O से शुरू होता है। क्योंकि जब आउटपुट शून्य होता है तो टीवीसी होता है शून्य भी. जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता है, वे बढ़ते जाते हैं। हालाँकि, शुरुआत में यह तेजी से बढ़ा और फिर बढ़ते रिटर्न के नियम के कारण घटती दर पर वृद्धि हुई। उसके बाद रेट पर ह्रासमान प्रतिफल के नियम के कारण कुल परिवर्तनीय लागत भी बढ़ जाती है, कुल लागत भी बढ़ जाती है प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है और फिर उत्पादन के एक निश्चित स्तर के बाद फिर से बढ़ती है भी धीरे-धीरे बढ़ती दर से बढ़ता है।

6.4.4 औसत और सीमांत लागत के बीच संबंध

अल्पकाल में औसत लागत कुल लागत से अधिक महत्वपूर्ण होती है। फर्म को पता होना चाहिए प्रति इकाई लागत या औसत लागत। यदि हम उत्पाद की कीमत जानते हैं, तो हमें यह जानना होगा यह जानने के लिए अल्पकालिक औसत लागत कि कंपनी किसी दिए गए स्तर पर लाभ कमाएगी या हानि का उत्पादन। अल्पावधि औसत लागत (एसएसी) आउटपुट की प्रति इकाई लागत है। तो SAC=TC/Q और औसत निश्चित लागत AFC=TFC/Q और AVC =TFC/Q के बराबर है। इसलिए औसत लागत समीकरण को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। एसएसी=टीसी/क्यू =टीवीसी+ टीएफसी/क्यू=एएफसी+एवीसी। उपरोक्त समीकरण के अनुसार अल्पावधि एसएसी औसत निश्चित और परिवर्तनशील से प्रभावित होता है लागत. सीमांत लागत उत्पादन की एक और इकाई के उत्पादन द्वारा कुल लागत में जोड़ा जाने वाला योग है। सीमांत लागत MC=TC/Q.

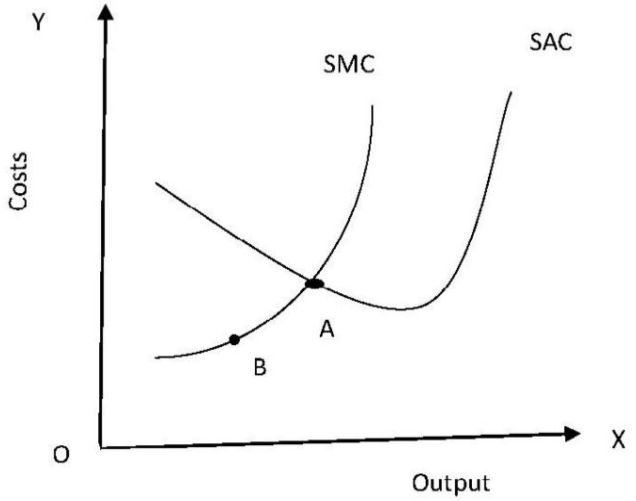

चित्र 6.4 औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध

अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र एसएमसी और अल्पकालीन औसत लागत वक्र एसएसी प्रारंभ में यू-आकार के होते हैं जैसा चित्र 6.4 में दिखाया गया है। प्रारंभ में एसएमसी और एसएसी वक्र ढलान पर होते हैं बाएँ से दाएँ नीचे की ओर। इस बिंदु पर SAC वक्र SMC वक्र के नीचे है।

एसएमसी वक्र एसएसी वक्र से पहले एक न्यूनतम बिंदु तक पहुंचता है। उसके बाद एसएमसी और एसएसी दोनों बढ़ रहे हैं। बढ़ता हुआ एसएमसी वक्र एसएसी वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है और चला जाता है ऊपर। तब एसएमसी वक्र एसएसी वक्र के ऊपर स्थित होता है। एसएसी न्यूनतम बिंदु के बाईं ओर एक एसएमसी <एसएसी और दाईं ओर एसएमसी> एसएसी।

6.5. राजस्व विश्लेषण

वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति उनकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है। की मांग एवं आपूर्ति वस्तुएँ मिलकर वस्तु की कीमत निर्धारित करती हैं। राजस्व एक फर्म द्वारा प्राप्त प्राप्तियां है विभिन्न कीमतों पर निश्चित मात्रा में सामान बेचना। कंपनी अधिकतम कमाई करना चाहती है उत्पादन लागत को न्यूनतम रखकर मुनाफा कमाना। तो इसके बारे में जानना जरूरी है उत्पादन की लागत के साथ-साथ फर्मों का राजस्व भी।

6.5.1 राजस्व की विभिन्न अवधारणाएँ

राजस्व एक फर्म द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त प्राप्तियां हैं।

राजस्व की तीन अवधारणाएँ हैं।

वे हैं (1) कुल राजस्व, (2) औसत राजस्व और (3) सीमांत राजस्व

1. कुल राजस्व: कुल राजस्व विभिन्न इकाइयों को बेचने से फर्म की कुल आय है एक निश्चित कीमत पर एक वस्तु। उदाहरण के लिए, यदि कोई फर्म कुल 50 पुस्तकें प्रत्येक 20 रुपये पर बेचती है राजस्व 1000 रुपये है.

कुल राजस्व (टीआर) = उत्पाद की कीमत (पी) एक्स मात्रा (क्यू)

2. औसत राजस्व: औसत राजस्व उत्पादन की एक इकाई की कीमत है। औसत आमदनी कुल राजस्व को बेची गई वस्तुओं की संख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी 50 किताबें बेचता है और कुल राजस्व 1000 रुपये है। तो औसत राजस्व = 20 रुपये

$$\text{औसत राजस्व} = \frac{\text{कुल राजस्व}}{\text{मात्रा}} \quad (\text{या}) \quad \text{एआर} = \frac{\text{टी.आर.}}{\text{क्यू}} \quad (\text{या}) \quad \text{पी} = \frac{\text{पीएक्सक्यू}}{\text{क्यू}}$$

3. सीमांत राजस्व: सीमांत राजस्व किसी को बेचकर अर्जित अतिरिक्त राजस्व है किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई। दूसरे शब्दों में किसी की बिक्री के कारण कुल राजस्व में परिवर्तन एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को सीमांत राजस्व कहा जाता है।

सीमांत राजस्व = $\frac{\text{कुल राजस्व में परिवर्तन}}{\text{मात्रा में परिवर्तन}}$ एमआर = $\frac{\triangle \text{टी.आर.}}{\triangle \text{क्यू}}$

6.5.2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत और सीमांत राजस्व वक्र

पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाज़ार में, बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, सभी वस्तुएँ सजातीय हैं। किसी वस्तु की कीमत उसकी आपूर्ति और से निर्धारित होती है माँग। पूरे उद्योग में उद्योग की सभी फर्मों की कीमतें समान हैं। परफेक्ट के तहत प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमत अपरिवर्तित रहती है। इसलिए औसत राजस्व और सीमांत राजस्व बराबर है.

तालिका-5: कुल राजस्व, औसत राजस्व और सीमांत राजस्व
पूर्ण प्रतियोगिता में

मात्रा (क्यू) कीमत (पी)		कुल आय (टीआर)	औसत आय (एआर)	सीमांत आय (श्री)
1	15	15	15	15
2	15	30	15	15
3	15	45	15	15
4	15	60	15	15
5	15	75	15	15
6	15	90	15	15
7	15	105	15	15
8	15	120	15	15
9	15	135	15	15
10	15	150	15	15

पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत 15 रुपये निर्धारित की जाती है। कोई भी मात्रा इस कीमत पर बेचा जा सकता है. औसत राजस्व सीमांत रिटर्न कीमत के बराबर है नहीं बदला गया है।

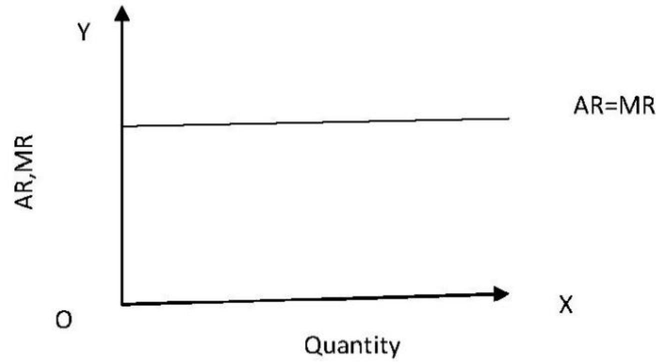

चित्र 6.5 एआर, एमआर पूर्ण प्रतिस्पर्धा में

6.6 सारांश

आपूर्ति शब्द का प्रयोग बिक्री के लिए उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है एक निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर बाजार। अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी. आपूर्ति का सिद्धांत बताता है कि कीमत में कमी से आपूर्ति कम हो जाएगी। यदि परिवर्तन होते हैं कीमत में बदलाव के बिना आपूर्ति के निर्धारकों में भी बदलाव होंगे आपूर्ति वक्र। उत्पादन की लागत विभिन्न कारकों के लिए भुगतान किया गया कुल पारिश्रमिक है किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया. लागतों को मुख्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और अवसर लागत। राजस्व एक फर्म द्वारा अर्जित आय है विभिन्न कीमतों पर सामान बेचकर। राजस्व अवधारणाएँ तीन प्रकार की होती हैं। वे हैं 1. कुल राजस्व 2. औसत राजस्व 3. सीमांत राजस्व. पूर्ण प्रतिस्पर्धा में एआर और एमआर रेखाएं एक्स अक्ष के समानांतर हैं।

6.7 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. आपूर्ति फलन को समझाइये।
2. आपूर्ति के नियम को परिभाषित करें।
3. आपूर्ति अनुसूची के बारे में बताएं।
4. निश्चित लागत क्या हैं?
5. परिवर्तनीय लागत क्या हैं?
6. कुल राजस्व क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. आपूर्ति के निर्धारकों के बारे में लिखिए।
2. आपूर्ति में परिवर्तन को समझाइये।
3. लागतों के प्रकारों को वर्गीकृत करें।
4. औसत लागत और सीमांत लागत के बीच संबंध स्पष्ट करें।
5. विभिन्न प्रकार की राजस्व अवधारणाओं की व्याख्या करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. अल्पकालीन लागत वक्र की प्रकृति को ग्राफ की सहायता से समझाइये
2. औसत राजस्व और सीमांत राजस्व वक्र की प्रकृति को पूर्ण रूप से समझाइए
   प्रतियोगिता।

6.8 शब्दावली

आपूर्ति: किसी वस्तु की वह मात्रा जो किसी उत्पादक द्वारा बिक्री के लिए तैयार है
किसी निश्चित समय पर दी गई कीमत उस वस्तु की आपूर्ति कहलाती है।

आपूर्ति का नियम: आपूर्ति का नियम बिक्री के लिए प्रस्तावित कीमत और मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध बताता है

धन लागत: किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए की गई धन लागत को कहा जाता है
पैसे की लागत.

निश्चित लागत: निश्चित लागत वे खर्च हैं जो तदनुसार नहीं बदलते हैं
अल्पावधि में उत्पादन में परिवर्तन के साथ।

कुल राजस्व: किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित कीमत पर बेचने से फर्म की कुल आय को कुल राजस्व कहा जाता है।

6.9 सन्दर्भ

1. सूक्ष्मअर्थशास्त्र - डॉ.बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय
2. सूक्ष्मअर्थशास्त्र - बीए प्रथम वर्ष तेलुगु अकादमी।
3. सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत- एम.एल. झिंगन।

अध्याय

7

बाज़ार विश्लेषण

7.0 उद्देश्य परिचय
7.1
7.2 बाज़ार: अर्थ और वर्गीकरण 7.2.1 बाज़ार का अर्थ
7.2.2 बाज़ार का वर्गीकरण

7.2.2 (ए) समय आधारित बाजार 7.2.2
(बी) क्षेत्र आधारित बाजार 7.2.2 (सी)
प्रतिस्पर्धा आधारित बाजार 7.3
पूर्ण प्रतियोगिता: अर्थ, विशेषताएँ और मूल्य निर्धारण
7.3.1 पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अर्थ 7.3.2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के
लक्षण 7.3.3 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण 7.4
अपूर्ण प्रतिस्पर्धा: एकाधिकार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच
तुलना,
एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और एकाधिकार
7.4.1 एकाधिकार 7.4.1
(ए) एकाधिकार का अर्थ 7.4.1 (बी) एकाधिकार
की विशेषताएँ 7.4.2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार
के बीच तुलना 7.4.3 एकाधिकार प्रतियोगिता 7.4.3.1(ए) एकाधिकार प्रतियोगिता का
अर्थ 7.4.3.2(बी) एकाधिकार प्रतियोगिता के
लक्षण 7.4.4 अल्पाधिकार 7.4.4.1 अल्पाधिकार का अर्थ 7.4.4.2
अल्पाधिकार की विशेषताएँ 7.4.5 एकाधिकार 7.4.5.1 एकाधिकार का अर्थ
7.4.5.2 एकाधिकार
की विशेषताएँ 7.5 सारांश 7.6 मॉडल
प्रश्न 7.7 शब्दावली 7 .8 सन्दर्भ

7.0. उद्देश्य

बाज़ार की अवधारणा को समझें;

पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ और इसकी विशिष्ट विशेषताओं को जानें;

पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण को समझें

एकाधिकार का अर्थ और इसकी विशिष्ट विशेषताएं समझा सकेंगे;

एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धा का अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझ सकेंगे;

अल्पाधिकार का अर्थ और उसकी विशेषताओं को समझें; और

अल्पाधिकार और एकाधिकार का अर्थ और इसकी विशेषताएँ समझें।

7.1 परिचय

जैसा कि हम जानते हैं कि बाजार में प्रतिदिन लेन-देन होता है। इस जगह में वस्तुओं एवं सेवाओं का एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान होता है। इस इकाई में हम चर्चा करने जा रहे हैं बाज़ार: अर्थ और वर्गीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता: अर्थ, विशेषताएँ और मूल्य निर्धारण और अपूर्ण प्रतिस्पर्धा: एकाधिकार, पूर्ण के बीच तुलना प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार, एकाधिकार प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और एकाधिकार।

7.2 बाज़ार: अर्थ और वर्गीकरण

7.2.1 बाज़ार का अर्थ

एडवर्ड्स ने बाजार को एक ऐसे तंत्र के रूप में परिभाषित किया जिसके द्वारा खरीदार और विक्रेता को लाया जाता है एक साथ। बाज़ार वह स्थान है जहाँ क्रेता और विक्रेता एक स्थान पर मिलते हैं। सामान्यतः शब्द 'बाजार' का प्रयोग सब्जी बाजार, फल बाजार, सर्राफा बाजार, शेयर जैसे स्थानों को दर्शाने के लिए किया जाता है बाज़ार आदि। हाल के दिनों में, खरीदार और विक्रेता ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर वस्तुओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं आधुनिक तकनीक के कारण. हम देख सकते हैं कि लोग बिक्री का लेन-देन कर रहे हैं और ऑनलाइन, मोबाइल फोन/मोबाइल ऐप और इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सुविधाएँ।

7.2.2 बाज़ार का वर्गीकरण

हम देख सकते हैं कि बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता आर्थिक रूप से जुड़ने के लिए मिलते हैं लेन-देन.

बाज़ारों का वर्गीकरण तीन कारकों पर आधारित है। वे हैं:

मैं) समय आधारित बाज़ार,

द्वितीय) क्षेत्र आधारित बाज़ार और

iii) प्रतिस्पर्धा आधारित बाज़ार।

7.2.2 (ए) समय आधारित बाजार

इस बाजार में समयावधि महत्वपूर्ण है. वस्तुओं और आपूर्ति के आधार पर समायोजन किया जाता है समय सीमा। समयावधि यानी लंबी अवधि के आधार पर बाज़ारों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है चालित बाज़ार, अल्पकालीन बाज़ार और अति अल्पकालीन बाज़ार।

मैं। लंबी अवधि के बाजार: लंबी अवधि के बाजार में, आपूर्ति में वृद्धि को पूरा किया जा सकता है माँग। निर्माता लंबे समय में मांग के आधार पर सभी इनपुट में बदलाव कर सकता है अवधि। लंबी अवधि में आपूर्ति में आवश्यक समायोजन करना संभव है।

द्वितीय. अल्पावधि बाजार: अल्पावधि बाजार में, आपूर्ति को कुछ हद तक बदला जा सकता है। यह श्रम जैसे कुछ परिवर्तनीय आदानों को बदलकर संभव है।

iii. बाज़ार अवधि या अत्यंत अल्पकालीन बाज़ार: अत्यंत अल्पकालीन बाज़ार में, उत्पादक समयावधि कम होने के कारण वस्तुओं के उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए सप्लाई तय है. नाशवान वस्तुओं का इस प्रकार का बाजार होगा।

7.2.2 (बी) क्षेत्र आधारित बाजार

क्षेत्र आधारित, बाज़ारों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में वर्गीकृत किया जाता है। ये बाज़ार हमें कमोडिटी बिक्री के लिए बाज़ार का आकार या विस्तार बताते हैं। इसका आकार ये बाज़ार वस्तुओं की मांग, परिवहन सुविधाओं और स्थायित्व पर निर्भर करते हैं अच्छे आदि का

मैं। स्थानीय बाज़ार: स्थानीय बाज़ार वह स्थान है जहाँ उत्पादित वस्तुएँ बेची जाती हैं क्षेत्र। इन वस्तुओं में स्थायित्व कम होता है। सब्जियाँ, फूल, फल जैसे नाशवान वस्तुएँ आदि का उत्पादन और विपणन उसी क्षेत्र में किया जा सकता है।

द्वितीय. राष्ट्रीय बाज़ार: यदि वस्तु की मांग और आपूर्ति पूरे देश में होती है इसे राष्ट्रीय बाज़ार कहा जाता है। जैसे: गेहूं, चावल, कपास आदि।

iii. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार: यदि वस्तुओं का क्रय-विक्रय सभी जगह होता है विश्व में इसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहा जाता है। जैसे: सोना, चाँदी, पेट्रोल आदि।

7.2.2 (सी) प्रतिस्पर्धा आधारित बाजार

प्रतिस्पर्धा की प्रकृति के आधार पर, बाज़ारों को पूर्ण प्रतिस्पर्धा में वर्गीकृत किया जाता है अपूर्ण प्रतियोगिता।

मैं। पूर्ण प्रतियोगिता: पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसा बाजार है जहां बड़ी संख्या में लोग होते हैं खरीदार और विक्रेता बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक सजातीय उत्पाद में लगे हुए हैं।

द्वितीय. अपूर्ण प्रतिस्पर्धा: इस, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में, प्रतिस्पर्धा नहीं है क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बिल्कुल सही। एक ही उत्पाद के लिए अलग-अलग कीमतें हैं। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा, में वर्गीकृत किया गया है। अल्पाधिकार और एकाधिकार.

7.3 पूर्ण प्रतियोगिता: अर्थ, विशेषताएँ और कीमत
दृढ़ निश्चय

7.3.1 पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ

बड़ी संख्या में उत्पादन करने वाली फर्मों की विशेषता वाली एक पूर्ण प्रतियोगिता सजातीय सामान. उद्योग में फर्मों का नि:शुल्क प्रवेश और अस्तित्व, पूर्ण गतिशीलता उत्पादकों और परिवहन लागत का अभाव।

7.3.2 पूर्ण प्रतियोगिता के लक्षण

पूर्ण प्रतियोगिता की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं:

1. खरीददारों और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या: खरीददारों और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या है बाज़ार में विक्रेता, विक्रेता और ख़रीदारों में से कोई भी बाज़ार को प्रभावित नहीं कर सकता। में पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता कीमत स्वीकार करते हैं लेकिन कीमत तय नहीं करते चीज़ें। बाजार किसी वस्तु की कीमत तय कर सकता है.

2. सजातीय उत्पाद: उद्योग में सभी कंपनियाँ सजातीय वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।
सामान गुणवत्ता, आकार, पैकिंग और सौदे की अन्य शर्तों आदि के मामले में समान हैं
यह सुविधा पूरे बाजार में कीमत की एकरूपता सुनिश्चित करती है।

3. फर्म एक मूल्य लेने वाली कंपनी है: फर्म को निर्धारित मूल्य पर सामान बेचना होता है
उद्योग क्योंकि फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है। बाज़ार या उद्योग यह तय करता है
बाजार की मांग और बाजार आपूर्ति के आधार पर कीमत। इसलिए उद्योग मूल्य निर्माता है और
फर्म कीमत लेने वाली है।

4. नि:शुल्क प्रवेश और निकास: फर्मों का बाजार में नि:शुल्क प्रवेश और नि:शुल्क निकास है
पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किसी भी समय बाजार। इसका मतलब है कि नहीं है
नई फर्म में प्रवेश और निकास पर प्रतिबंध।

5. पूर्ण ज्ञान: विक्रेता और खरीदार दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है
सामान और उनकी कीमतों के बारे में. किसी फर्म के लिए भिन्न कीमत वसूल करना संभव नहीं है।
यह सुविधा बाज़ार में एक समान कीमत सक्षम बनाती है।

6. उत्तम गतिशीलता: उत्पादन के कारक (भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन)
पूर्ण गतिशीलता हो (एक फर्म से दूसरी फर्म में जाने के लिए स्वतंत्र) ताकि कोई प्रतिबंध न हो-
कानूनी या मौद्रिक (माल की आवाजाही में व्यय शामिल)। यह सुविधा यह सुनिश्चित करती है
पूरे बाज़ार में कीमत एक समान होती है।

7. कोई विक्रय लागत नहीं: पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कोई विक्रय लागत नहीं होती, क्योंकि
पूर्ण ज्ञान और सजातीय वस्तुओं की धारणा। निर्माता के पास नहीं है
विज्ञापन लागत.

7.3.3 पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मूल्य निर्धारण

पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग किसकी सहायता से कीमत निर्धारित करता है
बाजार की ताकतें यानी मांग और आपूर्ति और फर्मों को उस कीमत का पालन करना चाहिए। विक्रेता और
खरीदार कीमत लेने वाले होते हैं, कीमत बनाने वाले नहीं। निम्नलिखित तालिका और चित्र इसे समझने में मदद करते हैं
बाजार संतुलन मूल्य निर्धारण में मांग और आपूर्ति में परिवर्तन।

तालिका-1: मांग और आपूर्ति अनुसूची

कीमत (रुपये में)	मात्रा की मांग (केजी में)	मात्रा आपूर्ति (केजी में)
10	70	30
20	60	40
30	50	50
40	40	60
50	30	70

उपरोक्त तालिका वस्तु की मांग और आपूर्ति को दर्शाती है। कीमत में बदलाव मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा में स्वचालित रूप से परिवर्तन होता है। का रिश्ता कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। यदि कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है। यदि कीमत बढ़ने से आपूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो यहाँ कीमत और आपूर्ति है सकारात्मक संबंध.

वस्तु की कीमत रु. 10/- मांग की मात्रा 70 किलोग्राम और आपूर्ति की मात्रा है 30 किलोग्राम है. जब कीमत बढ़ जाती है रु. 10/- से रु. मांग की मात्रा 20/- 60 किलोग्राम है और आपूर्ति की मात्रा 40 किलोग्राम है। जब कीमत रु. से बढ़ गई. 20/- से रु. 30/- की मात्रा 50 किलोग्राम पर मांग और आपूर्ति बराबर है। इस कीमत (रु. 30/-) को संतुलन कीमत कहा जाता है, संतुलन आपूर्ति और मांग 50 किलोग्राम है। जब कीमत रु. से बढ़ गई. 30/- से रु. 40/- मांग की मात्रा घटाकर 40 किलोग्राम कर दी गई है और आपूर्ति की मात्रा बढ़ाकर 60 किलोग्राम कर दी गई है। कब रुपये से बढ़ी कीमत 40/- से रु. मांग से 50/- की मात्रा में 30 कि.ग्रा. की कमी की गई है आपूर्ति की मात्रा बढ़ाकर 70 किलोग्राम कर दी गई। यदि वस्तु की कीमत और मात्रा को दर्शाता है मांग का विपरीत या नकारात्मक संबंध होता है (यदि कीमत 50 रुपये तक बढ़ जाती है तो मांग कम हो जाती है)। से 30 किग्रा) और वस्तु की कीमत और आपूर्ति की मात्रा में सकारात्मक संबंध है (यदि कीमत)। रुपये बढ़ा दिया गया है. 50 की आपूर्ति भी बढ़कर 70 किलोग्राम हो गई)।

यह प्रक्रिया निम्नलिखित चित्र में बताई गई है।

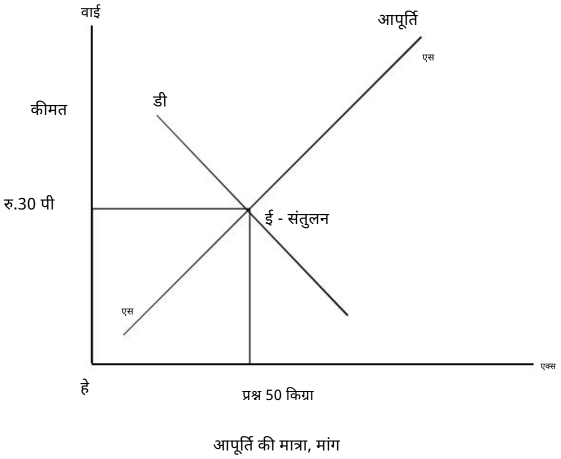

चित्र: 7.1 मूल्य निर्धारण

चित्र-7.1 में किसी वस्तु की आपूर्ति एवं मांग को 'X' अक्ष पर दर्शाया गया है वस्तु की कीमत 'Y' अक्ष पर है। चित्र में, एसएस आपूर्ति वक्र है और डीडी है मांग वक्र। 'ई' एक संतुलन बिंदु है जहां आपूर्ति और मांग वक्र दोनों प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे। ओपी कीमत संतुलन कीमत (रु. 30/-) है और ओक्यू मात्रा संतुलन है आपूर्ति और मांग (50 किग्रा)।

7.4 अपूर्ण प्रतिस्पर्धा

वास्तविक दुनिया में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार उपलब्ध नहीं है। इसमें आदर्श स्थितियाँ हैं केवल। आइए दूसरे बाजार यानी अपूर्ण बाजार पर चर्चा करें। अपूर्ण बाज़ार विशेषताएँ हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार के विपरीत। विक्रेता के आकार के आधार पर इसे 4 में वर्गीकृत किया गया है प्रकार. वे हैं (i) एकाधिकार, (ii) एकाधिकार प्रतियोगिता, (iii) अल्पाधिकार और (iv) एकाधिकार।

7.4.1 एकाधिकार: अर्थ एवं विशेषताएँ

7.4.1 (ए) एकाधिकार का अर्थ

पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाज़ार में एकाधिकार की विशेषताएँ भिन्न होती हैं। शब्द 'मोनो' का अर्थ है एकल और 'पॉली' का अर्थ है विक्रेता। एकाधिकार एक बाजार संरचना है जिसमें वहाँ एक ही विक्रेता है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का कोई करीबी विकल्प नहीं है फर्म और प्रवेश में बाधाएं हैं।

उदाहरण: भारतीय रेलवे जो भारत सरकार के अधीन संचालित है। एकाधिकार भी प्रतिस्पर्धा की अनुपस्थिति का तात्पर्य है।

7.4.1 (बी) एकाधिकार के लक्षण

एकाधिकार की विशेषताएं: एकाधिकार की विशेषता है:

1. एकल विक्रेता: एकाधिकार में, उत्पाद का उत्पादन करने वाली केवल एक फर्म होती है। पूरा उद्योग में यह एकल फर्म शामिल है।

2. कोई करीबी विकल्प नहीं: यह माना जाता है कि उत्पाद का कोई करीबी विकल्प नहीं है।

3. एकाधिकार में एक मजबूत बाधाएं मौजूद हो सकती हैं और किसी नई फर्म के प्रवेश से पहले ही मौजूद हो सकती हैं बाज़ार।

4. एकाधिकार के तहत, फर्म और उद्योग एक ही हैं।

5. एकाधिकारवादी एक समय में किसी को भी नियंत्रित कर सकता है। यानी उत्पाद की कीमत या मात्रा उत्पाद। वह एक समय में दोनों को नियंत्रित नहीं कर सकता।

6. एकाधिकारवादी का लक्ष्य न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ होता है।

7.4.2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच तुलना,

पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार के बीच तुलना

संपूर्ण प्रतियोगिता	एकाधिकार
1. विक्रेताओं की बड़ी संख्या और बड़ी संख्या 1. एकल विक्रेता	और अनेक क्रेता, क्रेताओं की संख्या
2. उत्तम स्थानापन्न वस्तुएँ	2. कोई बंद विकल्प नहीं
3. फर्मों का निःशुल्क प्रवेश और निःशुल्क निकास	3. एकाधिकार में मजबूत बाधाएँ होती हैं। प्रवेश और निकास की कोई गुंजाइश नहीं.
4. उद्योग और फर्म के बीच अंतर	4. फर्म और उद्योग एक ही हैं
5. विक्रेता और खरीदार दोनों ही कीमत हैं। 5. निर्माता या तो मात्रा से निर्धारित होती है, लेकिन दोनों से नहीं। उद्योग	कीमत निर्धारित कर सकता है या लेने वाला, कीमत उत्पादन की
6. बाजार की एक समान कीमत	6. कीमत मांग के आधार पर भिन्न होती है।
7. सजातीय वस्तुएँ	7. सामान सजातीय हो भी सकता है और नहीं भी।
समान हैं। मूल्य वक्रों का ढलान नीचे की ओर होगा। रेखा OX पी=एआर=एमआर	8. AR, MR वक्र अलग-अलग हैं, ये 8. कीमत, AR और MR अक्ष के समानांतर है। पी=एआर>एमआर.

7.4.3 एकाधिकार प्रतियोगिता

7.4.3.1 (ए) एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ

एकाधिकार प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जिसमें किसी वस्तु के बाजार में बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता का उत्पाद अन्य विक्रेताओं के उत्पाद से कुछ मामलों में भिन्न होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद विभेदन होता है।

जेएस बैंस के अनुसार, "एकाधिकार प्रतियोगिता एक बाजार संरचना है जहां बड़ी संख्या में विक्रेता होते हैं, जो विभेदित लेकिन करीबी स्थानापन्न उत्पाद बेचते हैं।"

उदाहरण: रेस्तरां, टूथपेस्ट का बाज़ार आदि।

7.4.3.2 (बी) एकाधिकार प्रतियोगिता के लक्षण

चम्बर्लिन के अनुसार एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा की विशेषताएँ

1. बड़ी संख्या में फर्में: एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत बड़ी संख्या में कंपनियां होती हैं
फर्में निकट संबंधी उत्पाद बेचती हैं, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार से कम।
बाज़ार में बड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कोई भी एक उत्पादक प्रभावित नहीं कर सकता
कुल उत्पादन।

2. उत्पाद विभेदीकरण: उत्पाद विभेदीकरण एकाधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है
प्रतियोगिता। यह भेदभाव गुणवत्ता, पैकेजिंग, रंग आदि के आधार पर हो सकता है
यह भेदभाव महज़ धारणा का विषय भी हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर आपने अलग-अलग ब्रांड के साबुन देखे होंगे। भले ही वे अलग दिखते हों
अलग-अलग रंग होने से उत्पाद का उपयोग एक जैसा होता है।

3. विक्रय लागत: एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत कंपनियां विज्ञापन पर बहुत अधिक खर्च करती हैं
ग्राहकों को आकर्षित करने और अपना उत्पाद बेचने के लिए उनका उत्पाद। प्रत्येक फर्म अपने उत्पाद को विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास करती है जिसके लिए उसे कुछ अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। यह कहा जाता है
विक्रय लागत.

4. गैर-मूल्य प्रतियोगिता: एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत, कभी-कभी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करती हैं
कीमत बदले बिना एक दूसरे के साथ। वे विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, उपहार शुरू कर सकते हैं
योजनाएं या विज्ञापन आदि के मामले में प्रतिस्पर्धा।

इस प्रकार, कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और अधिकतम संभव बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए हर संभव तरीके से प्रतिस्पर्धा करती हैं।

5. फर्मों के प्रवेश और निकास की स्वतंत्रता: लंबे समय में नई कंपनियां उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं और
इंडस्ट्री से बाहर भी जा सकते हैं.

6. मांग वक्र की प्रकृति: एकाधिकार की तरह, एकाधिकार प्रतियोगिता में भी एक होता है नीचे की ओर झुका हुआ माँग वक्र बाएँ से दाएँ नीचे की ओर। हालाँकि अस्तित्व के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धियों की स्थिति, वक्र की तीव्रता की डिग्री थोड़ी कम है, जो दर्शाती है मांग की अधिक कीमत लोच।

7.4.4 अल्पाधिकार

7.4.4.1 अल्पाधिकार का अर्थ

शब्द "ओलिगोपॉली" ग्रीक शब्दों से लिया गया है - 'ओलिगोस' का अर्थ है कुछ और 'पोलीन' का अर्थ है बेचना। अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण रूप है। अल्पाधिकार मौजूद है
जब उत्पाद बेचने वाली कुछ कंपनियाँ हों। डब्ल्यूएच फेलनर ने अल्पाधिकार पर एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था, "कुछ लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा"। ईएच चेम्बरलिन, हॉल और हिच और पॉल एम.स्वीज़ी ने अल्पाधिकार के सिद्धांतों को विकसित किया। अल्पाधिकार को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है
कुछ अल्पाधिकार फर्मों के बीच। इन फर्मों के उत्पाद या तो निकट स्थानापन्न या सजातीय हो सकते हैं।

उदाहरण: मोबाइल सेवा प्रदाता, कार उद्योग, एयरलाइंस आदि।

7.4.4.2 अल्पाधिकार की विशेषताएँ

अल्पाधिकार की विशेषता निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. अल्पाधिकार बाज़ार में उत्पाद के सीमित (कुछ) विक्रेता होते हैं।

2. परस्पर निर्भरता: कंपनियाँ आपस में परस्पर निर्भरता रखती हैं।

3. विक्रय लागत: अल्पाधिकार कंपनियाँ विज्ञापन पर खर्च करती हैं। इन फर्मों की विक्रय लागत होती है।

4. समूह व्यवहार: बचने के लिए सभी निर्माता एक साथ आते हैं और एक समूह बनाते हैं प्रतियोगिता।

5. मूल्य कठोरता: अल्पाधिकार बाजार में, कीमत फर्मों द्वारा तय की जाती है। यह बदला नहीं गया है.

7.4.5 एकाधिकार

7.4.5.1 एकाधिकार का अर्थ

डुओपॉली (ग्रीक डुओ (दो) + पॉली (बेचने के लिए) से) एक विशिष्ट प्रकार का अल्पाधिकार है जहां केवल बाज़ार में दो निर्माता मौजूद हैं। डुओपॉली एक ऐसा बाज़ार है जहां केवल दो निर्माता मौजूद हैं बाजार। यह अल्पाधिकार का एक सीमित रूप है। डुओपोली मॉडल फ्रेंच द्वारा विकसित किया गया था अर्थशास्त्री ऑगस्टिन कौरनॉट.

7.4.5.2 एकाधिकार के लक्षण

1. बाजार में दो उत्पादक मौजूद हैं

2. वस्तुएँ सजातीय हैं

3. उत्पादन लागत शून्य है

4. निर्माता अपनी परस्पर निर्भरता को नहीं जानते

7.5 सारांश

इस पाठ में हमने बाज़ार का अर्थ, बाज़ारों का वर्गीकरण, पर चर्चा की। प्रतिस्पर्धा आधारित बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार और अपूर्ण बाजार यानी एकाधिकार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार और एकाधिकार।

7.6 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें

1. बाजार को परिभाषित करें

2. क्षेत्र आधारित बाज़ारों पर एक नोट लिखें।

3. समय आधारित बाज़ारों पर एक नोट लिखें।

4. प्रतिस्पर्धा आधारित बाज़ारों पर एक नोट लिखें।

5. पूर्ण प्रतियोगिता क्या है?

6. एकाधिकार को परिभाषित करें।

7. एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाज़ार क्या है?

8. अल्पाधिकार को परिभाषित करें।

9. डुओपोली क्या है?

10.संतुलन कीमत को समझाइये।

11. विक्रय लागत क्या हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दें

1. समय और क्षेत्र के आधार पर बाज़ारों का वर्गीकरण समझाइये।
2. पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत निर्धारण की व्याख्या करें।
3. एकाधिकार क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या हैं?
4. अल्पाधिकार क्या है? इसकी विशेषताएँ क्या हैं?
5. एकाधिकार की अवधारणा और इसकी विशेषताओं की व्याख्या करें।
6. पूर्ण प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार की तुलना करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दीजिए

1. बाज़ारों का वर्गीकरण समझाइये।
2. पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ क्या हैं?
3. संतुलन कीमत क्या है? इसे ग्राफ़ से कैसे निर्धारित किया जाता है? व्याख्या करना।

7.7 शब्दावली

बाज़ार: बाज़ार एक ऐसा तंत्र है जहाँ बिक्री और खरीद की गतिविधियाँ होती हैं सामान और सेवाएँ होती हैं।

पूर्ण प्रतियोगिता: पूर्ण प्रतिस्पर्धा एक ऐसा बाजार है जहां बड़ी संख्या में प्रतिस्पर्धा होती है खरीदार और विक्रेता मौजूद हैं। सभी सामान एक समान हैं और एक ही कीमत पर बेचे जाते हैं।

एकाधिकार: एकाधिकार एक ऐसा बाज़ार है जिसमें एक ही निर्माता होता है और उत्पाद नहीं होगा कोई करीबी विकल्प है.

उत्पाद विभेदीकरण: विभिन्न उत्पादों के बीच छोटे-छोटे अंतर मौजूद होते हैं फर्म। इनकी मांग की क्रॉस लोच अधिक होती है।

बिक्री लागत: कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों पर खर्च करेंगी। इन व्ययों को विक्रय लागत कहा जाता है।

अल्पाधिकार: अल्पाधिकार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कुछ कंपनियाँ माल का उत्पादन करती हैं। ए की कीमत अच्छाई का निर्णय फर्मों द्वारा स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से किया जाता है।

डुओपॉली: डुओपॉली एक ऐसा बाजार है जहां बाजार में केवल दो उत्पादक मौजूद हैं। यह है एक अल्पाधिकार का सीमित रूप।

संतुलन कीमत: संतुलन कीमत वह कीमत है जहां मांग और आपूर्ति होती है बाजार में बराबर.

7.8 सन्दर्भ

1. तेलुगु अकादमी से इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक।
2. वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र (318), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।
3. तेलुगु अकादमी से बीए द्वितीय वर्ष मैक्रो इकोनॉमिक्स
4. मैक्रो इकोनॉमिक्स एमएल सेठ, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा प्रकाशित

अध्याय

8

वितरण के सिद्धांत

8.0 उद्देश्य
8.1 परिचय
8.2 आय का वितरण
8.2.1 कार्यात्मक वितरण
8.2.2 व्यक्तिगत वितरण
8.3 कारक मूल्य निर्धारण।
8.4 सीमांत उत्पादकता वितरण का सिद्धांत 8.4.1 सिद्धांत 8.4.2
सिद्धांत की
मान्यताएँ 8.4.3 आलोचना

8.5 किराए का अर्थ: अवधारणाएं और किराए की रिकार्डियन सिद्धांत 8.5.1 अर्थ 8.5.2
किराए की
अवधारणाएं 8.5.3 किराए
का रिकार्डियन सिद्धांत 8.6 मजदूरी, अवधारणाएं,
प्रकार 8.6.1 मजदूरी अवधारणा 8.6.2
मजदूरी के प्रकार 8.6.3 के
निर्धारक वास्तविक मज़दूरी
8.7 ब्याज: अर्थ और अवधारणाएँ

8.7.1 ब्याज
8.7.2 रुचि की अवधारणाएँ 8.8
लाभ: अर्थ और अवधारणाएँ 8.8.1 लाभ की
प्रकृति
8. 8.2 लाभ की अवधारणाएँ 8.9
सारांश 8.10
मॉडल परीक्षण प्रश्न
8.11 मॉडल उत्तर
8.12 शब्दावली
8.13 सन्दर्भ

8.0. उद्देश्य

आय वितरण के प्रकारों को वर्गीकृत करें।

सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या करता है।

रिकार्डो रेंट थ्योरी की व्याख्या करता है

वास्तविक मजदूरी के निर्धारकों की व्याख्या करता है।

रुचियों की अवधारणाओं की व्याख्या करता है।

लाभ की अवधारणा को समझाता है।

8.1. परिचय

वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन के कारकों की आवश्यकता होती है। भूमि श्रम, पूंजी, संगठन।
इन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। उन्हें उत्पादन प्रक्रिया में उनकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। भूमि, जो उत्पादन का कारक है, का भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक है
किराया कहा जाता है, श्रम को दिया गया पारिश्रमिक मजदूरी कहा जाता है, सेवाओं के लिए पूंजी को दिया गया मूल्य ब्याज कहा जाता है, और सेवाओं के लिए दिया गया पुरस्कार उद्यमी को लाभ कहा जाता है।

राष्ट्रीय आय उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त सभी रिटर्न का योग है। अतः यह इकाई दर्शाती है कि उत्पादन के कारकों के बीच आय कैसे वितरित की जाती है।

8.2 आय वितरण

आय वितरण दो प्रकार के होते हैं।

1. कार्यात्मक वितरण.

2. व्यक्तिगत वितरण.

8.2.1 कार्यात्मक वितरण

उत्पादन के कारकों की सेवाओं के लिए पुरस्कारों का वितरण कार्यात्मक कहलाता है
वितरण। वे हैं किराये के रूप में भूमि, मजदूरी के रूप में श्रम, ब्याज के रूप में पूंजी, उद्यमी के रूप में
लाभ। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत वितरण का वर्णन करता है
कार्यों के लिए. कार्यों के आधार पर वितरण को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. सूक्ष्म
वितरण 2. स्थूल वितरण।

1. सूक्ष्म-वितरण: सूक्ष्म-वितरण बताता है कि विभिन्न के लिए पुरस्कारों की दरें कैसी हैं

उत्पादन के कारक निर्धारित होते हैं। यह उत्पादक कारकों की सापेक्ष कीमतें निर्धारित करता है।

दरों से तात्पर्य भूमि के किराये, श्रम के लिए मजदूरी, पूंजी के लिए ब्याज और लाभ से है

उद्यमी।

2. मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन: मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब विभिन्न कारकों के सापेक्ष शेयर हैं

राष्ट्रीय आय में. यानी इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में लगान और मज़दूरी का हिस्सा कितना है.

8.2.2 व्यक्तिगत वितरण

व्यक्तियों के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण व्यक्तिगत वितरण कहलाता है। यह

व्यक्तियों के बीच आय असमानता के कारणों का विश्लेषण करता है।

8.3 कारक मूल्य निर्धारण का निर्धारण

हालाँकि, उत्पाद मूल्य निर्धारण की तरह, कारक मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है,

फिर भी दोनों के बीच मूलभूत अंतर हैं जो कारक मूल्य निर्धारण को अलग बनाते हैं

लिखित:

(i) किसी उत्पाद और कारक की मांग की प्रकृति में अंतर होता है। की मांग

एक उत्पाद अपनी सीमांत उपयोगिता के आधार पर प्रत्यक्ष मांग है, जबकि एक कारक की मांग है

व्युत्पन्न माँग। यह उस उत्पाद की मांग से उत्पन्न होता है जिसके उत्पादन में मदद मिलती है।

(ii) किसी उत्पाद की आपूर्ति उसके उत्पादन की मौद्रिक लागत पर निर्भर करती है, जबकि किसी उत्पाद की आपूर्ति

कारक इसकी अवसर लागत पर निर्भर करता है।

(iii) श्रम और उद्यमी जैसे कुछ कारकों का मूल्य निर्धारण सामाजिक से प्रभावित होता है

और मानवीय कारक, जबकि उत्पाद का मूल्य निर्धारण इन कारकों से बहुत कम प्रभावित होता है।

8.4 सीमांत उत्पादकता के वितरण का सिद्धांत

8.4.1 सिद्धांत

सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के एक कारक की कीमत निर्धारित होती है

इसकी सीमांत उत्पादकता द्वारा. को नियोजित करके कुल उत्पादन में वृद्धि की गई

किसी कारक की अतिरिक्त इकाई, जो उत्पादन के अन्य सभी कारकों को स्थिर रखती है, कहलाती है

सीमांत उत्पादकता. इस सिद्धांत के अनुसार, उत्पादन के एक कारक की कीमत बराबर होती है इसकी सीमांत उत्पादकता के लिए. यह सिद्धांत जे.बी.क्लार्क द्वारा विकसित किया गया था। सीमांत उत्पादकता उत्पादन के एक कारक का उपयोग करने से प्राप्त अतिरिक्त आउटपुट है।

दूसरे शब्दों में, सीमांत उत्पाद अतिरिक्त का उपयोग करने से कुल उत्पादन में वृद्धि है कारक। चूंकि उत्पादन के कारक सजातीय हैं, इसलिए एक कारक को प्रतिस्थापित किया जा सकता है दूसरा, इसलिए उत्पादक सीमांत तक एक कारक को दूसरे कारक से प्रतिस्थापित करता रहता है उत्पादन के सभी कारकों की उत्पादकता बराबर होती है। इस सिद्धांत को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है निम्नलिखित उदाहरण. मान लीजिए कि 10 मजदूर 100 किताबें बनाते हैं। एक अतिरिक्त को नियोजित करके मजदूर अर्थात 11वाँ मजदूर यदि कुल उत्पादन में 110 पुस्तकें बढ़ जाये तो अतिरिक्त कुल उत्पादन में 10 पुस्तकों की वृद्धि (110-100=10 पुस्तकें) कहलाती है सीमांत भौतिक उत्पाद (एमपीपी), सीमांत भौतिक उत्पाद या अधिशेष को गुणा करके उत्पाद की लागत के साथ, हमें सीमांत उत्पाद मूल्य (एमवीपी) या सीमांत प्राप्त होता है उत्पाद राजस्व (एमआरपी)।

जब उत्पादन कारक की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया जाता है, तो कुल राजस्व में परिवर्तन होता है सीमांत उत्पाद राजस्व कहा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत राजस्व इसके बराबर होता है कीमत। प्रत्येक फर्म सीमांत कारक लागत (एमएफसी) की तुलना सीमांत राजस्व से करती है उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के कारकों का उपयोग करते समय उत्पाद (एमआरपी)। के कारक उत्पादन को सीमांत राजस्व की सीमा तक उत्पादन प्रक्रिया में नियोजित किया जाता है उत्पाद (एमआरपी) सीमांत कारक लागत (एमएफसी) से अधिक है। लंबे समय में, कंपनियां बंद कर देती हैं सीमांत कारक लागत (एमएफसी) के बराबर होने पर उत्पादन के कारकों की भर्ती सीमांत राजस्व उत्पाद (एमआरपी) और औसत राजस्व उत्पाद (एआरपी)। यानी फर्में लंबे समय में (AFC=MFC=MRP=ARP) बराबर होने पर संतुलन तक पहुँचें।

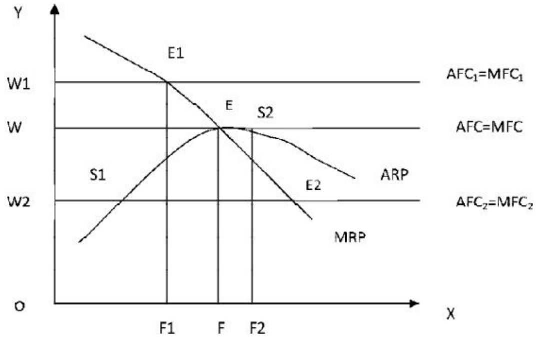

चित्र 8.1 कारक बाजार में फर्म का संतुलन

जब फर्म बिंदु E पर संतुलन में होती है, तो AFC=MFC, ARP और MRP बराबर होते हैं। यहां ही फर्म कारक की इकाइयों के लिए OW मूल्य का भुगतान करती है। यदि उत्पादन की लागत बढ़कर OW हो जाए- OW1, फर्म को E1S1 की राशि में घाटा होता है। के कारकों को भुगतान की गई कीमत उत्पादन F1E1 है। यह F1S1 से अधिक है। इसका मतलब है कि उत्पादन की औसत लागत अधिक है औसत राजस्व से अधिक. इन शर्तों के तहत कुछ कंपनियां उद्योग छोड़ देंगी। इसलिए OW में उत्पादन की लागत वापस AFC पर आ जाती है और फर्म संतुलन पर पहुँच जाती है। यदि की लागत उत्पादन OW2 तक गिर जाता है तो फर्म S2 E2 लाभ अर्जित करेगी। इस समय नई कंपनियाँ प्रवेश करती हैं उद्योग और AFC OW स्तर तक बढ़ जाता है और फर्म बिंदु E पर संतुलन में होती है।

इस OW कीमत पर ARP=MRP=AFC=MFC।

8.4.2 सिद्धांत की मान्यताएँ

1. उत्पाद बाजार और कारक बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है
2. उत्पादन के कारकों का पूर्ण रोजगार होता है।
3. किसी कारक की सभी इकाइयाँ सजातीय होती हैं।
4. कारकों की पूर्ण गतिशीलता होती है
5. उत्पादन के कारकों को एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है
6. उत्पादन के कारकों को उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार विभाजित किया जा सकता है।
7. टेक्नोलॉजी में कोई बदलाव नहीं.
8. यह सिद्धांत दीर्घकाल में लागू होता है।

8.4.3 आलोचना

1. उत्पादन इकाइयों के कारक सजातीय नहीं होते हैं।
2. उत्पादन के कारक पूर्णतः गतिशील नहीं हैं।
3. उत्पादन के कारकों के बाजार में कोई पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं है।
4. उत्पादन के कारकों का पूर्णतः उपयोग नहीं किया जाता है।
5. उत्पादन के कारक हमेशा प्रतिस्थापन योग्य नहीं होते हैं।
6. टेक्नोलॉजी में बदलाव को नजरअंदाज करते हैं.
7. यह सिद्धांत अल्पावधि में लागू नहीं होता.
8. उत्पादन के कारक विभाज्य नहीं हैं।
9. इस सिद्धांत में प्रमुख दोष यह है कि यह आपूर्ति की उपेक्षा करता है।

8.5 किराए का अर्थ: अवधारणाएं और किराए का रिकार्डियन सिद्धांत

8.5.1 किराया अर्थ: सामान्य भाषा में किराया शब्द का अर्थ है भुगतान की गई राशि भूमि, मकान, दुकान आदि के उपयोग के लिए मालिक। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, '' आय भूमि के स्वामित्व और प्रकृति के मुफ्त उपहारों से प्राप्त धन को सामान्यतः लगान कहा जाता है।

8.5.2 किराये की अवधारणाएँ

किराये में दो अवधारणाएँ हैं। 1. अनुबंध किराया 2.आर्थिक किराया।

1. अनुबंध किराया: उपयोग के लिए पूर्व-व्यवस्थित अनुबंध के तहत मालिक को भुगतान की गई राशि एक निश्चित अवधि के लिए भूमि, भवन और मशीनरी जैसी सेवाएं।

इसे कॉन्ट्रैक्ट रेंट कहा जाता है. अनुबंध किराया को सकल किराया के रूप में भी जाना जाता है। इसमें शामिल है a) परिसंपत्तियों के सुधार में उपयोग की गई पूंजी के लिए ब्याज बी) प्रबंधन की मजदूरी सी) मूल्यह्रास और रखरखाव शुल्क घ) जोखिम लेने के पुरस्कार के रूप में लाभ

2. आर्थिक लगान: आर्थिक लगान की शास्त्रीय अवधारणा भूमि का प्रतिफल या भुगतान है सेवा। रिकार्डो के अनुसार, आर्थिक लगान अधिक उपजाऊ भूमि पर अधिशेष है सीमांत या कम उपजाऊ भूमि पर.

8.5.3 किराए का रिकार्डियन सिद्धांत

डेविड रिकार्डो, इंग्लैंड के 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों में से एक हैं लगान का शास्त्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया।

रिकार्डो की परिभाषा के अनुसार "किराया वह हिस्सा है जो मकान मालिक को उपयोग के लिए दिया जाता है।" मिट्टी की मूल और अविनाशी शक्तियों का

1. स्पष्टीकरण:

रिकार्डो ने एक की सहायता से बताया कि किस प्रकार मिट्टी में अंतर से लगान निकलता है उदाहरण। गुणवत्ता एवं उर्वरता के आधार पर भूमि ए, बी, सी ग्रेड की होती है। मान लीजिए कुछ जनसंख्या बढ़ने पर लोग अपनी खाद्य आवश्यकताओं के लिए नई जगह पर चले जाते हैं। पहला इस क्षेत्र में आने वाले लोगों ने अत्यधिक उपजाऊ भूमि यानी ए ग्रेड भूमि पर खेती की। उत्पादन की लागत श्रम एवं पूंजी के रूप में रु. 4500 और 250 बोरी अनाज का उत्पादन। कोई नहीं है

अधिशेष क्योंकि फसल बेचने से प्राप्त राजस्व उत्पादन की लागत के बराबर है। तो ए ग्रेड जमीन का कोई किराया नहीं है. जैसे-जैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती है और कुछ और लोग भी क्षेत्र में प्रवास करें, खाद्यान्न की मांग बढ़ जाएगी। परिणामस्वरूप, कम उपजाऊ 'बी' ग्रेड भूमि पर रुपये के समान निवेश के साथ खेती की जाती है। 4500 और इससे उत्पादित आउटपुट बी श्रेणी की भूमि मात्र 200 बोरा अनाज है। तो 'ए' ग्रेड भूमि पर उत्पादक अधिशेष 250- है 200=50 बैग. जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यदि कुछ और लोग इस क्षेत्र में पलायन कर गये और भूमि की मांग बढ़ जाती है और उन्हें कम उपजाऊ 'सी' श्रेणी की भूमि पर खेती करनी पड़ती है भी। यदि वे C पर 4500 रुपये का निवेश करके केवल 150 बैग अनाज उगा सकते हैं, तो कुल लागत कितनी होगी उत्पादन और कुल राजस्व बराबर हो जाएगा 'सी' श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं लगेगा। 'सी' ग्रेड भूमि को ही सीमान्त भूमि कहा जाता है। इसे एक तालिका के रूप में समझाया गया है।

भूमि ग्रेड	की लागत उत्पादन (रुपये)	उत्पादन बैग में	फिजिकल में किराया रूप	धन कीमत
ए	4500	250	100	3000
बी	4500	200	50	1500
सी	4500	150	-	-

उपरोक्त तालिका में 'सी' श्रेणी की भूमि सीमांत भूमि या बिना किराये वाली भूमि है, जहां की कुल लागत है उत्पादन कुल राजस्व के बराबर है। 'सी' के खाद्यान्न के एक बैग के उत्पादन की लागत ग्रेड भूमि 30 रुपये है। (4500/150=30) इसलिए 'ए' ग्रेड भूमि से 100 बैग अधिशेष प्राप्त होता है। खाद्यान्न या रु 3000(30X100=3000). इसी प्रकार, 'बी' ग्रेड भूमि से 50 का अधिशेष प्राप्त होता है खाद्यान्न के बैग, या रु (30X50 = 1500)।

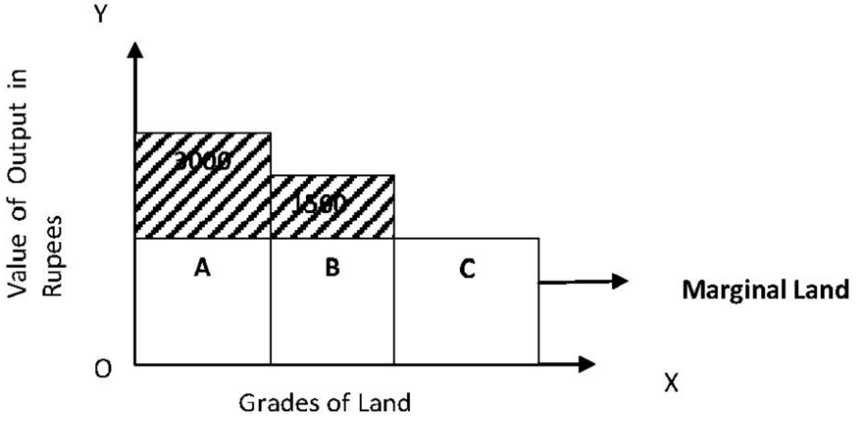

चित्र 8.2 किराया निर्धारण

उपरोक्त मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किराया या अंतर अधिशेष को दर्शाता है। 'सी' पर किराया नहीं उठता

भूमि को श्रेणीबद्ध करें क्योंकि यह सीमांत भूमि है।

2. सिद्धांत की मान्यताएँ

1. बाज़ार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है।
2. जमीन की आपूर्ति तय है.
3. मिट्टी की उर्वरता में अंतर होता है।
4. भूमि में अविनाशी शक्तियां निहित हैं।
5. भूमि घटते प्रतिफल के नियम के अधीन है
6. अकेले भूमि का किराया अभिशाप.
7. किराया लंबे समय में बढ़ता है

3. आलोचना

1. बाज़ार में कोई पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं है
2. भूमि की कोई अविनाशी शक्तियाँ नहीं हैं
3. यह मान लिया गया है कि सबसे पहले सबसे अच्छी भूमि पर खेती की जाएगी लेकिन यह हमेशा सच नहीं है।
4. यह मानता है कि किराया केवल भूमि से ही प्राप्त होता है। लेकिन आर्थिक किराया इसमें एक तत्व है सभी कारकों की आय.

उपरोक्त मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किराया या अंतर अधिशेष को दर्शाता है। किराया नहीं है 'सी' ग्रेड भूमि पर उत्पन्न होता है क्योंकि यह सीमांत भूमि है।

8.6 मजदूरी, अवधारणाएं और प्रकार

8.6.1 मजदूरी की अवधारणा

मजदूरी नियोक्ता द्वारा श्रम की सेवाओं के लिए भुगतान है, एक मजदूर का तनाव हो सकता है शारीरिक या मानसिक तनाव. श्रमिकों को उनकी सेवा का पुरस्कार किसी भी रूप में मिल सकता है मजदूरी या मज़दूरी. मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी दैनिक या साप्ताहिक या मासिक हो सकती है और वार्षिक. इन्हें टाइम वेज कहा जाता है। रकम के हिसाब से मजदूरी भी दी जाती है एक मजदूर द्वारा किये गये कार्य को टुकड़ा मजदूरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक दर्जी को 400 रुपये का भुगतान किया जा सकता है वर्दी सिलने के लिए.

8.6.2 मजदूरी के प्रकार

मजदूरी दो प्रकार की होती है। 1. धन मजदूरी, 2. वास्तविक मजदूरी

मैं। मौद्रिक मजदूरी: मौद्रिक मजदूरी से तात्पर्य प्राप्त धन आय की राशि से है
मजदूरों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पुरस्कार के रूप में उन्हें मौद्रिक मजदूरी कहा जाता है।

द्वितीय. वास्तविक मजदूरी: वास्तविक मजदूरी से तात्पर्य प्राप्त धन मजदूरी की क्रय शक्ति से है
कर्मी।

8.6.3 वास्तविक मजदूरी के निर्धारक

1. कीमत स्तर: मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर पर निर्भर करती है। यदि कीमत स्तर
उच्च है, पैसे की क्रय शक्ति कम होगी। कीमत स्तर जितना कम होगा, उतना अधिक होगा
पैसे की क्रय शक्ति.

2. नकद वेतन: अन्य चीजें अपरिवर्तित रहेंगी। नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच सीधा संबंध है। यदि नकद वेतन बढ़ता है, तो वास्तविक वेतन बढ़ता है। नकद मजदूरी में कमी से वास्तविक मजदूरी में कमी आएगी।

3. नौकरी की स्थिरता: यदि नौकरी स्थायी है, तो उसका वास्तविक वेतन अधिक होगा, भले ही उसका पैसा कितना भी हो
वेतन कम है. अस्थायी रोज़गार के मामले में उसकी वास्तविक मज़दूरी कम होती है, हालाँकि उसकी मौद्रिक मज़दूरी कम होती है
उच्च है।

4. कार्य की प्रकृति: यदि कार्य उच्च जोखिम वाला है तो श्रमिक की वास्तविक मजदूरी कम होगी
पैसे की मज़दूरी अधिक है।

5. भविष्य की संभावनाएँ: यदि मजदूर काम करता है और उसके पास क्षमता है तो वास्तविक मजदूरी अधिक होती है
भविष्य में पदोन्नति की संभावना. पदोन्नति न होने पर वास्तविक वेतन कम और अधिक होता है
वेतन।

6. अतिरिक्त आय: कुछ व्यवसायों में कर्मचारियों को कमाई का मौका मिलता है
मौद्रिक वेतन कम होने पर भी अतिरिक्त आय। उदाहरण के लिए इंजीनियर. यह करेगा
वास्तविक वेतन बढ़ाएँ.

7. सामाजिक प्रतिष्ठा: कुछ नौकरियाँ समुदाय में प्रतिष्ठा लाती हैं। परिणामस्वरूप, उनकी मौद्रिक
मज़दूरी कम है लेकिन वास्तविक मज़दूरी अधिक है। यद्यपि एक बैंक कर्मचारी का मौद्रिक वेतन
और एक न्यायाधीश समान हैं, एक न्यायाधीश का वास्तविक वेतन सामाजिक स्थिति के कारण अधिक है।

8. भुगतान का तरीका: श्रमिकों को आम तौर पर नकद में वेतन मिलता है। लेकिन कभी-कभी वे होते हैं
आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क आवास, चिकित्सा और परिवहन सुविधाएं प्रदान की गईं
मज़दूरी इससे उनकी वास्तविक मज़दूरी बढ़ जाती है।

8.7 रुचि का अर्थ और अवधारणाएँ

8.7.1 ब्याज

ब्याज एक उधारकर्ता द्वारा लिए गए ऋण के लिए ऋणदाता को किया गया भुगतान है। यह आमतौर पर व्यक्त किया जाता है
प्रति वर्ष उधार लिए गए प्रति सौ रुपये की दर के रूप में। लेकिन अर्थशास्त्र की दृष्टि से
ब्याज पूंजी की सेवाओं के उपयोग के लिए भुगतान के भुगतान के रूप में है। के अनुसार
मिल ब्याज मात्र संयम का पारिश्रमिक है। मार्शल ने ब्याज को प्रतीक्षा का प्रतिफल माना। कीन्स ने कहा, ब्याज पैसे की तरलता के साथ मिलने वाला प्रतिफल है।

8.7.2 रुचि की अवधारणाएँ

रुचि की अवधारणाएँ दो प्रकार की होती हैं। वे हैं 1.सकल ब्याज 2.शुद्ध ब्याज

1. सकल ब्याज: वह भुगतान जिसे उधारकर्ता ऋणदाता को छोड़कर करता है
मूलधन को सकल ब्याज कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित भुगतान शामिल हैं।

मैं। शुद्ध ब्याज: यह केवल पूंजी या धन के उपयोग के लिए भुगतान है।

द्वितीय. जोखिम लेने का इनाम: जब ऋणदाता पैसा उधार देता है तो उसे जोखिम का सामना करना पड़ता है। दिया गया ऋण वापस नहीं आ सकता। इसलिए ऋणदाता अतिरिक्त रिटर्न प्राप्त करना चाहता है। जोखिम तत्व जितना अधिक होगा सकल ब्याज दर उतनी ही अधिक होगी। असुरक्षित ऋण सुरक्षित ऋणों की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं
वे उच्च प्रीमियम दर रखते हैं।

iii. असुविधा के लिए पुरस्कार: जब एक ऋणदाता पैसा उधार देता है तो वह इसके उपयोग को छोड़ देता है
ऋण की अवधि. उसे कुछ असुविधा महसूस होगी. जरूरत पड़ने पर पैसा वापस नहीं आ सकता। उसे कहीं और उधार लेना पड़ सकता है. ब्याज दर तय करने में ऋणदाता शामिल होता है
इसमें ऐसी असुविधाओं का प्रतिफल है।

iv. प्रबंधन के लिए पुरस्कार: ऋणदाता को रखरखाव के लिए कुछ खर्च करना पड़ सकता है
कर्मचारियों के वेतन जैसे उधार खातों का। कभी-कभी उसे मुकदमा दायर करना पड़ता है

ऋण की वसूली. ऋणदाता अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ राशि लेता है

प्रबंधन। यह सकल ब्याज दर में भी शामिल है.

2. शुद्ध ब्याज: शुद्ध ब्याज वह है जो ऋणदाता के पास इनाम में कटौती के बाद बचता है

जोखिम लेना, असुविधा, सकल हित से प्रबंधन

8.8 लाभ: अर्थ और अवधारणाएँ

एक उद्यमी विभिन्न इनपुट का उपयोग करके सामान का उत्पादन करता है। जब ये सामान बेचा जाता है बाजार, वे आय अर्जित कर सकते हैं। अन्य के लिए भुगतान करने के बाद उसके पास जो राशि बची थी उनकी सेवाओं के लिए उत्पादन के कारकों को लाभ कहा जाता है। उद्यमी का राजस्व अधिक होता है उत्पादन लागत से अधिक उसे लाभ मिलता है।

8.8.1 लाभ की प्रकृति

अर्थशास्त्रियों द्वारा मुनाफ़े की विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है। तौस्सिग ने इसे "वह" कहा है
मिश्रित और परेशान करने वाली आय।'' वेब्लिन और हॉब्सन का मानना है कि "मुनाफा अनर्जित आय है।"
और इसका श्रेय कुछ पूंजीपतियों द्वारा स्थापित संस्थागत एकाधिकार के अस्तित्व को देते हैं।
क्लार्क, नाइट और शुम्पीटर ने कहा कि यह एक आय है जो परिवर्तन से उत्पन्न होती है,
एक गतिशील दुनिया में अनिश्चितता और नवाचार।

8.8.2 लाभ की अवधारणाएँ

लाभ की विभिन्न अवधारणाएँ हैं। वे हैं सकल लाभ, शुद्ध लाभ, सामान्य लाभ,
सामान्य लाभ,

1. सकल लाभ: उद्यमी द्वारा अर्जित कुल आय को सकल लाभ कहा जाता है। कुल राजस्व और कुल लागत के बीच के अंतर को सकल लाभ माना जाता है। सकल लाभ में निम्नलिखित पहलू शामिल हैं- ए) यदि निर्माता अपने व्यवसाय में अपनी भूमि या भवन का उपयोग करता है तो इनका भुगतान सकल लाभ में शामिल किया जाता है, बी) मूल्यह्रास शुल्क और अंतर्निहित मजदूरी सकल लाभ में शामिल की जाती है और सी) उसके लिए देय ब्याज उसकी अपनी पूंजी

व्यापार।

2. शुद्ध लाभ: यह उद्यमी द्वारा विशेष रूप से अपने उद्यमशीलता कार्यों के लिए अर्जित पुरस्कार है। शुद्ध लाभ को शुद्ध लाभ भी कहा जाता है। शुद्ध लाभ में निम्नलिखित मदें शामिल हैं।

मैं। शुद्ध लाभ बीमा योग्य जोखिमों और अनिश्चितताओं को सहन करने का प्रतिफल है।

द्वितीय. उद्यमी की योग्यता को दिया गया पुरस्कार।

iii. उत्पादन के कारकों का उचित अनुपात में समन्वय करने का प्रतिफल।

iv. यह नए उत्पादों और नई तकनीकों जैसे नवाचारों को पेश करने का पुरस्कार है

उत्पादन।

v. ये लाभ मुद्रास्फीति, अन्य कंपनियों के बंद होने और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं

विपत्तियाँ आदि; ये शुद्ध लाभ का हिस्सा हैं।

3. सामान्य लाभ: उद्यम को चलाने के लिए पुरस्कार के रूप में लाभ का भुगतान किया जाता है

व्यापार। सामान्य लाभ को उत्पादन की लागत या माल की कीमत में शामिल किया जाता है।

जब सामान्य लाभ होता है, तो कोई नई फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं करती है या कोई मौजूदा फर्म नहीं छोड़ती है

उद्योग के लिए.

4. असामान्य लाभ: यदि फर्म का कुल राजस्व कुल लागत से अधिक है

उत्पादन होता है, तो कंपनी को असामान्य लाभ मिलता है।

8.9 सारांश

वितरण का सिद्धांत उत्पादन के विभिन्न कारकों और उनके पुरस्कारों का वर्णन करता है।

आम तौर पर उत्पादन के किसी भी कारक की कीमत उसकी आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है।

वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को मूल्य निर्धारण के लिए लागू किया जा सकता है

उत्पादन के सभी कारक. यह सिद्धांत बताता है कि उत्पादन के किसी भी कारक की कीमत होनी चाहिए

इसके सीमांत राजस्व उत्पादन के बराबर हो। डेविड रिकार्डो के अनुसार किराया किसके कारण उत्पन्न होता है?

मिट्टी में अंतर. मज़दूरी एक श्रमिक की सेवाओं का प्रतिफल है। वास्तविक मजदूरी अधिक है

मौद्रिक मजदूरी से भी महत्वपूर्ण. ब्याज पूंजी के मालिक द्वारा प्राप्त आय है।

लाभ उत्पादन में उद्यमियों की सेवाओं के लिए दिया जाने वाला पारिश्रमिक है

प्रक्रिया।

8.10 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. आर्थिक किराया क्या है?
2. समय वेतन क्या हैं?
3. शुद्ध ब्याज क्या है?
4. शुद्ध लाभ क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. आय वितरण के प्रकारों को वर्गीकृत करें?
2. मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच अंतर लिखें?
3. सकल लाभ बताएं?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. लगान के रिकार्डियन सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन करें?
2. वास्तविक मजदूरी क्या हैं? वे कौन से कारक हैं जो वास्तविक मजदूरी निर्धारित करते हैं?
3. लाभ क्या है? विभिन्न लाभ अवधारणाओं की व्याख्या करें?

8.11 शब्दावली

मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन: मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब विभिन्न कारकों के सापेक्ष शेयर हैं राष्ट्रीय आय में. यानी इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय में लगान और मज़दूरी का हिस्सा कितना है.

अनुबंध किराया: उपयोग के लिए पूर्व-व्यवस्थित अनुबंध के तहत मालिक को भुगतान की गई राशि एक निश्चित अवधि के लिए भूमि, भवन और मशीनरी जैसी सेवाएं। इसे अनुबंध कहा जाता है किराया।

शुद्ध ब्याज: शुद्ध ब्याज वह है जो ऋणदाता के पास इनाम में कटौती के बाद बचता है जोखिम लेना, असुविधा, सकल हित से प्रबंधन।

असामान्य लाभ: यदि फर्म का कुल राजस्व उत्पादन की कुल लागत से अधिक है, तो कंपनी को असामान्य मुनाफ़ा मिलता है.

8.13 सन्दर्भ

1. सूक्ष्म अर्थशास्त्र - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय
2. सूक्ष्म अर्थशास्त्र - बीए प्रथम वर्ष तेलुगु अकादमी
3. सूक्ष्म आर्थिक सिद्धांत - एम.एल. झिंगन

अध्याय

9

राष्ट्रीय आय विश्लेषण

9.0. उद्देश्य

9.1. परिचय

9.2. राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ

9.3. राष्ट्रीय आय के निर्धारण कारक 9.4. राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ 9.4.1.

बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद

9.4.2. कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद

9.4.3. सकल घरेलू उत्पाद

9.4.4. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

9.4.5. कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

9.4.6. व्यक्तिगत आय

9.4.7. प्रयोज्य आय 9.4.8. राष्ट्रीय आय

9.4.9. वास्तविक राष्ट्रीय आय

9.4.10. सकल मूल्य जोड़ा गया

9.4.11. प्रति व्यक्ति आय 9.5. राष्ट्रीय आय के

घटक

9.6. राष्ट्रीय आय का मापन - विधियाँ

9.6.1. आउटपुट विधि या उत्पाद विधि 9.6.2. आय विधि

9.6.3. व्यय विधि 9.7. राष्ट्रीय आय की कठिनाइयाँ

एवं महत्व 9.7.1. राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का महत्व 9.8. भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान

9.9. सारांश 9.10. मॉडल

परीक्षा प्रश्न 9.11. शब्दावली 9.12. संदर्भ

28.0. उद्देश्य

- राष्ट्रीय आय का अर्थ समझें।
- सकल आय और शुद्ध आय में अंतर बताएं।
- राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने वाले कारकों को समझें।
- मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर करें।
- राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझें।
- राष्ट्रीय आय के विभिन्न घटकों को समझाइये।
- बाजार कीमतों और कारक कीमतों के बीच अंतर बताएं।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को जानें।
- राष्ट्रीय आय का महत्व जानें।

9.1. परिचय

व्यापक-आर्थिक विश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक राष्ट्रीय है आय। यह पूरी अर्थव्यवस्था के समग्र प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इसका विश्लेषण यह दर्शाता है कि किसी देश की कुल आय की गणना कैसे की जाती है। यह हमें इसकी जांच करने में मदद करता है विभिन्न परिभाषाएँ, अवधारणाएँ, घटक, गणना विधियाँ कठिनाइयाँ और महत्व राष्ट्रीय आय की गणना के

9.2. राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ

राष्ट्रीय आय को कई प्रकार से परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय आय अंतिम मूल्य है एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का। दूसरे तरीके से, कुल किसी देश द्वारा किसी अवधि के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य समय। दूसरे शब्दों में, यह उन सभी कारकों की आय का योग है जो एक के दौरान उत्पन्न होती है उत्पादन वर्ष अर्थात उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कुल आय के रूप में किराया, मजदूरी, ब्याज और मुनाफा।

विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय की सबसे अलग-अलग परिभाषा दी है आधुनिक परिभाषा साइमन कुजनेट की परिभाषा है।

साइमन कुज़नेट के अनुसार, राष्ट्रीय आय "वस्तुओं का शुद्ध उत्पादन" है और वर्ष के दौरान देश की उत्पादक प्रणाली के हाथों में आने वाली सेवाएँ अंतिम उपभोक्ताओं में से।"

9.3. राष्ट्रीय आय के निर्धारण कारक

ऐसे कई प्रभाव हैं जो राष्ट्रीय आय के आकार को निर्धारित करते हैं एक देश। यह इन प्रभावों का लेखा-जोखा है कि एक देश की आय अधिक हो सकती है दूसरे की तुलना में.

ए) प्राकृतिक और मानव संसाधन

देश के संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता शायद सबसे महत्वपूर्ण है इसकी राष्ट्रीय आय पर प्रभाव। उदाहरण उपजाऊ मिट्टी, बिजली के तैयार स्रोत, अनुकूल जलवायु, नौगम्य नदियाँ आदि का देश की उत्पादन क्षमता पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

उद्यम क्षमता: राष्ट्रीय आय में श्रम शक्ति की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण, बुद्धि, उद्यमशीलता कौशल, निर्णय लेने की क्षमता आदि।

पूंजी निर्माण: पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता सबसे बड़े प्रभावों में से एक है कुल आउटपुट पर.

बी)प्रौद्योगिकी की स्थिति

यह राष्ट्रीय आय पर एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभावशाली कारक है। एक ऐसा देश जिसके पास खराब तकनीकी ज्ञान से बड़े आकार की राष्ट्रीय आय नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा नहीं होगा अपने संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग करने की स्थिति में।

सी) राजनीतिक स्थिरता

उत्पादन को उच्चतम स्तर पर बनाए रखने के लिए यह एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, जब किसी देश में राजनीतिक स्थिरता होती है तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

9.4. राष्ट्रीय आय की अवधारणाएँ

अब हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। को समझने के लिए

विभिन्न अवधारणाएँ, हमें दो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ जाननी चाहिए और वे हैं

ए) बाज़ार कीमतें = कारक लागत + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

बी) कारक मूल्य = कारक लागत + सब्सिडी - अप्रत्यक्ष कर

9.4.1. बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपीएमपी)

बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, जिसमें शुद्ध विदेशी आय घटा विदेशियों द्वारा प्रेषित आय शामिल है।

जीएनपीएमपी = सी + आई + जी + (एक्स - एम) + (आर - पी)

जहां C=कुल खपत, I=सकल निवेश, G=सरकारी व्यय,

एक्स=निर्यात, एम=आयात, आर=विदेश से आय प्राप्तियां, पी=विदेशियों द्वारा प्रेषित आय।

9.4.2. कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद

कारक लागत पर जीएनपी का अर्थ उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित सभी आय का योग है

(भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन) एक देश में एक वर्ष के दौरान।

कारक लागत पर जीएनपी = एमपी पर जीएनपी-अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

9.4.3. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

सकल घरेलू उत्पाद सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है

एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित आय को जीडीपी के रूप में जाना जाता है। ऐसा होता है

विदेश से आय शामिल नहीं है.

जीडीपी = जीएनपी - विदेश से शुद्ध आय

या

जीडीपी = सी + आई + जी + जेड

जहां C=निवेश, G=सरकारी व्यय, Z=शुद्ध निर्यात

यदि शुद्ध निर्यात सकारात्मक है, तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है और यदि शुद्ध निर्यात नकारात्मक है, तो

जीडीपी घटती है.

जेड - जीडीपी

जेड - जीडीपी

9.4.4. बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपीएमपी)

जब किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है

स्थिर पूंजी की कुछ टूट-फूट है। इसे स्थिर पूंजी की टूट-फूट कहा जाता है

उपभोग मूल्यह्रास है। यदि हम हताशा के मूल्य को के मूल्य से घटा दें

जीडीपी, हमें एनएनपी मिलता है।

एमपी पर एनएनपी = बाजार मूल्यों पर जीएनपी - मूल्यह्रास (स्थिर पूंजी की खपत)

9.4.5. कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (एनएनपीएफसी)

कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय के रूप में भी जाना जाता है। यह योग है

भूमि, श्रम, पूंजी के योगदान के लिए संसाधन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अर्जित सभी आय का

और उद्यमशीलता क्षमता जो वर्ष के शुद्ध उत्पादन में जाती है।

कारक लागत पर एनएनपी = जीएनपी (एफसी) कारक लागत - मूल्यह्रास

फैक्टरी लागत पर एनएनपी = बाजार मूल्य पर एनएनपी - अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी

9.4.6. व्यक्तिगत आय (पीआई)

व्यक्तिगत आय वास्तव में सभी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त सभी आय का योग है

किसी दिए गए वर्ष के दौरान परिवार।

पीआई = राष्ट्रीय आय (एनएनपी एफसी) - सामाजिक सुरक्षा योगदान -

कॉर्पोरेट आयकर - अवितरित कॉर्पोरेट लाभ + स्थानांतरण भुगतान

9.4.7. प्रयोज्य आय (डीआई)

व्यक्तिगत आय का एक अच्छा हिस्सा सरकार को आयकर, व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि जैसे व्यक्तिगत करों के रूप में भुगतान करने के बाद, व्यक्तिगत आय का जो कुछ बचता है उसे डिस्पोजेबल आय कहा जाता है।

प्रयोज्य आय = व्यक्तिगत आय - व्यक्तिगत कर

इसलिए, प्रयोज्य आय का या तो उपभोग किया जा सकता है या बचाया जा सकता है

प्रयोज्य आय = उपभोग + बचत।

9.4.8. नाममात्र आय

वर्तमान कीमतों पर नाममात्र आय को राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आय

वर्तमान कीमतों के साथ गणना की जाती है, तो इसे नाममात्र आय कहा जाता है।

9.4.9. वास्तविक राष्ट्रीय आय

वास्तविक राष्ट्रीय आय को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। मापने के लिए किसी देश की वास्तविक आय के लिए किसी विशेष वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है जिसमें सामान्य कीमतों का स्तर न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है। आधार वर्ष के लिए मूल्य स्तर माना जाता है 100 हो.

वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है।

9.4.10. सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)

जोड़ा गया मूल्य सामग्री इनपुट या मध्यवर्ती के मूल्य में कटौती करके प्राप्त किया जाता है आउटपुट के संगत मूल्य से उत्पाद।

जोड़ा गया मूल्य = आउटपुट का मूल्य - मध्यवर्ती उत्पाद

9.4.11. प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय किसी देश विशेष में लोगों की औसत आय है वर्ष। प्रति व्यक्ति आय की गणना राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है काउंटी.

प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय/जनसंख्या

यदि प्रति व्यक्ति आय को वर्तमान कीमतों से मापा जाता है तो इसे नाममात्र कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। यदि इसे स्थिर कीमतों से मापा जाए तो इसे रियल प्रति कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय.

9.5. राष्ट्रीय आय के घटक

किसी देश में राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्तर (Y) निम्नलिखित पाँच से बनता है अवयव:

1. उपभोग (सी) 2. निवेश (आई) 3. सरकारी व्यय 4. निर्यात (एक्स) 5.आयात (एम)। इनमें से पहले चार देश के भीतर आय पैदा करते हैं, जबकि आयात करते हैं दूसरे देशों में आय पैदा करें। इस प्रकार

किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का वास्तविक स्तर इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है

वाई = सी + एस + जी + (एक्स - एम)

उपभोग: उपभोग परिवार द्वारा किया गया कुल व्यय है

वस्तुएँ और सेवाएँ। उपभोग का स्तर आय के स्तर पर निर्भर करता है। जब लोग

आय प्राप्त करने पर वे उसका अधिकांश भाग खर्च कर देते हैं और उसका कुछ भाग बचा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आय (Y) उपभोग (सी) प्लस बचत (एस) के बराबर।

वाई =सी + एस

निवेश: निवेश उन वस्तुओं की खरीद है जिनका अभी तक उपभोग नहीं हुआ है

भविष्य में धन उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: बुनियादी सुविधाओं आदि पर व्यय।

सरकारी व्यय: सरकार द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं पर किया गया व्यय

समाज के उपयोग के लिए। उदाहरण: पुलिस, सेना, सड़क, रेलवे आदि पर व्यय।

निर्यात: किसी देश की कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य

समय की अवधि और जो विदेशों में बेचे जाते हैं।

आयात: वे वस्तुएँ और सेवाएँ जो किसी देश के निवासियों द्वारा लाई जाती हैं। लेकिन उस

देश के बाहर बनाये गये हैं।

शुद्ध विदेशी आय (एक्सएम): निर्यात के मूल्य के बीच का अंतर

किसी देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आयात को ध्यान में रखा गया है।

राष्ट्रीय आय में निवेश निवेश (आई), निर्यात (ई) और सरकार हैं

व्यय (जी) और राष्ट्रीय आय का रिसाव बचत (एस), आयात (आई) और कर (टी) हैं।

9.6. राष्ट्रीय आय का मापन

राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन विधियाँ हैं और वे हैं

ए) उत्पाद विधि या आउटपुट विधि

बी) आय विधि या साधन लागत विधि

सी) व्यय विधि या परिव्यय विधि

9.6.1. आउटपुट विधि या उत्पाद विधि

इस विधि को मूल्य वर्धित विधि, इन्वेंटरी विधि, कमोडिटी के नाम से भी जाना जाता है

सेवा विधि. इस पद्धति में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य अलग-अलग होता है

सकल राष्ट्रीय ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को बाजार मूल्यों से गुणा किया जाता है

उत्पाद (जीएनपी)।

जीएनपी = (क्यू1 पी1 + क्यू2 पी2 + ………. + Qn Pn) + विदेश से शुद्ध आय।

जहां जीएनपी = सकल राष्ट्रीय उत्पाद

'Q' वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है

'पी' वस्तुओं और सेवाओं की कीमत है

1, 2, 3 ………. n अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हैं।

मध्यस्थ वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाना चाहिए। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

9.6.2. आय विधि

इस विधि को कारक लागत विधि, विभाजित विधि के नाम से भी जाना जाता है विधि, राष्ट्रीय आय का अनुमान सभी कारकों की आय को एकत्रित करके (के रूप में) लगाया जाता है उत्पादन के इन कारकों (भूमि, भूमि) के मालिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ) लेखांकन वर्ष में घरेलू क्षेत्र के भीतर श्रम, पूंजी और आयोजक) इस प्रकार राष्ट्रीय आय देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़कर प्राप्त की जाती है।

राष्ट्रीय आय = R + W + I + P

जहां R = किराया, W = मजदूरी, I = ब्याज, P = लाभ।

स्थानांतरण भुगतान के रूप में आय इसमें शामिल नहीं है। यह विधि बताती है वितरणात्मक शेयरों के अनुसार हमें राष्ट्रीय आय।

9.6.3. व्यय विधि

इस विधि को परिव्यय विधि, प्रयोज्य विधि, आधुनिक विधि के नाम से भी जाना जाता है इस विधि से समाज द्वारा किया गया कुल व्यय, व्यक्तिगत उपभोग, व्यय परिवारों का, फर्मों का व्यय, वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद और शुद्ध निर्यात वहाँ हैं.

एनआई = ईएच + ईएफ + ईजी + शुद्ध निर्यात।

जहां एनआई = राष्ट्रीय आय, ईएच = परिवारों का व्यय, ईएफ = का व्यय फर्में, ईजी=सरकारों का व्यय।

यह विधि इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय के बराबर है व्यय।

हमने ऊपर राष्ट्रीय आकलन की तीन वैकल्पिक विधियों के बारे में बताया है आय। राष्ट्रीय आय तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका इन तीनों तरीकों को कर्मचारी बनाना होगा ताकि उनकी क्रॉस चेकिंग से अधिक सटीकता प्राप्त हो सके और अधिक प्रकाश डाला जा सके विवरण।

9.7. राष्ट्रीय आय के मापन में कठिनाइयाँ

जब हम मापना शुरू करते हैं तो कुछ वैचारिक समस्याएं सामने आती हैं किसी देश की राष्ट्रीय आय। कुछ समस्याएं नीचे दी गई हैं:

a) कृषि उत्पादन को मापना बहुत कठिन है क्योंकि उत्पादन केवल आधा होता है शेष बाजार में आते हैं और स्वयं उपभोग के लिए उपयोग करते हैं।

ख) अधिकांश ग्रामीण किसान अशिक्षित हैं, वे इसके बारे में उचित जानकारी नहीं देंगे आउटपुट.

ग) गृहिणियों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली सेवाएं और उपभोग किया गया उत्पादन घर पर मापना कठिन है।

घ) कई वस्तुओं से गुजरने पर उनकी दोहरी गिनती की संभावना होती है आकृतियाँ

ई) अवैध गतिविधियों से अर्जित आय राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है।

च) निःशुल्क प्रदान की गई सेवाएँ जीएनपी में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका आदान-प्रदान होता है कल्याण।

छ) टिकाऊ वस्तु का मूल्य मापना बहुत कठिन है।

9.7.1. राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का महत्व

राष्ट्रीय आय सांख्यिकी के कई महत्वपूर्ण उपयोग हैं जिनकी बहुत आवश्यकता है उनके नियमित संचालन के लिए। राष्ट्रीय आय अनुमान केवल एक ही आंकड़ा प्रदान नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय दर्शाने के साथ-साथ विभिन्न के संबंध में विस्तृत आंकड़े भी प्रदान करता है राष्ट्रीय आय के घटक.

राष्ट्रीय आय अनुमान के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं:

ए) राष्ट्रीय आय अनुमान से समग्र उत्पादन प्रदर्शन का पता चलता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र।

ख) प्रति व्यक्ति आय हमें लोगों के औसत जीवन स्तर के बारे में जानकारी देती है।

ग) आर्थिक कल्याण काफी हद तक राष्ट्रीय आय के स्तर पर निर्भर करता है
और लोगों का औसत जीवन स्तर

घ) एक निश्चित अवधि में राष्ट्रीय आय अनुमानों की तुलना करके हम जान सकते हैं
चाहे अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो, स्थिर हो या गिर रही हो।

ई) बजटीय आवंटन में राष्ट्रीय आय अनुमान अधिक उपयोगी होते हैं।

च) राष्ट्रीय आय अनुमान राष्ट्रीय आय के वितरण पर प्रकाश डालते हैं
आय की विभिन्न श्रेणियां जैसे मजदूरी, लाभ, किराया और ब्याज।

छ) अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका का अनुमान लगाया जा सकता है।

9.8. भारत में राष्ट्रीय आय अनुमान

आजादी से पहले भारत में गणना करने वाले पहले व्यक्ति "दादाभाई नौरोजी" थे 1867-68 में राष्ट्रीय आय। उसके बाद कई अर्थशास्त्रियों जैसे विलियम डिग्बी, फिडली शिर्रास, केटी शा, कंबट्टा और आरसी देसाई जैसे कई लोगों ने राष्ट्रीय आय की गणना की। वर्ष 1931 में-32 वी.के.आर.वी.राव ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना की।

आज़ादी के बाद अगस्त 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय नियुक्त किया
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में आय आकलन समिति (एनआईसी)।
राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में सिफारिशें करना। अन्य सदस्य
इस समिति में डीआर गाडगिल और डॉ. वीकेआरवी राव हैं। वर्तमान में, 'राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय' (एनएसओ) को राष्ट्रीय आय तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है
अनुमान।

भारत में राष्ट्रीय आय की गणना दो तरीकों से की जाती है, वे हैं 1) आउटपुट विधि और 2) आय विधि। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के उद्देश्य से, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को 13 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है और वे हैं

1) पशुपालन सहित कृषि 2) मछली पकड़ना 3) वानिकी और कटाई 4) खनन और उत्खनन 5) विनिर्माण [पंजीकृत और अपंजीकृत] 6) निर्माण 7) बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति 8) परिवहन, भंडारण और संचार 9) होटल और रेस्तरां 10) बैंकिंग और बीमा 11) रियल एस्टेट, आवास और व्यवसाय का स्वामित्व सेवाएँ 12) लोक प्रशासन और रक्षा 13) अन्य सेवाएँ।

9.9. सारांश

व्यापक आर्थिक विश्लेषण में राष्ट्रीय आय सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है में समग्र आर्थिक गतिविधि के स्तर का सबसे व्यापक माप दर्शाता है अर्थव्यवस्था। इसलिए इसे समग्र प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पैमाना माना जाता है अर्थव्यवस्था की। यह एक मूल्य अवधारणा और प्रवाह अवधारणा है। मापने की तीन विधियाँ हैं राष्ट्रीय आय को मापने की आधुनिक विधि सर्वोत्तम है। राष्ट्रीय आय को मापने के द्वारा, हम देश में लोगों के जीवन स्तर को समझ सकते हैं।

9.10. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. जीएनपी क्या है?
2. प्रति व्यक्ति आय समझाइये
3. कारक लागत पर एनएनपी?
4. व्यक्तिगत आय
5. व्यय विधि
6. सब्सिडी
7. मध्यवर्ती माल
8. नाममात्र राष्ट्रीय आय

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने वाले कारक कौन से हैं?
2. व्यक्तिगत आय और निपटान आय के बीच अंतर बताएं।
3. राष्ट्रीय आय के घटक लिखिए
4. जीएनपी बाजार मूल्य और जीएनपी कारक मूल्य के बीच अंतर स्पष्ट करें।
5. नाममात्र राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय के बीच अंतर लिखिए।
6. राष्ट्रीय आय की गणना का महत्व लिखिए।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइये।
2. राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें
3. भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों को स्पष्ट कीजिए।
4. भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है?

9.11. शब्दकोष

1. राष्ट्रीय आय: उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक देश.
2. मध्यवर्ती वस्तुएँ: वह वस्तुएँ जो उत्पादन की प्रक्रिया में हैं।
3. मूल्यह्रास: स्थिर पूंजी की टूट-फूट
4. कारक लागत: यह वस्तु के उत्पादित पक्ष की कीमत है।
5. शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद: सकल राष्ट्रीय उत्पाद-मूल्यह्रास।
6. सकल घरेलू उत्पाद: यह सभी अंतिम वस्तुओं का कुल मौद्रिक मूल्य है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सेवाएँ। इसमें शामिल नहीं है विदेशी आय.
7. प्रति व्यक्ति आय: यह लोगों की औसत आय है। राष्ट्रीय आय विभाजित है देश की जनसंख्या के साथ.

   प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय/जनसंख्या।
8. सकल मूल्य वर्धित: आउटपुट का मूल्य - मध्यवर्ती सामान

9.12. संदर्भ

1. सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत- सी.रंगराजन, बी.एच.ढोलकिया
2. आधुनिक अर्थशास्त्र सिद्धांत- केके डेवेट
3. मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी- एमसी। वैश्य

अध्याय

10

रोज़गार का सिद्धांत

10.0 उद्देश्य

10.1 परिचय

10.2 आय और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत

10.2.1 धारणाएँ

10.2.2 वस्तु एवं मुद्रा बाजार संतुलन: बाजार का नियम कहें

10.2.3 मुद्रा बाजार संतुलन

10.2.4 श्रम बाज़ार संतुलन

10.2.5 वेतन मूल्य लचीलापन:

10.2.6 रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख पहलू

10.2.7 सिद्धांत की सीमाएँ और आलोचना

10.3 आय और रोजगार का कीनेसियन सिद्धांत

10.3.1 समग्र आपूर्ति

10.3.2 समग्र मांग

10.3.3 प्रभावी मांग:-

10.3.4 आय और रोजगार के कीनेसियन सिद्धांत के प्रमुख पहलू:

10.4. सारांश

10.5 मॉडल परीक्षा प्रश्न

10.6. शब्दकोष

10.0. उद्देश्य

रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या करता है।

कुल मांग, समग्र आपूर्ति और प्रभावी मांग का अर्थ बताता है।

आय और रोजगार के कीनेसियन सिद्धांत की व्याख्या करता है।

10.1 परिचय

अर्थशास्त्र का शास्त्रीय स्कूल आर्थिक विचार का पहला आधुनिक स्कूल था। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मुख्य उद्देश्य यह था कि मुक्त बाज़ार विनियमित हो सकें खुद। यानी अहस्तक्षेप. शास्त्रीय सिद्धांत का आधार साय का बाज़ार का नियम है जिसे मार्शल और पिगौ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने समझाया श्रम के लिए अलग-अलग बाजारों में विभाजित उत्पादन और रोजगार का निर्धारण, माल और पैसा. इस अध्याय में हम वस्तु एवं मुद्रा बाजार संतुलन पर चर्चा करेंगे। कहते हैं बाज़ार का नियम श्रम बाज़ार और संतुलन: पिगौ की वेतन कटौती नीति कीनेसियन आय और रोजगार का सिद्धांत.

10.2 आय और रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत

शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों के अनुसार, देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है संतुलन स्तर. उनका दृढ़ विश्वास है कि अहस्तक्षेप से पूर्ण रोजगार मिलता है अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है कि लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं होगी। को उनके लिए, पूर्ण रोज़गार एक सामान्य स्थिति थी, और इससे किसी भी विचलन को माना जाता था कुछ असामान्य. शास्त्रीय सिद्धांत का आधार साय का बाज़ार का नियम है जो था मार्शल और पिगौ जैसे शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा आगे बढ़ाया गया। यह समझाया गया है कि उत्पादन और रोजगार के निर्धारण को श्रम, वस्तुओं, के लिए अलग-अलग बाजारों में विभाजित किया गया है। और पैसा।

10.2.1 धारणाएँ

मुक्त बाज़ार मूल्य प्रणालियाँ हैं।

मुद्रास्फीति के बिना भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है।

श्रम और उत्पाद बाज़ारों में पूर्ण प्रतिस्पर्धा है।

श्रम शक्ति सजातीय है.

अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन को दो भागों अर्थात उपभोग में विभाजित किया जाना है और निवेश.

दीर्घकाल में संतुलन बना रहेगा।

बाज़ार का दायरा सीमित नहीं है. इसका विस्तार होता है.

10.2.2 वस्तु एवं मुद्रा बाजार संतुलन: बाजार का नियम कहें

19वीं सदी की शुरुआत के एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्ट से ने प्रसिद्ध कानून विकसित किया बाज़ारों का. यानी, "आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है"। जेबी से के नियम के अनुसार, आपूर्ति उत्पन्न होती है उसकी अपनी माँग; वस्तुओं की पूर्ण पूर्ति के तहत आपूर्ति हमेशा मांग (एस = डी) के बराबर होती है अर्थव्यवस्था में उत्पादित. उत्पादन वस्तुओं के लिए बाज़ार बनाता है; बेचना उसी स्तर पर है समय पर खरीदारी, जिससे अधिक उत्पादन होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में आय का सृजन होता है किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में। वह आय मांग को जन्म देती है। कोई नहीं है बेरोजगारी. यह अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अतः सामान्य नहीं हो सकता अतिउत्पादन और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या। यदि सामान्य है अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन होने पर कुछ मजदूरों को अपनी नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लंबे समय में, मांग और आपूर्ति बढ़ने पर अर्थव्यवस्था स्वतः ही पूर्ण रोजगार की ओर अग्रसर हो जाएगी माल बराबर हो जाता है.

10.2.3 मुद्रा बाजार संतुलन

वस्तु बाजार संतुलन मुद्रा बाजार संतुलन और श्रम बाजार की ओर ले जाता है संतुलन। यह समझाया गया है कि अधिकांश आय उत्पादन के कारकों से आती है इनाम आय. आय का उपयोग उपभोग और बचत के माध्यम से किया जाता है। यदि बचत आय पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर खर्च किया जाता है तो इसे निवेश कहा जाता है। का रिश्ता बचत और निवेश के बीच सकारात्मक और बराबर (S=I) है। ब्याज की लचीली दर खेलती है मुद्रा बाजार संतुलन में एक प्रमुख भूमिका।

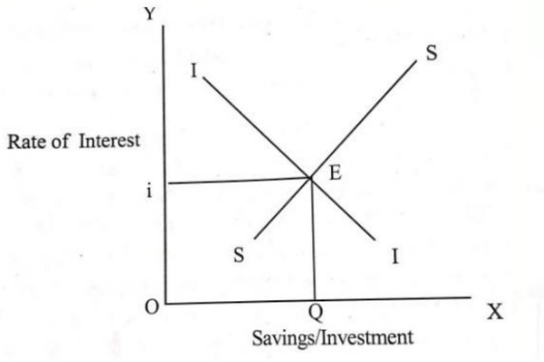

चित्र 10.1 मुद्रा बाज़ार संतुलन

उपरोक्त चित्र में बताया गया है कि बचत और निवेश के साथ मुद्रा बाजार संतुलन है
बराबर है। (एस=आई). OX-अक्ष बचत/निवेश और OY-अक्ष ब्याज दर दर्शाता है। जमा पूंजी
और निवेश ब्याज दर O पर बराबर हैं। E संतुलन बिंदु है। की दर
इरादे अपने आप बदल जाते हैं और इसी के आधार पर बचत और निवेश भी बदल जाते हैं
संतुलन बिंदु।

10.2.4 श्रम बाज़ार संतुलन

श्रम बाजार में श्रम की मांग और श्रम की आपूर्ति का स्तर निर्धारित करते हैं
उत्पादन और रोजगार. शास्त्रीय अर्थशास्त्री श्रम की मांग को मानते हैं
वास्तविक मजदूरी दर का कार्य.

डीएन = एफ (डब्ल्यू/पी) जहां डीएन = श्रम की मांग, डब्ल्यू = मजदूरी दर और पी = मूल्य स्तर। डिवाइडिंग
मजदूरी दर (डब्ल्यू) मूल्य स्तर (पी) से, हमें वास्तविक मजदूरी दर (डब्ल्यू/पी) मिलती है।

10.2.5 वेतन कटौती नीति

शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है।
शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने दृढ़ता से कहा कि उच्च मजदूरी दरें इसके मुख्य कारणों में से एक हैं
बेरोजगारी. बेरोजगारी की स्थिति में, वेतन में सामान्य कटौती से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी
पूर्ण रोजगार स्तर तक. यह तर्क इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्यक्ष है
और धन तथा मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी के बीच आनुपातिक संबंध।

रोज़गार का पिगौ वेतन कटौती सिद्धांत, जिसका नाम अर्थशास्त्री आर्थर सी. पिगौ के नाम पर रखा गया है
एक आर्थिक सिद्धांत जो आर्थिक मंदी के समय मजदूरी कम करने का सुझाव देता है

बेरोजगारी को कम करने और रोजगार को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। सिद्धांत पर आधारित है

यह विचार है कि बेरोजगारी का प्राथमिक कारण मजदूरी और कीमतों के बीच असमानता है। में

पिगौ का सिद्धांत, यदि मजदूरी अधिक लचीली होती और उसे कम करने की अनुमति दी जाती, तो समायोजन प्रक्रिया होती

अधिक चिकना होगा. कम वेतन से कंपनियों की लागत कम हो जाएगी, जिससे कम हो सकती है

वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें और बढ़ी हुई मांग। इससे मांग में बढ़ोतरी पैदा होगी

कंपनियों को अधिक श्रमिकों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहन, जिससे बेरोजगारी कम हो।

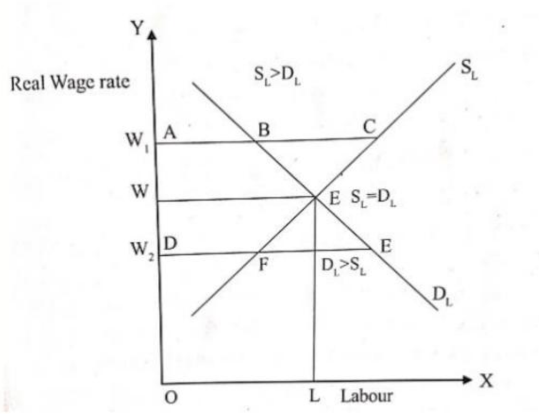

चित्र-10.2: श्रम बाजार संतुलन वेतन कटौती नीति

उपरोक्त चित्र 10.2 में बताया गया है कि श्रम बाजार संतुलन में, OX-अक्ष लिया जाता है

श्रम पर और वास्तविक मजदूरी दर पर ओए-अक्ष लिया गया। यदि मजदूरी दरें OW2 हैं, तो श्रम

मांग अधिक है और आपूर्ति कम है (डीएल > एसएल)। इसलिए, मजदूरी दर बढ़ जाती है। मजदूरी दर है

OW1 , श्रम आपूर्ति अधिक है और श्रम मांग कम है (SL DL)। अत: मजदूरी दर गिरती है। OW मजदूरी दर पर, श्रम की आपूर्ति और श्रम की मांग बराबर होती है (SL = DL)। यह है

'ई' श्रम की आपूर्ति और मांग के बराबर है जो पूर्ण रोजगार के साथ संतुलन की ओर ले जाता है।

10.2.6 रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रमुख पहलू

पहलू:

पूर्ण रोजगार का महत्व

अनैच्छिक बेरोजगारी अनुपस्थित है

पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है।

मौद्रिक मजदूरी में कमी से वास्तविक मजदूरी में भी कमी आती है।

वेतन और कीमत में लचीलापन बाजार के नियम के अनुसार होता है।

बाज़ार के नियम के कारण, कोई अतिउत्पादन और सामान्य बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं है।

लोग अपनी पूरी आय उपभोग और निवेश पर खर्च करते हैं

बचत निवेश के बराबर है

बचत को बराबर करने के लिए ब्याज दर को तदनुसार बदला जा सकता है
निवेश

10.2.7 सिद्धांत की सीमाएँ और आलोचना

शास्त्रीय सिद्धांत की धारणा वास्तविक दुनिया में लागू नहीं होती है।

पूर्ण रोज़गार अवास्तविक है.

आपूर्ति अपनी माँग स्वयं निर्मित करती है, जो सदैव संभव नहीं है।

सामान्य रोज़गार में वेतन कटौती की नीति नहीं बढ़ाई जा सकती; यह संभव नहीं है।

शास्त्रीय अर्थशास्त्री का तर्क है कि बेरोजगारी वेतन कठोरता के कारण है
बिल्कुल सच नहीं है.

किसी अर्थव्यवस्था में, पैसा उत्पादन और रोजगार निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आधुनिक अर्थव्यवस्था में, धन के बीच संतुलन हासिल करना संभव नहीं है
आपूर्ति और मांग।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि बचत से निवेश और पूंजी बनती है
संचय, आर्थिक विकास को गति देना। हालाँकि, इसमें विरोधाभास भी हो सकता है
ऐसी स्थिति जहां बढ़ी हुई बचत आवश्यक रूप से वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकती है
निवेश और कुल मांग। ऐसा इसलिए क्योंकि बचत से कमी आ सकती है
उपभोग व्यय में, जिससे समग्र आर्थिक गतिविधि में गिरावट आई।

शास्त्रीय अर्थशास्त्र न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करता है
अर्थव्यवस्था, मुक्त बाज़ारों के स्व-समायोजन तंत्र पर निर्भर है। हालांकि यह
कल्याणकारी सरकारें प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

10.3 आय और रोजगार का कीनेसियन सिद्धांत

आय और रोजगार का कीनेसियन सिद्धांत, ब्रिटिश अर्थशास्त्री द्वारा विकसित
1930 के दशक में जॉन मेनार्ड कीन्स, शास्त्रीय को एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं
रोजगार का सिद्धांत. यही वह समय था जब जेएम कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'जनरल' लिखी थी

लिखित'। इसमें उन्होंने 1930 के दशक की महामंदी की व्याख्या प्रस्तुत की और सुझाव दिया समाधान के उपाय. उन्होंने आय और रोजगार का अपना सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। यह समग्र मांग की भूमिका और बाजार विफलताओं की संभावना पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है अनैच्छिक बेरोजगारी के लिए.

10.3.1 समग्र आपूर्ति

समग्र आपूर्ति सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं की कुल आपूर्ति है किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार के एक विशेष स्तर पर उद्यमी एक साथ होते हैं। रोजगार के रूप में बढ़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है। जैसे-जैसे कुल उत्पादन बढ़ता है, कुल आपूर्ति बढ़ती है। इसलिए, कुल आपूर्ति रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। निर्माता के लिए जारी रखने के लिए उत्पादन में उन्हें कम से कम उत्पादन लागत वसूल करनी चाहिए; इसे आपूर्ति कहा जाता है कीमत। तो कुल आपूर्ति मूल्य वह न्यूनतम राशि है (जो लागत के बराबर है)। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादक को प्राप्त होना चाहिए यदि वे उत्पादित उत्पादन को किसी विशेष स्थान पर बेचते हैं रोजगार का स्तर.

कुल आपूर्ति मूल्य वह धनराशि है जो उद्यमियों को प्राप्त होनी चाहिए उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से। सकल आपूर्ति मूल्य: "श्रम के रोजगार के किसी भी स्तर पर, कुल आपूर्ति" के रूप में परिभाषित करें कीमत वह कुल राशि है जो अर्थव्यवस्था में सभी उद्यमियों द्वारा एक साथ ली जाती है। यदि उसे पुरुषों की दी गई संख्या द्वारा उत्पादित उत्पादन की बिक्री से प्राप्त होने की उम्मीद करनी चाहिए यह उन्हें नियोजित करने के लायक ही होगा।

तालिका-1: समग्र आपूर्ति मूल्य अनुसूची

रोजगार का स्तर (एन) लाखों में कुल आपूर्ति मूल्य (करोड़ रुपये में)	
10	250
12	300
14	350
16	400
18	450
20	500

उपरोक्त तालिका में, यह देखा गया है कि कुल आपूर्ति कीमतें के स्तर के साथ बढ़ती हैं

रोज़गार। 10 लाख के रोजगार स्तर के साथ, निर्माता को जितनी राशि चाहिए

राहत रु. है. 10 लाख कर्मचारियों द्वारा उत्पादित आउटपुट बेचकर 250 करोड़ रु. जब 12

लाख श्रमिक कार्यरत हैं, उद्यमियों को 300 करोड़ मिलना ही चाहिए। उसी तरह से,

जब उत्पादकों को न्यूनतम राशि अर्थात् रु. प्राप्त होने की आशा होती है। 350

करोड़, रु. 400 करोड़ रु. 450 करोड़, और रु. 500 करोड़, 14 लाख को रोजगार देंगे, 16

लाख, 18 लाख और 20 लाख श्रमिक। जब रु. 500 करोड़ कुल आपूर्ति मूल्य है,

रोजगार का स्तर 20 लाख है. 20 लाख श्रमिकों को रोजगार मिलने का अनुमान है

पूर्ण रोजगार का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि आउटपुट को बढ़ाया नहीं जा सकता.

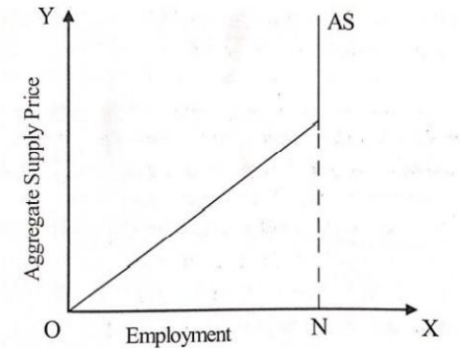

उपरोक्त आरेख में बताया गया है कि कुल आपूर्ति मूल्य ओए-अक्ष पर लिया गया है

और OX-अक्ष पर रोजगार का स्तर, या श्रमिकों की संख्या। के स्तर के रूप में

रोजगार O से N तक बढ़ता है, कुल आपूर्ति मूल्य भी बढ़ता है, अर्थात

जैसे-जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, कुल आपूर्ति मूल्य की मात्रा भी बढ़ती है

बढ़ती है।

10.3.2 समग्र मांग

समग्र मांग उत्पादन और रोजगार को निर्धारित करती है: कीन्स ने तर्क दिया कि समग्र मांग

मांग, जिसमें उपभोग (सी), निवेश (आई), सरकारी खर्च और शुद्ध शामिल है

निर्यात, उत्पादन और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

अर्थव्यवस्था। कुल मांग में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि में परिवर्तन हो सकता है,

उच्च बेरोजगारी या मुद्रास्फीति की अवधि के लिए अग्रणी।

एडी= सी+आई

तालिका-2: कुल मांग मूल्य अनुसूची

रोजगार का स्तर (एन) लाखों में कुल मांग मूल्य (करोड़ रुपये में)	
10	325
12	350
14	375
16	400
18	425
20	450

उपरोक्त तालिका रोजगार के स्तर और कुल के बीच संबंध को बताती है

माँग। रोज़गार का स्तर उद्यमियों द्वारा अपेक्षित आय को बढ़ाता है,

और समग्र मांग मूल्य बढ़ जाता है। उद्यमियों का रोजगार स्तर 10 लाख है

श्रमिकों, और वे रुपये की राशि राहत की उम्मीद करते हैं। उत्पादन की बिक्री से 325 करोड़ रु

10 लाख श्रमिकों द्वारा निर्मित। यदि वे चाहें तो 16 लाख श्रमिकों को रोजगार देने को तैयार होंगे

उम्मीद यह है कि उन्हें रु. 400 करोड़.

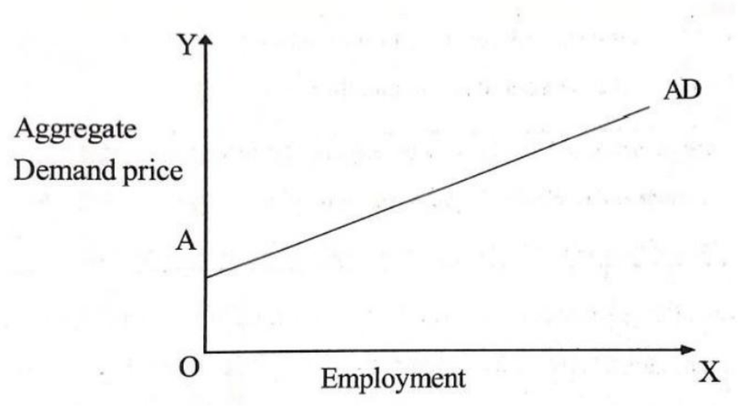

उपरोक्त ग्राफ़ में, कुल मांग मूल्य को ओए-अक्ष और के स्तर पर लिया गया है

रोज़गार को OX-अक्ष पर लिया गया है। कुल मांग मूल्य स्तर का एक कार्य है

रोजगार का। ON पर, कुल मांग मूल्य, अर्थात, उद्यमियों की राशि

प्राप्त करने की अपेक्षा, OD है, और oN1 के रोजगार स्तर पर, अपेक्षित प्राप्तियाँ हैं

OD1. इस प्रकार, जैसे-जैसे रोजगार का स्तर बढ़ता है, कुल मांग मूल्य बढ़ता है।

10.3.3 प्रभावी मांग

प्रभावी मांग की अवधारणा अर्थशास्त्री जॉन के काम से निकटता से जुड़ी हुई है मेनार्ड कीन्स. कीन्स ने तर्क दिया कि स्तर निर्धारित करने के लिए प्रभावी मांग महत्वपूर्ण है किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और रोजगार का. प्रभावी मांग काल्पनिक या से भिन्न है संभावित मांग, जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए व्यक्तियों की इच्छाओं या चाहतों को संदर्भित करती है, चाहे उन्हें खरीदने की उनकी क्षमता कुछ भी हो।

प्रभावी मांग समग्र मांग और समग्र आपूर्ति से निर्धारित होती है, जहां समग्र मांग और कुल आपूर्ति एक बिंदु पर बराबर होती है जिसे प्रभावी मांग कहा जाता है। प्रभावी मांग ही रोजगार का स्तर तय करेगी. इस बिंदु पर, राशि होने की उम्मीद है प्राप्त होता है और उद्यमियों को जो राशि प्राप्त होनी चाहिए वह बराबर है। इस बिंदु पर उद्यमी सामान्य लाभ कमाते हैं।

रोज़गार का स्तर (एन) लाखों में	कुल आपूर्ति मूल्य (करोड़ रुपये में)	कुल मांग मूल्य (करोड़ रुपये में)
10	250	325
12	300	350
14	350	375
16	400	400
18	450	425
20	500	450

उपरोक्त तालिका लाखों श्रमिकों में रोजगार के विभिन्न स्तरों, कुल आपूर्ति को दर्शाती है कीमतें, और कुल मांग कीमतें। जब अपेक्षित राशि (कुल मांग) मूल्य) और प्राप्त होने वाली राशि (कुल आपूर्ति मूल्य) रुपये के बराबर है। 400 करोड़, रोजगार का स्तर 16 लाख श्रमिक। यह बिंदु प्रभावी मांग को दर्शाता है।

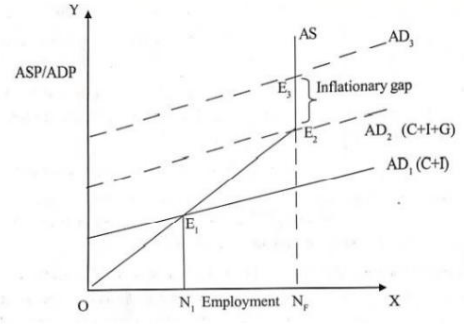

उपरोक्त आंकड़े में, कुल मांग मूल्य वक्र (एडीपी) और कुल आपूर्ति मूल्य वक्र (एएसपी) एक दूसरे को बिंदु ई पर काटते हैं। यह संतुलन बिंदु को दर्शाता है। संतुलन रोजगार के चालू स्तर पर प्राप्त किया गया है। उपरोक्त में यह मान लिया गया है कि ON आरेख पूर्ण रोज़गार को नहीं दर्शाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में निष्क्रिय कारक हैं उत्पादन। कीनेसियन विश्लेषण में, इसे अल्परोज़गार संतुलन माना जाता है।

रोजगार के कीन्स सिद्धांत में कहा गया है कि पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए, ऊपर की ओर बदलाव करना होगा कुल मांग वक्र आवश्यक है। इसे सरकारी खर्च से किया जा सकता है जब भी निजी उद्यमी अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का प्रदर्शन नहीं करते हैं निवेश में रुचि. इसके साथ, AD वक्र (C+I) नए बिंदु पर AD (C+I+G) के रूप में स्थानांतरित हो जाता है प्रभावी माँग E का, जहाँ अर्थव्यवस्था पूर्ण रोज़गार स्तर तक पहुँचती है, अर्थात, ON। आगे ई., एडी में और वृद्धि से मुद्रास्फीति (सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि) होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है एएस में वृद्धि की गुंजाइश है क्योंकि सभी संसाधनों का संभावित रूप से उपयोग किया जा चुका है। इसलिए, अंतराल ई और ई के बीच मुद्रास्फीति अंतर कहा जाता है।

10.3.4 आय और रोजगार के कीनेसियन सिद्धांत के प्रमुख पहलू:

1. आउटपुट रोजगार और आय विनिमेय शब्द हैं।
2. रोजगार और आय प्रभावी मांग पर निर्भर करते हैं।
3. प्रभावी मांग कुल मांग और समग्र आपूर्ति द्वारा नियंत्रित होती है।
4. चूंकि अल्पावधि में समग्र आपूर्ति स्थिर रहती है, कीन्स ने इस पर ध्यान केंद्रित किया कुल मांग।
5. दो क्षेत्रों वाली अर्थव्यवस्था (अर्थात, घर और फर्म) में कुल मांग उपभोग व्यय और निवेश व्यय से निर्धारित होती है।

10.4. सारांश

एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेबी से, जेएस मिल और एन. सीनियर जैसे पुराने शास्त्रीय अर्थशास्त्री अहस्तक्षेप नीति में विश्वास (किसी भी आर्थिक गतिविधियों में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं) रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत विकसित किया। यह सिद्धांत बताता है कि पूर्ण रोजगार एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता. रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत इसे खारिज करता है

मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी की संभावना। अर्थव्यवस्था हमेशा बनी रहेगी पूर्ण रोजगार संतुलन. जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी उत्कृष्ट कृति 'द जनरल थ्योरी' में 1936 में प्रकाशित 'ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी' ने एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किया किसी अर्थव्यवस्था में संतुलन कुल आय और आउटपुट के निर्धारण की व्याख्या करना।

10.5 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. शास्त्रीय अर्थशास्त्र का अर्थ है?
2. वस्तु बाजार संतुलन क्या है?
3. मुद्रा बाजार संतुलन क्या है?
4. श्रम बाज़ार संतुलन क्या है?
5. वेतन कटौती नीति से आप क्या समझते हैं?
6. पूर्ण रोज़गार से आप क्या समझते हैं?
7. समग्र आपूर्ति क्या है?
8. समग्र मांग क्या है?
9. प्रभावी मांग क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. जेबी से के नियम की व्याख्या करें "आपूर्ति अपनी मांग स्वयं बनाती है"
2. रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की मान्यताओं की व्याख्या करें।
3. प्रभावी मांग की अवधारणा को समझाइये।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
2. रोजगार के कीनेसियन सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या करें।

10.6. शब्दकोष

1. वेतन कटौती नीति: एसी पिगौ कम वेतन दर से लागत में कमी आएगी

   उत्पादन, जिससे कीमतें कम हुईं, जिसके परिणामस्वरूप माल की मांग अधिक हो गई।

2. पूर्ण रोजगार: एक ऐसी स्थिति जहां वे सभी श्रमिक जो सक्षम और इच्छुक हैं

   काम से रोजगार मिलता है.

3. समग्र आपूर्ति मूल्य: समग्र आपूर्ति मूल्य धन की कुल राशि है

   जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उद्यमियों को एक साथ प्राप्त करने की उम्मीद करनी चाहिए

   पुरुषों की दी गई संख्या द्वारा उत्पादित उत्पाद की बिक्री से, यदि यह उचित हो

   उन्हें नियोजित करने लायक.

4. कुल मांग मूल्य: किसी दिए गए उत्पाद के लिए कुल मांग मूल्य

   रोजगार की राशि आय की कुल राशि है, जो अपेक्षित है

   जब उस मात्रा में श्रम नियोजित किया जाता है तो उत्पादित उत्पादन की बिक्री से।

5. प्रभावी मांग: प्रभावी मांग कुल मांग से निर्धारित होती है और

   समग्र आपूर्ति जहां कुल मांग और समग्र आपूर्ति एक बिंदु पर बराबर होती है

   उसे प्रभावी मांग कहा जाता है।

10.7 सन्दर्भ

1. तेलुगु अकादमी से इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक।

2. वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र (318), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।

3. तेलुगु अकादमी से बीए द्वितीय वर्ष मैक्रो इकोनॉमिक्स

4. मैक्रो इकोनॉमिक्स एमएल सेठ, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा प्रकाशित

अध्याय 11

सार्वजनिक वित्त और बजट

11.0. उद्देश्य

11.1. परिचय

11.1.1. सार्वजनिक वित्त की अवधारणा

11.1.2. सार्वजनिक वित्त के घटक

11.1.3. पुनर्भुगतान के तरीके

11.2. केंद्र राज्य वित्तीय संबंध

11.3. संघीय वित्त

11.4. वित्त आयोग

11.5. बजट

11.5.1. बजट के घटक

11.5.2. बजट के प्रकार

11.5.3. बजट घाटा

11.6. सारांश

11.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

11.8. शब्दकोष

11.9. संदर्भ

11.0. उद्देश्य

सार्वजनिक वित्त को परिभाषित करें

सार्वजनिक वित्त की शाखाओं की सूची बनाएं

सार्वजनिक राजस्व

सरकारी व्यय

सार्वजनिक ऋण

केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध

संघीय वित्त - वित्त आयोग

बजट

11.1. परिचय

सार्वजनिक वित्त अर्थशास्त्र की शाखाओं में से एक है। का मतलब समझने के लिए सार्वजनिक वित्त के लिए पूर्व-आवश्यकता "सार्वजनिक और वित्त" शब्दों का कुछ ज्ञान होना है। सार्वजनिक शब्द एक सामूहिक शब्द है जिसका तात्पर्य व्यक्तियों के संग्रह से भी है यह समुदाय के सभी सदस्यों को संदर्भित करता है और वित्त धन संसाधन या राजस्व है। जनता वित्त का तात्पर्य सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों से है। सार्वजनिक वित्त शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है इंग्लैंड देश में समय.

11.1.1. सार्वजनिक वित्त की अवधारणा

सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक प्राधिकरणों की आय और व्यय से संबंधित है। सार्वजनिक शब्द का प्रयोग राज्य सरकार या केंद्रीय और स्थानीय निकायों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सार्वजनिक वित्त सरकार द्वारा धन जुटाने और खर्च करने के उद्देश्यों, तरीकों और प्रभावों का अध्ययन करता है समाज को पुलिस राज्य से बदलने में समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए कल्याणकारी राज्य के लिए.

ह्यू डाल्टन के अनुसार “इसका संबंध आय और व्यय से है सार्वजनिक प्राधिकरण और इसे एक दूसरे के समायोजन के साथ।

एडम स्मिथ के अनुसार "सार्वजनिक वित्त राज्य के राजस्व और व्यय की प्रकृति और सिद्धांतों की जांच है"।

आधुनिक सरकारें आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। वे बुनियादी सुविधाओं पर खूब पैसा खर्च करते हैं. हाल ही में सरकारें गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर भारी मात्रा में खर्च कर रही हैं
उनकी आबादी का दलित वर्ग।

सरकार द्वारा की जाने वाली गतिविधियों का आय, उत्पादन, पर प्रभाव पड़ेगा।
रोजगार और अर्थव्यवस्था का सामान्य मूल्य स्तर। सरकार को अपने कर्तव्य निभाने के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है। यह विभिन्न कर लगाता है। यदि आवश्यक हो तो यह धन उधार लेता है, कभी-कभी घाटे के वित्तपोषण का सहारा लेता है। यह विभिन्न आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पर पैसा खर्च करता है। इसलिए, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के बारे में जानना आवश्यक है

ये मिलकर सार्वजनिक वित्त का निर्माण करते हैं जो वृहत अर्थशास्त्र के प्रमुख पहलुओं में से एक है।

11.1.2. सार्वजनिक वित्त के घटक

ए) सार्वजनिक राजस्व

सार्वजनिक राजस्व का अर्थ है कर लगाकर राजस्व एकत्र करना तथा प्राप्त करना
लोगों से कई अन्य रूपों में पैसा। से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है
विभिन्न स्रोतों को सार्वजनिक राजस्व कहा जाता है। सार्वजनिक राजस्व को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है
प्रकार 1) कर राजस्व 2) गैर-कर राजस्व

1. कर राजस्व

जनता से करों के रूप में प्राप्त राजस्व को कर राजस्व कहा जाता है।
राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जनता से वसूले जाने वाले कर दो प्रकार के होते हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर.

प्रत्यक्ष कर: आय के आधार पर व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाने वाला कर
व्यय। उदाहरण: व्यक्तिगत आयकर, ब्याज कर और व्यय कर

व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति और पूंजीगत संपत्तियों पर लगाए गए कर।

उदाहरणार्थ: संपत्ति कर, उपहार कर, संपदा शुल्क।

अप्रत्यक्ष कर: वे कर जिनका बोझ अंतिम कर में स्थानांतरित किया जा सकता है

भुगतानकर्ता को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है अर्थात वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर। उदाहरणार्थ: उत्पाद शुल्क

शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष कर है

जिसने भारत में कई व्यक्तिगत करों का स्थान ले लिया है। फ्रांस ऐसा करने वाला पहला देश था

1954 में जीएसटी लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम पारित किया गया

संसद (122वां संशोधन अधिनियम) 29 मार्च, 2017 को अधिनियम लागू हुआ

1 जुलाई, 2017 को जीएसटी एक व्यापक, बहु चरण, गंतव्य आधारित कर है

प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया गया। सरल शब्दों में जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो कि लगाया जाता है

इस प्रणाली के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति। जीएसटी के लिए चार (4) स्लैब तय हैं

दरें यानी 5%, 12%, 18% और 28%।

इस प्रणाली के अंतर्गत 3 कर लागू होते हैं।

1) सीजीएसटी (केंद्रीय जीएसटी): केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी।

2) एसजीएसटी (राज्य जीएसटी): राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जीएसटी।

3) आईजीएसटी (एकीकृत जीएसटी): एकीकृत जीएसटी केंद्र और राज्यों द्वारा लगाया जाएगा

समवर्ती रूप से।)

पहले के अप्रत्यक्ष कर शासन में, दोनों द्वारा कई अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे

राज्य और केंद्र. राज्य मुख्य रूप से मूल्य वर्धित कर (वैट) के रूप में कर एकत्र करते हैं।

प्रत्येक राज्य के अलग-अलग नियम और कानून थे। माल की अंतरराज्यीय बिक्री पर कर लगाया गया

केंद्र द्वारा.

2. गैर कर राजस्व

सरकार को करों के अलावा अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त होता है और ऐसे राजस्व को राजस्व कहा जाता है

गैर-कर राजस्व. गैर-कर राजस्व के स्रोत इस प्रकार हैं:

क) प्रशासनिक राजस्व: सरकार को कुछ प्रशासनिक कार्यों के लिए धन प्राप्त होता है

सेवाएँ। उदाहरण: लाइसेंस शुल्क, ट्यूशन शुल्क जुर्माना, विशेष मूल्यांकन आदि।

ख) वाणिज्यिक राजस्व: आधुनिक सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ स्थापित करती हैं

कुछ वस्तुओं का निर्माण करते हैं और कुछ सेवाएँ प्रदान करते हैं। उन्होंने कीमतों का आदान-प्रदान किया।

इसलिए ऐसी इकाइयाँ अपने उत्पाद बेचकर राजस्व अर्जित करती हैं। उदाहरण: आईओएल, बीएसएनएल, बीएचईएल,

टीएसआरटीसी, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया आदि।

ग) ऋण और अग्रिम: जब सरकार को करों से राजस्व प्राप्त होता है

और गैर-कर स्रोत सरकारी व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं हैं

यह देश के भीतर संचालित वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है

जनता से भी. आधुनिक सरकार विदेशों से भी ऋण प्राप्त कर सकती है

सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। उदाहरण: आईबीआरडी, आईएमएफ, एडीबी, आदि।

घ) सहायता अनुदान: सहायता अनुदान का अर्थ है बिना किसी शर्त के प्राप्त करना

पुनर्भुगतान. उनका भुगतान नहीं किया जाता. राज्य सरकारें ऐसे अनुदान प्राप्त करती हैं

केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को विदेशों से ऐसे अनुदान प्राप्त हो सकते हैं

सरकारें या कोई अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसी। अनुदान दो प्रकार के होते हैं.

मैं) सामान्य अनुदान: जब सामान्य रूप से धन की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है

बिना किसी उद्देश्य को बताए इसे सामान्य अनुदान कहा जाता है।

द्वितीय) विशिष्ट अनुदान: जब कोई अनुदान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिया जाता है तो उसे कहा जाता है

सामान्य अनुदान. इसे किसी अन्य उद्देश्य पर खर्च नहीं किया जा सकता. उदाहरण: शिक्षा अनुदान,

स्वास्थ्य अनुदान, बाढ़ अनुदान।

बी) सार्वजनिक व्यय

सार्वजनिक व्यय सार्वजनिक प्राधिकरणों - केंद्र, राज्य द्वारा किया गया व्यय है और नागरिकों की सामूहिक आवश्यकताओं या उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। पूंजी के संचयन में सार्वजनिक व्यय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो इसे नियंत्रित करती है उत्पादक क्षमता में वृद्धि दर.

सार्वजनिक व्यय वह व्यय है जो सरकार विभिन्न कार्यों में करती है आर्थिक क्रियाकलाप। सार्वजनिक व्यय समाज को धन हस्तांतरित करता है। अगर बढ़ोतरी होती है सार्वजनिक व्यय में, समुदाय की आय में भी वृद्धि होगी। इसलिए देश में विकास होता है. सार्वजनिक व्यय घटेगा तो आय स्तर भी गिर जायेगा जिससे देश में विकास नहीं हो पायेगा।

ग) सार्वजनिक ऋण

सरकार सार्वजनिक ऋण का विकल्प तब चुन सकती है जब उसका व्यय उसके राजस्व से अधिक हो। ऐसी स्थिति में सरकार देश या विदेश के विभिन्न स्रोतों से धन उधार लेती है। इससे सार्वजनिक ऋण बनता है।

सार्वजनिक ऋण के प्रकार: स्रोतों के आधार पर सार्वजनिक ऋण को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

i) आंतरिक ऋण: आंतरिक सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा उधार ली गई निधि से है
देश के भीतर इसके नागरिक, वित्तीय संस्थान और अन्य एजेंसियां।

ii) बाहरी ऋण: बाहरी ऋण से तात्पर्य भौगोलिक क्षेत्र से बाहर विदेशी निवेशकों, एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरकार द्वारा उधार ली गई धनराशि से है।
इसके नियंत्रण में क्षेत्र, सरकार द्वारा विदेशी बैंकों, विदेशी सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे आईएमएफ, आईबीआरडी, आईएफसी आदि से उधार लिया गया ऋण।

सार्वजनिक ऋण का मोचन: मोचन का अर्थ है किसी ऋण का पुनर्भुगतान। बिल्कुल निजी के रूप में
व्यक्ति या संस्था को अपना ऋण चुकाना है, उसने उधार लिया है इत्यादि
सरकार को सार्वजनिक ऋण पर न केवल ब्याज देना पड़ता है बल्कि मूलधन भी चुकाना पड़ता है
नियत तारीख।

पुनर्भुगतान के निम्नलिखित फायदे हैं

i) सबसे पहले यह सरकार को दिवालिया होने से बचाता है।

ii) दूसरे यह सरकार के फिजूलखर्च को हतोत्साहित करता है।

iii) तीसरा यह ऋणदाताओं का विश्वास बनाए रखता है।

iv) यह भावी पीढ़ी को कर्ज के बोझ से बचाता है।

11.1.3. पुनर्भुगतान के तरीके

1. अस्वीकृति: इसका तात्पर्य सरकार द्वारा ऋण चुकाने से इंकार करना है। केवल सोवियत
रूस ने 1917 में इस पद्धति का पालन किया था। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक दिनों में यह पद्धति नहीं है
यह इसलिए संभव है क्योंकि अनुबंधों को स्वीकार और सम्मान किया जाना चाहिए।

2. रिफंडिंग: रिफंडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिपक्व बांड को नए से बदल दिया जाता है
बांड.

3. परिवर्तन: सार्वजनिक ऋण के परिवर्तन का अर्थ है पुराने ऋण के बदले नये ऋण का विनिमय।
रूपांतरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक ऋण को उच्च से उच्चतर में शामिल करना या बदलना शामिल है
ब्याज की कम दर.

4. वास्तविक पुनर्भुगतान: वास्तविक पुनर्भुगतान के लिए निम्नलिखित तरीकों का पालन किया जाता है

सार्वजनिक ऋण।

ए) सिंकिंग फंड: इस पद्धति में, एक फंड बनाया जाता है जिसमें एक निश्चित राशि होती है बकाया ऋण की अदायगी के लिए हर वर्ष राजस्व जमा किया जाता है। के अनुसार डाल्टन को राजकोष के वर्तमान राजस्व से एक डूबती निधि बनानी चाहिए और ऋण से बाहर नहीं.

ख) अधिशेष राजस्व: सफाई के लिए वार्षिक रूप से अधिशेष बजट की नीति अपनाई जा सकती है सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता पर पुनर्भुगतान के लिए एक कोष बनाने के बजाय धीरे-धीरे। लेकिन हाल के वर्षों में, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण अधिशेष बजट दुर्लभ है घटना।

ग) टर्मिनल वार्षिकियां: सरकार टर्मिनल वार्षिकियां जारी कर सकती है, जो परिपक्वता का एक हिस्सा है। प्रत्येक वर्ष क्रमानुसार विभाजित किया जाता है। इस विधि में ऋण होता है वार्षिक भुगतान किया जाता है और इसलिए राज्य का बोझ भी बहुत कम हो जाता है।

घ) पूंजीगत लेवी: पूंजीगत लेवी से तात्पर्य संपत्ति और धन पर बहुत भारी कर से है। यह है एक निश्चित मूल्य से ऊपर की पूंजीगत संपत्ति पर एक बार के लिए लगाया गया कर। दरअसल पूंजी अनुत्पादक युद्ध ऋण के कारण युद्ध के तुरंत बाद लेवी बदल दी जाती है।

11.2. केंद्र राज्य वित्तीय संबंध

भारत संघीय ढांचे वाला देश है. केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों को मान्यता दी गई है जैसा कि लगभग सभी संघों में बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक संविधान के अनुच्छेद 263 से 281 तक ने विस्तृत प्रावधान किए हैं जो वितरण के संबंध में केंद्र को निर्देश प्रदान करते हैं राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों की

गौरतलब है कि केंद्र सरकार इसमें अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आधुनिक समय में संघीय ढांचे वाले देशों में आर्थिक विकास प्राप्त करना। भारत स्वतंत्रता के बाद एक महासंघ का गठन किया गया, प्रावधान। अत: आवश्यक प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध जो हैं एक महासंघ के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें संघीय राजकोषीय संबंधों द्वारा शासित होती हैं। इसलिए, राजकोषीय बनाने वाले वित्तीय हस्तांतरणों को विस्तार से जानना आवश्यक है केंद्र और राज्य के बीच समायोजन. जबकि संघ संसद विशिष्ट पर कर लगाती है संघ सूची के अनुसार वस्तुएँ, राज्य विधायिका राज्य के अनुसार विशिष्ट वस्तुओं पर कर लगाती है सूची।

i) संघ सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ: संघ सरकार के पास विशिष्ट शक्तियाँ होती हैं
पर कर लगाना

1) निगम कर

2) सीमा शुल्क कर

3) पूंजीगत लाभ कर

4) इनकम टैक्स पर सरचार्ज

5) रेलवे किराया

6) तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क

7) माल आदि पर अंतिम कर।

राज्य सरकारों की विशेष शक्तियाँ: राज्य सरकार के पास विशेष शक्तियाँ हैं
पर टैक्स लगाओ

1) भू-राजस्व

2) स्टाम्प ड्यूटी

3) संपदा शुल्क

4) प्रवेश कर

5) बिक्री कर

6) वाहनों और विलासिता आदि पर कर।

7) संपत्ति और भवनों पर कर

8) कृषि भूमि पर संपदा शुल्क

केंद्र सरकार आर्थिक रूप से स्वतंत्र है क्योंकि, उसके पास अधिक धन है
उसकी आवश्यकता हैं। इसके विपरीत राज्य सरकारें आर्थिक रूप से निर्भर हैं क्योंकि उनके पास अधिक नहीं है
उनकी आवश्यकता से अधिक पैसा। रखरखाव के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं
कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की।

भारत में संविधान इन्हें बनाने के लिए राज्य सरकार को सहायता अनुदान प्रदान करता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र अनुच्छेद 275 आदिवासियों के विकास के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है कुछ राज्यों में कल्याण. यदि कोई प्राकृतिक जलवायु जैसे बाढ़ या सूखा पड़ता है तो उस स्थिति में राज्यों को सहायता अनुदान भी प्रदान किया जाता है।

विविध शक्तियाँ: विविध शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं

1) संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद संविधान का प्रावधान किया गया समेकित निधि का, जिससे नगर पालिकाओं को संसाधनों की आपूर्ति की जाती है और ग्राम पंचायतें.

2) अनुच्छेद 360 के अनुसार, राष्ट्रपति उस समय राज्य को वित्तीय शक्तियाँ दे सकता है वित्तीय आपातकाल की घोषणा. कर राजस्व के वितरण के अलावा, केंद्र सरकार राज्यों के वित्तीय संसाधनों को जोड़ने के लिए दो अन्य तरीकों का पालन करती है।

i) केंद्रीय ऋणों की उन्नति और

ii) राज्यों को सहायता अनुदान दिया गया

11.3. संघीय वित्त

संघीय वित्त केंद्र और राज्य दोनों सरकारों और उनके वित्त का प्रतिनिधित्व करता है संबंध। इस वित्त प्रणाली के तहत राजस्व और व्यय की सभी वस्तुओं को विभाजित किया जाता है केंद्रीय के बीच. राज्य और स्थानीय सरकारें।

"संघीय वित्त का तात्पर्य संघीय और राज्य सरकारों के वित्त से है और दोनों के बीच संबंध।" - आरएन भार्गव

संघीय वित्त की विशेषताएँ:

1) संविधान के आधार पर आय के स्रोत और व्यय की मदें दी गई हैं केंद्र और राज्य सरकारों को.

2) संघीय व्यवस्था में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

3) भले ही राज्य में स्वशासन हो। वे केन्द्रीय के अधीन रहते हैं
सरकार।

4) यदि केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद है, तो उन्हें इस प्रकार सुलझाया जाता है
संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार.

संघीय सरकार के सफल संचालन की शर्त:

1) सभी सरकारों के पास राजस्व और उत्पन्न आय के स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए
और संसाधनों को जुटाना।

2) सभी सरकारों के पास इसे पूरा करने के लिए अपने संसाधनों पर पूरी शक्ति होती है
आवश्यकताएं।

संघीय वित्तीय प्रणाली के विकास और प्रावधान:

भारतीय अधिनियम 1935 के आधार पर भारत में संघीय वित्त प्रणाली का विकास किसके द्वारा किया गया था?
ब्रिटिश सरकार. यह अधिनियम वित्तीय स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांत प्रदान करता है
प्रांत.

1) आर्थिक रूप से मजबूत केंद्र प्राप्त करने के लिए:

i) केंद्र राजस्व का अधिक लचीला और अधिक उपज देने वाला स्रोत रहा है।

ii) केंद्र को मुद्रा मुद्रण और बैंकिंग के विषयों को महत्व दिया गया है
और घाटे के वित्तपोषण का सहारा लेने की शक्ति।

iii) केंद्र सरकार को कुछ विशेष स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं
आय।

iv) अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं।

2) कुशल कार्यों और वित्तीय शक्ति को आवंटित करने के लिए: संविधान ने वर्गीकृत किया है
यह तीन प्रकार की सूचियों अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कार्य करती है।

3) संसाधन हस्तांतरण प्रदान करना: संसाधनों को स्थानांतरित करने के लिए संविधान ने प्रावधान किया है
तीन प्रकार के साधन हैं, वे हैं कर बँटवारा, अनुदान और ऋण।

4) संसाधन हस्तांतरण में लचीलापन प्रदान करना: वित्त आयोग हर साल
केंद्र से राज्य तक संसाधनों के परिवर्तन की सिफारिश करता है।

11.4. वित्त आयोग

वित्त आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत की गई है। आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष के लिए की जाती है और इसमें एक अध्यक्ष, सचिव और 4 सदस्य होते हैं। अब तक 15 वित्त आयोगों की नियुक्ति की जा चुकी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. एनके सिंह हैं।

वित्त आयोग के कार्य:

i) करों की शुद्ध आय का प्रतिशत जिसे बीच विभाजित किया जा सकता है
संघ और राज्य.

ii) राज्यों के बीच ऐसे करों की आय के हिस्से का आवंटन।

iii) जिन सिद्धांतों से सहायता अनुदान का वितरण किया जाएगा
राज्यों के बीच भारत सरकार की निधि को समेकित करना।

iv) जनजातीय क्षेत्रों के लिए अनुदान सहायता और आवंटन।

v) किसी विशेष राज्य के लिए विशेष अनुदान।

15वाँ वित्त आयोग

भारत सरकार ने 27 नवंबर को 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति की।
2017 एनके सिंह अध्यक्ष के रूप में। की जनसंख्या डेटा का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है
गणना के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया। यह पहला आयोग है जिसने प्रस्तुत किया है
जीएसटी लागू होने के बाद की सिफारिशें

11.5. बजट

बजट की अवधारणा: 'बजट' शब्द फ्रांसीसी शब्द 'बैगुएट' से लिया गया है
मतलब एक छोटा सा चमड़े का थैला. बजट राजस्व और व्यय को दर्शाने वाला एक वार्षिक विवरण है
एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का (1 अप्रैल - 31 मार्च)। इसे बजट द्वारा तैयार किया जाता है
प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। हालाँकि इसमें बजट शब्द का जिक्र नहीं है
संविधान, लेकिन यह अनुच्छेद 112 में अनिवार्य है। इसे केंद्र सरकार प्रस्तुत करेगी
संसद के समक्ष अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का "वार्षिक वित्तीय विवरण"।
सरकार के। बजट भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है।
बजट की तैयारी हर साल सितंबर महीने में की जाती है.

बजट में शामिल हैं -

1. पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े

2. चालू वर्ष के लिए बजट और संशोधित आंकड़े

3. अगले वर्ष के लिए बजट अनुमान।

सरकार हर साल विधानमंडल के सामने अपना वार्षिक बजट पेश करती है अनुमोदन। कभी-कभी सरकार द्वारा वॉयस ऑन अकाउंट बजट पेश किया जाता है पूर्ण बजट पेश करना संभव नहीं. संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार यह सरकार के लिए किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य है भारत की समेकित निधि से धन। लेखानुदान बजट 2 महीने तक रहता है हालाँकि, इसे बढ़ाया जा सकता है। चुनावी साल होने पर इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है.

उद्देश्य:

बजट का मुख्य उद्देश्य कर के लिए विधानमंडल की मंजूरी प्राप्त करना है विभिन्न सरकारी गतिविधियों के लिए संसाधनों का प्रस्ताव और आवंटन।

मैं। संसाधनों का आवंटन

द्वितीय. संसाधनों का वितरण

iii. घरेलू अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण

iv. आय और धन का पुनर्वितरण

संसाधनों का पुनर्आबंटन

vi. स्थिरता के साथ आर्थिक विकास

सातवीं. सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन

11.5.1. बजट के घटक

बजट के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं i) प्राप्तियां ii) व्यय और iii) घाटा।

i) प्राप्तियाँ: प्राप्तियाँ सरकार द्वारा विभिन्न माध्यमों से एकत्र किए गए राजस्व को संदर्भित करती हैं मतलब। प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं अर्थात् राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत प्राप्तियाँ।

राजस्व प्राप्तियाँ: राजस्व प्राप्तियाँ सरकार का राजस्व है। उदाहरणार्थ: आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क आदि।

पूंजीगत प्राप्तियां: पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो दायित्व उत्पन्न करती हैं सरकारी संपत्ति में कमी का कारण उदाहरण: ऋण, उधार आदि की वसूली विनिवेश प्राप्तियाँ.

ii) बजट व्यय: बजट व्यय अनुमानित व्यय को संदर्भित करता है सरकार द्वारा विभिन्न पूंजीगत व्यय और राजस्व के तहत खर्च किया गया व्यय।

पूंजीगत व्यय: इस व्यय में सड़कों के निर्माण पर व्यय शामिल है, पुल, भवन आदि

राजस्व व्यय: इस व्यय में वेतन, ब्याज, भुगतान, पेंशन, सब्सिडी आदि

iii) घाटा: बजट घाटा सभी प्राप्तियों और खर्चों के बीच का अंतर है सरकार का राजस्व और पूंजीगत खाता दोनों।

11.5.2. बजट के प्रकार

राजस्व के अंतर के आधार पर बजट 3 प्रकार के होते हैं और व्यय.

1) संतुलित बजट: इस प्रकार में अनुमानित राजस्व और अनुमानित व्यय होता है बराबर (आर = ई).

2) अधिशेष बजट: इस प्रकार में अनुमानित सरकारी राजस्व से अधिक होगा अनुमानित व्यय (आर>ई).

3) घाटे का बजट: यह उस बजट को संदर्भित करता है जिसमें कुल व्यय से अधिक होता है कुल राजस्व (आर<ई).

11.5.3. बजट घाटा

बजट घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां सरकार का बजट खर्च होता है इसकी बजट प्राप्तियों से अधिक है। बजट घाटे चार प्रकार के होते हैं। वे हैं:

1. राजस्व घाटा: जब राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक हो। तब राजस्व घाटा उत्पन्न होता है.

राजस्व घाटा = राजस्व आय - राजस्व व्यय

2) बजट घाटा: कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित किया जाता है बजट घाटे के रूप में.

3) राजकोषीय घाटा: बजट घाटे और बाजार उधार के योग को राजकोषीय कहा जाता है घाटा।

4) प्राथमिक घाटा: राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच का अंतर है प्राथमिक घाटा के रूप में जाना जाता है।

11.6. सारांश

लोकतांत्रिक सरकार में सार्वजनिक वित्त राजस्व और व्यय है सरकार। हर साल सरकार संसद/विधानसभा में बजट पेश करती है राजस्व और व्यय के लक्ष्य. राजस्व के लिए बजट एक महत्वपूर्ण घटक है और व्यय.

11.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दीजिए।

1. सार्वजनिक वित्त को परिभाषित करें।
2. सार्वजनिक व्यय से क्या तात्पर्य है?
3. सार्वजनिक ऋण क्या है?
4. पूंजी लेवी क्या है?
5. संघीय वित्त क्या है?
6. बजट क्या है?
7. राजकोषीय घाटा क्या है?
8. जीएसटी क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. सार्वजनिक वित्त के स्रोत क्या हैं?

2. सार्वजनिक ऋण के मोचन के तरीकों की व्याख्या करें।

3. वित्त आयोग की व्याख्या करें।

4. बजट घाटे की व्याख्या करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दीजिए।

1. भारत में केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों का विश्लेषण करें।

2. संघीय वित्त पर एक निबंध लिखें।

3. बजट की अवधारणा एवं घटकों का वर्णन करें।

4. सार्वजनिक ऋण के प्रकार बताइये।

11.8. शब्दकोष

1. सार्वजनिक वित्त: यह सार्वजनिक प्राधिकरणों (केंद्रीय, केंद्रीय) की आय और व्यय से संबंधित है।

   राज्य और स्थानीय सरकार)

2. पूंजीगत लेवी: यह पूंजीगत संपत्ति और संपदा पर लगाया जाने वाला कर है।

3. सार्वजनिक व्यय: सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किया गया व्यय।

4. सार्वजनिक ऋण: सरकार की आंतरिक और बाह्य उधारी

   स्रोत।

5. ऋण मोचन: ब्याज का भुगतान और मूल राशि का पुनर्भुगतान

   सरकार।

6. राजकोषीय नीति: यह सरकार के निर्णयों, परिवेश, खर्च और कर निर्धारण को संदर्भित करती है।

7. बजट: एक निर्धारित अवधि के लिए आय और व्यय का अनुमान।

8. बजट घाटा: बजट घाटा तब होता है जब सरकार का व्यय अधिक होता है

   इसके राजस्व से अधिक.

9. संघीय वित्त: इसका अर्थ है आय के विभिन्न शीर्षों का विभाजन और समन्वय और केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच व्यय।

10.संतुलित बजट: संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें कुल प्राप्तियां और कुल खर्च बराबर हैं.

11.9. संदर्भ

1. बीपी त्यागी: सार्वजनिक वित्त
2. आर. सुंदरसनराव: भारत में संघीय राजकोषीय हस्तांतरण।
3. डॉ. ब्रौ: सार्वजनिक वित्त बीए 420 सीओ-ई
4. तेलुगु अकादमी: इंटरमीडिएट पाठ्यपुस्तक बोर्ड
5. भारतीय बजट 2022

अध्याय 12

धन

12.0. उद्देश्य

12.1. परिचय

12.2. धन की अवधारणा

12.3. धन का विकास

12.4. वस्तु विनिमय प्रणाली

12.5. धन की परिभाषाएँ

12.6. धन की संबंधित अवधारणाएँ

12.7. धन के प्रकार

12.8. धन के कार्य

12.8.1. धन के प्राथमिक कार्य

12.8.2. धन के द्वितीयक कार्य

12.8.3. धन के आकस्मिक कार्य

12.8.4. धन के स्थिर और गतिशील कार्य

12.9. धन आपूर्ति के घटक

12.10. सारांश

12.11. मॉडल परीक्षा प्रश्न

12.12. शब्दकोष

12.13. संदर्भ

12.0. उद्देश्य

धन के विकास को समझाइये

वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधाओं का विश्लेषण करें।

धन की अवधारणा को परिभाषित करें

धन के प्रकारों को वर्गीकृत करें

मुद्रा के कार्य समझाइये

धन के महत्वपूर्ण घटक बताइये।

12.1. परिचय

आम तौर पर मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। आर्थिक क्षेत्र में धन का विशेष स्थान है ज़िंदगी। मनुष्य ने अनुभवों से सीखा है कि वह अपने जीवनयापन के लिए धन कमाता है और खर्च करता है वस्तुओं और सेवाओं पर अर्जित धन। किसी व्यक्ति का जीवन स्तर निर्भर करता है पैसे की क्रय शक्ति. क्रय शक्ति का तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं की संख्या से है जिसे एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि से खरीदा जा सकता है। कीमतों में बदलाव लाता है पैसे की क्रय शक्ति में परिवर्तन के बारे में. जैसे-जैसे पैसे की क्रय शक्ति बदलती है, कुछ वर्गों को लाभ होता है और अन्य को हानि होती है। पैसा वस्तुओं और सेवाओं के लिए अवसर प्रदान करता है कम प्रयास से और बिना देरी के लोगों के बीच आदान-प्रदान किया जा सके।

इस इकाई में आप धन की अवधारणा और कार्यों के बारे में सीखेंगे।

12.2. धन की अवधारणा

आज हम पैसे के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, आमतौर पर हमारा मतलब यह होता है कि वह अमीर है। इसके विपरीत अर्थशास्त्री मनी इन शब्द का प्रयोग करते हैं एक अधिक विशिष्ट तरीका. एक अर्थशास्त्री के लिए धन का तात्पर्य सभी धन से नहीं बल्कि केवल एक धन से है इसका प्रकार. आधुनिक समुदायों में, पैसा उन संपत्तियों का भंडार है जिनका उपयोग आसानी से किया जा सकता है दैनिक लेन-देन करें।

12.3. धन का विकास

'पैसा' शब्द रोम की देवी जूनो मोनेटा के नाम से लिया गया है। में एक

आदिम समाज में लोग वस्तुओं का विनिमय अन्य वस्तुओं से करते थे। यह सीधा आदान-प्रदान

प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चूँकि वस्तु विनिमय प्रणाली संचालन में अत्यंत असुविधाजनक थी,

आपसी आदान-प्रदान के लिए मूल्य का एक सामान्य माप, अर्थात् पैसा, पेश किया गया था। पहले

सिक्कों के प्रचलन के बाद विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उदाहरण के लिए, के बाद से

बहुत पहले से, अनाज, 'कौड़ी के गोले' और मवेशियों का उपयोग धन के रूप में किया जाता था। इसके बाद आया

धातु के सिक्कों का उपयोग - सोना, चांदी, तांबे के सिक्के। रोमन काल में 'बेसेंट' एक सोने का सिक्का था,

मौर्य काल में 'पना' चांदी का सिक्का मानक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था। आजकल हम

कागजी मुद्रा है. आधुनिक अर्थव्यवस्था में हाल के घटनाक्रम क्रेडिट मनी में हैं

ड्राफ्ट, चेक, प्लास्टिक मनी - क्रेडिट और डेबिट कार्ड और डिजिटल मनी के रूप -

ऑनलाइन लेनदेन आदि,

12.4. वस्तु विनिमय प्रणाली

धन के अभाव में विनिमय को असंभव नहीं समझना चाहिए। वस्तु विनिमय प्रणाली

धन के अस्तित्व में आने से पहले इसका अभ्यास किया जाता था। हमारे देश में वस्तु-विनिमय की यह व्यवस्था आज भी कायम है

कुछ हद तक गाँवों में प्रचलित है। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान-प्रदान कहलाता है

वस्तु विनिमय प्रणाली। बड़े पैमाने पर उत्पादन के इन दिनों में यह विधि ठीक से काम नहीं कर पाई है।

ऐसे लोगों को ढूंढने में कई दिन लग सकते हैं. इस पद्धति से न केवल समय बर्बाद होता है बल्कि नुकसान भी होता है

कई कठिनाइयों के लिए.

वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधाएँ

वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधाएँ निम्नलिखित हैं।

(i) आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव: जब वस्तुओं का सीधे आदान-प्रदान करना होता है

माल के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेता दोनों की इच्छाएँ मेल खाएँ। के लिए

उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के पास बकरियाँ हैं और वह बदले में आलू लेना चाहता है, उसे कोई और ढूँढ़ना होगा

जिस व्यक्ति के पास आलू है और उसे बदले में बकरियाँ चाहिए।

(ii) मूल्य के भंडारण का अभाव: वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहीत नहीं किया जा सकता है। उनका मूल्य घट जाता है।

उनमें से कुछ कुछ समय बाद पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि लोग मवेशियों, अनाज और अन्य चीजों का व्यापार करते हैं

ऐसी नाशवान वस्तुओं के मूल्य को लंबी अवधि तक संग्रहीत करना बहुत कठिन होता है।

(iii) वस्तुओं की विभाज्यता का अभाव: एक और कठिनाई यह है कि कुछ वस्तुएँ छोटे-छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अनाज जैसी वस्तुओं को कई भागों में बाँटा जा सकता है और जो वस्तु हम चाहते हैं उसके बदले में। लेकिन सभी वस्तुएँ विभाज्य नहीं हैं। कल्पना करना यदि गाय, बकरी और माल घर, कोट आदि जानवरों को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाए मूल्य नष्ट हो जाएगा.

(iv) मूल्य के सामान्य माप का अभाव: इसमें कोई सामान्य माप मूल्य नहीं है वस्तु विनिमय प्रणाली। सभी वस्तुओं का मूल्य समान नहीं होता। का निपटारा करना कठिन है विनिमय की शर्तें. मान लीजिए कि एक बकरी को चावल के बदले में दिया जाना है, तो यह तय करना मुश्किल है एक बकरी के लायक चावल की मात्रा.

(v) अलग-अलग भुगतान करने में कठिनाई: वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत सामान उधार लेना पड़ता है और पुनर्भुगतान माल में किया जाना चाहिए। यदि समय के बीच वस्तु का मूल्य बदल जाता है ऋण लिया जाता है और जिस समय ऋण चुकाया जाता है, ऋणदाता या उधारकर्ता को नुकसान हो सकता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो ऋणदाता को हानि होती है, यदि वह बढ़ता है तो ऋणदाता को हानि होगी कर्जदार को नुकसान होगा.

इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत आने वाली विभिन्न कठिनाइयों ने धन को जन्म दिया।

12.5. धन की परिभाषाएँ

पैसा कई अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषित एक अवधारणा है। धन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विचार निम्नानुसार हैं।

(i) रॉबर्टसन ने पैसे को ऐसी किसी भी चीज़ के रूप में परिभाषित किया है जिसके लिए भुगतान व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है माल या अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों के निर्वहन में।

(ii) क्राउथर ने पैसे को 'कुछ भी जो विनिमय के माध्यम के रूप में आम तौर पर स्वीकार्य है और जो एक ही समय में मूल्य के माप और भंडार के रूप में कार्य करता है' के रूप में परिभाषित किया है।

(iii)वॉकर के अनुसार 'पैसा वही है जो पैसा करता है'।

(iv) सेलिगमैन ने पैसे को "एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया है जो सामान्य स्वीकार्यता रखती है।"

धन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आम तौर पर सभी सदस्यों को स्वीकार्य होना चाहिए उस समाज में जो इसका उपयोग करता है। धन को खाते की एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। हर एक देश खाते और मुद्रा की अपनी मौद्रिक इकाई होती है। उदाहरण के लिए भारत में रुपया, भारत में डॉलर संयुक्त राज्य अमेरिका आदि हमारे देश में सभी संपत्तियों का मूल्य रुपये के रूप में व्यक्त किया जाता है।

12.6. धन की संबंधित अवधारणाएँ

धन से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ हैं। वे मुद्रा, तरलता और निकट मुद्रा हैं।

(i) मुद्रा: मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम है। संक्षेप में यह है

धन, सिक्कों और कागजी नोटों के रूप में, आमतौर पर सरकार और केंद्र द्वारा जारी किया जाता है

किनारा। धन में न केवल मुद्रा बल्कि मांग और सावधि जमा भी शामिल है
बैंक.

(ii) तरलता: यह उस दक्षता को संदर्भित करता है जिसके साथ किसी संपत्ति को धन में परिवर्तित किया जा सकता है।

सभी संपत्तियों में सबसे अधिक तरल संपत्ति पैसा ही है।

(iii) नियर मनी: नियर मनी शब्द में अत्यधिक तरल संपत्ति शामिल है जो नहीं है

पैसा लेकिन आसानी से पैसे में बदला जा सकता है। निम्नलिखित परिसंपत्तियाँ निकटतम स्थानापन्न हैं

से पैसा। इसलिए इन्हें निकट या अर्ध मुद्रा कहा जाता है। निकट मुद्रा के उदाहरणों में शामिल हैं (ए)

वाणिज्यिक बैंकों में बचत और सावधि जमा (बी) डाकघरों में बचत जमा

और डाकघर बांड (सी) मनी मार्केट फंड (डी) सरकारी ट्रेजरी बिल (ई) की इकाइयां

यूटीआई (एफ) सरकारी प्रतिभूतियां (जी) संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयर।

12.7. धन के प्रकार

मोटे तौर पर मुद्रा दो मुख्य प्रकार की होती है (ए) धातु मुद्रा या सिक्के और (बी)

कागज के पैसे। इन्हें आगे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

(i) वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा: यह मुद्रा का वह रूप है जिसमें

अंकित मूल्य पैसे के आंतरिक मूल्य के बराबर है। इसे फुल बॉडी मनी भी कहा जाता है। पूर्व:

सिक्के. वह मुद्रा जिसका अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, कहलाती है

प्रतिनिधि धन. उदाहरणार्थ: कागजी मुद्रा।

(ii) वैध मुद्रा और वैकल्पिक मुद्रा: वैध मुद्रा जो वैध हो

मंजूरी यानी कोई भी इसे भुगतान के माध्यम के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। एक के भीतर हर कोई

देश को इसे स्वीकार करना होगा. उदाहरण: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया धन। कोई वैकल्पिक पैसा नहीं है

इसके पीछे कानूनी मंजूरी है. लेकिन आस्था और विश्वास पर इसे स्वीकार किया जाएगा। सभी प्रकार के चेक,

ड्राफ्ट, डिबेंचर, शेयर, क्रेडिट कार्ड और ऐसे अन्य वैकल्पिक पैसे हैं।

(iii) धात्विक मुद्रा और कागजी मुद्रा: धात्विक मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो कि है

सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओं से बनी कागजी मुद्रा से तात्पर्य उस मुद्रा से है जो कि है

कागजी करेंसी नोटों के रूप में। उदाहरण: 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोट।

(iv) मानक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा: मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका आंतरिक रूप

मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर है. सांकेतिक धन वह धन है जिसका आंतरिक मूल्य कम होता है

इसका अंकित मूल्य. उदाहरण: 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के।

(v) क्रेडिट मनी: क्रेडिट मनी को बैंक मनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसका तात्पर्य बैंक जमा से है

लोगों द्वारा बैंकों में रखा जाता है जो मांग पर देय होता है और एक पक्ष से स्थानांतरित किया जा सकता है

चेक के उपयोग के माध्यम से दूसरे को। चेक एक उपकरण है जिसका उपयोग बैंक को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है

जमा करता है और यह धन के रूप में कुछ सुविधाएं प्रदान करता है।

12.8. धन के कार्य

आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा महत्वपूर्ण कार्य करती है जिन्हें वर्गीकृत किया गया है

डेविड किनले इस प्रकार हैं:

इन कार्यों को (i) प्राथमिक कार्य (ii) द्वितीयक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है

(iii) आकस्मिक कार्य और (iv) स्थिर और गतिशील कार्य।

12.8.1. धन के प्राथमिक कार्य

धन के प्राथमिक कार्य दो प्रकार के होते हैं:

(i) विनिमय का माध्यम: विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का उपयोग बिक्री और खरीद में किया जाता है

वस्तुओं और सेवाओं का. कोई भी व्यक्ति उपलब्ध धन के बदले में सामान और सेवाएँ प्राप्त कर सकता है

हमारे पास। इस प्रकार, धन ने आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को दूर कर दिया , में सामना करना पड़ा

वस्तु विनिमय प्रणाली और लेनदेन में समय और ऊर्जा कम हो गई।

(ii) मूल्य का माप: बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापती है

वस्तुओं और सेवाओं की खरीद। मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई को भी दूर कर दिया है

मूल्य के एक सामान्य माप के रूप में कार्य करके। विभिन्न वस्तुओं के मूल्य व्यक्त किये जाते हैं

पैसों की बात करें तो। इसे कीमत कहते हैं. रु. 40 प्रति किलो, रु. 20 एक दर्जन आदि, माप का प्रतिनिधित्व करते हैं

मूल्य का। मूल्य के माप के रूप में मुद्रा ने लेन-देन को सरल और आसान बना दिया है।

12.8.2. धन के द्वितीयक कार्य

धन के प्राथमिक कार्यों के अलावा, धन के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जो द्वितीयक कार्य कहलाते हैं। ये द्वितीयक कार्य नीचे दिए गए अनुसार व्यक्त किए गए हैं:

(iii) मूल्य का भंडार: पैसा मूल्य के भंडार के रूप में कार्य करता है। चूँकि पैसे में मूल्य होता है इसलिए लोग बचत करते हैं वे अपनी कमाई का एक हिस्सा पैसे के रूप में किसी भी समय किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए उपयोग कर सकते हैं।

(iv) आस्थगित भुगतान का मानक: भिन्न भुगतान का अर्थ भविष्य का भुगतान है। धन समय बीतने के बाद वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान में भी सहायक है। इसका मतलब है कि साथ पैसे की मदद से लोग केवल प्रतिबद्धता पर ही सामान और सेवाएँ खरीद और बेच सकते हैं, भविष्य में भुगतान किस्तों के रूप में किया जा सकता है। वेतन का भुगतान, किस्तें, ऋण आदि विभिन्न भुगतानों के उदाहरण हैं।

(v) मूल्य का स्थानांतरण: धन का मूल्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है व्यक्ति और किसी भी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर। चल-अचल वस्तुओं का विक्रय एवं क्रय धन के सहयोग से अचल संपत्ति भी बनाई जा सकती है।

12.8.3. धन के आकस्मिक कार्य

धन के प्राथमिक और द्वितीयक कार्यों के अलावा कुछ आकस्मिक कार्य भी होते हैं जो आम तौर पर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित हैं। ये कार्य हैं:

(i) राष्ट्रीय आय का वितरण: धन के योगदान को मापने में सहायक होता है देश के विभिन्न भागों की राष्ट्रीय आय। धन राष्ट्रीय वितरण को सुगम बनाता है उत्पादन के विभिन्न कारकों में आय, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन सभी शामिल हैं उत्पादन के किसी कार्य में सहयोग करें।

(ii) सीमांत उपयोगिता/उत्पादकता का समानीकरण: उपयोगिता या उत्पादकता जैसी अवधारणाएँ पैसे के संदर्भ में मापा जाता है। एक उपभोक्ता के साथ-साथ एक निर्माता भी उपयोगिताओं को मापता है विभिन्न वस्तुओं और उत्पादन के कारकों को धन की सहायता से प्राप्त करना और अधिकतम प्राप्त करने का प्रयास करना संतुष्टि या अधिकतम रिटर्न.

(iii) ऋण का आधार: व्यावसायिक गतिविधि की प्रगति ऋण प्रणाली से जुड़ी होती है देश। ऋण प्रणाली की संपूर्ण शक्ति धन पर आधारित है। बैंक बनाते हैं क्रेडिट पैसा. मुद्रा आपूर्ति देश की ऋण प्रणाली को प्रभावित करती है।

(iv) तरलता: किसी भी परिसंपत्ति की विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने की क्षमता को तरलता कहा जाता है। पैसा सभी परिसंपत्तियों में सबसे अधिक तरल है यानी, पैसे को वस्तुओं के बदले आसानी से बदला जा सकता है बिना किसी कठिनाई के सेवाएँ।

12.8.4. धन के स्थिर और गतिशील कार्य

पॉल आइंजिग ने धन के कार्यों को दो व्यापक श्रेणियों अर्थात् स्थिर और में वर्गीकृत किया गतिशील कार्य:

(i) स्थैतिक कार्य: धन के प्राथमिक और द्वितीयक कार्य अर्थात् माध्यम विनिमय, मूल्य का माप, मूल्य का भंडार और आस्थगित भुगतान के मानक कहलाते हैं स्थैतिक कार्य. किसी देश का आर्थिक विकास स्थिरता से प्रभावित नहीं होता है कार्य.

(ii) गतिशील कार्य: गतिशील कार्य वे हैं जो परिवर्तन लाते हैं आर्थिक स्थितियाँ जैसे मूल्य स्तर, उत्पादन का स्तर, उपभोग, वितरण, सामान्य मूल्य स्तर और रोजगार आदि।

12.9. धन आपूर्ति के घटक

मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य किसी विशेष समय में जनता द्वारा रखे गए कुल धन से है अर्थव्यवस्था। यह एक स्टॉक अवधारणा है. मुद्रा आपूर्ति के घटक भिन्न-भिन्न हो सकते हैं विभिन्न देश। मुद्रा आपूर्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा: मुद्रा में सिक्के और कागजी मुद्रा शामिल होती है। आमतौर पर किसी भी देश में केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करता है। भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ भारत केंद्रीय बैंक है. यह 2000,500,200,100 50, 20 और 10 के सभी नोट जारी करता है रुपये। केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय एक रुपये का नोट और सिक्के जारी करता है।

2. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाई गई मांग जमा: बैंक जमा एक महत्वपूर्ण हैं मुद्रा आपूर्ति का घटक. वाणिज्यिक बैंक स्वीकृत जमाओं से ऋण बनाते हैं जनता से. प्राथमिक जमाओं की सहायता से बैंकों द्वारा बनाई गई जमाएँ कहलाती हैं व्युत्पन्न जमा.

मनी एग्रीगेट्स: आरबीआई ने मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों के लिए आंकड़े प्रकाशित किए, अर्थात, M0 , M1 , M2 और M3 . इन्हें इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

M0 = प्रचलन में मुद्रा + आरबीआई के पास बैंकरों की जमा राशि + आरबीआई के पास अन्य जमा

भारतीय रिज़र्व बैंक

एम1 = जनता के पास मुद्रा + बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा + अन्य जमा
आरबीआई के साथ

एम2 = एम1 + बैंकिंग प्रणाली में बचत जमा का समय देयता भाग + बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्र + एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली सावधि जमा। (सीडी को छोड़कर)

एम3 = एम2 + एक वर्ष की परिपक्वता अवधि में सावधि जमा + बैंकों की कॉल/टर्म उधार।

स्रोत: आरबीआई रिपोर्ट - www.rbi.org.in/scripts

12.10. सारांश

मुद्रा को एक ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे आम तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है।

पैसा समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

किसी व्यक्ति का जीवन स्तर धन की क्रय शक्ति पर निर्भर करता है।

क्रय शक्ति से तात्पर्य वस्तुओं या सेवाओं की एक निश्चित मात्रा से है
किसी निश्चित समय पर पैसे से खरीदारी की जा सकती है।

मुद्रा और सिक्कों के प्रचलन से पहले विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता था
धन। उदाहरण के लिए अनाज, मवेशी आदि।

वस्तु के बदले वस्तु का आदान-प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है।

वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत आने वाली असुविधाओं ने धन को जन्म दिया।

मुद्रा से संबंधित अवधारणाएँ मुद्रा, तरलता और निकट धन हैं।

मोटे तौर पर धन के दो मुख्य प्रकार हैं अर्थात् धातु धन या
सिक्के और कागजी मुद्रा.

इन्हें आगे विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कमोडिटी मनी, लीगल
निविदा, वैकल्पिक, टोकन मनी और क्रेडिट मनी आदि,

धन के कार्यों को प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य, के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आकस्मिक कार्य, स्थिर और गतिशील कार्य।

विनिमय का माध्यम, मूल्य का माप, मूल्य का भंडार, स्थगित का मानक भुगतान और मूल्य का हस्तांतरण मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य हैं।

मुद्रा आपूर्ति में सेंट्रल बैंक द्वारा जारी मुद्रा और डिमांड डिपॉजिट शामिल हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाया गया।

12.11. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है?
2. टोकन मनी से क्या तात्पर्य है?
3. आप धन के आस्थगित भुगतान के मानक के बारे में क्या जानते हैं?
4. धन के स्थिर और गतिशील कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट करें।
5. धन के घटक क्या हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या असुविधाएँ होती हैं?
2. धन की परिभाषाएँ संक्षेप में समझाइये।
3. मुद्रा से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. विभिन्न प्रकार के धन के बीच अंतर बताइए।
2. मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्यों को समझाइये।

12.12. शब्दकोष

पैसा: पैसा वह चीज़ है जिसे आम तौर पर भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है।

वस्तु-विनिमय प्रणाली: वस्तुओं के बदले वस्तुओं के सीधे आदान-प्रदान को वस्तु-विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है।

मुद्रा: मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम है। संक्षेप में यह है सिक्कों और कागजी नोटों के रूप में पैसा।

तरलता: किसी भी परिसंपत्ति की विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करने की क्षमता को तरलता कहा जाता है।

वैधानिक मुद्रा : वैधानिक मुद्रा जिसे स्वीकार करने की कानूनी मंजूरी हो

भुगतान का माध्यम.

क्रेडिट मनी: क्रेडिट मनी से तात्पर्य बैंक जमा से है जो मांग पर देय होती है

और किसी भी समय एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित किया जा सकता है।

12.13. संदर्भ

इंटरमीडिएट तेलुगु अकादमी पाठ्य पुस्तक

बीए मैक्रो इकोनॉमिक्स

अध्याय

13

बैंकिंग

13.0. उद्देश्य

13.1. परिचय

13.2. बैंकिंग की अवधारणा

13.3. वाणिज्यिक बैंकों की परिभाषाएँ

13. 4. वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

13. 4.1. जमा स्वीकार करना

13. 4.2. ऋण और अग्रिम

13. 4.3. साख का निर्माण

13. 4.4. एजेंसी के कार्य

13. 4.5. सामान्य उपयोगिता सेवाएँ

13. 5. नेट बैंकिंग

13.6. सेंट्रल बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक

13.6.1. भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य

13.6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

13.7. सारांश

13.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

13.9. शब्दकोष

13.10. संदर्भ

13.0. उद्देश्य

बैंकिंग की अवधारणा को समझाइये।

वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों का वर्गीकरण कीजिए

नेट बैंकिंग के फायदे बताएं।

बचत और सावधि जमा के बीच अंतर बताइए।

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें।

13.1. परिचय

बैंकिंग एक व्यावसायिक गतिविधि है. बैंक जनता से जमा राशि प्राप्त करते हैं और उसे जरूरतमंद लोगों को उधार देते हैं। आधुनिक दिनों में, बैंकिंग किसी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी देश की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है।

13.2. बैंकिंग की अवधारणा

'बैंकिंग' शब्द ग्रीक शब्द 'बैंक' से लिया गया है जिसका अर्थ है बेंच। प्राचीन में

यूनानी, इफिसस, डेल्फ़ी और ओलंपिस के प्रसिद्ध मंदिरों का उपयोग निक्षेपागार के रूप में किया जाता था। इन

मंदिर धन उधार लेन-देन के स्थान हैं। भारत में कागजी मुद्रा को हुंडी कहा जाता है

बंगाल के जगतसेठों, पटना के शाहों, मद्रास के चेट्टियारों द्वारा जारी किए गए आदेश सर्वत्र स्वीकार किए गए

देश भी और बाहर भी. 1606 में एम्स्टर्डम के व्यापारियों ने एक बैंक बनाया जिसका स्वामित्व था

शहर। इस बैंक ने दो शताब्दियों तक सफलतापूर्वक बैंकिंग लेनदेन संचालित किया। दौरान

17वीं सदी, लंदन में सुनार बैंकर बन गये। यह केवल 19वीं शताब्दी थी

विश्व में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ।

13.3. वाणिज्यिक बैंकों की परिभाषाएँ

बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो जनता से धन जमा और अग्रिम स्वीकार करता है

उधारकर्ताओं को ऋण. बैंक एकत्रित धन का उपयोग परिवारों को ऋण देने के लिए करते हैं

फर्म और सरकार। लोग अपना अतिरिक्त धन दो कारणों से बैंकों में जमा करते हैं

– पैसे की सुरक्षा और कुछ ब्याज राशि अर्जित करना।

आरएस सेयर्स के अनुसार, "बैंक ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके ऋण आमतौर पर स्वीकार किए जाते हैं
अन्य लोगों के ऋणों का निपटान.

क्राउथर का कहना है, "एक वाणिज्यिक बैंक उन लोगों से पैसा इकट्ठा करता है जिनके पास अतिरिक्त पैसा होता है या जिनके पास पैसा होता है
वे इसे अपनी आय से बचा रहे हैं और उन लोगों को पैसा उधार देते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

हर्बर्ड एल.हर्ट ने बैंकर की परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दी है जो व्यवसायिक सम्मान की सामान्य प्रक्रिया में है
उन व्यक्तियों द्वारा उसे जारी किए गए चेक जिनके लिए उसे वर्तमान में धन प्राप्त होता है
खाता।"

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार "बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो स्वीकार करता है
उधार देने या जनता से चुकाए जाने वाले पैसे की जमा राशि का निवेश करने के उद्देश्य से
मांग या अन्यथा और चेक, ड्राफ्ट, भुगतान आदेश या अन्यथा द्वारा निकासी योग्य है
एक बैंक के दायरे में"।

13.4. वाणिज्यिक बैंकों के कार्य

एक वाणिज्यिक बैंक एक संगठित वित्तीय संस्थान है जो जमा स्वीकार करता है
जनता उद्योग, व्यापार, कृषि और उपभोक्ताओं आदि को धन उधार देती है और प्रदान करती है
अपने ग्राहकों के लिए उपयोगी सेवाओं की संख्या। वित्तीय क्षेत्र में बैंकों की अद्वितीय भूमिका है।
बैंकों के पास देश के देय उत्पादन की प्रकृति और मात्रा निर्धारित करने की शक्ति है
इस तथ्य से कि प्रचलन में मौजूद धन का एक बड़ा हिस्सा बैंकों के नियंत्रण में है।
एक वाणिज्यिक बैंक के मुख्य उद्देश्य हैं (ए) लोगों से जमा राशि जुटाना और
संस्थान और (बी) ऋण का विस्तार यानी कमाई की दृष्टि से जरूरतमंदों के लिए ऋण आगे बढ़ाना
नफा। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से जमा स्वीकार करते हैं और
अग्रिम ऋण. अतः वाणिज्यिक बैंक के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं (1) स्वीकृति
जमा का (2) ऋण और अग्रिम का भुगतान।

13.4.1. जमा स्वीकार करना

जमा से तात्पर्य उस धन से है जो लोग बैंकों में रखते हैं। बैंक चार प्रकार के स्वीकार करता है
जनता से जमा और निम्नलिखित खाते रखता है।

i) चालू/मांग जमा: ये जमा विशेष रूप से व्यापारिक लोगों के लिए हैं
जो अक्सर बड़ी रकम का लेन-देन करते हैं। इन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मांग पर चुकाया जा सकता है।

आम तौर पर इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता. लेकिन ग्राहकों से रखरखाव शुल्क लेते हैं विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए। ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है.

ii) बचत जमा: ये जमा आम जनता जैसे छोटे व्यवसाय के लिए सुविधाजनक हैं लोग, कर्मचारी और निम्न एवं मध्यम आय वाले लोग। लोग जमा और निकासी कर सकते हैं किसी भी समय पैसा. बैंक निकासी की राशि और संख्या पर एक सीमा लगाते हैं समय की एक विशेष अवधि. सावधि जमा की तुलना में ब्याज दर कम होगी।

iii) सावधि जमा: ये जमा एक निश्चित अवधि के लिए स्वीकार किए जाते हैं, जैसे 7 दिन, 46 दिन, 90 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष इत्यादि। ब्याज की दर अवधि की लंबाई के साथ बदलती रहती है और जमा राशि. की समाप्ति के बाद ही इन जमाओं को निकाला जा सकता है अवधि। हालाँकि कोई भी ऐसी जमाओं पर ऋण ले सकता है या उन्हें रद्द करके पैसा प्राप्त कर सकता है ब्याज को पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ना।

iv) आवर्ती जमा: ये जमाएँ सावधि जमा के प्रकार हैं। लोग एक निश्चित अवधि तक समय-समय पर एक निश्चित राशि जमा करें। रकम मिलती रहती है संचित। इन जमाओं पर दिया जाने वाला ब्याज तुलनात्मक रूप से बचत जमाओं से अधिक है और सावधि जमा से भी कम।

13.4.2. ऋण और अग्रिम का भुगतान

बैंक जमा राशि का उपयोग सावधानी से करता है। चूंकि सभी जमाकर्ता अपनी रकम एक साथ नहीं निकालते समय के साथ, बैंक जमा राशि के साथ व्यापार करने का उपक्रम करता है। यह योजना बनाता है और हमेशा कुछ न कुछ रखता भी है केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार जमाकर्ताओं की मांगों को पूरा करने के लिए नकद शेष किनारा।

क) मांग ऋण: वह ऋण जिसे मांग पर वापस लिया जा सकता है, मांग ऋण कहलाता है। कोई परिपक्वता नहीं बताई गई है. संपूर्ण ऋण राशि ऋण राशि में जमा की जाती है उधारकर्ता का. वे सुरक्षा दलालों को पसंद करते हैं जिनकी क्रेडिट ज़रूरतों में आम तौर पर उतार-चढ़ाव होता है, व्यक्तिगत सुरक्षा और वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऐसे ऋण लें।

ख) अल्पावधि ऋण: अल्पावधि ऋण व्यक्तिगत सुरक्षा के रूप में दिए जाते हैं कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण के लिए ऋण। पूरी राशि एक किस्त में चुकाई जाती है या ऋण की अवधि के दौरान कई किस्तों में।

ग) नकद ऋण: यह व्यवसायियों को ऋण प्रदान करने का एक और तरीका है। इस व्यवस्था के तहत स्वीकृत राशि एक बार में नहीं दी जाती है, बल्कि एक खाता खोला जाता है और उधारकर्ता को आवश्यकता पड़ने पर राशि निकालने की अनुमति है। बैंक शुल्क ब्याज केवल उस राशि के लिए है जो उधारकर्ता उपयोग करता है, संपूर्ण ऋण के लिए नहीं स्वीकृत।

घ) ओवरड्राफ्ट: बैंक चयनित ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करते हैं। ग्राहक अपनी जमा राशि से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस पर ब्याज देना होगा अतिरिक्त राशि जिसे अल्प अवधि के भीतर चुकाना होगा। की राशि ओवर ड्राफ्ट की अनुमति उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करती है। ओवरड्राफ्ट केवल चालू खातों के संबंध में ही किया जा सकता है।

ई) विनिमय बिलों की छूट: बैंक विनिमय बिल धारक को इसकी अनुमति देते हैं विनिमय बिल को सुरक्षा के रूप में रखते हुए कुछ पैसे निकालने के लिए। यह नहीं देगा पूरी राशि लेकिन उस पर छूट दें अर्थात अंकित मूल्य से कम भुगतान करें। जब बिल परिपक्व हो जाता है, यह इसे पार्टी को भुगतान के लिए भेजता है और जमाकर्ता को शेष राशि का भुगतान करता है अपना कमीशन काटने के बाद. विनिमय बिल 90 की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं दिन.

एफ) क्रेडिट कार्ड: क्रेडिट कार्ड मूल रूप से एक भुगतान तंत्र है जो अनुमति देता है खरीदारी करने के लिए धारक. बैंक ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इस कार्ड के साथ, कार्ड धारक किसी भी दुकान से उधार पर सामान खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है कुछ नियमों के अधीन दुकानों से सामान खरीदना। की राशि बिल उन बैंकों से एकत्र किया जाता है जिन्होंने क्रेडिट कार्ड जारी किया है। उदाहरण: एसबीआई, कार्ड एलीट, एचडीएफसी रेगलिया क्रेडिट कार्ड आदि,

13.4.3. साख का निर्माण

बैंक अपने ग्राहकों को प्राप्त राशि में से उन्हें अग्रिम ऋण देकर साख बनाते हैं जनता से जमा का रूप. सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित रखना आवश्यक है केंद्रीय बैंक के पास उनके नकदी भंडार का प्रतिशत। बैंक ऋण और अग्रिम देते हैं प्राथमिक जमा की कुल राशि का भाग. जब कोई बैंक किसी ग्राहक को ऋण देता है, यह नकद भुगतान के बजाय ऋण को जमा खाते में जमा करता है। इस प्रकार व्युत्पन्न जमा हैं बनाया था।

13.4.4. एजेंसी के कार्य

वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और प्रदर्शन के लिए कमीशन प्राप्त करते हैं एजेंसी निम्नानुसार कार्य करती है।

क) एक वाणिज्यिक बैंक सदस्यता, प्रीमियम, किराया आदि का भुगतान करता है अपने ग्राहकों के निर्देशों के अनुसार.

बी) यह चेक, विनिमय बिल, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी के माध्यम से धन एकत्र करता है अन्य बैंकों से उनके ग्राहकों के नोट आदि।

ग) अपने ग्राहकों की सलाह पर उनकी संपत्ति के 'ट्रस्टी' और 'कार्यकारी' के रूप में कार्य करता है ग्राहक.

घ) यह सोना, चांदी बेचता और खरीदता है , अपने ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियाँ और शेयर।

ई) लाभांश, शेयरों और डिबेंचर पर ब्याज का संग्रह इसकी ओर से किया जाता है ग्राहक.

13.4.5. सामान्य उपयोगिता सेवाएँ

क) धन का स्थानांतरण: यह सस्ते और आसानी से धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर आदि के माध्यम से जगह-जगह

बी) बैंक साख पत्र, यात्री चेक और उपहार चेक जारी करते हैं।

c) यह व्यापारियों को अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है और प्रदान करता है अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों के बारे में समान जानकारी।

घ) बैंक अपने ग्राहकों को उनके मूल्यवान आभूषण रखने के लिए लॉकर की सुविधा प्रदान करते हैं और सुरक्षित अभिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। इस प्रयोजन के लिए सेवा किराया एकत्र किया जाता है।

ई) सरकार, सार्वजनिक और निजी निकायों द्वारा जारी हामीदारी प्रतिभूतियाँ।

च) विदेशी मुद्रा का लेन-देन।

छ) ग्राहकों को जमा करने में सक्षम बनाने के लिए एटीएम (स्वचालित टेलर मशीनें) स्थापित करना और कुछ सीमाओं के अधीन नकदी निकाल सकते हैं। ग्राहक एटीएम सुविधा का उपयोग कर सकते हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड का उपयोग करना।

विकासशील देश में वाणिज्यिक बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बचत जुटाते हैं पूंजी निर्माण के लिए. बैंक ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शाखाएँ खोलकर प्रचार-प्रसार कर सकते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रीकरण की प्रक्रिया. वे न केवल उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करते हैं बल्कि पूंजी बाजार को विकसित करने में भी मदद करता है। वे किसी देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीति का पालन करके।

13.5. नेट बैंकिंग

आजकल अधिकांश बैंकों में मानव और मैनुअल टेलर काउंटरों का स्थान लिया जा रहा है स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम)। बैंकिंग गतिविधियां कंप्यूटर, इंटरनेट से हो रही हैं और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन जिन्हें नेट बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। नेट बैंकिंग इसे इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या वेब बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है।

इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों को पारंपरिक रूप से उपलब्ध लगभग हर सेवा प्रदान करती है जमा, स्थानान्तरण और ऑनलाइन बिल भुगतान सहित स्थानीय शाखा। वस्तुतः हर बैंकिंग संस्था के पास कुछ प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग है, जो डेस्कटॉप संस्करणों और इसके माध्यम से उपलब्ध है मोबाइल क्षुधा। ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, उपभोक्ताओं को बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं है अपने अधिकांश बुनियादी बैंकिंग लेनदेन पूरे करें। वे यह सब अपने आप कर सकते हैं हालाँकि, सुविधा, जहाँ भी वे चाहते हैं यानी घर पर, काम पर, या हमारे काम के रास्ते पर इस सुविधा का उपयोग करने के लिए सीमा शुल्क को इंटरनेट एक्सेस वाले एक कंप्यूटर की आवश्यकता है। नेट के उदाहरण बैंकिंग में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) आदि, सेवा तक पहुंचने के लिए, ग्राहकों को पंजीकरण करना होगा उनके बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा के लिए।

मोबाइल बैंकिंग (एम-बैंकिंग) एक नवीनतम बैंकिंग सेवा है जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है एक मोबाइल संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन। मोबाइल बैंकिंग में ग्राहक कर सकता है जब वह रोमिंग में हो यानी एक ही स्थान पर तैनात न हो तो बैंक की सेवाओं का लाभ उठा सकता/सकती है। यह भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में हुई थी। कई बैंक जैसे SBI, HDFC, AXIS और ICICI बैंक आदि इंटरनेट पर वित्तीय लेनदेन कर रहे हैं।

इंटरनेट बैंकिंग के फायदे

इस सुविधा का उपयोग करने वाला ग्राहक लेनदेन संबंधी और गैर-लेन-देन संबंधी कार्य कर सकता है शामिल:

क) ऑनलाइन खाता खोलना सरल और संचालित करना आसान है।

बी) ग्राहक खाता विवरण देख सकता है।

ग) यह 24 x 7 सेवाएँ हैं।

घ) ग्राहक किसी निश्चित अवधि के लिए लेनदेन के इतिहास की जांच कर सकता है संबंधित बैंक.

ई) बैंक, स्टेटमेंट, विभिन्न प्रकार के फॉर्म, एप्लिकेशन डाउनलोड किए जा सकते हैं।

एफ) ग्राहक फंड ट्रांसफर कर सकता है, किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान कर सकता है, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज कर सकता है कनेक्शन आदि। इससे डाक व्यय पर समय और धन दोनों की बचत होती है।

छ) ग्राहक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीद और बिक्री कर सकता है।

ज) ग्राहक निवेश और व्यापार कर सकता है।

i) ग्राहक बुकिंग, परिवहन, यात्रा पैकेज और मेडिकल पैकेज कर सकता है।

जे) यह लेनदेन करने का एक सुरक्षित तरीका है।

k) इंटरनेट बैंकिंग से ग्राहक यात्रा, कागजी काम की परेशानियों से बच जाता है।

एल) आजकल, बैंकिंग प्रणाली में इंटरनेट बैंकिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राहकों वाई-फाई या 3जी, या 4जी कनेक्शन का उपयोग करके अपने मोबाइल फोन पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

13.6. सेंट्रल बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय बैंक देश की बैंकिंग और वित्तीय संस्था में सर्वोच्च संस्था है। यह बैंकिंग के आयोजन, विनियमन, पर्यवेक्षण और विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है किसी देश की व्यवस्था. प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 तारीख को हुई थी अप्रैल 1935 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ। प्रारंभ में इसका स्वामित्व निजी शेयरधारकों के पास था लेकिन 1949 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है भारत। RBI अधिनियम 1934 के अनुसार, यह केंद्रीय बैंक के सभी कार्य करता है।

13.6.1. भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य

a) भारत में मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करना।

बी) बैंक नोटों के मुद्दे को विनियमित करना।

ग) मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का संचालन।

घ) बढ़ती चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचा होना
जटिल अर्थव्यवस्था.

ई) विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।

च) राष्ट्रीय समर्थन के लिए वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करना
उद्देश्य.

13.6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक कई महत्वपूर्ण कार्य करता है जिनकी चर्चा इस प्रकार है
अंतर्गत।

क) सामान्य कार्य

1. मुद्रा जारी करना: भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार दिया गया है देश में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट वैध मुद्रा हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का निर्गम विभाग मुद्रा और सिक्के जारी करता है। केवल एक रूपये के सिक्के, इससे कम मूल्य के नोट वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं भारत। भारतीय रिज़र्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ रुपये का रिजर्व रखना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम 115 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए।

2. सरकार का बैंकर: भारतीय रिज़र्व बैंक एक एजेंट, सलाहकार और के रूप में कार्य करता है सरकार का बैंकर. एक बैंकर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक को जमा राशि प्राप्त होती है सरकार की ओर से नकद, चेक और ड्राफ्ट आदि। यह अल्पावधि ऋण प्रदान करता है सरकार और सरकार की ओर से विदेशी मुद्राएँ बेचती और खरीदती है। यह भी सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है, नए ऋण जारी करता है, इन ऋणों के लिए सदस्यता प्राप्त करता है, ब्याज का भुगतान करता है उन पर और अंततः इन ऋणों को चुकाता है। केंद्रीय बैंक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है सरकार। एक सलाहकार के रूप में यह सरकार को समय-समय पर सभी बैंकिंग पर सलाह देता है लेन-देन.

3. बैंकर्स बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक इसके लिए नियम और कानून बनाता है वाणिज्यिक बैंकों को उतनी धनराशि पसंद होती है जितनी उन्हें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। यह अनुपात को नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। यह वाणिज्यिक बैंकों के बिलों में भी छूट देता है। यह सभी बैंकों को मार्गदर्शन प्रदान करता है और उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कभी-कभी रिज़र्व बैंक ऑफ भारत वाणिज्यिक बैंकों का निरीक्षण करता है और सुधार के तरीके और साधन सुझाता है।

4. अंतिम ऋणदाता: भारतीय रिज़र्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है

सहारा। यह अनुमोदित प्रतिभूतियों पर छूट देकर सभी बैंकों को वित्त की अंतिम आवश्यकता प्रदान करता है
और संपार्श्विक ऋण और अग्रिम।

5. क्लियरिंग हाउस: भारतीय रिजर्व बैंक स्थानांतरण के लिए क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है
वाणिज्यिक बैंकों के आपसी दावों का निपटान। चूंकि वाणिज्यिक बैंक अपना रखते हैं

रिज़र्व बैंक के पास नकदी भंडार होने से दावों का निपटारा करना आसान और सुविधाजनक हो जाता है

रिज़र्व के साथ रखे गए उनके खातों में स्थानांतरण प्रविष्टियाँ करके उनके बीच
बैंक ऑफ इंडिया।

6. विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक: भारतीय रिजर्व बैंक एक के रूप में कार्य करता है

हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक। यह रुपये के बाहरी मूल्य को बनाए रखता है। यह

विदेशी मुद्रा की प्राप्ति और भुगतान दोनों को नियंत्रित करता है। यह स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है

बाज़ार में विदेशी मुद्राओं की खरीद और बिक्री द्वारा विनिमय दर का निर्धारण।

7. ऋण नियंत्रक: भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया नियंत्रण ऋण। यह ब्याज दरें निर्धारित करता है,

ऋण की मात्रा और विभिन्न क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनाया

अर्थव्यवस्था में ऋण को नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक तरीके। मात्रात्मक विधियां

इसका उद्देश्य ऋण की लागत और उपलब्धता को नियंत्रित करना है, जबकि गुणात्मक तरीके प्रभावित करते हैं
ऋण का उपयोग एवं दिशा.

बी) पर्यवेक्षी कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंकिंग और वित्तीय को विनियमित और प्रशासित करने की शक्तियाँ हैं

हमारे देश में सिस्टम.

1. भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को लाइसेंस देता है।

2. विभिन्न घटकों पर समय-समय पर जानकारी मांगकर बैंकों का निरीक्षण करता है
संपत्ति और देताएं।

3. निर्देश जारी करता है और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता है।

ग) प्रचारात्मक और विकासात्मक कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रकार के प्रचारात्मक और विकासात्मक कार्य करता है

राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए कार्य करता है। यह धन और पूंजी के विकास में मदद करता है

बाज़ार।

1. यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक शाखा बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार की योजना बना रहा है क्षेत्र.

2. यह विशिष्ट समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष एजेंसियां बनाता है। महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं (i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए। (ii) औद्योगिक विकास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) और (iii) केंद्र और राज्य को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने के लिए प्रायोजित वित्तीय निगम (आईएफसीआई, एसएफसी)। उद्योग.

13.7. सारांश

बैंकिंग समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जहां बैंकिंग एक व्यावसायिक गतिविधि है धन जमा जनता से एकत्र किया जाता है, और इन जमाओं को स्थानांतरित किया जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति. एक वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्थान है। के मुख्य कार्य वाणिज्यिक बैंक जमा स्वीकार कर रहे हैं और ऋण दे रहे हैं। वाणिज्यिक बैंक स्वीकार करते हैं चार प्रकार की जमाएँ अर्थात् चालू, बचत, सावधि और आवर्ती जमा। व्यावसायिक बैंक जनता के विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार के ऋण, अर्थात् मांग ऋण, अल्पावधि ऋण, नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, विनिमय बिलों में छूट आदि प्रदान करते हैं। बैंक प्राथमिक जमाओं से ऋण बनाते हैं। नेट बैंकिंग के अंतर्गत सभी बैंकिंग लेनदेन होते हैं

इंटरनेट पर आयोजित किया गया। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक है। यह है सभी वित्तीय संस्थानों का शीर्ष बैंक। भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है किसी देश में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करना। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एकाधिकार शक्ति है हमारे देश में करेंसी नोट जारी करें। भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गदर्शन प्रदान करता है राष्ट्रीय उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए वाणिज्यिक बैंक और उनकी निगरानी करना।

13.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. ओवरड्राफ्ट के क्या फायदे हैं?

2. क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की कैसे मदद करते हैं?

3. भारतीय रिजर्व बैंक के उद्देश्य क्या हैं?

4. आप समाशोधन गृह के बारे में क्या जानते हैं?

5. भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रचारात्मक कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जमाराशियाँ लिखिए?

2. वाणिज्यिक बैंकों के एजेंसी कार्य क्या हैं?

3. कैश क्रेडिट और ओवर ड्राफ्ट के बीच अंतर बताएं।

4. नेट बैंकिंग के फायदे बताएं।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों की व्याख्या करें।

2. भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें।

13.9. शब्दकोष

बैंकिंग: बैंकिंग एक व्यावसायिक गतिविधि है जहाँ से धन जमा किया जाता है
जनता को और बदले में व्यापारियों जैसे जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान किया जाता है,
किसान, उद्योगपति आदि

जमा: जमा से तात्पर्य उस धन से है जो लोग बैंकों में रखते हैं।

आवर्ती जमा: सावधि जमा खातों का एक प्रकार आवर्ती जमा खाता है।
एक व्यक्ति एक नियमित अवधि के लिए समान समय अंतराल पर भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, ए
व्यक्ति परिपक्वता अवधि के रूप में पांच वर्ष की अवधि चुन सकता है और एक निश्चित राशि कमा सकता है
पांच साल तक हर महीने पैसा. इन जमाओं पर ब्याज की उच्च दर होती है।

चेक: चेक एक कागज है जो बैंक को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है
व्यक्ति का खाता उस व्यक्ति को जिसके नाम पर चेक बनाया गया है।

ओवर ड्राफ्ट: चयनित ग्राहकों को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं। बैंक अनुमति देता है
ऐसे ग्राहकों को अपने खाते से और अपनी जमा राशि से अधिक राशि निकालनी होगी। हालांकि
ग्राहकों को अधिक निकाली गई राशि पर ब्याज देना होगा।

13.10. संदर्भ

इंटरमीडिएट तेलुगु अकादमी पाठ्य पुस्तक।

बीए मैक्रो इकोनॉमिक्स.

अध्याय

14

मुद्रास्फीति और व्यापार चक्र

14.0 उद्देश्य

14.1 परिचय

14.2 मुद्रास्फीति की परिभाषाएँ

14.3 मुद्रास्फीति के प्रकार

14.4 मुद्रास्फीति के कारण

14.5 मुद्रास्फीति के प्रभाव

14.6 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

14.7 व्यापार चक्र

14.8 व्यापार चक्र की विशेषताएं

14.9 व्यापार चक्र के चरण

14.10 सारांश

14.11 मॉडल परीक्षा प्रश्न

14.12 शब्दावली

14.13 सन्दर्भ

14.0. उद्देश्य

मुद्रास्फीति और उसके प्रकारों को परिभाषित करें

मुद्रास्फीति के कारणों को पहचानें

मुद्रास्फीति के प्रभावों को समझाइये

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाएं

मूल्य स्थिरीकरण की आवश्यकता को समझें

व्यापार चक्र के चरणों को समझें

व्यापार चक्रों के प्रभाव का विश्लेषण करें

14.1. परिचय

अर्थशास्त्र में, मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि है एक समयावधि में एक अर्थव्यवस्था।

उदाहरण: एक सीज़न में किसी वस्तु की कीमत बढ़ती रहती है, हालाँकि मात्रा बनी रहती है जो उसी।

तालिका नंबर एक

का नाम माल	6 महीने की अवधि में कीमत में बदलाव					
	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
पेट्रोल (प्रति 1 लीटर)	90	95	98	100	102	105

वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप आम लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है आदमी कम हो जाता है. यह लोगों के आर्थिक जीवन और कल्याण को कई तरह से प्रभावित करता है।

मुद्रास्फीति को रोकने के लिए वस्तुओं की कीमतों को लंबे समय तक स्थिर रखा जाना चाहिए

किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास को सशक्त बनाना।

उच्च मुद्रास्फीति कई देशों के आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है

पहलू। इसलिए, मुद्रास्फीति के निर्धारकों की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है।

मुद्रास्फीति मूल्य तंत्र को बाधित करती है, निवेश और बचत को हतोत्साहित करती है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है

निश्चित आय समूह और ऋणदाता अंततः नैतिकता के पतन की ओर ले जाते हैं।

14.2 मुद्रास्फीति की परिभाषाएँ

"मुद्रास्फीति" शब्द का तात्पर्य एक निश्चित अवधि में सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि से है।

पिगौ के अनुसार 'मुद्रास्फीति तब होती है जब धन की आय अधिक बढ़ रही हो

कमाई गतिविधि में वृद्धि के अनुपात में"।

सैमुएलसन के अनुसार, 'मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि को दर्शाती है।'

14.3 मुद्रास्फीति के प्रकार

मुद्रास्फीति के मूल्य के आधार पर प्रकार:

1. रेंगती मुद्रास्फीति: जब कीमत में वृद्धि बहुत धीमी और छोटी होती है, तो इसे रेंगती मुद्रास्फीति कहा जाता है

मुद्रा स्फ़ीति। यह प्रति वर्ष 3% से अधिक नहीं है.

2. चलती मुद्रास्फीति: यह मुद्रास्फीति का दूसरा चरण है। जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है

3% से 10% प्रति वर्ष के बीच को वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है।

3. चालू मुद्रास्फीति: जब मूल्य स्तर में वृद्धि प्रति वर्ष 10% से 20% के बीच होती है

चालू मुद्रास्फीति कहलाती है. यह अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है.

4. सरपट मुद्रास्फीति: यदि मुद्रास्फीति दर प्रति वर्ष 20% से अधिक हो तो इसे सरपट मुद्रास्फीति कहा जाता है

मुद्रा स्फ़ीति। ये बेहद खतरनाक है.

5. अति मुद्रास्फीति: यह तब होता है जब कीमतें दो या तीन अंकों की दर से बहुत तेजी से बढ़ती हैं। डब्ल्यूपीआई

(संपूर्ण बिक्री मूल्य सूचकांक) का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है।

मांग प्रेरित मुद्रास्फीति और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति

डिमांड पुल मुद्रास्फीति का तात्पर्य कुल मांग में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति से है कुल आपूर्ति से अधिक वस्तुओं के लिए, यह मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति है। मूल्य - बढ़ोत्तरी मुद्रास्फ़ीति उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण।

14.4 मुद्रास्फीति के कारण

मुद्रास्फीति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

सरकार के योजनागत और गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि।

सरकार द्वारा घाटे का वित्तपोषण।

लंबी अवधि की विकास परियोजनाओं में भारी निवेश।

अनुत्पादक आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की उदार उपलब्धता।

जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर.

प्रत्यक्ष करों में कमी, अर्थव्यवस्था की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि।

14.5 मुद्रास्फीति के प्रभाव

a) उत्पादन पर: मुद्रास्फीति का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है उत्पादन। यह मुद्रास्फीति के प्रकार पर निर्भर करता है।

हल्की मुद्रास्फीति उद्यमियों के लाभ मार्जिन को बढ़ाती है। अत: इससे उत्पादन बढ़ता है।

उच्च या अति मुद्रास्फीति उत्पादन में बाधा डालती है।

ख) वितरण पर:

महंगाई का असर सभी वर्ग के लोगों पर एक समान नहीं पड़ता है. इसका लोगों के कुछ वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

मुद्रास्फीति के दौरान ऋणदाताओं को नुकसान होता है। समूह के रूप में देनदारों को लाभ होगा।

उत्पादकों को लाभ होता है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों की बिक्री से अधिक कीमत मिलती है। लेकिन मुद्रास्फीति के दौरान उनकी क्रय शक्ति कम होने से श्रमिकों को नुकसान होता है।

ऋणदाता, कर्मचारी, पेंशनभोगी, उपभोक्ता और सरकार अत्यधिक घाटे में हैं मुद्रा स्फ़ीति। देनदार, निवेशक, व्यापारी और कृषक लाभान्वित होते हैं मुद्रा स्फ़ीति।

14.6 मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय

मौद्रिक उपाय: किसी देश का केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति की जाँच कर सकता है
धन और ऋण की आपूर्ति को सीमित करना।

राजकोषीय उपाय: राजकोषीय उपायों का तात्पर्य कराधान, सरकारी व्यय आदि से है
सार्वजनिक उधार. ताकि महंगाई को कम किया जा सके.

प्रत्यक्ष उपाय: इनमें मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग शामिल है
माल।

14.7 व्यापार चक्र

समग्र आर्थिक गतिविधि में उतार-चढ़ाव जो एक अर्थव्यवस्था एक अवधि के दौरान अनुभव करती है समय, यानी, आर्थिक गिरावट की अवधि के साथ बारी-बारी से समृद्धि की अवधि को कहा जाता है "व्यापार चक्र"। व्यापार चक्र आर्थिक गतिविधि के चक्र हैं जो एक के पीछे एक घूमते हैं अन्य, वृद्धि और गिरावट के साथ। व्यापार चक्र की अवधि आमतौर पर 5 से 8 वर्ष तक होती है। वे विस्तार और संकुचन के चरणों में चक्रीय होते हैं और बार-बार और काफी हद तक पुनरावृत्ति करते हैं समान पैटर्न. अच्छे व्यापार में, व्यापार चक्र में बढ़ती कीमतें और कम बेरोजगारी शामिल होती है स्तर. इसके विपरीत, व्यापार में, एक व्यापार चक्र में गिरती कीमतें और उच्च बेरोजगारी शामिल होती है स्तर. व्यापार चक्र उत्पादन, रोजगार और मूल्य स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव हैं इसके साथ ही। इनके अलावा मजदूरी की दरें, ब्याज दरें, कर, निर्यात, आयात, बचत, बैंक जमा और धन हस्तांतरण की गति सभी बदल जाती है।

14.8 व्यापार चक्र की विशेषताएं

ए) व्यापार चक्र समय-समय पर होते हैं, हालांकि वे समान नियमितता प्रदर्शित नहीं करते हैं।

बी) इन चक्रों की अवधि अलग-अलग होती है।

ग) व्यापार चक्र में विस्तार, शिखर, संकुचन और गर्त के अलग-अलग चरण होते हैं।

घ) व्यापार चक्र आम तौर पर मुक्त बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं।

ई) वे व्यापक भी हैं। एक या अधिक क्षेत्रों में गड़बड़ी आसानी से हो जाती है
अन्य सभी क्षेत्रों में प्रेषित।

च) कृषि क्षेत्र की तुलना में, औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिकूलता की संभावना अधिक है

व्यापार चक्रों का प्रभाव.

छ) व्यापार चक्रों के घटित होने से पहले उनकी सटीक भविष्यवाणी करना कठिन है।

ज) व्यापार चक्रों का समाज की भलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

14.9 व्यापार चक्र के चरण

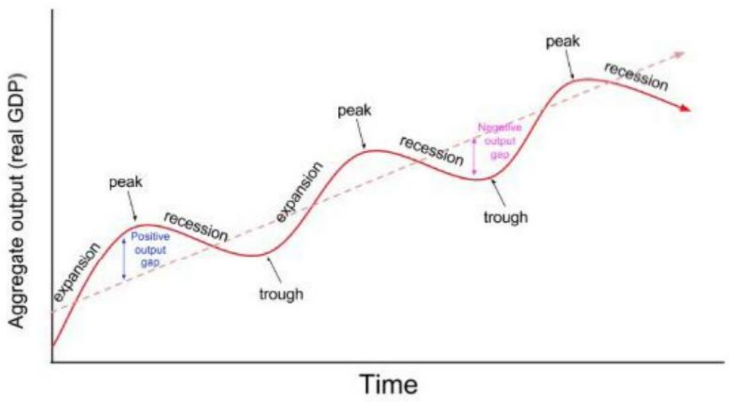

क) विस्तार: विस्तार चरण की विशेषता राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि है,

रोजगार, कुल मांग, पूंजी और उपभोक्ता व्यय, बिक्री, मुनाफा, बढ़ रहा है

स्टॉक की कीमतें और बैंक ऋण। इस चरण में, कीमतें और लागत भी तेजी से बढ़ती हैं। माँग

सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के लिए वृद्धि। कुल मिलाकर समृद्धि बढ़ रही है और

लोग उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते हैं।

कुछ समय बाद व्यावसायिक गतिविधि अंततः अपने चरम पर पहुँच जाती है।

बी) शिखर: शिखर शब्द व्यापार चक्र के शीर्ष या उच्चतम बिंदु को संदर्भित करता है। उत्पादन

कीमतें भी तेजी से बढ़ती हैं जिससे जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है और निश्चित आय पर अधिक दबाव पड़ता है

कमाने वाले. वास्तविक मांग स्थिर हो जाती है.

ग) संकुचन: अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती नहीं रह सकती। संकुचन के दौरान,

निवेश और रोजगार के स्तर में गिरावट आई है। उत्पादकों ने अपनी कीमतें कम कर दीं

उनकी सूची का निपटान करने और उनके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए। उपभोक्ताओं

उनकी खरीदारी स्थगित करें. निवेश घटने लगता है.

घ) अवसाद: अवसाद मंदी का गंभीर रूप है और इसकी विशेषता है

बेहद सुस्त आर्थिक गतिविधियां. व्यापार चक्र के इस चरण के दौरान, विकास

दर ऋणात्मक हो जाती है तथा राष्ट्रीय आय एवं व्यय के स्तर में तेजी से गिरावट आती है।

उत्पादों और सेवाओं की मांग घट जाती है, कीमतें न्यूनतम स्तर पर होती हैं और तेजी से गिरावट आती है।

ब्याज दरों में आएगी गिरावट. उद्योगों को अतिरिक्त क्षमता से नुकसान होता है। पर

मंदी की गहराई, सभी आर्थिक गतिविधियाँ निचले स्तर को छू रही हैं और गर्त का चरण है

पहुँच गया।

ई) रिकवरी: अर्थव्यवस्था लगातार सिकुड़ती नहीं रह सकती। यह निम्नतम तक पहुँच जाता है

आर्थिक गतिविधि का स्तर गर्त कहा जाता है और फिर ठीक होने लगता है। व्यापक बेरोजगारी

श्रमिकों को प्रचलित दरों से कम वेतन स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। निर्माता अनुमान लगा रहे हैं

कम लागत और बेहतर व्यावसायिक वातावरण।

व्यवसायिक आत्मविश्वास धीरे-धीरे बढ़ता है। तकनीकी प्रगति के लिए नयेपन की आवश्यकता है

नई प्रकार की मशीनों और पूंजीगत वस्तुओं में निवेश। बैंकिंग व्यवस्था अब धीरे-धीरे

व्यापारिक विश्वास के साथ मेल खाते हुए ऋण का विस्तार करना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे निवेश बढ़ता है, वहां

उत्पादन, रोजगार, साधन भुगतान, प्रयोज्य आय, उपभोक्ता में वृद्धि है

कुल मांग, अधिक वस्तुओं और सेवाओं को पूरा करने के लिए खर्च, कुल मांग आदि

उत्पादित है।

14.10 सारांश

दुनिया के कई देश आज महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं। महँगाई न केवल प्रभावित करती है

लोगों का आर्थिक जीवन और कल्याण लेकिन कुछ मामले स्थिरता को चुनौती देते हैं

सरकार। आधुनिक सरकारें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नीतिगत उपाय कर रही हैं

स्थितियाँ. मुद्रास्फीति की मध्यम दर वाली अर्थव्यवस्था वांछनीय है। कीमतों में कोई वृद्धि

उत्पादन में गुणात्मक परिवर्तन के कारण मुद्रास्फीति नहीं होती है। सामान्य तौर पर लगातार वृद्धि

अर्थव्यवस्था का मूल्य स्तर और मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए WPI (संपूर्ण बिक्री मूल्य सूचकांक) का उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति की मांग

यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं

कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होती है
लागत-प्रेरित मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। अपस्फीति मुद्रास्फीति के विपरीत है, जहां उपभोक्ता की कीमतें
माल घटता जाता है. राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन में वृद्धि या स्थिर वृद्धि होती है
रिफ्लेशन कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन वह स्थिति है जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों चलती हैं
अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी पर.

14.11 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. बढ़ती महंगाई
2. चलती महंगाई
3. दौड़ती/सरपट दौड़ती महंगाई
4. अति मुद्रास्फीति

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं?
2. मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं?
3. मुद्रास्फीति के मुख्य कारण क्या हैं?
4. मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है?
5. हम मुद्रास्फीति को कैसे रोक सकते हैं?
6. व्यापार चक्र की विशेषताएं क्या हैं?
7. अवसाद क्या है?
8. पुनर्प्राप्ति अगले चरण के विस्तार की ओर कैसे ले जाती है?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. व्यापार चक्र को परिभाषित करें। व्यापार चक्रों के चरणों को एक चित्र की सहायता से समझाइए।
2. लोगों के जीवनयापन की लागत पर मुद्रास्फीति के प्रभावों का विश्लेषण करें और सुझाव दें
   मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए पुनः उपाय।

14.12 शब्दावली

मुद्रास्फीति: बहुत कम वस्तुओं के पीछे बहुत अधिक पैसा।

लागत वृद्धि मुद्रास्फीति: यह उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण है।

स्टैगफ्लेशन: वह स्थिति जहां मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ती रहती हैं अर्थव्यवस्था में.

14.13 सन्दर्भ

वृहत आर्थिक विश्लेषण: एडवर्ड शापिरो

मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी: एमएल झिंगन

उन्नत आर्थिक सिद्धांत: एचएल आहूजा

अध्याय भा क विकास

15

15.0. उद्देश्य 15.1.
परिचय

15.2. भारत में आर्थिक विकास 15.3. विकसित/

विकासशील देशों के वर्गीकरण को समझना 15.3.1. विश्व बैंक रिपोर्ट-2019 के अनुसार वर्गीकरण 15.4.

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएँ 15.4.1. उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति

व्यक्ति आय (पीसीआई)

15.4.2. मानव विकास सूचकांक एचडीआई 15.4.3.

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों का महत्व 15.4.4. बेहतर जीवन स्तर 15.4.5.

तकनीकी उन्नति और आधुनिकीकरण 15.4.6.

जनसंख्या की कम वृद्धि 15.5. विकासशील देशों की विशेषताएँ 15.5.1. निम्न

प्रति व्यक्ति आय 15.5.2. उच्च जनसंख्या वृद्धि दर

15.5.3. पूंजी निर्माण का निम्न स्तर 15.5.4. बेरोजगारी का उच्च स्तर 15.5.5.

उत्पादकता का निम्न स्तर 15.5.6. अपर्याप्त

बुनियादी सुविधाएं 15.5.7. निरक्षरता 15.5.8.

जीवन स्तर का निम्न स्तर 15.5.9. द्वैतवादी अर्थव्यवस्था

15.6. सारांश 15.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न 15.8. शब्दकोष

15.9. संदर्भ

15.0. उद्देश्य

विकसित/विकासशील देशों की विशिष्ट विशेषताओं से परिचित होना।

उन कारकों का विश्लेषण करता है जो भारतीयों के अविकसितता और ठहराव का कारण बनते हैं

अर्थव्यवस्था

प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों का वर्गीकरण कीजिए

भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं को समझाइए

विकासशील देशों के पिछड़ेपन के कारणों की व्याख्या करें।

15.1. परिचय

यह अध्याय विकास की विशेषताओं और विशेषताओं का परिचय देने के लिए बनाया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं के साथ विकसित अर्थव्यवस्थाएँ। पहले में अध्यायों में हमने आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास का अध्ययन किया है। हम चर्चा करेंगे हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां भारत में ब्रिटिश सरकार किसके संरक्षण और संवर्धन को लेकर अधिक चिंतित थी उनके देश के आर्थिक हित। ऐसी नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाती हैं। भारत ब्रिटिश शासन से पहले भारत की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि कृषि ही मुख्य थी अधिकांश लोगों के लिए व्यवसाय, देश की अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ भिन्न थीं विनिर्माण गतिविधियों के प्रकार. भारत ने अपनी विकास दर में एक कदम ऊपर दर्ज किया है पिछले कुछ दशकों में अपने सुधार प्रयासों के माध्यम से।

15.2. भारत में आर्थिक विकास

ब्रिटिश शासन के तहत, भारत में कृषि क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ था अविकसित औद्योगिक क्षेत्र. 1950-51 में, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, और बड़े पैमाने पर निरक्षरता थी. मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊँची थीं। यह देय था गरीबी के कारण चिकित्सा सुविधाओं की कमी और पौष्टिक भोजन का निम्न स्तर। भारतीय आज़ादी के समय की अर्थव्यवस्था ख़राब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। का स्तर औद्योगिक गतिविधियाँ बहुत कम थीं और असमान औद्योगिक विकास हुआ था।
किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग, बीमा जैसे मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। परिवहन, संचार, बिजली, आदि।

के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में जबरदस्त बदलाव आया है पचास साल की योजना। राष्ट्रीय आय की संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन होता है आर्थिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम. हालाँकि, संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं धीमी गति से रखें. भारत में कुछ गहरे परिवर्तन हुए हैं, जो सुझाव है कि अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत मजबूत हैं। बचत की वर्तमान दर और निवेश उस स्तर पर पहुंच गया है जिसे दस साल पहले भी झूठ कहकर खारिज कर दिया जाता था भारत के लिए आशा. इस महत्वपूर्ण आयाम पर भारत अब पूरी तरह से विश्व का एक हिस्सा है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ। भारत को विभिन्न उत्पादों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखा जाता है। ये सब हैं भारत में योजना के कारण संभव हुआ। पहली आठ योजनाओं में विकास पर जोर दिया गया बुनियादी और भारी उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र, लेकिन लॉन्च के बाद से 1997 में नौवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर कम स्पष्ट हो गया और देश में योजना को लेकर जो मौजूदा सोच है, उसमें भारत एक बनकर उभरा है दसवीं योजना के अंत तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएँ।

भारत की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में शुरू की गई थी पीवी नरसिम्हा राव का नेतृत्व. नए आर्थिक सुधारों ने नई दिशा दी और भारतीय अर्थव्यवस्था का आयाम. इस नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिये पहली बार वैश्विक प्रदर्शन। इस नई आर्थिक नीति में पी.वी.नरसिम्हा राव की सरकार ने आयात शुल्क कम किया, निजी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित क्षेत्र खोला, और निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। इसे एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है विकास का. नई आर्थिक नीति का तात्पर्य आर्थिक उदारीकरण या छूट से है आयात शुल्क; बाजार विनियमन या निजी और विदेशी खिलाड़ियों के लिए बाजार खोलना; और देश की आर्थिक शाखाओं का विस्तार करने के लिए करों में कटौती की गई।

भारत के योजना आयोग ने आर्थिक पंचवर्षीय योजना का पर्यवेक्षण किया देश का विकास. हालाँकि, 2014 में, 65 वर्षीय योजना आयोग था भंग कर दिया गया और एक थिंक टैंक - नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) - उसकी जगह ले ली. यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। चूँकि यह एक के रूप में कार्य करता है सरकार के थिंक टैंक या एक दिशात्मक और नीति डायनेमो के रूप में, यह सलाह प्रदान करता है रणनीतिक नीति केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मायने रखती है। इसके अलावा, यह इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों महत्व के आर्थिक मुद्दे शामिल हैं।

15.3. विकसित/विकासशील देशों के वर्गीकरण को समझना

एक विकासशील देश को आम तौर पर कुछ हद तक उसके आर्थिक उत्पादन से परिभाषित किया जाता है। इस बात पर बहुत बहस हुई है कि विकसित और विकसित के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए विकासशील देश, जिसकी किसी भी परिभाषा को कोई सार्वभौमिक स्वीकृति नहीं है। इसलिए, वहाँ हैं कोई सामान्य स्वीकृत मानदंड नहीं है जो उन्हें वर्गीकृत करने के औचित्य की व्याख्या करता हो उनके विकास का स्तर.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) देशों का वर्गीकरण प्रणाली मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका उद्देश्य इसमें शामिल करना है विकास के अनेक कारकों पर विचार करें। विश्व बैंक का विश्व का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के अनुमान पर आधारित है। में विश्व बैंक द्वारा निकाली गई विश्व विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित मानदंड का उपयोग किया जाता है वर्गीकृत देशों में:

15.3.1 विश्व बैंक रिपोर्ट-2019 के अनुसार वर्गीकरण

मैं। उच्च आय समूह: प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) यूएस $12695 प्रति वर्ष और ऊपर। उदाहरण: यूएसए, यूके, फ्रांस, सिंगापुर आदि।

द्वितीय. उच्च मध्य आय समूह: प्रति व्यक्ति आय 4096 अमेरिकी डॉलर के बीच $12694. उदाहरण: अर्जेंटीना, क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका मालदीव आदि।

iii. निम्न मध्यम आय समूह: प्रति व्यक्ति आय यूएस $1046 और $4095 के बीच। उदाहरण: भारत, फिलीपींस, अंगोला, पाकिस्तान, भूटान आदि।

iv. निम्न आय समूह: प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर $1045 या उससे कम। उदाहरण: अफगानिस्तान, सूडान, नाइजर, युगांडा, इथियोपिया आदि।

विकसित देश वे अर्थव्यवस्थाएँ हैं जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में विकसित होती हैं और औद्योगीकरण. विकसित देशों को उन्नत देश भी कहा जाता है वे आत्मनिर्भर राष्ट्र हैं। विकासशील देश विकसित देशों पर निर्भर रहते हैं देश भर में उद्योग स्थापित करने में उनका समर्थन करें।

15.4. विकसित अर्थशास्त्र की विशेषताएँ

एक ऐसा देश जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन हो और उसके नागरिकों के लिए संसाधन उपलब्ध हों विकसित देश कहा जाता है. विकसित अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से बेहतर परिणाम दिखाती है और उस देश के गैर-आर्थिक कारक।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई)

औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों का महत्व।

जीवन स्तर का उच्च स्तर।

प्रौद्योगिकी उन्नति और आधुनिकीकरण

जनसंख्या की निम्न वृद्धि दर

द्वैतवादी अर्थव्यवस्था

15.4.1. उच्च सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई)

प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश की आर्थिक स्थिति का माप है आउटपुट जो इसके लोगों की संख्या के लिए जिम्मेदार है। यह देश की जीडीपी को उसकी जनसंख्या से विभाजित करता है। विकसित देशों की जीडीपी ऊंची है। जैसे-जैसे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है, उपलब्ध वस्तुएँ और सेवाएँ भी वृद्धि. इसलिए, उच्च उत्पादन उच्च घरेलू आय से जुड़ा है। प्रत्येक वर्ष, विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। इसका मतलब है कि लोग कमा रहे हैं पर्याप्त आय ताकि वे खर्च करने के साथ-साथ व्यवसाय में निवेश कर सकें या भविष्य के लिए बचत कर सकें। ये बचत या निवेश देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करते हैं। अक्सर विकसित देश होते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे व्यापक क्षेत्रों में सकारात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ है। अधिक शिक्षा सुविधाएँ, बुनियादी ढाँचा, आदि।

तालिका-1: क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर प्रति व्यक्ति जीएनआई (2020)

देश	यूएस$ में प्रति व्यक्ति जीएनआई क्रय शक्ति समता
यूएसए	70480
यूके	49420
स्विट्ज़रलैंड	75860
जर्मनी	59680
भारत	7270
चीन	19170

स्रोत: ttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD

15.4.2. मानव विकास सूचकांक - एचडीआई

मानव विकास सूचकांक शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर आधारित है प्रति व्यक्ति आय। एक विकसित देश में शिक्षा महत्वपूर्ण है। साक्षरता उच्च है, शिक्षा सुलभ है, और लोग कई वर्ष स्कूलों में बिताते हैं। अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच भी है प्रदान किया गया है, और शिशु मृत्यु दर कम है। जीडीपी प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है। ये सभी कारक मानव विकास सूचकांक निर्धारित करने में उपयोगी हैं। अत: इन देशों का भला है एचडीआई स्कोर. एचडीआई में विकसित देशों का स्कोर सबसे अधिक है, आमतौर पर 0.8 से ऊपर।

तालिका-2: एचडीआई स्कोर और वर्ष 2020 के अनुसार देशों की रैंकिंग

देश	एचडीआई मूल्य	पद
नॉर्वे	0.957	1
यूके	0.932	13
यूएसए	0.926	17
दक्षिण अफ्रीका	0.709	114
ब्राज़िल	0.765	84
भारत	0.645	131
पाकिस्तान	0.557	154

स्रोत: https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि विकसित देश उच्च स्कोर वाले हैं एचडीआई मूल्य और अच्छी रैंक। नॉर्वे 0.957 के साथ शीर्ष स्थान पर है, भारत विकासशील है देश 0.645 एचडी वैल्यू के साथ 131वें रैंक पर है।

15.4.3. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों का महत्व

विकसित देशों की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है। हम कर सकते हैं इन अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम है। महत्व है सेवा और औद्योगिक क्षेत्रों को उनकी आर्थिक वृद्धि के लिए दिया गया। विस्तार और इन क्षेत्रों के विकास से बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। इसलिए, लोगों की आय भी बढ़ गया.

उदाहरण के लिए, 2020 में फ्रांस को सकल घरेलू उत्पाद का 71.16% उद्योग से और 16.45% प्राप्त हुआ। सेवाओं से. केवल 1.6% हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। के मामले में रोजगार, कृषि क्षेत्र में 2.53 प्रतिशत, उद्योग में 20.43 और 77.04 प्रतिशत सेवा क्षेत्र दर्ज किया गया है।

भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 53.89% और उद्योग का योगदान 25.92% है। जबकि कृषि का हिस्सा 20.19% है. अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में रोजगार का हिस्सा भारत में सेवाएं इस प्रकार हैं: सेवाएँ 32.28%, उद्योग 25.12% और कृषि 42.6%। से उपरोक्त उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि विकसित राष्ट्र की आय एवं रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में यह बहुत कम है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकास की स्थिति प्राप्त करती है, सेवा यह क्षेत्र उत्पादन और रोजगार का प्रमुख हिस्सा बनेगा।

15.4.4. बेहतर जीवन स्तर

जीवन स्तर एक शब्द है जिसका उपयोग आय, आवश्यकताओं के स्तर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। विलासिता, और अन्य सामान और सेवाएँ जो आम तौर पर लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। विकसित देशों में जीवन स्तर ऊँचा होता है। आम तौर पर किसी देश का जीवन स्तर इसका तात्पर्य अपने लोगों के धन, आराम, भौतिक वस्तुओं और आवश्यकता से है। इन देशों अपने लोगों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करें। जीवन की अच्छी गुणवत्ता का गहरा संबंध है जीवन का एक मानक जो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है। लोगों की क्रय शक्ति अधिक है ये अर्थव्यवस्थाएँ.

उच्चतम जीवन स्तर वाले देश अपने अधिकांश लोगों को सभ्य जीवन प्रदान करते हैं नागरिक. इन देशों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा, मुफ्त शिक्षा और सुविधाएं हैं ऐसी सुविधाएँ विकसित की गईं जिनका उपयोग इसके सभी नागरिक कर सकते हैं।

15.4.5. तकनीकी उन्नति और आधुनिकीकरण

प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान जैसे तकनीकी कौशल का अनुप्रयोग है वस्तुओं और सेवाओं के पुनरुत्पादन जैसे व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए तरीके और प्रक्रिया।

विकसित देश हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग में आगे हैं। वे विनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, परिवहन आदि में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं नई तकनीक की मदद से उद्योगों में उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है जगह। तकनीकी प्रगति से प्राकृतिक का अधिकतम उपयोग करने की क्षमता में सुधार होता है संसाधन। ये देश अनुसंधान और विकास पर अधिक खर्च करने में सक्षम हैं तकनीकी उन्नति। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करके, जर्मनी और जापान का तेजी से विकास हुआ। द्वितीय में ये दोनों देश नष्ट हो गये

विश्व युध्द। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अन्य उन्नत औद्योगिक देशों के पास सब कुछ है उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से अपनी औद्योगिक ताकत हासिल की। वास्तव में, आर्थिक उत्पादन की नई तकनीकों को अपनाने से विकास को बढ़ावा मिलता है।

विकसित अर्थव्यवस्थाएं नवप्रवर्तन और भविष्योन्मुखी मूल्यवर्धित विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं उत्पाद. इन देशों में लोग उन्नत प्रौद्योगिकी की खोज में लगे हुए हैं विभिन्न क्षेत्र।

15.4.6. जनसंख्या की कम वृद्धि

विकसित देशों में एकल परिवार को प्रोत्साहन की अवधारणा निम्न स्तर की ओर ले जा रही है जनसंख्या की वृद्धि दर. विकसित अर्थव्यवस्थाएँ अपने संसाधनों को बहुत अच्छे से खर्च कर सकती हैं जनसंख्या के छोटे आकार के कारण. संसाधनों की कमी नहीं देखी जाती. अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च स्तर की शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया जनसंख्या की कम वृद्धि दर. इन देशों की प्रति व्यक्ति आय और समृद्धि उच्च है निम्न जनसंख्या वृद्धि दर और बचत या पूंजी निर्माण की उच्च दर के कारण हैं। जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण इन देशों में औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है।

15.5. विकासशील देशों की विशेषताएँ

15.5.1. प्रति व्यक्ति आय कम:

कम प्रति व्यक्ति वास्तविक आय विकास की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है अर्थव्यवस्थाएँ। औसत आय वाले व्यक्ति के पास निवेश या बचत करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। वे पूरी अर्जित राशि उपभोग पर खर्च करें। इसलिए, वे बचत या निवेश नहीं करते हैं। इस प्रकार, यह गरीबी का एक चक्र बनाता है। पूर्ण गरीबी में लोगों का प्रतिशत (निम्न गरीबी वाले लोग)। विकासशील देशों में आय) अधिक है।

भारत में 2017-18 के अनुसार जीडीपी 115224 रुपये और प्रति व्यक्ति आय 87586 रुपये है। वही 2018-19 में 134186 रुपये और 94566 रुपये है। जब विकसित अर्थव्यवस्था से तुलना की जाती है ये मूल्य बहुत कम हैं.

15.5.2. उच्च जनसंख्या वृद्धि दर

अधिकांश विकासशील देशों में, जनसंख्या अलग-अलग दरों पर बढ़ रही है 2% और 4% प्रति वर्ष। बढ़ती चिकित्सा सुविधाओं के कारण अचानक गिरावट आई है

मृत्यु दर में, लेकिन जन्म दर में कोई गिरावट नहीं हुई है। इतना
जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है. अधिक जनसंख्या का मतलब है कम जीएनपी प्रति व्यक्ति आय, अधिक
गरीबी, बेरोजगारी, इत्यादि का स्तर।

स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक थी। 1951 से 1981 तक,
भारत की जनसंख्या 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 1981 में 683 मिलियन हो गई,
वार्षिक वृद्धि दर 2.14%। 1981 से 2011 तक यह विकास दर घटकर 1.8% रह गई। यहां तक की
हालाँकि जनसंख्या की वृद्धि दर कम है, फिर भी अधिक जनसंख्या के साथ, भारत अभी भी एक है
विकासशील देश।

15.5.3. पूंजी निर्माण का निम्न स्तर

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, आय के निम्न स्तर और उपभोग की उच्च दर के कारण,
पूंजी निर्माण या बचत का स्तर कम है। इन देशों को अक्सर "राजधानी-" कहा जाता है
गरीब" अर्थव्यवस्थाएँ। इन देशों में, न केवल पूंजी भंडार बड़े पैमाने पर छोटा है, बल्कि
पूंजी निर्माण की वर्तमान दर भी बहुत कम है। जब पूंजी निर्माण कम होता है, तो होता है
उद्योगों और सेवाओं के विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं। यह स्थिति निम्न स्तर की ओर ले जाती है
उत्पादन और रोजगार. इसलिए, यह एक दुष्चक्र है।

आरबीआई 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, सकल घरेलू बचत जीडीएस दर 29.4% है और सकल
मौजूदा कीमतों पर घरेलू निवेश जीडीआई दर 32.5% है। इसकी तुलना में यह बहुत कम है
विकसित अर्थव्यवस्थाएँ।

15.5.4. बेरोजगारी का उच्च स्तर

विकासशील देशों में बेरोज़गारी की समस्याएँ अधिक और आम हैं। दोनों शहरी
और ग्रामीण क्षेत्र बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि के कारण यदि
नए उद्योग या सेवाएँ स्थापित नहीं होती हैं तो वह स्थिति बढ़ती है
बेरोजगारी. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ती है, इसलिए
इनमें से अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जहां बहुत अधिक नहीं हैं
उनके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

भारत में शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के साथ बेरोजगारी फैल रही है।
औद्योगिक क्षेत्र श्रम शक्ति की वृद्धि के साथ-साथ विस्तार करने में विफल रहा है। में
भारत में बेरोजगारी संरचनात्मक है और पूंजी की कमी का परिणाम है।

15.5.5. उत्पादकता का निम्न स्तर

प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर, प्रचुर श्रम शक्ति, बुनियादी ढांचे की कमी, और आदिम विनिर्माण विधियाँ विकास में उत्पादन के निम्न स्तर में योगदान करती हैं देशों. शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश की कमी के कारण अभी भी पुराने तरीके ही चल रहे हैं विनिर्माण में अपनाया गया। इसके परिणामस्वरूप कम उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ।

भारत में बाजार का छोटा आकार, पूंजी की कमी, ढांचागत सुविधाओं की कमी और तकनीकी पिछड़ापन उत्पादकता के निम्न स्तर के कारक हैं।

15.5.6. अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं

बुनियादी ढांचे में भवन, सड़कें, पुल, परिवहन सुविधाएं, बिजली आपूर्ति शामिल हैं। दूरसंचार आदि ये सुविधाएँ उद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं और सेवाएँ। विकासशील देशों में ये सभी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।

भारत में पूंजी की कमी और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार होता है सुविधाएँ।

15.5.7. निरक्षरता

विकासशील देशों में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। अशिक्षा कई सामाजिक कारणों का कारण बनती है और आर्थिक समस्याएँ। प्रौद्योगिकी और गैर-तकनीकी कौशल हासिल करने के लिए, न्यूनतम शिक्षा का स्तर आवश्यक है. शिक्षा एचडीआई की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है।

आजादी के बाद से भारत में निरक्षरता दर में गिरावट आई है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 74% है। भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण की खराब गुणवत्ता देखी जाती है भारत में। भारत में उच्च बेरोजगारी दर पर साक्षरता का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिकांश अशिक्षा के कारण बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

15.5.8. जीवन स्तर का निम्न स्तर

विकासशील देशों में जीवन स्तर निम्न है। जीवन का यह निम्न स्तर गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से कम आय, खराब चिकित्सा सुविधाओं, सीमित शिक्षा सुविधाओं और अपर्याप्त आवास सुविधाओं और कई अन्य मामलों में, अवसाद और निराशा के सामान्य भय के रूप में प्रकट होता है।

भारत में, ग्रामीण और शहरी जीवन स्तर के बीच बहुत अधिक अंतर है। तक में शहरी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों का तेजी से बढ़ना निम्न जीवन स्तर का संकेत देता है।

15.5.9. द्वैतवादी अर्थव्यवस्था

द्वैतवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उन्नत और आधुनिक क्षेत्रों के एक साथ अस्तित्व से है पारंपरिक और पिछड़े क्षेत्र। आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का सह-अस्तित्व शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन का लक्ष्य है। धनवान का सह-अस्तित्व, उच्च बड़ी संख्या में निरक्षरों और बहुत उच्च जीवन स्तर के सह-अस्तित्व के साथ शिक्षित और बहुत ही निम्न जीवन स्तर के साथ।

भारतीय अर्थव्यवस्था को द्वैतवादी विशेषता वाला माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल है दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं - अविकसित और प्रगतिशील भी। एक बहुत अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो अविकसित हैं और निम्न वर्ग के हैं पिछड़े वर्ग। इसमें अर्थव्यवस्था के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था में लोगों का बहुत छोटा हिस्सा समृद्ध और विकसित है। इसमें शहरी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अपनाने के लिए तैयार है जबकि दूसरा हिस्सा अभी बहुत पीछे है पीछे।

15.6. सारांश

विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। भारत एक विकासशील देश है. भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थिर एवं आश्रित अर्थव्यवस्था थी अपनी स्वतंत्रता के समय. प्रति व्यक्ति आय कम थी। विदेशी व्यापार को प्रेरित किया गया इंग्लैण्ड के उद्योगों की आवश्यकताएँ पूरी करना। लोगों की निर्भरता बहुत अधिक थी कृषि और कई बेरोजगार थे। साक्षरता दर कम थी, जन्म दर अधिक थी दर और उच्च मृत्यु दर, स्वास्थ्य मानक काफी कम थे और महामारी लगातार फैल रही थी। नियोजित अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति वास्तव में प्रभावशाली थी। हमारा स्वतंत्रता की स्थिति की तुलना में उद्योग कहीं अधिक विविध हो गए हैं।

15.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. मानव विकास सूचकांक (HDI) के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं?
2. विकसित देशों की विशेषताएँ सूचीबद्ध करें।

3. उच्च आय समूह वाले देशों को परिभाषित करें।

4. द्वैतवादी अर्थव्यवस्था क्या है?

5. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?

6. भारत में उत्पादकता के निम्न स्तर के क्या कारण हैं?

7. 'पूंजीगत गरीब' अर्थव्यवस्थाओं की व्याख्या करें।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र के महत्व की व्याख्या करें।

2. उन्नत तकनीकी उन्नति और आधुनिकीकरण पर संक्षिप्त नोट्स लिखें
देशों.

3. भारत में जनसंख्या वृद्धि को समझाइये।

4. नीति आयोग को समझाइये।

5. बेरोजगारी की समस्या को समझाइये।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की व्याख्या करें

2. जीएनआई प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों के वर्गीकरण की व्याख्या करें।

3. विकसित देशों की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें।

15.8. शब्दकोष

1. पीसीआई: प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) या कुल आय, अर्जित औसत आय को मापती है एक निर्दिष्ट वर्ष में किसी दिए गए क्षेत्र (शहर, क्षेत्र, देश, आदि) में व्यक्ति। इसकी गणना द्वारा की जाती है क्षेत्र की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करना।

2. मानव विकास सूचकांक: मानव विकास सूचकांक (HDI) एक सारांश है मानव विकास के प्रमुख आयामों में औसत उपलब्धि का माप: एक लंबा और स्वस्थ जीवन, जानकार होना और जीवन स्तर का सभ्य होना।

3. जीवन स्तर: जीवन स्तर एक शब्द है जिसका उपयोग आय के स्तर का वर्णन करने के लिए किया जाता है, आवश्यकताएँ, विलासिता, और अन्य वस्तुएँ और सेवाएँ जो आम तौर पर आसानी से उपलब्ध होती हैं निर्दिष्ट जनसंख्या.

4. पूंजी निर्माण: पूंजी निर्माण पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध संचय है, जैसे एक लेखांकन अवधि के दौरान उपकरण, उपकरण, परिवहन संपत्ति और बिजली खास देश।

5. बेरोजगारी: उस व्यक्ति की स्थिति जो काम करने में सक्षम है, सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहा है, लेकिन कोई काम नहीं मिल पा रहा है.

6. बुनियादी ढाँचा: किसी देश, शहर या क्षेत्र की सेवा करने वाली मूलभूत सुविधाएँ और प्रणालियाँ, जैसे परिवहन और संचार प्रणाली, बिजली संयंत्र, और स्कूल आदि।

7. निरक्षरता: निरक्षरता पढ़ने या लिखने में असमर्थ होने का गुण या स्थिति है।

15.9. संदर्भ

1. इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र के लिए पाठ्यपुस्तक। टीएसबीआईई तेलंगाना।

2. सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, दसवीं कक्षा। टीओएसएस

3. सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, दसवीं कक्षा। एससीईआरटी तेलंगाना

4. एनसीईआरटी कक्षा 11, 12 अर्थशास्त्र

5. ब्रौ, बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र

6. इग्नू बीए अर्थशास्त्र

7. एनआईओएस अर्थशास्त्र

8. https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks

9. स्रोत: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD

10. सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण। भारत की।

अध्याय

16

जनसांख्यिकी

16.0. उद्देश्य

16.1. परिचय

16.2. भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताएं

16.2.1. भारत में जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर

16.2.2. जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दर

16.2.3. लिंगानुपात

16.2.4. आयु संरचना

16.3. जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा एवं कारण

16.3.1. भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा

16.3.2. भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण

16.3.3. भारत में जनसंख्या विस्फोट के उपाय

16.4. भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक और क्षेत्रीय वितरण

16.4.1. व्यावसायिक संरचना

16.4.2. भारत में कामकाजी जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

16.4.3. क्षेत्रवार रोजगार एवं उत्पादन प्रभाग

16.5. भारत में जनसंख्या नीति

16.5.1 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति-2000 के उद्देश्य

16.6. सारांश

16.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

16.8. शब्दकोष

16.9. संदर्भ

16.0. उद्देश्य

जनसांख्यिकी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें,

भविष्य की भलाई के लिए वर्तमान जनसंख्या प्रवृत्तियों के परिणामों को समझें,

भारत की जनसंख्या का आकार और पिछले कुछ दशकों में इसकी वृद्धि की व्याख्या करें,

जन्म और मृत्यु दर के आंकड़ों की तुलना करें,

'जनसंख्या विस्फोट', कारण, उपाय बताएं

भारत में जनसंख्या के व्यावसायिक और क्षेत्रीय वितरण का वर्णन करता है

भारत की जनसंख्या नीति बताएं और

जन्म नियंत्रण में परिवार नियोजन का महत्व बताएं।

16.1. परिचय

जनसांख्यिकी दो ग्रीक शब्दों 'डेमोस' (लोग) और 'ग्राफी' से मिलकर बना है। (अध्ययन) का अर्थ है, लोगों का वर्णन। जनसांख्यिकी जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन है। इसमें जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण आदि में परिवर्तन का अध्ययन शामिल है। यह जांच करता है प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर के परिणामस्वरूप जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण में परिवर्तन और प्रवासन. सभी जनसांख्यिकीय अध्ययन गणना की प्रक्रिया पर आधारित हैं जिसे जनगणना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रहने वाले लोगों के बाद डेटा का व्यवस्थित संग्रह शामिल है एक देश में। नीतियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए जनसांख्यिकीय डेटा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लोगों का आर्थिक विकास और कल्याण। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे भारत की जनसंख्या की वृद्धि का पैटर्न, संरचना विशेषताएँ और वितरण।

16.2. भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताएं

16.2.1. भारत में जनसंख्या का आकार और वृद्धि दर

जनसंख्या का आकार और वृद्धि जनसांख्यिकीय के दो महत्वपूर्ण घटक हैं एक विकासशील देश में घटनाएँ. वे विशेषताएँ जो आकार में परिवर्तन निर्धारित करती हैं किसी भी देश की जनसंख्या का जन्म, मृत्यु और प्रवास होता है। जनसंख्या का अर्थ है संख्या किसी विशेष समय पर उस देश या विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की। गिनती करने के लिए जनसंख्या के आधार पर भारत में प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिए 'जनगणना' आयोजित की जाती है।

कुल जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है

2011 की जनगणना के अनुसार चीन के बाद 1210 मिलियन। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के पास है

विश्व के कुल भूमि क्षेत्र का 2.4% और जनसंख्या का 17.7% हिस्सा। के अनुसार

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार नवंबर में विश्व की कुल जनसंख्या 7874 मिलियन है

2021. 11 जुलाई को 'विश्व जनसंख्या दिवस' माना जाता है क्योंकि इसी दिन उनकी आखिरी संतान हुई थी

5 वें अरब का जन्म 1987 में हुआ।

तालिका-1: 1901 से भारत में जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	कुल जनसंख्या (लाखों में)	वार्षिक औसत विकास दर (%)	दशकीय वृद्धि दर (%)
1901	238	-	-
1911	252	0.56	5.8
1921	251	-0.03	-0.3
1931	279	1.04	11.0
1941	319	1.33	14.2
1951	361	1.25	13.3
1961	439	1.96	21.6
1971	548	2.22	24.8
1981	683	2.20	24.7
1991	846	2.14	23.9
2001	1028	1.95	21.5
2011	1210	1.63	17.7

जैसा कि तालिका-1 से देखा जा सकता है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर धीमी थी

1881 और 1921 के बीच जनसंख्या में 15 मिलियन की वृद्धि हुई। उच्च मृत्यु दर

और इस चरण में जन्म दर देखी गई। इस काल में अकाल एवं महामारी फैली

उच्च मृत्यु दर का मुख्य कारण. वर्ष 1921 को भारत में विभाजनकारी वर्ष माना जाता है

जनसांख्यिकी क्योंकि इस वर्ष तक जनसंख्या की वृद्धि स्थिर नहीं थी।

हम 1921-1951 की अवधि के दौरान जनसंख्या में लगातार वृद्धि देख सकते हैं। एक

इस अवधि में जनसंख्या में 110 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। दशकीय विकास दर

1951 में 13.3% थी। मृत्यु दर में गिरावट की दर गिरावट की दर से अधिक रही है

जन्म दर में. 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट का मुख्य कारण बढ़ा हुआ स्तर था

अकाल और महामारी रोगों पर नियंत्रण।

1951-1981 की अवधि के दौरान भारत ने 'जनसंख्या विस्फोट' का अनुभव किया। आबादी इन 30 वर्षों की अवधि के दौरान 322 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई है। दशक का 24.7% जनसंख्या वृद्धि दर 1981 में देखी गई। इस अवधि के दौरान बहुत बड़ा अंतर था आर्थिक विकास गतिविधियों में तेजी के कारण जन्म दर और मृत्यु दर के बीच, लोगों की चिकित्सा और जीवन स्थितियों में और सुधार।

1981 से 2011 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या 683 मिलियन से बढ़कर 1210 हो गई दस लाख। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान दशकीय वृद्धि दर 17.7% दर्ज की गई। आर्थिक विकास, परिवार नियोजन में समुचित सुधार धीमी वृद्धि के लिए जिम्मेदार था इन 30 वर्षों के दौरान जनसंख्या की दर.

16.2.2. जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दर

किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर निर्भर करती है इसकी जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन। भारत में, पलायन बहुत कम है. इसलिए, यह एक नहीं है जनसंख्या निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक विकास

जैसा कि ऊपर अध्ययन किया गया है जनसंख्या वृद्धि दर थी 1921 तक उच्च मृत्यु दर के कारण उच्च नहीं था उच्च जन्म दर. जैसा कि हम दी गई तालिका-2 में देखते हैं, a के कारण उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई इन्फ्लूएंजा और अन्य संक्रमण। अकेले 1918 में 15 इन्फ्लूएंजा से लाखों लोग मरे। इसके दौरान अवधि जन्म दर 46 से 49 प्रति के बीच थी हजार, और मृत्यु दर 44 से 49 के बीच थी। अत: जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत कम थी।

तालिका-2 भारत में जन्म और मृत्यु दर

दशक	जन्म (प्रति 1000)	मृत्यु (प्रति 1000)
1891-1900	45.8	44.4
1901-1911	48.1	42.6
1911-1920	49.2	48.6
1921-1930	46.4	36.3
1931-1940	45.2	31.6
1941-1950	39.9	27.4
1951-1960	40.0	18.0
1961-1970	41.2	19.2
1971-1980	37.2	15.0
1981-1990	29.5	9.3
1991-2000	25.4	8.4
2001-2011	21.8	7.1

यदि हम तालिका-2 का विश्लेषण करें, तो 1911-20 के दौरान दर्ज की गई मौतों का प्रतिशत 48.6 प्रति हजार से घटकर 2010-11 में 7.1 हो गया। हम 1920 के बाद मृत्यु दर में तेजी से गिरावट देख सकते हैं, इसका कारण सूखे के प्रभाव में कमी और विभिन्न संक्रमणों पर नियंत्रण है।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता भी मृत्यु दर में गिरावट के लिए जिम्मेदार थी। दूसरी ओर 1911 के दौरान जन्म दर 49.2 प्रति 1000 थी-

20. 2001-11 में यह वृद्धि दर घटकर 21.8 प्रति हजार रह गई।

2001-11 के दौरान, जन्म और मृत्यु दर दोनों में अलग-अलग बहुत भिन्नताएं थीं भारत के राज्य. केरल, तमिलनाडु, तत्कालीन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पंजाब में जन्म दर में कम वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में जन्म दर बहुत अधिक है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए जन्म दर में गिरावट, विवाह, संयुक्त परिवार, परिवार नियोजन के प्रति लोगों का रुझान परिवर्तन करना होगा।

शिशु मृत्यु दर (आईएमआर): यह जनसंख्या वृद्धि दर को भी प्रभावित करती है। शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) प्रति 1000 पर एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या है जीवित जन्म। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में शिशु मृत्यु दर 218 थी और इसमें गिरावट आई 2010-11 तक घटकर 47 रह गया। जिससे शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, पोषण योजनाओं का कार्यान्वयन इत्यादि पर। किसी देश का आर्थिक विकास शिशु मृत्यु दर पर निर्भर करता है। एक ऊंचा शिशु मृत्यु दर के परिणामस्वरूप देश की कार्यशील जनसंख्या में गिरावट आ रही है।

16.2.3 लिंगानुपात

मुख्य संकेतक जो किसी देश की जनसंख्या की मानव गुणवत्ता निर्धारित करता है संसाधन लिंगानुपात है। इस लिंगानुपात को प्रति हजार महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है नर. हमारे देश में महिलाओं के लिए यह अनुपात सदैव नकारात्मक रहा है और धीरे-धीरे घटता जा रहा है। यह एक परेशान करने वाली विशेषता है. लिंगानुपात एक प्रमुख संकेतक है जो पुरुषों की समानता को मापता है और महिलाएं. 1901 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर 972 महिलाएँ थीं। यह संख्या 1951 में 946 से घटकर 2001 में 933 हो गई और 2011 में बढ़कर 940 हो गई।

हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात में भिन्नता है। लिंगानुपात में केरल 1084 और पुडुचेरी 1038 बेहतर स्थिति में हैं। हरियाणा और पंजाब 877 पर हैं और क्रमशः 893. साक्षरता दर का निम्न स्तर, गरीबी और सामाजिक रवैया जिम्मेदार हैं लिंग भेदभाव के लिए. लिंगानुपात नकारात्मक होने से महिलाओं के प्रति भेदभाव शुरू हो जाता है जन्म से। लड़के की चाहत के कारण कन्या शिशु मृत्यु दर अधिक है। कन्या संतान हैं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने में कम महत्वपूर्ण है। की भ्रूण हत्या कन्या शिशु अभी भी प्रचलन में है। कई परिवार लड़कियों को बोझ समझते हैं। इसलिए साक्षरता महिला बच्चों में भी दर कम है। अगर लैंगिक भेदभाव जारी रहा तो मुश्किल हो जाएगी आर्थिक विकास हासिल करने के लिए. समाज में बच्चियों के प्रति भेदभाव निश्चित रूप से बदलाव की जरूरत है.

16.2.4. आयु संरचना

जनसंख्या की आयु संरचना विभिन्न आयु के लोगों का वितरण है। यह है एक स्वास्थ्य सुविधाएं, कल्याणकारी योजनाएं और रोजगार सृजन प्रदान करने के लिए उपयोगी उपकरण (कार्यबल)।जनसंख्या की कार्यशील आयु 15-60 आयु समूह वर्ष, 0-14 मानी जाती है। वर्ष आयु समूह को बाल जनसंख्या, 60 वर्ष और उससे अधिक को वृद्ध आयु समूह माना जाता है।

15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या 1971 में 42% से घटकर 2011 में 31% हो गई है। 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में कमी से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की जा रही है उचित रूप से कार्यान्वित किया गया। इसी अवधि के दौरान 15-60 वर्ष की आयु वर्ग में वृद्धि हुई है 53% से 63.7%। इस समूह में वृद्धि से कामकाजी आबादी में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक आर्थिक विकास की ओर ले जाता है। आर्थिक विकास दर में वृद्धि के कारण वृद्धि जनसंख्या में कामकाजी उम्र के लोगों की हिस्सेदारी को जनसांख्यिकीय लाभांश कहा जाता है, जिस पर यह निर्भर करता है स्वास्थ्य देखभाल के स्तर में सुधार के साथ-साथ मानव संसाधन में वृद्धि पर। उन्नति के कारण चिकित्सा सुविधाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और पोषण में जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है भारत में।

16.3. जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा एवं कारण

16.3.1. भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा

माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या एक ज्यामितीय दर से बढ़ती है 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि, और खाद्य फसल उत्पादन अंकगणित दर यानी 1, 2, 3, 4 से बढ़ता है। आदि। अनियंत्रित होने पर जनसंख्या ज्यामितीय माध्य में बढ़ती है। जनसंख्या, यदि अनियंत्रित हो, हर 25 साल में दोगुना हो जाएगा. अत: जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण ही एकमात्र उपाय है दरिद्रता दूर करने का उपाय. मृत्यु दर और संख्या में पर्याप्त शिक्षा के कारण जन्म दर में इसी गिरावट के कारण जनसंख्या में वृद्धि होगी। भारत को इसका अनुभव हुआ 1951 और 1991 के बीच की स्थिति। यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई गई तो स्थिति गंभीर हो सकती है भोजन की कमी, गरीबी, बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, गिरावट जैसी समस्याएं पर्यावरण, पानी की कमी, जीवन यापन की उच्च लागत आदि।

16.3.2. भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण

भारत में जनसंख्या विस्फोट के तीन मुख्य कारण हैं। वे हैं: 1) निम्न मृत्यु दर 2) उच्च जन्म दर और 3) प्रवासन। प्रवासन का प्रभाव न्यूनतम है; हमें करने दो अब भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारणों का विश्लेषण करें।

I. कम मृत्यु दर के कारण

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: उन्नत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कारण प्लेग, हैजा, मलेरिया, चेचक, खसरा, टी.बी. आदि महामारियों में सुविधाएँ हैं नियंत्रित या समाप्त कर दिया गया है। अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है. यह है मृत्यु दर में कमी आई।

2. सूखा नियंत्रण: ब्रिटिश शासन के बाद भारत में फसल पैटर्न में बदलाव बढ़ा फसल सिंचाई सुविधाएँ, सूखे की स्थिति में प्रभावी कमी से मृत्यु दर में कमी आई। खाद्य फसलों के अधिशेष उत्पादन से भोजन की कमी दूर हो गई। इस मृत्यु दर के कारण कम हो चुका है।

3. अन्य: शिक्षा, गरीबी उन्मूलन योजनाओं का कार्यान्वयन, तेजी से शहरीकरण, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार आदि से मृत्यु दर में काफी कमी आई है।

द्वितीय. उच्च जन्म दर के कारण

ए) अर्थशास्त्र कारक

1. कृषि पर निर्भरता: कृषि के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है जनसंख्या नियंत्रण के बारे में मत सोचो. भारत में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता भी देखी जाती है। किसान परिवार में बच्चों को आर्थिक बोझ के रूप में नहीं देखा जाता है। इसलिए किसान परिवार संयुक्त परिवार के रूप में बड़े थे।

2. शहरीकरण: सुस्त औद्योगिकीकरण के कारण शहरीकरण तेजी से नहीं हुआ। व्यवसायों में बड़े बदलावों की कमी के कारण जन्म दर ऊँची थी।

3. गरीबी: गरीबी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। गरीब लोग बड़े को पसंद करते हैं परिवार. गरीब लोग अपने बच्चों को बोझ नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन मानते थे। इस तरह वृद्धि अधिक है.

बी) सामाजिक कारक

1. शीघ्र एवं सार्वभौमिक विवाह: भारत में विवाह एक सामाजिक बाध्यता है। ऐसा ही नहीं है सार्वभौमिक लेकिन कम उम्र में होता है। लगभग 80 प्रतिशत लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। 15 से 20 वर्ष की आयु की उपजाऊ अवधि। इस कारण जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक है।

2. संयुक्त परिवार प्रणाली: भारत मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। सामाजिक संरचना है संयुक्त परिवार प्रणाली का बोलबाला है। एक अतिरिक्त बच्चे के जन्म का कोई तत्काल कारण नहीं है माता-पिता को कष्ट. यह कारक भी उच्च जन्म दर के लिए उत्तरदायी है। वर्तमान में संयुक्त परिवार प्रथा तेजी से लुप्त हो रही है।

3. धार्मिक कारण: धर्म, अंधविश्वास और पिछड़ापन जैसे कारक भी उच्च जन्म दर में योगदान करें।

4. सामाजिक जागरूकता की कमी: परिवार नियोजन विधियों का अनुपालन न करना जनसंख्या वृद्धि दर को धीमा करना। परिवार नियोजन अभियान सफल नहीं हो पा रहा है धर्म और रीति-रिवाजों के कारण.

5. लड़के को प्राथमिकता: कई माता-पिता तब तक परिवार नियोजन स्वीकार नहीं करते जब तक उनके पास लड़का न हो पुत्र अथवा इच्छित संख्या में पुत्र। अतः जन्म दर अधिक है।

16.3.3. भारत में जनसंख्या विस्फोट के उपाय

तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर ने भारत के नागरिकों के लिए बड़ी कठिनाइयाँ पैदा कीं अर्थव्यवस्था। इससे रोज़गार की समस्याएँ पैदा हुईं, जीवन स्तर और शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ा स्तर. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रभावी संयोजन अपनाना है सामाजिक और आर्थिक उपाय.

ए) सामाजिक उपाय

1. शिक्षा का प्रसार: साक्षरता मानव व्यवहार को बदल देती है। यह बेहतर बनाता है जीवन की समझ. इसलिए शिक्षित युवक-युवतियां अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं परिवार और अंधविश्वास छोड़ें और छोटा परिवार या कम बच्चे रखें। की उम्र शिक्षा और रोजगार के कारण विवाह टल सकता है। इसके माध्यम से नियंत्रण जनसंख्या वृद्धि इसी देखी।

2. विवाह की न्यूनतम आयु: प्रजनन क्षमता विवाह की आयु पर निर्भर करती है। न्यूनतम विवाह की उम्र को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। भारत में विवाह के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है पुरुषों के लिए 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष की आयु कानून द्वारा निर्धारित की गई है और वर्तमान सरकार ने भी तय की है महिलाओं के लिए न्यूनतम कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। उच्च विवाह की उम्र जितनी अधिक होगी, प्रजनन दर उतनी ही कम होगी और जनसंख्या नियंत्रण होगा।

3. महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना: महिलाओं के प्रति आज भी भेदभाव होता है। वे हैं
अक्सर रसोई तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए महिलाओं को सामाजिक रूप से विकसित होने के अवसर दिए जाने चाहिए
और आर्थिक रूप से. उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए।

बी) आर्थिक उपाय

1. कृषि एवं उद्योग का विकास : यदि कृषि एवं उद्योग का समुचित विकास हो
विकास होगा, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा. जब उनकी आय बढ़ जाती है
वे अपना जीवन स्तर सुधारेंगे। इसलिए वे सुरक्षित रहने के लिए कम बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। यह
अधिक जनसंख्या की वृद्धि को कम करेगा।

2. अधिक रोजगार के अवसर और शहरीकरण: औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सकता है
शहरीकरण और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना। शहरीकरण और रोजगार सृजन के कारण, लोग
वे आर्थिक रूप से समझदार और छोटे परिवार वाले होते हैं। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है।

3. गरीबी उन्मूलन: गरीबी में रहने वाले लोग अपने बच्चों को एक आर्थिक संसाधन मानते हैं।
अतः यदि गरीबी दूर हो जाये तो कुछ हद तक जनसंख्या नियंत्रण पाया जा सकता है।

सी. परिवार नियोजन

भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया
1952 में. परिवार कल्याण कार्यक्रम ने जिम्मेदार और नियोजित को बढ़ावा देने की मांग की है
स्वैच्छिक आधार पर पितृत्व। इस पद्धति का तात्पर्य पसंद से परिवार से है न कि संयोग से।
निवारक उपाय अपनाकर लोग जन्म दर को नियंत्रित कर सकते हैं। इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है
बड़े पैमाने पर; इस विधि की सफलता सस्ते गर्भनिरोधक उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर करती है
जन्म नियंत्रण के लिए.

16.4. भारत में जनसंख्या का व्यावसायिक और क्षेत्रीय वितरण

16.4.1. व्यावसायिक संरचना

आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या का प्रतिशत एक महत्वपूर्ण सूचकांक है
विकास। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या का वितरण
व्यावसायिक संरचना के रूप में जाना जाता है। व्यवसायों की विशाल विविधता पाई जाती है
किसी भी देश में। व्यवसायों को आम तौर पर प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मैं)
प्राथमिक गतिविधियाँ: कृषि, पशुपालन, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन आदि शामिल हैं
उत्खनन आदि। ii) माध्यमिक गतिविधियाँ: विनिर्माण उद्योग, भवन निर्माण और शामिल हैं
निर्माण कार्य आदि और iii) तृतीयक गतिविधियाँ: इसमें परिवहन, संचार,
वाणिज्य, प्रशासन और अन्य सेवाएँ।

16.4.2. भारत में कामकाजी जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

अलग-अलग गतिविधियों में काम करने वाले लोगों का अनुपात विकसित और अलग-अलग होता है विकासशील देश। विकसित देशों में माध्यमिक स्तर के लोगों का अनुपात अधिक है और तृतीयक गतिविधियाँ। विकासशील देशों में काम का अनुपात अधिक होता है प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न बल.

2011 की जनगणना के अनुसार, 1210 मिलियन की आबादी में से 400 मिलियन हैं कामकाजी लोग यानी वे लोग जो उत्पादक गतिविधियों में शामिल हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि नहीं भारतीय रोजगार क्षेत्र में बहुत कुछ बदल गया है। कृषि आज भी मुख्य रोजगार है क्षेत्र। अधिक से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम करना जारी रख रहे हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र में उत्पादन में कमी आ रही है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में अधिक रोजगार पैदा करना।

हालाँकि देश की लगभग आधी श्रम शक्ति कृषि में है, फिर भी इसमें बहुत कुछ है सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छोटा हिस्सा। कृषि क्षेत्र में लगभग 50% कार्यबल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 19% है। में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में काफी गिरावट आई है. लेकिन कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का प्रतिशत है ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है. इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या अधिक है जरूरत है। कुछ लोगों को खेती से हटाने से खेती पर कोई असर नहीं पड़ेगा उत्पादन। इसे 'प्रच्छन्न बेरोजगारी' कहा जाता है और स्वाभाविक रूप से हम इस स्थिति को देखते हैं ग्रामीण कृषक परिवार. पूरा परिवार अपने छोटे से खेत पर निर्भर है। अगर अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें, इतने लोगों की जरूरत नहीं है कृषि में काम करें.

16.4.3. क्षेत्रवार रोजगार एवं उत्पादन प्रभाग

तालिका-3: सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी।

अर्थव्यवस्था का क्षेत्र	रोजगार में हिस्सेदारी प्रतिशत में		जीडीपी में हिस्सेदारी को PERCENTAGE	
	1951	2015	1951	2015
प्राइमरी सेक्टर	72	47	59	19
द्वितीयक क्षेत्र	11	22	13	28
तृतीय श्रेणी का उद्योग	17	31	28	53

यदि हम दी गई तालिका-3 का विश्लेषण करें, तो भारत में क्षेत्रवार रोजगार हिस्सेदारी 47% थी 2015 में कृषि में 22%, उद्योग में 22% और सेवा क्षेत्र में 31% इसी प्रकार देखें तो तीन क्षेत्रों में जीडीपी, कृषि की हिस्सेदारी 19%, उद्योग की हिस्सेदारी 28% और सेवाओं का हिस्सा 53% था। प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार में हिस्सा कम हो गया 1950 में 72% से 2015 तक 47%, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई इस अवधि के दौरान क्रमशः 11 से 22% और 17 से 31% तक। जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ी प्राथमिक क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा 1951 में 59% से घटकर 1915 तक 19% हो गया, जबकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के प्रतिशत शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई यह कालखंड। टेबल तीन; रोजगार क्षेत्र और के बीच अंतर को स्पष्ट रूप से दिखाएं निर्माण क्षेत्र। कृषि क्षेत्र से उत्पादन, जिसमें 47% रोजगार है, आउटपुट का केवल 19% हिस्सा है, जबकि सेवा क्षेत्र, जो 31% रोजगार देता है कुल उत्पादन का 53%। इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र में बड़ी श्रम शक्ति है और औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

16.5. भारत में जनसंख्या नीति

जनसंख्या वृद्धि एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है किसी राष्ट्र की संभावनाओं के साथ-साथ उसके लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण की भी। यह विशेष रूप से है यह सच है कि विकासशील देशों को इस संबंध में विशेष चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है यदि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ती रही, तो भारत जल्द ही कई सामाजिक समस्याओं का सामना करेगा। आर्थिक समस्यायें। बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी. हवा की हर सांस बुरी तरह प्रदूषित हो जाएगा और पानी की हर बूंद जहरीले पदार्थ से दूषित हो जाएगी। लोगों को जीवन की बुनियादी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराना लगभग असंभव हो जाएगा।

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत के पास आधिकारिक जनसंख्या नीति है आधी सदी से भी ज्यादा. वास्तव में, भारत संभवतः स्पष्ट रूप से घोषणा करने वाला पहला देश था 1952 में ऐसी नीति। 1952 के बाद, मृत्यु दर में तीव्र गिरावट नहीं आई। जन्म दर में समान गिरावट के साथ। पहली बार, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1976 में की गई थी। इस दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को झटका लगा राष्ट्रीय आपातकाल के वर्ष (1975-76)। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आपातकाल के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। दिशानिर्देश वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के भाग के रूप में तैयार किए गए थे।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 (एनपीपी 2000) किसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है लाभ उठाते समय सरकार स्वैच्छिक और सूचित विकल्प और नागरिकों की सहमति की ओर प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और लक्ष्य मुक्त दृष्टिकोण को जारी रखना परिवार नियोजन सेवाओं का प्रशासन करना। एनपीपी 2000 एक नीतिगत ढांचा प्रदान करता है प्रजनन को पूरा करने के लिए अगले दशक के दौरान लक्ष्यों को आगे बढ़ाना और रणनीतियों को प्राथमिकता देना और भारत के लोगों की बाल स्वास्थ्य आवश्यकताओं, और शुद्ध प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने के लिए कुल 2010 तक प्रजनन दर (टीएफआर)। यह मुद्दों को एक साथ संबोधित करने की आवश्यकता पर आधारित है आउटरीच और कवरेज को बढ़ाते हुए, बाल अस्तित्व, मातृ स्वास्थ्य और गर्भनिरोधक सरकार द्वारा प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक पैकेज, उद्योग और स्वैच्छिक गैर-सरकारी क्षेत्र, साझेदारी में काम कर रहे हैं।

16.5.1. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य

1. 14 वर्ष की आयु तक स्कूली शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना और स्कूल छोड़ने की संख्या को कम करना लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय का स्तर 20 प्रतिशत से नीचे।
2. शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 30 से कम करना।
3. मातृ मृत्यु दर को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 100 से कम करना।
4. रोकथाम योग्य सभी टीकों के विरुद्ध बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करना रोग।
5. लड़कियों के लिए विलंबित विवाह को बढ़ावा देना, 18 वर्ष से पहले नहीं और अधिमानतः उसके बाद 20 साल की उम्र.
6. प्रजनन क्षमता के लिए सूचना/परामर्श और सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना विकल्पों की एक विस्तृत टोकरी के साथ विनियमन और गर्भनिरोधक।
7. 80 प्रतिशत संस्थागत प्रसव तथा 100 प्रतिशत प्रसव प्रशिक्षित द्वारा कराना व्यक्ति.
8. दो बच्चों वाले छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
9. एड्स के प्रसार को रोकना, बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना प्रजनन पथ संक्रमण (आरटीआई) और यौन संचारित संक्रमण का प्रबंधन (एसटीआई) और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ)।
10. इसका लक्ष्य वर्ष 2045 तक स्थिर जनसंख्या तक पहुंचना है।

16.6. सारांश

जनसांख्यिकी, जनसंख्या का एक व्यवस्थित अध्ययन, जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र किया जाता है आर्थिक विकास के लिए, राज्य की नीतियों की योजना और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है और लोक कल्याण. भारत बहुमत के साथ दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है भारतीय युवा होते हैं। यह देश की आर्थिक वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भविष्य के वर्ष. युवाओं के लिए 'जनसंख्या विस्फोट' को समझना बहुत जरूरी है पीढ़ी। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य है कारक। रोजगार का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है भारत में विकास. हमारे प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए जन्म नियंत्रण बहुत आवश्यक है। उचित परिवार नियोजन का कार्यान्वयन अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।

16.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. जनसांख्यिकी क्या है?
2. जनसंख्या विस्फोट को समझाइये।
3. जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है?
4. शिशु मृत्यु दर को समझाइये।
5. माल्थस जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या करें
6. परिवार नियोजन क्या है?
7. भारत में व्यवसाय संरचना की व्याख्या करें।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. "लिंगानुपात" क्या है? भारत में यह इतना प्रतिकूल क्यों है?
2. भारत में जनसंख्या विस्फोट के उपाय बताइये।
3. भारत में कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की व्याख्या करें।
4. भारत में मृत्यु दर में गिरावट के क्या कारण हैं?
5. भारत में जनसंख्या की आयु संरचना बताएं।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. भारतीय जनसंख्या की जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताएं।
2. भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का परीक्षण करें।

3. भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं?

4. पिछले दशक में भारत में जन्म और मृत्यु दर में बदलाव का विश्लेषण करें।

5. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के उद्देश्य क्या हैं?

16.8. शब्दकोष

1. जन्म दर: किसी दिए गए क्षेत्र में एक निश्चित समय के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों की संख्या
   जनसंख्या।

2. मृत्यु दर: किसी दिए गए क्षेत्र में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक निश्चित समय के दौरान होने वाली मौतों की संख्या।

3. प्रजनन दर: बच्चे पैदा करने वाली आयु वर्ग में प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्म की संख्या
   15-49 वर्ष की.

4. शिशु मृत्यु दर: प्रति वर्ष एक वर्ष की आयु से पहले शिशुओं की मृत्यु की संख्या
   1000 जीवित जन्म.

5. मातृ मृत्यु दर: प्रति 1000 जीवित जन्म पर प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या।

6. लिंगानुपात: एक निश्चित समय में किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या
   अवधि।

7. जनसंख्या की आयु संरचना - विभिन्न आयु समूहों में व्यक्तियों का अनुपात सापेक्ष
   कुल जनसंख्या के लिए.

8. निर्भरता अनुपात: कामकाजी आयु समूह (अर्थात 15 - 64 वर्ष) के साथ आश्रितों (बुजुर्ग और बच्चे) का अनुपात

9. जीवन प्रत्याशा: यह उस वर्ष की अनुमानित संख्या को संदर्भित करता है जब एक औसत व्यक्ति के जीवित रहने की उम्मीद होती है।

16.9. संदर्भ

1. इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र के लिए पाठ्यपुस्तक। टीएसबीआईई, तेलंगाना।

2. सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, दसवीं कक्षा। टीओएसएस

3. सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक, दसवीं कक्षा। एससीईआरटी तेलंगाना

4. एनसीईआरटी कक्षा 11, 12 अर्थशास्त्र

6. https://nhm.gov.in/New_Updates_2018/Report_Population_Projection।

7. ब्रौ, बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र

8. इग्नू बीए अर्थशास्त्र

अध्याय 17 मानव संसाधन विकास

17.0. उद्देश्य

17.1. परिचय

17.2. मानव पूंजी और मानव विकास

17.3. मानव संसाधन विकास की अवधारणा

17.4. मानव संसाधन विकास का महत्व

17.5. किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका

17.5.1. भारत में शिक्षा और मानव विकास

17.5.2. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल और नीतियां मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना

17.5.3. भारत में स्वास्थ्य और मानव विकास

17.5.4. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएँ और नीतियाँ

17.6. मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

17.6.1. एचडीआई के घटक

17.6.2. एचडीआई का निर्माण

17.6.3. एचडीआई और देशों का वर्गीकरण

17.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

17.8. शब्दकोष

17.9. संदर्भ

17.0. उद्देश्य

- मानव विकास की अवधारणा को समझें
- मानव पूंजी और मानव विकास की अवधारणाओं को स्पष्ट करें
- भारत में मानव विकास में शिक्षा के महत्व का वर्णन करें
- भारत में मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका का विश्लेषण करें
- मानव विकास और आर्थिक विकास के महत्व को समझें
- मानव विकास सूचकांक की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें
- गणना और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर चर्चा करें
  देश।

17.1. परिचय

देश का आर्थिक विकास एक जटिल एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है। यह है विभिन्न कारकों जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या का आकार, पूंजी से प्रभावित सूत्रीकरण, मानव संसाधन, सामाजिक वातावरण, विदेशी व्यापार आदि मानव संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले कारकों में से एक हैं। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आर्थिक विकास में भूमिका. एक बड़ी चिंता लोगों को संपत्ति मानने को लेकर है संसाधनों का मतलब यह है कि उनका वस्तुकरण, वस्तुकरण और दुरुपयोग किया जाएगा। मनुष्य नहीं हैं "वस्तुएँ" या "संसाधन", लेकिन उत्पादक उद्यम में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी हैं।

अर्थशास्त्री अक्सर जनसंख्या को विकास में बाधक के रूप में देखते हैं न कि विकास में बाधा डालने वाले कारक के रूप में विकासात्मक गतिविधि में सहायता करें. हालाँकि, मनुष्य उत्पादन के लिए श्रम शक्ति प्रदान करता है और यदि किसी देश में श्रमिक कुशल, मूल्यवान और कुशल है, तो उसकी विकास में योगदान करने की क्षमता है निश्चित रूप से उच्च होगा.

17.2. मानव पूंजी और मानव विकास

सामान्य तौर पर, मानव संसाधन का वर्णन करने के लिए मानव पूंजी और मानव विकास का उपयोग किया जाता है लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है. मानव पूंजी एक अपेक्षाकृत संकीर्ण अवधारणा है

जो कौशल, शिक्षा, ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और दक्षताओं को संदर्भित करता है
मनुष्य एक कंपनी में लाता है, जबकि एक अर्थव्यवस्था में मानव विकास अपेक्षाकृत होता है
व्यापक अवधारणा जो एक समग्र आँकड़े द्वारा निर्धारित होती है जिसमें जीवन प्रत्याशा शामिल होती है,
शिक्षा, और प्रति व्यक्ति आय।

भारत ने आर्थिक विकास में मानव पूंजी के महत्व को बहुत पहले ही पहचान लिया था। सातवां
पंचवर्षीय योजना कहती है, "मानव संसाधन विकास (मानव पूंजी पढ़ें) आवश्यक है
किसी भी विकास रणनीति में, विशेष रूप से विशाल देश में, एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जानी चाहिए
जनसंख्या। सुदृढ़ आधार पर प्रशिक्षित और शिक्षित होकर, एक बड़ी आबादी स्वयं एक बन सकती है
आर्थिक विकास को गति देने और वांछित दिशाओं में सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करने में संपत्ति।"

17.3. मानव संसाधन विकास (एचआरडी) की अवधारणा

यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 1995 के अनुसार, मानव विकास इस प्रकार लोगों की पसंद को व्यापक बनाने के साथ-साथ प्राप्त कल्याण के स्तर को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। यह प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से संगठन विकास और कर्मियों के प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से मानव विशेषज्ञता को विकसित करने और उजागर करने की एक प्रक्रिया है।

यह भौतिक स्थितियों की भिन्नता द्वारा विशेषता वाली प्रक्रिया है। ये स्थितियाँ आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक, जैविक और सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं का भी पता लगाते हैं और उनका एहसास करते हैं। मानव विकास का दृष्टिकोण मानव जीवन की समृद्धि का विस्तार करने के बारे में है, न कि केवल उस अर्थव्यवस्था की समृद्धि जिसमें मनुष्य रहते हैं। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो लोगों और उनके अवसरों और विकल्पों पर केंद्रित है।

महबुब-उल-हक के अनुसार, "आर्थिक विकास और मानव विकास स्कूलों के बीच परिभाषित अंतर यह है कि पहला विशेष रूप से केवल एक विकल्प-आय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि दूसरा सभी मानव विकल्पों के विस्तार को अपनाता है।"

- चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो।"

17.4. मानव संसाधन विकास का महत्व

मानव विकास ग्रहण करने के बजाय लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है
कि आर्थिक विकास स्वचालित रूप से सभी के लिए अधिक खुशहाली की ओर ले जाएगा। आय वृद्धि

इसे अपने आप में साध्य के बजाय विकास के एक साधन के रूप में देखा जाता है। मानव विकास के बारे में है

लोगों को वह जीवन जीने की अधिक स्वतंत्रता देना, जिसे वे महत्व देते हैं। वस्तुतः इसका अर्थ लोगों का विकास करना है

योग्यताएं और उन्हें उनका उपयोग करने का मौका देना। उदाहरण के लिए, एक लड़की को शिक्षित करने से विकास होगा

उसके कौशल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है अगर उसे नौकरियों तक पहुंच से वंचित कर दिया जाए, या उसके पास अधिकार नहीं है

स्थानीय श्रम बाज़ार के लिए कौशल.

मानव विकास ही साध्य है जबकि आर्थिक विकास इस साध्य का एक साधन मात्र है।

विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का इलाज करना है

और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ, अंत के रूप में, मानव स्थिति में सुधार करने के लिए, विस्तार करने के लिए

लोगों की पसंद. एक सुपोषित, स्वस्थ, शिक्षित, कुशल, सजग श्रम शक्ति है

सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक संपत्ति. इस प्रकार, पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में निवेश

उत्पादकता के आधार पर उचित हैं। मानव विकास नागरिक को कम करने में मदद करता है

किसी समाज में गड़बड़ी और राजनीतिक सामाजिक स्थिरता में वृद्धि।

17.5. किसी राष्ट्र के विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की भूमिका

के विकास में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भूमिका एक महत्वपूर्ण इनपुट मानी जाती है

व्यक्ति के विकास के लिए राष्ट्र जितना महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास

इसका अर्थ है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि; स्वाभाविक रूप से, का योगदान

शिक्षित व्यक्ति की आर्थिक उन्नति अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। यदि कोई स्वस्थ है

व्यक्ति लम्बे समय तक निर्बाध श्रम आपूर्ति प्रदान कर सके, तभी स्वास्थ्य है

आर्थिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक। भारत जैसे विकासशील देश में,

जनसंख्या का एक बड़ा भाग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, जिसे बहुत से लोग वहन नहीं कर सकते

बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंचें। इसके अलावा, भारत का एक बड़ा वर्ग

जनसंख्या सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य देखभाल और उच्च शिक्षा तक पहुंचने का जोखिम नहीं उठा सकती।

इसके अलावा, जब बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को नागरिकों का अधिकार माना जाता है,

तो यह आवश्यक है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क प्रदान करे

योग्य नागरिकों और सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के लोगों के लिए लागत।

17.5.1. भारत में शिक्षा और मानव विकास

किसी देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा में निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यह अधिक उत्पादक बनाने में मदद करता है श्रम शक्ति और उसे बढ़े हुए ज्ञान और कौशल से संपन्न करना और व्यापकता प्रदान करना शिक्षकों, स्कूल और निर्माण के लिए रोजगार और आय अर्जित करने के अवसर श्रमिक, पाठ्यपुस्तक और कागज प्रिंटर, स्कूल वर्दी निर्माता आदि। यह बुनियादी प्रदान करता है कौशल और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में आधुनिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा इसे एक महान समतावादी उपाय के रूप में देखा जाता है जो मानव संसाधनों को बेहतर बनाने में मदद करेगा सामान्य तौर पर एक ओर और दूसरी ओर कम विशेषाधिकार प्राप्त और गरीबों को सक्षम बनाया जाएगा लोगों के वर्ग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए।

शिक्षा लोगों के सोचने के तरीकों को आधुनिक बनाने और क्रांतिकारी बदलाव लाने में मदद करती है। यह उन्हें अपने जीवन स्तर में सुधार करने की आवश्यकता के बारे में प्रबुद्ध करता है और इस उद्देश्य के लिए उनके परिवारों के आकार को सीमित करें। और इसलिए, यह परिवार की सर्वोत्तम विधि के रूप में कार्य करता है लंबी अवधि में योजना बनाना. अधिकांश विकासशील देशों ने अलग-अलग लॉन्च किए हैं सार्वभौमिक शिक्षा के कार्यक्रम इस आशा में कि वे मानवीय क्षमताओं में सुधार करेंगे गरीब लोगों की मदद करना और उन्हें अपने परिवार की कमाई बढ़ाने में सक्षम बनाना।

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की औसत साक्षरता दर 18.33% के मुकाबले 73.04% है। 1951. पुरुषों में साक्षरता दर 82.14% और महिलाओं में 65.46% है। केरल के पास था 93.91% की उच्चतम साक्षरता दर और उसके बाद लक्षद्वीप (92.28 प्रतिशत) है। और मिजोरम (91.58 प्रतिशत)। 63.82 प्रतिशत साक्षरता दर के साथ बिहार सूची में अंतिम स्थान पर है। देश से पहले अरुणाचल प्रदेश (66.95 प्रतिशत) और राजस्थान (67.06 प्रतिशत) हैं।

17.5.2. द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल और नीतियां

मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार

1. भारत सरकार के कोठारी आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें समान शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया राष्ट्रीय एकता और अधिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक उपलब्धि हासिल करने के अवसर विकास और 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को पूरा करना।

2. भारत सरकार ने 1986 में शिक्षा पर एक नई नीति पेश की। इसकी परिकल्पना की गई प्राथमिक शिक्षा और वयस्क शिक्षा का सार्वभौमिकरण। को उच्च प्राथमिकता दी थी शिक्षा में गुणात्मक सुधार. बाद में इस नीति को 1992 में संशोधित किया गया नीति में यह परिकल्पना की गई कि शिक्षा में एकरूपता लायी जाये, वयस्क शिक्षा बनायी जाये यह एक जन आंदोलन का कार्यक्रम है, जो सार्वभौमिक पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता प्रदान करता है प्रारंभिक शिक्षा आदि। बाद में, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय की घोषणा की है 29.07.2020 को शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) , यह पहली शिक्षा नीति है 21वीं सदी और इसका लक्ष्य हमारी बढ़ती विकासात्मक आवश्यकताओं को संबोधित करना है देश। यह नीति शिक्षा के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है संरचना, इसके विनियमन और शासन सहित, एक नई प्रणाली बनाने के लिए जो संरेखित हो 21वीं सदी की शिक्षा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ।

3. बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार-2009 अधिनियम पारित किया गया 4 अगस्त 2009 को संसद। इस अधिनियम के अनुसार, 6-14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा पूरा होने तक पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा प्रारंभिक शिक्षा आदि के

4. भारत सरकार ने भी कई योजनाएं और पहल शुरू कीं जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा योजनाएँ, अर्थात्, राष्ट्रीय मध्य कार्यक्रम- 1995 में स्कूलों में दिन का भोजन; 2001 में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए); कस्तूरबा गांधी 2004 में बालिका विद्यालय योजना; 2014 में पढ़े भारत-बढ़े भारत कार्यक्रम; बेटी 2015 में बचाओ, बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना, आदि।

17.5.3. भारत में स्वास्थ्य और मानव विकास

मानव पूंजी की गुणवत्ता सुधारने में स्वास्थ्य की भूमिका भी अधिक है और बढ़ती है श्रम उत्पादक क्षमता. एक स्वस्थ व्यक्ति अपना कार्य उचित एवं कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है रास्ता। एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति समाज में अधिक योगदान देता है व्यक्ति। श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार से राष्ट्रीय उत्पादन स्वतः ही बढ़ जाता है। इसलिए, स्वास्थ्य पर व्यय उत्पादक निर्माण और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण है श्रम शक्ति के साथ-साथ लोगों के जीवन और समाज की गुणवत्ता में सुधार लाने में भी।

भारत में सामान्य स्वास्थ्य मानक बहुत निम्न है। यह उच्च घटनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है देश में रुग्णता का. इसका मुख्य कारण पौष्टिक आहार की कमी, अपर्याप्तता है चिकित्सा देखभाल और अस्वच्छ परिस्थितियों में रहना। जिन लोगों को दो खाने भी नहीं मिलते एक दिन का भोजन संतुलित और पौष्टिक आहार का सपना नहीं देख सकता।

भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य मानक को ऊपर उठाने के लिए अपना कार्यक्रम तैयार किया। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल एवं चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम शुरू किये गये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों सहित गरीब लोगों की देखभाल सेवाएँ।

17.5.4. भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएँ और नीतियाँ

1. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की घोषणा 2003 में की गई थी सस्ती/विश्वसनीय उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने के उद्देश्य से तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाएँ भी बढ़ाना देश।

2. जननी सुरक्षा योजना (JSY) 12 अप्रैल 2005 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई थी क्षेत्र. इसे मातृ एवं नवजात शिशुओं की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मृत्यु दर को कम करना।

3. समान स्तर तक सार्वभौमिक पहुंच को सक्षम करने के लिए 2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। विशेष रूप से गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं जनसंख्या की।

4. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण: इसे भारत के प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना। मिशन के तहत सभी गांव, ग्राम पंचायत, जिले, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने खुद को "खुले में शौच मुक्त" (ओडीएफ) घोषित कर दिया है। 2 अक्टूबर 2019, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक, निर्माण करके ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालय।

5. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017: इसे 15 मार्च, 2017 को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह नीति अपने लक्ष्य के रूप में स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना करती है निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल अभिविन्यास के माध्यम से, सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण सभी विकासात्मक नीतियां, और बिना अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच परिणामस्वरूप किसी को भी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

6. आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन: इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधान मंत्री। इसमें 10 करोड़ से अधिक गरीबों को शामिल किया जाएगा कमजोर परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को 5 लाख तक कवरेज प्रदान करना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष रुपये। आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन चल रहे केंद्र प्रायोजित को समाहित कर देगा योजनाएं - राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस)।

17.6. मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)

मानव विकास सूचकांक (HDI) की अवधारणा को 1990 में किसके भाग के रूप में पेश किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) मापने का एक साधन प्रदान करेगा तीन व्यापक क्षेत्रों में आर्थिक विकास - प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य और शिक्षा। मानव विकास सूचकांक इसे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मुहाबुल-उल-हक द्वारा तैयार और लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारतीय थे 1990 में अर्थशास्त्री अमर्त्य कुमार सेन। एचडीआई विकास के स्तर में बदलाव को ट्रैक करता है समय के साथ देशों की. प्रत्येक वर्ष, यूएनडीपी एक विकास रिपोर्ट तैयार करता है, जो प्रदान करता है वर्ष के दौरान परिवर्तनों का अद्यतन, साथ ही वैश्विक जैसे किसी विशेष विषय पर एक रिपोर्ट वार्मिंग और विकास, और प्रवासन और विकास।

एचडीआई जीएनपी को प्रतिस्थापित नहीं करता है लेकिन इसकी वास्तविक स्थिति की समझ को काफी हद तक जोड़ता है समाज कई मायनों में. सूचकांक की शुरूआत इस बात की स्पष्ट स्वीकृति थी विकास वृद्धि की तुलना में काफी व्यापक अवधारणा है, और इसमें कई प्रकार शामिल होने चाहिए सामाजिक और आर्थिक कारक. एचडीआई की दो मुख्य विशेषताएं हैं: 0 से 1 तक का पैमाना (0 का मतलब है कोई विकास नहीं या सबसे खराब प्रदर्शन और 1 का मतलब है पूर्ण विकास या सर्वोत्तम प्रदर्शन)।

17.6.1. एचडीआई के घटक

मानव विकास सूचकांक, जो तीन समान रूप से भारित घटकों पर आधारित है

हैं

(ए) लंबे और स्वस्थ जीवन को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है;

(बी) शिक्षा को भारित औसत द्वारा मापा जाता है

i) वयस्क साक्षरता दर (इस मानदंड को 2/3 महत्व दिया गया है) और,

ii) स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (इस मानदंड को 1/3 महत्व दिया गया है) (सी) सभ्य जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी यूएस $ में) द्वारा मापा जाता है।

तालिका-1: मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए आयाम

DIMENSIONS	संकेतक	आयाम अनुक्रमणिका	न्यूनतम मूल्य	अधिकतम कीमत
लम्बा और स्वस्थ जीवन	जीवन प्रत्याशा जन्म	जीवन प्रत्याशा जन्म	20	85
ज्ञान	ए) अपेक्षित वर्ष स्कूली शिक्षा का b) माध्य वर्ष शिक्षा	शिक्षा सूचकांक	0 0	18 15
एक सभ्य का मानक जीविका	प्रति व्यक्ति जीएनआई (पीपीपी यूएस$)	जीएनआई सूचकांक	100 यूएस डॉलर	75,000 अमेरिकी डॉलर

स्रोत: यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020

नोट: पीपीपी का मतलब क्रय शक्ति समता है, यह विभिन्न देशों में कीमतों का माप है।

वे देश जो पूर्ण क्रय शक्ति की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करते हैं देशों की मुद्राओं का.

17.6.2. एचडीआई का निर्माण

एचडीआई मानव विकास का एक सारांश माप है, यह औसत उपलब्धियों को मापता है किसी देश में मानव विकास के तीन बुनियादी आयाम। तालिका 17.1 से पता चलता है स्वास्थ्य आयाम का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से किया जाता है; शिक्षा का आयाम है 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों के औसत और अपेक्षित के आधार पर मापा जाता है स्कूल में प्रवेश करने की आयु वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष। जीवन स्तर का आयाम है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा मापा जाता है।

पहला कदम प्रत्येक आयाम के लिए उप-सूचकांक बनाना है। न्यूनतम और अधिकतम मान संकेतकों को 0 से 1 (शून्य से) के बीच सूचकांकों में बदलने के लिए सेट करने की आवश्यकता है एक)। प्रत्येक आयाम सूचकांक की गणना निम्नानुसार की जाती है।

$$\text{आयाम सूचकांक} = \frac{\text{वास्तविक मूल्य - न्यूनतम मूल्य}}{\text{अधिकतम मूल्य - न्यूनतम मूल्य}}$$

17.6.3. एचडीआई और देशों का वर्गीकरण

एचडीआई का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि देश विकसित है, विकासशील है और अल्प विकसित है।

एचडीआई मूल्यों के आधार पर, देशों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्:

ए) एचडीआई 0.80 और उससे अधिक वाले उच्च मानव विकास वाले देश,

बी) एचडीआई 0.50 से 0.79 वाले मध्यम मानव विकास वाले देश, और

ग) 0.50 से कम एचडीआई मान वाले निम्न मानव विकास वाले देश।

17.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. मानव विकास को परिभाषित करें।
2. एचडीआई के घटक क्या हैं?
3. पीपीपी का विस्तार करें.
4. जेएसवाई क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. मानव विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करें।
2. मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका स्पष्ट करें।
3. मानव विकास के महत्व के बारे में लिखिए।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. भारत में आर्थिक विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या भूमिका है?
2. मानव विकास सूचकांक को परिभाषित करें? और एचडीआई की गणना कैसे करें?

17.8. शब्दकोष

1. मानव पूंजी: यह एक अपेक्षाकृत संकीर्ण अवधारणा है जो कौशल, शिक्षा, को संदर्भित करती है।

ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव और योग्यताएँ जो मनुष्य किसी कंपनी में लाते हैं।

2. मानव विकास: यह अपेक्षाकृत व्यापक अवधारणा है जो समग्रता से निर्धारित होती है
आँकड़ा जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है।

3. क्रय शक्ति समता (पीपीपी): इसका मतलब क्रय शक्ति समता है, यह एक माप है
विभिन्न देशों में कीमतों की तुलना करने के लिए विशिष्ट वस्तुओं की कीमतों का उपयोग किया जाता है
देशों की मुद्राओं की पूर्ण क्रय शक्ति।

4. मानव संसाधन विकास (एचआरडी): मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण शामिल है
किसी व्यक्ति को पहली बार काम पर रखने के बाद, नए कौशल सीखने के अवसर प्रदान करना, वितरण करना
संसाधन जो कर्मचारी के कार्यों और किसी भी अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए फायदेमंद हैं।
एचआरडी (मानव संसाधन विकास) लोगों को अधिक सक्षम बनाता है।

17.9. संदर्भ

1. वीके मिश्रा और एसके पुरी द्वारा भारत अर्थव्यवस्था
2. आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था और तेलुगु अकादमी का विकास
3. तेलंगाना सामाजिक-आर्थिक आउटलुक 2022
4. यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2020

राष्ट्रीय आय रुझान और क्षेत्रीय योगदान

अध्याय

18

18.0. उद्देश्य

18.1. परिचय

18.2. भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन का इतिहास

18.3. राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में रुझान

18.4. राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान

18.5. प्राथमिक क्षेत्र का योगदान

18.6. सारांश

18.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

18.8. शब्दकोष

18.9. संदर्भ

18.0. उद्देश्य

राष्ट्रीय आय का अर्थ समझें।

राष्ट्रीय आय के रुझान को समझें।

भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानों की व्याख्या करें।

सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को समझें।

राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान को समझें।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका स्पष्ट करें।

18.1. परिचय

व्यापक आर्थिक विश्लेषण में राष्ट्रीय आय एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अंतिम किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। यह इकाई भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानों के इतिहास, प्रवृत्तियों से संबंधित है देश में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में। सकल घरेलू विकास दर विभिन्न वर्षों में उत्पाद (जीडीपी) और प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय आय के रुझानों के अलावा इस इकाई में राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान पर भी चर्चा की गई है।

राष्ट्रीय आय के रुझान अलग-अलग समय में अर्थव्यवस्था के विकास को दर्शाते हैं, राष्ट्रीय आय की संरचना में संरचनात्मक परिवर्तन। वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र है भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। पंचवर्षीय योजनाओं से पहले सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत थी छोटा। योजना की शुरुआत के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ती गई।

18.2. भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन का इतिहास

आजादी से पहले दादाभाई नौरोजी को पहला व्यक्ति माना जाता है
उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द पॉवर्टी इन' में 1867-68 में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की
'भारत में ब्रिटिश शासन', जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया था। अन्य भी हैं
उल्लेखनीय अनुमानों में राष्ट्रीय आय का अनुमान भी शामिल था, 1899 में विलियम डिग्बी,
अंततः 1911, 1922 में शिर्रास, 1921 में शाह और खंबाटा और 1931-40 में आरसी देसाई
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया' है। प्रथम वैज्ञानिक विधि किसके द्वारा बनाई गई थी?
1931-32 में प्रोफेसर वीकेआरवी राव ने अर्थव्यवस्था को कृषि जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया
क्षेत्र और कॉर्पोरेट क्षेत्र. उनके अनुसार राष्ट्रीय आय 1689 करोड़ प्रति है
1932 में प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये थी।

स्वतंत्रता के तुरंत बाद, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय की नियुक्ति की
अगस्त 1949 में आंकड़े संकलित करने और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए समिति (एनआईसी)।
समिति की अध्यक्षता प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने की और इसमें प्रोफेसर डीआर गाडगिल और प्रोफेसर शामिल थे।
वीकेआरवी राव. राष्ट्रीय आय समिति की पहली रिपोर्ट 1954 में सामने आई
उस समय भारत की राष्ट्रीय आय 8710 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपये थी
1948-49. सामान्य वर्ष को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। आधार
दशकों से और हाल ही में वर्ष बदल रहा था। सीएसओ ने एक नई श्रृंखला शुरू की
2011-12 को आधार वर्ष मानकर राष्ट्रीय आय।

18.3. राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में रुझान

पिछले 70 वर्षों में भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है
भारतीयों पर नियोजन के प्रभाव के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है
अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों को पहले मौजूदा कीमतों पर एकत्र किया जाता है
और फिर उस दौरान मूल्य स्तर में किसी भी बदलाव के प्रभाव को खत्म करने के लिए स्थिर कीमतें
अवधि। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि परिवर्तन का सूचक है
लोगों का जीवन स्तर. हालाँकि किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आकलन
प्रति व्यक्ति आय के रुझानों की जांच करके अधिक सटीक रूप से अनुमान लगाया जा सकता है
कारक लागत पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के समान ही बात।

तालिका-1: शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	
	वर्तमान कीमतें स्थिर कीमतें वर्तमान	कीमतें स्थिर कीमतें		
2011-12 सीरीज				
1950-51	9531	448483	265	12493
1980-81	135470	1352931	1995	19925
1999-2000	1779304	3800560	17775	37968
2010-11	6756720	7373384	56971	62170
2015-16	12162398	9963681	94797	77659
2016-17	13623936	10782092	104880	83003
2017-18	15140418	11508774	115224	87586
2018-19[तीसरा आरई]	16713054	12226019	125946	92133
2019-20[दूसरा आरई]	17716597	12641633	132115	94270
2020-21 [प्रथम आरई]	17194158	11536004	126855	85110
2021-22 [पीई]	20529727	12519976	150007	91481
2022-23 [एई]	23594934	13347932	170620	96522

आरई: संशोधित अनुमान; पीई: अनंतिम अनुमान; एई: उन्नत अनुमान

स्रोत: i) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2022

ii) आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 सांख्यिकीय परिशिष्ट

उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 71 वर्षों (1950-51 से 2021-22) के दौरान शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि हुई। शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई 1950-51 में 4,48,483/- करोड़ रूपये से बढ़कर 1950-51 में 1,25,19,976/- करोड़ रूपये तक स्थिर कीमतों पर 2021-22 में 1,25,19,976/- करोड़ रुपये, जबकि मौजूदा कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय 1950-51 में 9531/- करोड़ रूपये से बढ़कर 2,05,29,727/- करोड़ रूपये हो गयी 2021-22 में. प्रति व्यक्ति आय भी 1950-51 में 12,493 रुपये से बढ़कर 91,481 रुपये हो गई। 2021-22 में स्थिर कीमतों पर भी वर्तमान कीमतों पर यह 265/- रुपये से बढ़ गया इसी अवधि में रु. 1,50,007/-. इस प्रकार तालिका-1 में प्रस्तुत आंकड़ों से ऐसा कहा जा सकता है प्रारंभ से ही शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है योजना का.

तालिका-2: शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	राष्ट्रीय आय (करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (रुपये)	
	वर्तमान कीमतें स्थिर कीमतें वर्तमान कीमतें स्थिर कीमतें			
2011-12 सीरीज				
1951-52	6.3	3.8	4.6	2.1
1961-62	5.6	3.6	3.2	1.3
1971-72	6.9	4.8	3.7	2.5
1981-82	16.8	6.0	14.6	4.0
1991-92	13.8	0.5	11.6	-1.5
2001-02	8.1	4.8	6.0	2.7
2011-12	14.6	5.0	11.4	2.1
2017-18	11.6	6.7	9.9	5.5
2011-22 (पीई)	19.4	8.5	18.3	7.5

पीई: अनंतिम अनुमान

स्रोत: i) राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2022

ii) आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 सांख्यिकीय परिशिष्ट

शुद्ध राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर प्रस्तुत की गई है तालिका 2। पिछले 20 वर्षों (2001-02 से 2021-22) तक शुद्ध राष्ट्रीय की वार्षिक वृद्धि दर 2021-22 में आय लगातार बढ़ रही है, अनंतिम अनुमान यह दर्शा रहे हैं कि वृद्धि होगी स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय की दर 8.5% है। जबकि मौजूदा कीमतों में यह है 19.4% वहीं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर भी स्थिर मूल्यों पर 7.5% है मौजूदा कीमतों में 18.3%।

18.4. राष्ट्रीय आय में क्षेत्रीय योगदान

एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय योगदान द्वारा राष्ट्रीय आय का अध्ययन स्पष्ट करता है आर्थिक संरचना की शारीरिक रचना. विभिन्न क्षेत्र जैसे प्राथमिक, माध्यमिक और क्षेत्र राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। लेबल 10.3 विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में।

तालिका-3: राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र		
1950-51	57.2	14.8	25.0
2000-01	25.1	22.1	52.4
2010-11	17.7	27.0	55.3
2018-19	16.1	29.6	54.3
2020-21	20.19	25.92	53.89

स्रोत: i) सांख्यिकी मंत्रालय

ii) आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

तालिका-3 से यह देखा जा सकता है कि प्रारंभ में प्राथमिक क्षेत्र ने बड़ा योगदान दिया राष्ट्रीय आय का हिस्सा. लेकिन वर्तमान में सेवा क्षेत्र इसका प्रमुख स्रोत है भारत में राष्ट्रीय आय 2020-21 में अकेले सेवा क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान 53.89% रहा

आय में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में भारी गिरावट आई है। में व्यापक रुझान घरेलू उत्पाद की बदलती संरचना निम्नलिखित हैं।

18.5. प्राथमिक क्षेत्र का योगदान

प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पकड़ने, वानिकी और लॉगिंग, खनन शामिल हैं और उत्खनन. नियोजन काल के प्रारम्भिक दिनों में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था सकल घरेलू उत्पाद प्रमुख है। 1950-51 और में इसका योगदान 57.2% है 2020-21 में हाल के वर्ष। में 20.19% का योगदान दिया। इस प्रकार वर्षों से प्राथमिक का हिस्सा जीडीपी में सेक्टर में गिरावट आई है. कृषि की हिस्सेदारी में गिरावट का मुख्य कारण है संरचनात्मक परिवर्तन जो हो रहा था। हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), संचार, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़े हैं कृषि। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटने का यही कारण है।

18.5.1. द्वितीयक क्षेत्र का योगदान

द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और शामिल हैं जल आपूर्ति में 1950-51 में 14.8% से 2020-21 में 25.92% तक लगातार वृद्धि देखी गई है।

18.5.2. क्षेत्रीय क्षेत्र का योगदान

क्षेत्रीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है जिसमें आईटी, व्यापार, परिवहन,

कमी, संचार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएँ।

1950-51 में सेवा क्षेत्र का योगदान 25% था और 2020-21 में यह बढ़कर 53.89% हो गया है।

इन वर्षों में सेवा क्षेत्र, विशेषकर सूचना क्षेत्र का भारी योगदान बढ़ा है

प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, परिवहन और संचार क्षेत्र दिखाए गए हैं

हाल के वर्षों में भारी वृद्धि.

18.6. सारांश

उपरोक्त विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीयों की संख्या में अचानक उछाल आया है

अर्थव्यवस्था को पूरा किए बिना उत्तर-औद्योगिक सेवा अर्थव्यवस्था के चरण में स्थानांतरित करना

औद्योगीकरण का चरण. औद्योगिक क्षेत्र को जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है.

18.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. भारत में आजादी से पहले पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था?
2. राष्ट्रीय आय आकलन समिति में सदस्य कौन होते हैं?
3. सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के लिए क्या सबक हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. प्रति व्यक्ति आय के रुझान स्पष्ट करें?
2. राष्ट्रीय आय में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों की क्या भूमिका है?
3. किसी अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय संरचना क्या है?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. भारत में राष्ट्रीय आय की प्रवृत्तियों की व्याख्या करें।

2. सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान पर निम्नलिखित तालिका के लिए एक पाई चार्ट बनाएं। चर्चा करना

   क्षेत्रों का योगदान

क्षेत्र	2000-01	2018-19
प्राथमिक	25.1%	16.1%
माध्यमिक	22.1%	29.6%
इलाका	52.4%	54.3%

18.8. शब्दकोष

1. राष्ट्रीय आय: उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य

   एक वित्तीय वर्ष के दौरान देश.

2. विकास दर= $\frac{\text{Current value} - \text{Previous value}}{\text{Previous value}}$ x 100

3. प्रति व्यक्ति आय: यह लोगों की औसत आय है। राष्ट्रीय आय का बँटवारा होता है

   देश की जनसंख्या के साथ.

   प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{National Income}}{\text{Population}}$

4. प्राथमिक क्षेत्र: इसमें कृषि, मछली पकड़ने, वानिकी और लॉगिंग, खनन और शामिल हैं

   उत्खनन.

5. द्वितीयक क्षेत्र: इसमें विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस और पानी शामिल हैं

   आपूर्ति।

6. क्षेत्रीय क्षेत्र: इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन, भंडारण, शामिल हैं।

   संचार, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, सामुदायिक और व्यक्तिगत सेवाएँ।

18.9. संदर्भ

1. मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत - सी. रंगराजन, बीएच ढोलकिया।

2. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

3. तेलुगु अकादमी, इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की पाठ्यपुस्तक।

अध्याय

19

गरीबी और बेरोजगारी

19.0. उद्देश्य

19.1. परिचय

19.2. परिभाषा

19.3. गरीबी के प्रकार

19.4. गरीबी रेखा

19.5. गरीबी के कारण

19.6. गरीबी के परिणाम

19.7. बेरोजगारी

19.8. बेरोजगारी के प्रकार

19.9. बेरोजगारी की गणना कैसे की जाती है?

19.10. बेरोजगारी के कारण

19.11. बेरोजगारी के परिणाम

19.12. सरकार - गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के उपाय

19.13. समाप्त

19.14. मॉडल परीक्षा प्रश्न

19.15. शब्दकोष

19.16. संदर्भ

19.0. उद्देश्य

- गरीबी की विभिन्न अवधारणाओं को समझें
- गरीबी के कारण और उसके परिणाम स्पष्ट करें
- विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी का विश्लेषण करें
- गरीबी और बेरोजगारी के बीच संबंध स्पष्ट करें
- बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करें
- गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम बताएं।

19.1. परिचय

गरीबी दुनिया के कई देशों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। यह है एक गंभीर वित्तीय समस्या. हालाँकि विकसित, विकासशील देशों में भी गरीबी मौजूद है कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों (तीसरी दुनिया के देशों) में बड़े पैमाने पर गरीबी है। गरीबी हो सकती है इसे एक सामाजिक-आर्थिक घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय कम और उच्च है आय असमानता है तो यह कहा जा सकता है कि उस देश में गरीबी है। गरीबी एक है भारत की प्रमुख समस्याएँ

19.2. परिभाषा

धन और भोजन जैसी मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की कमी या कमी की स्थिति और कपड़े गरीबी के अस्तित्व को दर्शाते हैं। गरीबी की परिभाषाएँ बार-बार बदलती रहती हैं। कमी न्यूनतम जीवन स्तर, कुपोषण, अशिक्षा, बाल विकास में पिछड़ापन आदि दरिद्रता के लक्षण हैं। इसलिए, गरीबी सामाजिक के साथ एक बहुआयामी अवधारणा है, आर्थिक और राजनीतिक पहलू.

19.3. गरीबी के प्रकार

भारत में गरीबी को दो तरह से परिभाषित किया गया है, पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी।

1. पूर्ण गरीबी: भोजन जैसी बुनियादी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के साधनों का पूर्ण अभाव।

वस्त्र और आश्रय. पूर्ण गरीबी भी पूरा न कर पाने की स्थिति है

न्यूनतम निर्वाह व्यय. न्यूनतम आवश्यकताओं की मात्रा की गणना की जाती है

जीवन यापन की न्यूनतम लागत निर्धारित करने के लिए बाजार कीमतों के आधार पर। गरीबी भी हो सकती है

लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली कैलोरी के आधार पर परिभाषित किया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद के अनुसार

शोध के अनुसार, ये भौतिक मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2,400 कैलोरी और 2,100 है

शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी. इससे कम राशि लेने वालों पर विचार किया जा सकता है

गरीब। भारत जैसे विकासशील देशों में पाई जाने वाली गरीबी पूर्ण गरीबी है।

2. सापेक्ष गरीबी: सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य आर्थिक असमानता से है। इसके तहत

अवधारणा, अर्थव्यवस्था में 5 से 10 प्रतिशत लोग न्यूनतम आय स्तर वाले हैं और

5 से 10 प्रतिशत की तुलना में जीवन स्तर अपेक्षाकृत खराब माना जाता है

उच्चतम आय स्तर और जीवन स्तर वाली जनसंख्या। यह अवधारणा अधिकतर है

अमीर देशों में उपयोग किया जाता है।

भारत में गरीबी मापने के लिए गरीबी रेखा का उपयोग किया जाता है। 'गरीबी रेखा' एक विधि है

किसी व्यक्ति की आय और उपभोग स्तर के आधार पर उसकी गरीबी का स्तर ज्ञात करना।

19.4. गरीबी रेखा

सरल शब्दों में, गरीबी रेखा वह मौद्रिक आय है जो किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए

जीवन की बुनियादी सुविधाएं वहन करें। विश्व स्तर पर, गरीबी रेखा $2.15 प्रति दिन निर्धारित है। यह

राशि को हाल ही में विश्व बैंक द्वारा 2022 में अद्यतन किया गया था।

भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि उपभोग पर आधारित है

स्तर और यदि खपत किसी दिए गए न्यूनतम स्तर से नीचे आती है, तो घरेलू (परिवार)।

5) को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कहा जाता है। उपभोग आधारित गरीबी रेखा में,

नमूना आधारित सर्वेक्षण एक संदर्भ अवधि (जैसे 30 दिन) का उपयोग करते हैं जिसमें घर यानी परिवार शामिल होते हैं

5 में से पिछले 30 दिनों की उनकी खपत के बारे में पूछा जाता है और उन्हें प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है

सामान्य उपभोग.

सरकार ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की देश में गरीबी और गरीबों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए। समिति ने कहा कि 2011-12 में भारत में गरीबों की संख्या जनसंख्या का 29.5% से कहीं अधिक थी। वह मतलब 10 में से 3 व्यक्ति गरीब हैं। सी रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार:

रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति। 1,407 रुपये प्रति माह (47 रुपये/दिन) को गरीब माना जाना चाहिए शहरी और रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति। 972 प्रति माह (32 रुपये/दिन) माना जाना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब.

2011 के लिए तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा को व्यक्ति द्वारा खर्च करने वाला माना गया था रुपये से कम शहरों में 1,000 रुपये प्रति माह (33 रुपये प्रतिदिन) वाले व्यक्ति को गरीब माना जाना चाहिए रुपये से कम खर्च गांवों में 816 रुपये प्रति माह (27 रुपये प्रतिदिन) को गरीब माना जाना चाहिए।

गरीबी रेखा की गणना: भारत में गरीबी का आकलन अब नीति आयोग द्वारा किया जाता है टास्क फोर्स द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना की जाएगी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एमओएसपीडी)। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएसओ) हर 5 साल में एक नमूना सर्वेक्षण आयोजित करता है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाएं।

विभिन्न समितियों द्वारा गरीबी का अनुमान

वर्ष	लकड़ावाला समिति अनुमान			तेंदुलकर समिति अनुमान			रंगराजन समिति अनुमान		
	ग्रामीण शहरी कुल			ग्रामीण शहरी कुल			ग्रामीण शहरी कुल		
1993-94 37.3		32.4	36.0	50.1	31.8	45.3	-	-	-
2004-05 28.3		25.7	27.5	41.8	25.7	37.2	-	-	-
2009-10 -		-	-	33.8	20.9	29.8	39.6	35.1	38.2
2011-12 -		-	-	25.7	13.7	21.9	30.9	26.4	29.5

19.5. गरीबी के कारण

भारत में गरीबी के कई कारण हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं:

19.5.1. प्रवासीय शासनविधि

भारत में गरीबी का मूल कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है। भारत को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया में, अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को लूटा, कच्चे माल को कम कीमतों पर लिया और उन्हें वापस बेच दिया भारत में बहुत अधिक कीमतों पर। इसके कारण स्वदेशी कारखाने और मिलें बंद हो गईं भारत में और भारत आर्थिक रूप से अंग्रेजों पर अधिक निर्भर हो गया। धीरे-धीरे लोग हैं बिना रोजगार के गरीबी में धकेल दिया गया।

19.5.2. जनसंख्या वृद्धि - जनसंख्या का अत्यधिक दबाव

भारत में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे ऊँचे भूमि भूखंडों का विखंडन होता है। परिणामस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति को भूमि उपलब्ध हो गई बहुत कम हो गया है, जिससे परिवारों के पास आय और उत्पादन के लिए पर्याप्त भूमि नहीं रह गई है। उच्च जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। पर निर्भरता बढ़ती जा रही है कमाने वालों, सदस्यों का उपभोग स्तर कम है और वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

19.5.3. कम आर्थिक वृद्धि और विकास

गरीबी स्थिर या धीमी गति से चलने वाली आर्थिक प्रगति का भी परिणाम है। एक समस्या यह है आर्थिक विकास की दर जनसंख्या वृद्धि की दर के साथ तालमेल नहीं रखती है। भारत में, वांछित स्तर के लिए आवश्यक आर्थिक विकास दर बहुत कम है। इसलिए, बीच का अंतर वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता का स्तर एवं आवश्यकता बनी रहती है। परिणाम है गरीबी।

19.5.4. बेरोजगारी और अल्परोजगार

आकस्मिक श्रमिकों में बेरोजगारी अधिक है, जो श्रम शक्ति का बड़ा हिस्सा हैं। उनके में मामला बेरोजगारी और गरीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुई है एक ओर जनसंख्या और श्रम शक्ति और दूसरी ओर अपेक्षाकृत कम पूंजी निर्माण और दूसरी ओर आर्थिक विकास दर. इसके अलावा, रोजगार के अवसरों का सृजन संगठित क्षेत्र बहुत कम है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है।

19.5.5. मुद्रास्फीति और खाद्य कीमतों में वृद्धि

मुद्रास्फीति की दर और खाद्य कीमतों का स्तर एक महत्वपूर्ण कारक है गरीबी। मुद्रास्फीति, विशेषकर खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने से न्यूनतम खपत बढ़ जाती है बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय. इसलिए महंगाई बढ़ रही है, खासकर खाने की चीजों में कीमतें, कई परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल देती हैं।

19.5.6. धन एवं संसाधनों का असमान वितरण

धन और संसाधनों का असमान वितरण किसी देश में आय असमानता का कारण बनता है। देय इस असंतुलन से देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और विकास प्रभावित होता है। गरीबी तेजी से बढ़ता है

19.5.7. असंतुलित औद्योगीकरण

उद्योग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। में उद्योग का संकेन्द्रण एक ही राज्य या स्थान उस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाता है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं गैर-औद्योगिक क्षेत्र में सीमित हैं। ये क्षेत्र भयंकर गरीबी से ग्रस्त हैं।

19.5.8. संसाधनों का दुरुपयोग

देश में लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने की जरूरत है राष्ट्रीय आय वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए उचित देश के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक का उपयोग न होना हमारे देश में नदियाँ, जंगल और खनिज संपदा जैसे संसाधन इसका कारण बन गए हैं गरीबी का.

19.5.9. निम्न स्तर की तकनीक

निम्न तकनीक भी गरीबी का कारण बनती है। अन्य विकसित देशों की तुलना में नहीं न केवल विनिर्माण क्षेत्र और कृषि उत्पादन प्रक्रियाओं में, बल्कि विपणन में भी हमारे देश में कौशल, वित्तपोषण और उत्पादन इकाइयों की स्थापना, प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है बहुत कम। इस कारण औसत उत्पादन कम होता है। यह निवेश और कमाई को कम करता है। यह अर्थव्यवस्था को गरीबी की ओर ले जाता है।

19.5.10. शिक्षा का निम्न स्तर

शिक्षा किसी व्यक्ति के आर्थिक अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक प्रत्यक्ष है शिक्षा और आय के बीच संबंध. लेकिन गरीब, संसाधनों की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाते अपने बच्चों को स्कूल भेजें. वे अपने बच्चों को काम पर भेजना और योगदान देना पसंद करते हैं स्कूलों में जाने के बजाय परिवार की आय। लेकिन शिक्षा की कमी या कम शिक्षा गरीबों को आर्थिक रूप से बढ़ने से रोकता है।

19.5.11. उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल (एलपीजी)

यह मॉडल कृषि और कृषि आधारित उद्योगों को दरकिनार कर देता है, जो मुख्य हैं अधिकांश लोगों के लिए रोजगार के साधन। एलपीजी पूंजी आधारित विकास पर जोर देती है। यह श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में भय पैदा किया। इसके बढ़ने की उम्मीद है बेरोजगारी और गरीबी का कारण।

19.4.12. सामाजिक परिस्थिति

भारत में गरीबी केवल आर्थिक और वाणिज्यिक कारकों से ही नहीं बल्कि अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है सामाजिक कारकों द्वारा. वंशानुक्रम कानून, जाति व्यवस्था, धार्मिक प्रथाएँ और कुछ परंपराएँ लोगों को और गरीबी में धकेलो।

19.6. गरीबी के परिणाम

गरीबी का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर गंभीर प्रभाव पड़ता है देश। हमारे देश में लगभग 800 मिलियन लोग गरीब के रूप में पहचाने जाते हैं; उनमें से अधिकांश जीवित हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और उचित नौकरियों के बिना रहते हैं। जीवन की कमी के कारण शहरों का विस्तार हो रहा है कई ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार और महानगरीय क्षेत्रों में प्रवासन। वहाँ पर भी, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के बिना, कई लोग मलिन बस्तियों में गरीबी और हताशा का जीवन जीते हैं, कचरा निपटान, बिजली और कई अन्य आवश्यकताएँ। गरीबी पूरे समाज को विभाजित करती है दो वर्गों में बाँटा गया, अमीर और गरीब। जबकि अमीर लोग विलासिता का जीवन जीते हैं, अमीर- वे न्यूनतम सुविधाएं भी वहन करने में असमर्थ हैं। गरीबी के कुछ परिणाम समस्या नीचे दी गई है।

1. निम्न जीवन स्तर एवं आवास समस्या:

गरीब लोगों के पास रहने की उचित स्थितियाँ नहीं हैं। वे भोजन, कपड़े आदि के लिए लड़ते हैं आश्रय। अधिकांश गरीब एक ही कमरे में रहते थे।

2. साफ़-सफ़ाई एवं स्वच्छता:

इन लोगों में साफ़-सफ़ाई और उचित सफ़ाई व्यवस्था के बारे में जागरूकता कम है। उचित स्वच्छता के अभाव के कारण वे हानिकारक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं।

3. कुपोषण:

गरीबों की आय का स्तर कम होने के कारण क्रय शक्ति कम होती है। वे नहीं कर सकते वे अच्छे भोजन पर खर्च करते हैं और इस प्रकार कुपोषित हो जाते हैं और बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं।

4. उच्च शिशु मृत्यु दर:

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 2019 के भारत में शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से 30 की एक वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है। हर साल 14 लाख बच्चे अपने पांचवें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। निमोनिया, मलेरिया, डायरिया संबंधी रोग और जीर्ण कुपोषण मौत का मुख्य कारण है।

5. शिक्षा का अभाव:

यूनिसेफ के अनुसार भारत में 25% से अधिक बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। लड़कों की तुलना में लड़कियाँ अधिक स्कूल छोड़ती हैं। यह स्थिति विशेषकर गरीबों में देखी जाती है लोग। हालाँकि भारतीय कानून पुरुषों और महिलाओं, विशेषकर महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना चाहते हैं निम्न सामाजिक जातियों के लोग शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। उनकी शिक्षा की कमी के कारण, भारत में उन्हें उचित रोजगार और वेतन मिलने की संभावना बहुत कम है।

6. बाल श्रम प्रणाली:

जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वे काम कर रहे हैं क्योंकि गरीब माता-पिता उन्हें भेजते हैं बच्चों को अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए आय अर्जित करने के लिए काम करना पड़ता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ऐसा होगा भविष्य में उन्हें और गरीबी की ओर धकेलें।

7. बाल विवाह:

हालाँकि बाल विवाह गैरकानूनी है, फिर भी यह कई भारतीय समाजों में होता है। लड़कियाँ जब वे बच्चे हों तो माँ बनें। कई लोग वयस्क होने से पहले ही मर जाते हैं। उनके खातिर गरीबी के कारण कई माता-पिता अपने बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर देते हैं।

8. बेरोजगारी:

गरीबी बेरोजगारी की समस्या को जन्म देती है। बेरोजगारी किसी देश को रोकती है एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। उच्च बेरोजगारी दर देश को रोकती है सभी पहलुओं में प्रगति हो रही है।

9. सामाजिक तनाव:

गरीबी समाज में आय असमानता बढ़ाती है। राष्ट्रीय संपदा असमान है अमीर और गरीब लोगों के बीच वितरित किया गया। धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है। इससे समाज में अशांति और असुरक्षा पैदा होती है।

10. व्यसन और आपराधिक गतिविधि:

गरीब लोग अपराध, हिंसा आदि जैसी सामाजिक रूप से अस्वीकार्य गतिविधियों का सहारा लेते हैं अपना पेट भरने के लिए आतंकवाद। वे नशे जैसी बुरी चीजों के आदी हैं।

19.7. बेरोजगारी

बेरोजगारी हर देश में लोगों को परेशान करने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है वर्तमान समय. सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी बहुत कठिन कार्य है किसी देश में रोज़गार की मात्रा काफी हद तक सरकारों के स्तर पर निर्भर करती है। विकास। इसलिए, जब कोई देश प्रगति करता है और उसकी उत्पादकता बढ़ती है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं.

दरअसल वह स्थिति जहां व्यक्ति में योग्यता, रुचि और योग्यता हो काम करो और काम न मिले तो उसे 'बेरोजगारी' कहते हैं। दूसरे शब्दों में - की स्थिति बाजार में प्रचलित मजदूरी के आसपास काम करने को तैयार होने के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा है/ अर्थव्यवस्था को 'बेरोजगारी' कहा जाता है। भारत की बेरोजगारी बिल्कुल अलग है विकसित देशों। लॉर्ड जे.एम. कीन्स के अनुसार बेरोजगारी का प्रभाव विकसित अर्थव्यवस्थाएँ समग्र माँग में कमी का परिणाम हैं।

19.8. बेरोजगारी के प्रकार

बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार इस प्रकार हैं:

19.8.1. संरचनात्मक बेरोजगारी

इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना से जुड़ी होती है। देय देश की अर्थव्यवस्था में भारी संरचनात्मक बदलाव से लेकर मांग-आपूर्ति में कमी आ सकती है व्यवधान. संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब ऐसी नौकरियाँ होती हैं जिनमें श्रमिकों के पास कौशल की कमी होती है

के लिए, या जब श्रमिक उपलब्ध हैं लेकिन असंतुलन के कारण भरने के लिए कोई नौकरियाँ नहीं हैं श्रमिकों की जनसंख्या और उपलब्ध नौकरियों के प्रकार। संरचनात्मक बेरोजगारी सर्वाधिक है तकनीकी रूप से उन्नत उद्योगों में स्पष्ट है। यह विकास का स्वाभाविक परिणाम है और तकनिकी प्रगति। ऐसा उपलब्ध नौकरियों के बीच बेमेल के कारण हो सकता है कार्यबल का कौशल. श्रम गतिशीलता से संरचनात्मक बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है।

19.8.2. रोजगार के अंतर्गत

'अल्परोजगार' वह स्थिति है जहां उपलब्ध उत्पादक संसाधन उपलब्ध हैं अधिकतम उपयोग नहीं किया गया या ऐसा वेतन लिया गया जिससे न्यूनतम राशि भी पूरी नहीं होती आवश्यकताएँ या जहाँ कोई अपनी क्षमता का अधिकतम सीमा तक उपयोग करने में असमर्थ है या है एक व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम नियोजित किया गया है। इस प्रकार की बेरोजगारी वाला देश शोषण करता है उनके कार्यबल की क्षमता.

19.8.3. प्रच्छन्न रोज़गार

यदि किसी उत्पादन प्रक्रिया में वास्तव में आवश्यकता से अधिक श्रमिक हैं, तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। इन्हें जारी रखने से अतिरिक्त कर्मचारी नहीं बढ़ेंगे उत्पादन। हटाने से उत्पादन कम नहीं होता. रैगनर नर्क का कहना है कि उनका सीमांत उत्पादकता शून्य (0) है और जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि यह नकारात्मक है। ये बेरोजगारी है विकासशील देशों में विशेषकर कृषि क्षेत्र में उच्च।

19.8.4. स्वैच्छिक बेरोजगारी

जो प्रचलित मजदूरी पर काम तो ढूंढ लेते हैं लेकिन अधिक की उम्मीद में काम पर नहीं जाते मजदूरी को 'स्वैच्छिक बेरोजगार' कहा जाता है। से कम कमाई होने पर बेरोजगार होना अपेक्षित वेतन, या आराम की उम्मीद में काम पर न जाना। स्वैच्छिक बेरोजगारी भी एक है वह व्यक्ति जो अपनी योग्यता से कम नौकरी मिलने पर नौकरी छोड़कर बेरोजगार हो जाता है।

19.8.5. स्वैच्छिक बेरोजगारी में

किसी अर्थव्यवस्था या वस्तु में प्रभावी मांग की कमी के कारण बेरोजगारी-उत्पादक संगठन को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है।

19.8.6. मौसमी बेरोजगारी

वहाँ केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए काम होता है और अल्प अवधि के लिए बेरोजगारी होती है कुछ ऋतुओं में और अन्य ऋतुओं में कोई काम न होने को 'मौसमी बेरोजगारी' या मौसमी कहा जाता है बेरोजगारी. आमतौर पर कृषि क्षेत्र में मजदूरों के पास केवल इसी दौरान काम होता है खेती और कटाई की अवधि. बाकी समय कोई काम नहीं है. इसका मतलब है कि वहाँ है साल में केवल 7-8 महीने ही काम मिलेगा। बाकी महीनों में कोई काम नहीं मिलेगा।

19.8.7. तकनीकी बेरोजगारी

अर्थव्यवस्था में नई प्रौद्योगिकियों के आने से उत्पन्न बेरोजगारी 'तकनीकी बेरोजगारी' कहलाती है।

19.8.8. चक्रीय बेरोजगारी

विकसित देशों में 'चक्रीय बेरोजगारी' व्यापारिक चक्रों के कारण उत्पन्न होती है कुल मांग में कमी अर्थात उत्पाद के लिए पर्याप्त मांग का अभाव। पीरियड्स के दौरान आर्थिक मंदी से 'चक्रीय बेरोजगारी' उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अस्थायी है.

19.8.9. शिक्षित बेरोजगारी

जो लोग किसी क्षेत्र में शिक्षित, प्रशिक्षित और कुशल होते हैं उन्हें 'शिक्षित' कहा जाता है 'बेरोजगार' अगर उन्हें काम नहीं मिलता है। भारत में, विशेषकर कस्बों और शहरों में, बेरोजगारी शिक्षित लोगों में उच्च है।

19.8.10. प्रतिरोधात्मक रोजगार

अस्थायी बेरोजगारी जो तब होती है जब श्रमिक एक व्यवसाय से बदल जाते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में दूसरे को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है।

19.9. बेरोजगारी की गणना कैसे की जाती है?

एक व्यक्ति जो मानक वर्ष के आधार पर 273 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, उसे मानक वर्ष के आधार पर माना जाता है एक कर्मचारी के रूप में बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग द्वारा स्थापित अनुमानों में बेरोजगारी के तीन अनुमान लगाये गये हैं एनएसएसओ (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन) के 27वें दौर में तैयार किया गया।

I. दीर्घकालिक बेरोजगारी या नियमित प्रमुख स्थिति रोजगार' द्वारा मापा जाता है
बेरोजगार लोगों की संख्या में अधिकांश लोग नियमित रोजगार की तलाश में हैं
साल का। यह उपाय नियमित की तलाश करने वालों के लिए अधिक उपयुक्त है
रोजगार या काम. जैसे- अच्छे पढ़े-लिखे और कुशल लोग साधारण को स्वीकार नहीं करते
नौकरियाँ इसे 'खुला रोजगार' भी कहा जाता है।

द्वितीय. साप्ताहिक स्थिति बेरोज़गारी को लोगों की संख्या में मापा जाता है। का अभाव
सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान कम से कम एक घंटा काम करें।

तृतीय. दैनिक स्थिति बेरोज़गारी - व्यक्तिगत दिनों या व्यक्ति वर्षों में मापी जाती है। यानी जिन लोगों ने ऐसा किया
सर्वेक्षण सप्ताह के दौरान एक दिन या कुछ दिन काम नहीं मिलता। 19.9 बेरोजगारी के कारण.

19.10. बेरोजगारी के कारण

1. बेरोज़गारी वृद्धि: भारत में आज़ादी के बाद से रोज़गार वृद्धि दर में वृद्धि हुई है
आर्थिक विकास दर से काफी कम है. इसके अलावा, आर्थिक विकास दर
भारत की बढ़ती कार्यबल के साथ तालमेल बिठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। नतीजतन,
बेरोजगारी व्यापक है.

2. श्रम शक्ति में वृद्धि: भारत में मृत्यु दर में बिना किसी कमी के तेजी से कमी आई है
जन्म दर में. इसके प्रभाव से भारत की जनसंख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इससे यह हुआ
बेरोजगारी और श्रम बल में बड़े विस्तार के लिए।

3. मशीनरी का अत्यधिक उपयोग: भारत में जनशक्ति बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इनके अंतर्गत
परिस्थितियाँ, देश में श्रम प्रधान उत्पादन तकनीक है। हालाँकि, भारत में,
पूंजी-सघन प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल उद्योग में बल्कि कृषि में भी होता है
बड़े पैमाने पर बेरोजगारी.

4. कौशल विकास कार्यक्रमों का अभाव: भारत में व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम
भारतीय उद्योग के लिए उपयुक्त संख्या में बहुत कम हैं। इसलिए, की कमी है
उद्योगों में आवश्यक कौशल वाली जनशक्ति।

5. रोजगार की उम्मीदें: भारत के शिक्षित युवा सफेदपोश नौकरी की आकांक्षा रखते हैं। वे करते हैं
आर्थिक गतिविधियों को चलाने में सक्षम नवोन्मेषी और उद्यमशीलता की भावना नहीं है
स्व-रोज़गार होने का. भारत में, कई स्नातक तब तक बेरोजगार रहना पसंद करते हैं
ऐसी नौकरी प्राप्त करें जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हो।

6. धीमी आर्थिक वृद्धि: भारत की समग्र आर्थिक वृद्धि बहुत धीमी रही है। अपर्याप्त सिंचाई सुविधाओं, बुनियादी ढांचे में वृद्धि और अपर्याप्त औद्योगिक विस्तार का परिणाम है ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार के अपर्याप्त अवसर।

7. श्रमिकों का ध्यान कम होना: श्रमिकों का ध्यान कम होना। परिवार से लगाव के कारण वहां नौकरी के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा. भाषा, धर्म और जलवायु जैसे कारक भी इसमें योगदान दें.

8. शिक्षा प्रणाली में खामियाँ: पूंजीवादी दुनिया में नौकरियाँ अत्यधिक विशिष्ट हैं लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली इन नौकरियों के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण और विशेषज्ञता प्रदान नहीं करती है। इस तरह काम करने के इच्छुक कई लोग कौशल की कमी के कारण बेरोजगार हो जाते हैं।

19.11. बेरोजगारी के परिणाम

1. गरीबी - बेरोजगारी से गरीबी आती है। बेरोजगारी के लंबे दौर के बाद युवा पैसा कमाने के लिए अवैध और गलत गतिविधियों का सहारा ले रहे हैं। इससे देश में अपराध भी बढ़ गया है.

2. सामाजिक समस्याएँ - बेरोजगार लोग आसानी से असामाजिक ताकतों के बहकावे में आ जाते हैं। इससे उनका देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से विश्वास उठ जाएगा।'

3. नशे की लत - अक्सर देखा जाता है कि बेरोजगार लोग नशे के आदी हो जाते हैं और शराब या आत्महत्या का प्रयास, जिससे देश के मानव संसाधन को नुकसान हो।

4. मानव संसाधनों की हानि - बेरोजगारी की समस्या के कारण मानव संसाधनों की हानि होती है। जैसा श्रमिक अपना अधिकतम समय बेहतर रोजगार के लिए समर्पित करते हैं जिसके परिणामस्वरूप काम का नुकसान होता है बहुमूल्य मानव-घंटों की हानि।

5. निम्न जीवन स्तर - बेरोजगारी की अवधि के दौरान, लोग रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, सौदेबाजी की शक्ति की कमी, कम वेतन और आय, जिससे उनके जीवन स्तर में गिरावट आती है।

6. अर्थव्यवस्था पर प्रभाव - इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि यदि संसाधनों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक श्रम शक्ति जल श्रमिक है, वे वास्तव में निर्भर हैं बाकी कामकाजी आबादी पर. इस प्रकार राज्य की सामाजिक-आर्थिक लागत होगी बढ़ोतरी। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी में 1 प्रतिशत की वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत की कमी आती है

7. श्रम का शोषण - बेरोजगारी की स्थिति में श्रमिकों का शोषण किया जाता है अधिकतम। मजदूरों को कम वेतन पर विभिन्न परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। यह श्रमिकों की कार्यकुशलता को दर्शाता है

8. कौशल के उपयोग की हानि - बेरोजगार लोग अपने कौशल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। यदि यह हो तो लंबे समय तक जारी रहने पर लोग अपना कौशल भी खो सकते हैं।

19.12.सरकारी गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन उपाय

बेरोजगारी रोकने के सभी उपाय गरीबी को कम करते हैं। यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, गरीबी धीरे-धीरे कम होगी. इसलिए अर्थशास्त्रियों का ध्यान आर्थिक दर में वृद्धि पर रहता है विकास। रोजगार सृजन के उद्देश्य से विकास योजनाएं लागू की गई हैं। एक भाग के रूप में इसमें छोटे स्तर पर रोजगार पर विशेष ध्यान देने के साथ तेजी से विकास हासिल करने का विचार किया गया है पैमाने के उद्योग. गरीबी उन्मूलन के लिए चरणों में अपनाए गए कार्यक्रमों को विभाजित किया गया है चार व्यापक श्रेणियां. आइए इन पर एक नजर डालें.

1. ग्रामीण गरीबों के लिए आय के स्रोत और विकास कार्यक्रम: ये कार्यक्रम मुख्य रूप से हैं इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। प्रमुख इस श्रेणी के अंतर्गत कार्यक्रम हैं - लघु किसान विकास एजेंसी (एसएफडीए), सीमांत किसान और कृषि मजदूर एजेंसी (एमएफएएल), एकीकृत ग्रामीण विकास। कार्यक्रम (आईआरडीपी) आदि योजनाएं ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गईं।

2. विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (डीडीपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि कुछ के लिए हैं विशेष प्रयोजन. वन और डेयरी विकास ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जो बढ़ते हैं क्षेत्र के कमजोर वर्गों की आय।

3. रियायती रोजगार के अवसरों के निर्माण के लिए कार्य कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना (एफडब्ल्यूपी), प्रधान मंत्री की एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन गरीबों के लिए कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) इसी श्रेणी में आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन बन गया है कार्यक्रम (एमजीएनआरईजीपी)।

4. न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम: इस चौथे प्रकार में न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम होता है और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया गरीब लोगों का उपभोग स्तर बढ़ाकर उनकी क्षमता बढ़ाना। इसमें बुनियादी शामिल है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, सड़क, विद्युतीकरण, आवास और पोषण।

हाल के वर्षों में, सरकार ने इससे निपटने के लिए दोतरफा रणनीति पेश की है भारत में गरीबी की समस्या.

1. उन क्षेत्रों का विस्तार जो उच्च श्रम तीव्रता की गारंटी देते हैं; और

2. गरीबों को शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य से सशक्त बनाकर वे उच्च स्तर पर प्रवेश कर सकते हैं कुशल और बेहतर भुगतान वाले क्षेत्र जो उन्हें गरीबी रेखा को पार करने में सक्षम बनाते हैं।

आजादी के बाद से, सरकारों ने कई कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं गरीबी और बेरोजगारी कम करें. गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी कुछ योजनाएं पिछले 2 दशकों में सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं नीचे दी गई हैं।

1. गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को कवरेज प्रदान करने के लिए जनश्री भीम योजना 2000
2. गांवों में न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000
3. अंत्योदय अन्न योजना 2000 गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा
4. असीहरा भीम योजना2000 बेरोजगार श्रमिकों के लिए मुआवजा
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 2001 सभी गांवों में पक्की सड़कें होनी चाहिए
6. केतिहार मजदूर बीमा योजना (KMBJ) 2001केतिहार मजदूर बीमा योजना (KMBJ)
7. शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई 2001) गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों की शिक्षा
8. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) 2001 रोजगार और खाद्य सुरक्षा
9. रोजगार जया प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना (JPNRGY) 2001
   गरीबी से जूझ रहे जिलों में रोजगार सृजन
10. वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (VAMBAY) 2001 शहरी में घरों का निर्माण
    स्लम क्षेत्र
11. राष्ट्रीय कार्य खाद्य योजना (NFFWP 2004 अनुपूरक वेतन रोजगार
    एकीकरण
12. जननी सुरक्षा योजना 2005 गर्भवती माताओं को देखभाल प्रदान करने के लिए
13. भारत निर्माण कार्यक्रम (बीएनपी) 2005 ग्रामीण बुनियादी ढांचे का प्रावधान (सिंचाई,
    जल आपूर्ति, सड़क, टेलीफोन और बिजली
14. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा):

    कम से कम 100 दिन की मजदूरी प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना वर्ष 2006 में रोजगार.

15. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: 2011 स्वरोजगार और कुशल लोगों तक पहुंच
    वेतन रोजगार के अवसर

16.राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन: 2013 शहरी गरीबों का स्वयं सहायता में गठन

समूह, कौशल विकास के अवसर पैदा कर रहे हैं

17.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमएवाई): 2016 में 50 मिलियन एलपीजी वितरित की जाएगी

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं के लिए कनेक्शन।

18.प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM): 2019 वृद्धावस्था संरक्षण एवं

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा (यूडब्ल्यू)

19.प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मा निर्भर निधि: 2020 माइक्रो-क्रेडिट सुविधाएं

COVID-1 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों के लिए

19.13. सारांश

भारत में गरीबी और बेरोजगारी की पुरानी समस्याएँ प्रमुख हो गई हैं चुनौतियाँ। हमारे देश में पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी दोनों मौजूद हैं। वे जो गरीबी रेखा से कम खर्च करने वाले गरीब माने जाते हैं। गरीबी के कई कारण हैं. गरीबी में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। बच्चे कुपोषण के शिकार हैं भारत में। बेरोजगारी गरीबी की मुख्य समस्या है। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं बेरोजगारी, जिनमें से एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम.

19.14. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. पूर्ण गरीबी को परिभाषित करें
2. गरीब किसे कहते हैं?
3. निम्न रोजगार क्या है?
4. तकनीकी बेरोजगारी कब होती है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. गरीबी के कोई दो परिणाम स्पष्ट कीजिए।

2. संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में लिखें।

3. गरीबी के मुख्य कारणों का विश्लेषण करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. आप कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी का संबंध गरीबी से है?

2. गरीबी उन्मूलन के लिए सरकारों द्वारा उठाए गए किसी भी कार्यक्रम के बारे में बताएं बेरोजगारी.

19.15. शब्दकोष

गरीबी रेखा - न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक आय का अनुमान जीवन की

उदारीकरण - सरकार द्वारा लगाई गई बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना विदेशी व्यापार और निवेश पर.

निजीकरण - सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी उद्यमों में स्थानांतरित करना

वैश्वीकरण - विदेश के कारण विभिन्न देशों का परस्पर जुड़ाव निवेश और विदेशी व्यापार

19.16. संदर्भ

1. तेलुगु अकादमी इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष

2. आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार

अध्याय

20

योजना एवं नीति आयोग

20.0 उद्देश्य

20.1 परिचय

20.2 योजनाओं की अवधारणा

20.3 योजनाओं का महत्व

20.4 योजनाओं के प्रकार

भारत में 20.5 पंचवर्षीय योजनाएँ

20.5.1 पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य

20.6 पंचवर्षीय योजनाएँ - सफलताएँ, असफलताएँ

20.6.1 उपलब्धियाँ

20.6.2 विफलताएँ

20.7 नीति आयोग

20.8. नीति आयोग की संस्थापक संरचना

20.9 नीति आयोग के उद्देश्य

20.10 नीति आयोग के कार्य

20.11 सारांश

20.12 मॉडल परीक्षा प्रश्न

20.13 शब्दावली

20.14 सन्दर्भ

20.0. उद्देश्य

• योजना के महत्व को पहचानें

• पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य बताइये

• योजनाओं में हुई प्रगति का मूल्यांकन करें

• योजनाओं को नीति आयोग से बदलने की आवश्यकता का विश्लेषण करें

• नीति आयोग के गठन और देश के विकास में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें।

20.1 परिचय

योजना का अर्थ है किसी उद्देश्य के साथ कार्य करना। व्यक्तिगत या राष्ट्रीय स्तर पर योजनाबद्ध तैयारी स्तर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। व्यक्ति का सामाजिक जीवन सदैव विभिन्न योजनाओं पर निर्भर रहता है योजनाएं. उसी प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन नीति निर्माताओं को एक मार्ग प्रदान करता है समाज में व्याप्त स्थितियों को सुधारना। यदि हैं तो यह प्रक्रिया अधूरी है कोई सकारात्मक परिणाम नहीं. स्वतंत्रता के बाद के विकासशील देश के रूप में, भारत को सुधार करने की आवश्यकता है लोगों के रोजगार के अवसर और आय। निवेश और विकास होना चाहिए पुनर्जीवित. वित्तीय क्षेत्र को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उस समय के हमारे नेताओं ने सोचा कि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध कराने और तेजी से लक्ष्य हासिल करने के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए देश का विकास ही सही दृष्टिकोण है. पंचवर्षीय योजनाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है हमारे देश के विकास में.

20.2 योजनाओं की अवधारणा

यदि संसाधन कम मात्रा में हों और बड़ी मात्रा में कल्याण प्रदान करना हो, योजना का क्रियान्वयन अति आवश्यक हो जाता है। प्रख्यात अर्थशास्त्री के अनुसार 'टोडारो' “विकास योजना एक केंद्रीय संस्था द्वारा सीधे और अंदर का एक प्रयास है कुछ मामले नियंत्रण, मुख्य आर्थिक चर (जीडीपी, खपत,) में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं किसी विशेष देश या क्षेत्र का निवेश, बचत, आदि)। आर्थिक सफलता नियोजन सरकार के प्रभाव, समर्थन और विनियमन पर निर्भर करता है। पहली बार गुन्नार मिर्डल (स्वीडन-अर्थशास्त्री) द्वारा प्रयुक्त वित्तीय नियोजन की अवधारणा।

नियोजन प्रक्रिया सरकार का आर्थिक उन्नति का प्रयास है

पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के साधनों के माध्यम से देश का विकास

एक निश्चित अवधि में. योजना बनाना और योजना का कार्यान्वयन करना दो अलग-अलग चीजें हैं। एक योजना

एक मुद्रित दस्तावेज़, एक ब्लूप्रिंट, एक वर्कशीट मॉडल है। योजना का कार्यान्वयन एक है

ब्लूप्रिंट के साथ-साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास भी।

20.3 योजनाओं का महत्व

योजना सभी प्रकार की वित्तीय समस्याओं के लिए रामबाण है। नियोजन के लाभ हैं...

किसी देश के आर्थिक विकास में योजना सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आर्थिक नियोजन एक नियोजित अर्थव्यवस्था की नीति का पालन करके आर्थिक विकास प्राप्त करने की एक रणनीति है।

देश के संसाधनों और धन का उपयोग देश की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

इस योजना से लोगों को नई नौकरी और रोजगार के साथ विकास में मदद मिलेगी
अवसर और जीवन स्तर में वृद्धि।

योजनाएँ बड़ी संख्या में लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।

यह देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करता है।

संसाधनों के उचित आवंटन से संतुलित क्षेत्रीय विकास होता है।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास दर ऊंची रहेगी.

एक नियोजित अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित परिवर्तन के अनुसार स्वयं को समायोजित करती है
अर्थव्यवस्था में स्थितियाँ. यह अर्थव्यवस्था को उतार-चढ़ाव से बचाता है
बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखते हुए व्यापार क्षेत्र।

सभी लोगों के लिए सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा
लोगों को समान अवसर प्रदान करना।

नियोजित अर्थव्यवस्था में संसाधनों की बर्बादी को रोका जाता है। संयमित रूप से प्रयोग किया जाता है

अधिक उत्पादन या कम उत्पादन से बचकर आर्थिक गतिविधियाँ बेहतर ढंग से प्रबंधित की जाती हैं
उत्पादन।

20.4 योजनाओं के प्रकार

वित्तीय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ क्रियान्वित हो रही हैं, आइये संक्षेप में जानते हैं जानिए कुछ महत्वपूर्ण के बारे में.

1. लोकतांत्रिक योजना - निरंकुश योजना: लोकतांत्रिक योजना में है उत्पादन के कारकों पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं। यह जनता की राय को महत्व देता है और जनता के लिए योगदान देता है। योजनाओं के लक्ष्य और उद्देश्य सभी उसी के अनुसार निर्धारित होते हैं जनता की राय के लिए. लोकतांत्रिक योजना में आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता होती है। निरंकुश या सत्तावादी योजना में सभी आर्थिक गतिविधियों का केंद्रीय नियंत्रण और निर्देशन शामिल होता है एक योजना के अनुसार. उपभोग, उत्पादन एवं वितरण सभी किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? नियोजन मशीनरी.

2. केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत योजना: निर्माण, अपनाना, योजना का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण केन्द्रीय योजना द्वारा किया जाता है अधिकार। नियोजन प्राधिकरण उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है। इस प्रकार के नियोजन का विस्तार शीर्ष स्तर से निचले स्तर तक होता है। विकेन्द्रीकृत योजना सबसे नीचे है-ऊपर। इसे केंद्रीय योजना प्राधिकरण द्वारा विभिन्न के परामर्श से तैयार किया जाता है देश की प्रशासनिक इकाइयाँ। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की योजना नीचे से ऊपर की ओर होती है, नीचे से शुरू करके ऊपर. इस योजना के तहत जिम्मेदारी स्थानीय और क्षेत्रीय की है अधिकारी जो योजना के बारे में वित्तीय निर्णय लेते हैं। यह एक बहुस्तरीय योजना है योजना के क्रियान्वयन के लिए एक से अधिक संगठन कार्य करते हैं।

3. परिप्रेक्ष्य योजना (परिप्रेक्ष्य योजना), वार्षिक योजना: इसका तात्पर्य है 15-20-25 साल की दीर्घकालिक योजना। 5 साल की योजनाओं के तहत अल्पकालिक योजनाओं को लागू किया जाता है एक निश्चित समयावधि के भीतर व्यापक उद्देश्यों को प्राप्त करना। यह दीर्घकालिक रूप से जारी रहता है योजना। प्रत्येक अल्पकालिक योजना को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वार्षिक योजनाओं में विभाजित किया गया है। वार्षिक बजट उनके उद्देश्यों और आवंटन के अनुसार लागू किए जाते हैं। सच्चाई में वार्षिक योजनाएँ वित्तीय नियोजन की सच्ची कार्यपत्रिकाएँ हैं

20.5 भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ

आजादी के बाद मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया घोषित के अनुसार भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा सलाहकार और विशेष निकाय सरकार का उद्देश्य कुशलतापूर्वक लोगों के जीवन स्तर को तेजी से ऊपर उठाना है देश के संसाधनों का उपयोग, उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसर सभी के लिए। योजना आयोग ने भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाएँ सुझाईं।

1951 से 2017 तक कुल 12 FYP लागू किए गए। पहली योजना शुरू हुई 1951-56 की अवधि के लिए, उसके बाद दूसरी योजना 1956-61 और तीसरी योजना 1961-67 के लिए क्रमश। लेकिन पाकिस्तान युद्ध और सूखे की स्थिति जैसे विभिन्न कारणों से योजना बना रहा है 1966-67 में अंतराल की घोषणा की गई। वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 में वार्षिक वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गईं. चौथी योजना इस योजना को 1969-74 की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। तब पाँचवीं योजना (1974-79), जिसने पार्टी में बदलाव के कारण अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं किया शक्ति। जनता सरकार सत्ता में आई और इस अवधि के लिए छठी योजना शुरू की 1978-83. 1980 में सरकार बदलने के साथ ही इस अवधि के लिए नई छठी योजना लागू की गई 1980-85 और 1985-90 की अवधि के लिए सातवीं योजना शुरू हुई। यद्यपि आठवीं योजना 1990 में शुरू हुई, अत्यावश्यकताओं के कारण, केवल 2 वार्षिक योजनाएँ फिर से लागू की गईं और 8वीं 1992-97 की अवधि के लिए योजना फिर से शुरू हुई। फिर बीच में 9वीं योजना लागू की गई 1997-2002, 2002-2007 के बीच 10वीं योजना, 2007-2012 के बीच 11वीं और 12वीं योजना थी 2012-17 के बीच लागू किया गया।

20.5.1 पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्य

प्रत्येक योजना कुछ मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आयोजित की जाती है। हालांकि वहां ऐसा है एक योजना से दूसरी योजना के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं में अंतर, उन सभी में कुछ दीर्घकालिकता होती है लक्ष्य। वे हैं

1) आर्थिक विकास
2) आत्मनिर्भरता
3) संतुलित क्षेत्रीय विकास
4) रोजगार के अवसरों का सृजन
5). आय असमानताओं में कमी 6) गरीबी उन्मूलन
7) आधुनिकीकरण
8) समावेशी व्यापक विकास और स्थिरता

तालिका-1: विभिन्न योजनाओं का मुख्य उद्देश्य (1951-2017)

क्र.सं. नहीं।	योजना अवधि	उद्देश्य
मैं	1951-56	कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास
द्वितीय	1956-61	भारी उद्योगों का विकास
तृतीय	1961-66	खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता
चतुर्थ	1969-74	सतत विकास, आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन
वी	1974-79	गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता
छठी	1980-85	लाभकारी रोजगार प्रदान करके गरीबी उन्मूलन,
सातवीं	1985-90	खाद्यान्न का उत्पादन, उत्पादकता में वृद्धि
आठवीं	1992-97	मानव संसाधन विकास
नौवीं	1997-2002	समानता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास
एक्स	2002-07	समानता, सामाजिक न्याय, मानव की गुणवत्ता में वृद्धि संसाधन
ग्यारहवीं	2007-12	व्यापक विकास,
बारहवीं	2012-17	स्थिरता के साथ समावेशी विकास

20.6 पंचवर्षीय योजनाएँ उपलब्धियाँ एवं विफलताएँ

भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी कर ली हैं। के दौरान मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए नियोजन अवधि. इसने कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। कुछ अन्य में, ऐसा हुआ आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिल पाती।

20.6.1 उपलब्धियाँ

मैं। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि: प्राथमिक उद्देश्यों में से एक भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना है। प्रत्यक्ष के रूप में आर्थिक नियोजन के परिणामस्वरूप, भारत की राष्ट्रीय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, हालाँकि नहीं जितनी तेजी से योजनाओं की भविष्यवाणी की गई थी। 1950 में राष्ट्रीय आय 2,24,786 करोड़ से बढ़ाई गई- 2011-12 की कीमतों पर 2017-18 में 51 से 139.52 करोड़। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गई इसी अवधि में 5,752 रुपये से 1,12,835 रुपये।

द्वितीय. कृषि क्षेत्र में प्रगति: सरकार ने औसतन 23 से

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में योजनागत व्यय का 24 प्रतिशत कृषि के विकास हेतु,

संबद्ध गतिविधियाँ और सिंचाई। इस योजना व्यय के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में कृषि

उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं

पानी, उर्वरक, कीटनाशक, संकर किस्म (HYV) बीज आदि की आपूर्ति का विस्तार करना

चयनित क्षेत्र. इस नई कृषि रणनीति के कारण हरित क्रांति हुई। यह सचमुच उत्कृष्ट है

चावल, गेहूँ और आलू उत्पादन में।

तृतीय. औद्योगिक प्रगति: कोयला, लोहा जैसे कुछ बुनियादी ढांचा उद्योगों में प्रगति

अयस्क, सीमेंट, उर्वरक, इस्पात, एल्यूमीनियम, पेट्रोलियम (कच्चा) और बिजली वास्तव में रही है

प्रभावशाली। धातुकर्म उद्योगों, रसायन और संबद्ध क्षेत्रों में भी प्रगति देखी गई

उद्योग. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1950-51 में 12.3 से बढ़कर 221.5 हो गया

2005-06 1950-51 की कीमतों पर। यह 4.6% वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है।

चतुर्थ. पूंजीगत वस्तुओं में आत्मनिर्भरता: भारत अब अपना अधिकांश औद्योगिक कार्य जारी रख सकता है

वृद्धि अर्थात कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों के लिए पूंजीगत वस्तुओं का घरेलू उत्पादन।

सीमेंट, रसायन, धातुकर्म ऊर्जा और परिवहन। इस क्षेत्र में आयात नगण्य है।

वी उपभोग्य सामग्रियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता: नियोजित वृद्धि के परिणामस्वरूप

अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में उत्पादन, प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत

आवश्यक उपभोग्य सामग्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। यह बढ़ोतरी कहीं ज्यादा होती

यदि जनसंख्या 2.1% प्रति वर्ष की दर से न बढ़ी हो या जनसंख्या वृद्धि न हुई हो

प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया गया था।

VI. बचत और निवेश में वृद्धि: प्रति व्यक्ति वृद्धि के बावजूद

इस अवधि के दौरान उपभोक्ता वस्तुओं की खपत, अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचत

सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 1950-51 में 8.9% से बढ़कर 2005-06 में 32.4% हो गया। सकल घरेलू पूंजी

गठन 8.7% से बढ़कर 33.8% हो गया।

सातवीं. आर्थिक बुनियादी ढांचे का विकास: एक और बड़ी उपलब्धि

महत्व आर्थिक बुनियादी ढांचे का निर्माण है जो नींव रखता है

औद्योगीकरण. सड़क परिवहन के विस्तार से बाज़ार का विस्तार हुआ। सिंचाई एवं ग्रामीण

विद्युतीकरण से कृषि को बढ़ावा मिला। जलविद्युत परियोजनाओं ने एक अवसर प्रदान किया है

औद्योगिक विस्तार के लिए.

आठवीं. आयात प्रतिस्थापन, निर्यात विविधीकरण: तेजी से उपलब्धि हासिल करने की नीति का पालन करना औद्योगीकरण से पूंजीगत वस्तुओं के लिए भारत की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई है। इसी प्रकार, पहले से आयातित उपभोक्ता वस्तुओं का अब बड़ी संख्या में उत्पादन किया जाता है घरेलू स्तर पर. इससे आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिला। नतीजतन, वस्तु संरचना भारत का निर्यात विनिर्माताओं, खनिज तेल और इंजीनियरिंग वस्तुओं के पक्ष में स्थानांतरित हो गया है।

नौवीं. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना प्रबंधकीय संवर्ग की एक और उपलब्धि है विकास योजना। इससे विदेशी विशेषज्ञों पर भारत की निर्भरता काफी कम हो गई है।

X. व्यापक शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता: सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारतीय योजना एक विशाल शिक्षा प्रणाली का विकास है - हमारे देश में है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन 1950-51 में 223 लाख से बढ़कर 2005-06 में 1283 हो गयी। 2011 तक साक्षरता में वृद्धि हुई थी से 74.04%।

तालिका-2: पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त विकास दर (1993-94 की कीमतों पर)

कारक कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद

क्र.सं. नहीं।	योजना	अपेक्षित विकास दर	हासिल
1	प्रथम पंचवर्षीय योजना	2.1	3.6
2	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	4.5	4.1
3	तीसरी पंचवर्षीय योजना	5.6	2.8
4	चौथी पंचवर्षीय योजना	5.7	3.3
5	पांचवी पंचवर्षीय योजना	4.4	4.8
6	छठी पंचवर्षीय योजना	5.2	5.7
7	सातवीं पंचवर्षीय योजना	5.0	6.0
8	आठवीं पंचवर्षीय योजना	5.6	6.8
9	नौवीं पंचवर्षीय योजना	6.5	5.4
10	दसवीं पंचवर्षीय योजना	8.0	7.5
11	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	9.0	8.3
12	बारहवीं पंचवर्षीय योजना	8.0	---

20.6.2 विफलताएँ

यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पंचवर्षीय योजनाओं ने हमारे देश को राह पर आगे बढ़ाया है विकास का लेकिन कुछ रुकावटें भी आई हैं। तय लक्ष्य दर नहीं है सभी योजनाओं में उपलब्धि हासिल की। कुछ उल्लेखनीय नुकसान.

1. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अपेक्षाकृत अधिक रहती है
2. बेरोजगारी बढ़ी. बेरोजगारी शहरी और ग्रामीण का मुख्य कारण है गरीबी
3. आय असमानता कम नहीं हुई है.
4. भूमि सुधार ठीक से लागू न होने के कारण भूमि वितरण असमान है।
5. क्षेत्रीय विकास में भी असमानताएँ हैं।

20.7. नीति आयोग

विकल्प के तौर पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया गया योजना आयोग को जो 64 वर्षों तक सेवा में था। नीति आयोग प्रमुख है भारत सरकार का नीति थिंक टैंक। राज्य के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद सरकारें, संबंधित संगठन, विशेषज्ञ और जनता, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक इसकी स्थापना का निर्णय लिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। संस्कृत भाषा में, 'नीति' शब्द नैतिकता व्यवहार एवं मार्गदर्शन को दर्शाता है। नीति आयोग की स्थापना की गई थी विकास प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण, दिशात्मक और रणनीतिक विचार प्रदान करें। नीति आयोग है एक सहकारी संघीय प्रणाली की ओर उन्मुख। देश की प्रगति में निभा रहे हैं अहम भूमिका यह प्रत्येक नीति पर राष्ट्रीय हितों, विशेषकर सुरक्षा चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करता है। सरकार के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने के अलावा भारत, नीति आयोग केंद्र, राज्यों और संघ को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है प्रदेश. इनका कार्यान्वयन सरकारों पर निर्भर है। नीति आयोग अब नहीं रहा योजना आयोग की तरह राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति। यह अब द्वारा किया गया है वित्त मंत्रित्व।

यह मुख्य नीति निर्धारण निकाय है जिससे अर्थव्यवस्था को गति देने की उम्मीद की जाती है देश का विकास. इसका लक्ष्य सक्रिय, मजबूत राज्यों का निर्माण करना है जो एक मजबूत राष्ट्र बनाने में मदद करें।

भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा. नीति आयोग ने मुख्य रूप से दो बनाये केंद्रों को "टीम इंडिया हब" और "नॉलेज एंड इनोवेशन हब" कहा जाता है।

1. टीम इंडिया: इससे भारतीय राज्यों की केंद्र के साथ साझेदारी होती है
   सरकार।
2. नॉलेज एंड इनोवेशन हब: यह थिंक टैंक क्षमताओं का निर्माण करता है
   संगठन।

20.8 नीति आयोग की स्थापना संरचना

नीति आयोग की संरचना में विभिन्न व्यक्ति शामिल हैं

एक। अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री.

बी। उपाध्यक्ष - प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है

सी। सदस्य; चार पूर्णकालिक सदस्य, दो अंशकालिक सदस्य (अग्रणी से)।
विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान)

डी। पदेन सदस्य: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के चार पदेन सदस्य,

ई. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (भारत सरकार के सचिव स्तर का)

एफ। गवर्निंग काउंसिल: एक परिषद जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं
और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल

जी। क्षेत्रीय परिषद; क्षेत्रीय परिषदें जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री और शामिल हैं
लेफ्टिनेंट गवर्नर एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं और आकस्मिकताओं को हल करने का प्रयास करते हैं। इस परिषद् का एक मुख्यमन्त्री कार्य करता है
अध्यक्ष।

एच। सचिवालय: केंद्रीय मंत्री, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रख्यात शिक्षाविद् हैं
सदस्य. नीति आयोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समर्थित है।

20.9 नीति आयोग के उद्देश्य

मैं। राष्ट्रीय प्राप्ति के लिए राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
उद्देश्य.

द्वितीय. यह आर्थिक के साथ-साथ प्राथमिकता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सलाह देता है

तृतीय. ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय रणनीतियाँ तैयार करने, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने और धीरे-धीरे सरकार के विभिन्न स्तरों पर इन्हें एकीकृत करने के लिए एक तंत्र विकसित करें।

चतुर्थ. समाज के विभिन्न वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें आर्थिक रूप से लाभ नहीं होता है आर्थिक सफलता

V. रणनीतिक और दीर्घकालिक नीति के लिए योजनाएँ बनाना, उनके विकास और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

VI. आर्थिक रणनीतियों एवं नीतियों में राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को महत्व देना।

सातवीं. किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उत्पादन को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना

आठवीं. अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय समस्या के लिए सम्मिलन अवसर प्रगतिशील एजेंडे में तेजी लाने का समाधान।

नौवीं. उन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का प्रभावी ढंग से परीक्षण और मूल्यांकन करना जिनके पास है सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन।

X. विकास प्रक्रिया में प्रवासी भारतीय नागरिकों की भागीदारी

XI. विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में प्रौद्योगिकी में सुधार। अच्छा प्रदान करना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर शासन।

बारहवीं. विकास प्रक्रिया में नागरिक भागीदारी बढ़ाना और प्रदान करना सभी के लिए अवसर.

20.10 नीति आयोग के कार्य

मैं। नीति आयोग का मुख्य कार्य सहकारी संघ की भावना को बढ़ावा देना है।

द्वितीय. राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में राज्यों को भागीदार बनाना। परशा।तैयारी करना एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर मात्रात्मक और गुणात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ समय की अवधि और उनके कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करना।

तृतीय. यह 'राष्ट्रीय एजेंडा' के निर्माण हेतु पर्याप्त समर्थन प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताएँ और रणनीतियाँ तथा उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा क्रियान्वित करना मंत्री और मुख्यमंत्री.

चतुर्थ. राज्यों को चुनौतियों से निपटने में मदद करना। नीति नियोजन बॉटम-अप मॉडल में डिज़ाइन किया गया है।

V. स्थानीय संस्थानों को मजबूत करना और ग्रामीण स्तर पर बेहतर योजना बनाना। यह विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करता है देश के भविष्य के हितों को ध्यान में रखते हुए.

VI. केंद्र और राज्य सरकारों के लिए आंतरिक परामर्श कार्य करता है

नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने का मामला।

सातवीं. यह केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों की मदद के लिए विशेषज्ञों के साथ डोमेन रणनीति तैयार करता है

वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए। स्वामित्व एवं तकनीकी का संवर्धन

विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान. यह सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है

और उन नीतियों की प्रभावशीलता का कार्यक्रम और मूल्यांकन करता है।

आठवीं. यह वैश्विक विशेषज्ञता और संसाधनों के दोहन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

नौवीं. नीति आयोग क्षमता और प्रौद्योगिकी बढ़ाएगा।

X. यह केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों की सहायता के लिए विशेषज्ञों के साथ रणनीति तैयार करता है।

20.11 सारांश

सामाजिक और आर्थिक नियोजन नीति निर्माताओं को सुधार करने का एक तरीका प्रदान करता है समाज में जो स्थितियाँ हैं। नियोजन प्रक्रिया सरकार का प्रयास है पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और उनके माध्यम से देश के आर्थिक विकास को बढ़ाना निश्चित अवधि में सिद्धि के साधन. विभिन्न प्रकार की योजनाएँ हैं। कुल 12 हमारे देश में 1951 से 2017 तक योजनाएं लागू की गईं।

योजना अवधि के दौरान हमारे देश ने मिश्रित परिणाम प्राप्त किये हैं। यह हासिल किया है कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता। कुछ अन्य में इसे उतनी सफलता नहीं मिली जितनी अपेक्षित।

के स्थान पर नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) का गठन किया गया योजना आयोग जो 64 वर्षों तक सेवा में था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं मंत्री और इसकी एक क्षेत्रीय परिषद है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हैं। मुख्य नीति आयोग का कार्य सहकारी संघ की भावना को बढ़ावा देना है। राज्य बनाना राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भागीदार। मात्रात्मक हासिल करने के लिए रणनीति तैयार करता है और समय की एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर गुणात्मक उद्देश्यों और उचित स्थापित करता है उनके कार्यान्वयन के लिए तंत्र.

20.12 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. योजना क्या है?
2. प्रथम योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई?
3. कौन सी पंचवर्षीय योजना दो बार शुरू की गई थी?
4. नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. योजनाओं का महत्व समझाइये
2. नीति आयोग की संगठनात्मक संरचना की व्याख्या करें।
3. योजनाओं के दीर्घकालिक लक्ष्य लिखिए।
4. योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग क्यों लाया गया?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से किसका समर्थन करते हैं?
2. नीति आयोग के मुख्य उद्देश्य लिखिए।
3. योजनाओं की उपलब्धियों एवं विफलताओं का संक्षेप में वर्णन करें।

20.13 शब्दावली

- NITI - नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग।
- योजना - योजना पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों और किसी दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के माध्यम से देश को विकसित करने के सरकार के प्रयासों की प्रक्रिया है।
  अवधि।

20.14 सन्दर्भ

1. भारतीय अर्थव्यवस्था 2022, मिश्रा और पुरी
2. तेलुगु अकादमी, इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष

अध्याय

21

कृषि क्षेत्र

21.0. उद्देश्य

21.1. परिचय

21.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं विकास

21.2. कृषि में कम उत्पादकता

21.2.1. भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

21.3. भारत में भूमि सुधार

21.3.1. भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी उपाय

21.4. भारत में हरित क्रांति और अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव

21.4.1. हरित क्रांति का प्रभाव

21.5. कृषि ऋण और ग्रामीण ऋणग्रस्तता

21.6. भारत में कृषि विपणन

21.6.1. कृषि विपणन में दोषों को रोकने के उपाय

21.7. भारत में कृषि मूल्य नीति

21.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

21.9. शब्दकोष

21.10. संदर्भ

21.0. उद्देश्य

कृषि के महत्व को समझें

कृषि में कम उत्पादकता के कारण बताइये

भूमि सुधारों पर चर्चा करें

हरित क्रांति के प्रभाव पर चर्चा करें

भारतीय किसानों की समस्याओं का विश्लेषण करें

21.1 परिचय

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह लोगों की जीवन शैली का एक हिस्सा है और भारत में संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रत्यक्ष और प्रदान करता है यह कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है तथा भोजन एवं चारा उपलब्ध कराता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 1. कृषि क्षेत्र 2. औद्योगिक क्षेत्र 3. सेवा क्षेत्र।

इस इकाई में आइए कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों यानी प्राथमिकता के बारे में जानें कृषि क्षेत्र का, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का विकास, निम्न के कारण उत्पादकता, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय, भूमि सुधार, हरित क्रांति, इसका प्रभाव, कृषि ऋण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि विपणन, मूल्य निर्धारण नीति, भारत की खाद्य सुरक्षा आदि।

21.1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व एवं विकास

विकसित और विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र बुनियादी आवश्यकताएँ प्रदान करता है जैसे कि खाद्य और गैर-खाद्य उत्पाद जैसे औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल। कृषि उत्पादों की आपूर्ति औद्योगिक क्षेत्र को की जाती है और यह टिकाऊपन में योगदान देता है विकास। दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि का 3% भारत में है और है गेहूं, फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में मछली. भारत का कृषि क्षेत्र दुनिया की 17% आबादी का भरण-पोषण करता है। सभी उपरोक्त आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है कारक.

1. राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा

प्रथम विश्व युद्ध के समय राष्ट्रीय आय का दो तिहाई हिस्सा कृषि से आता था क्षेत्र। प्रारंभ के बाद द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के विकास के साथ भारत में योजनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा घट गया। में 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 56.5% था, जो घटकर 19% रह गया। 2015-16 में और 2017-18 में 17.4%। एक अर्थशास्त्री कॉलिन क्लार्क का मानना है कि एक देश के रूप में विकसित राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट एक संकेतक है संरचनात्मक परिवर्तन का. केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 2% कृषि क्षेत्र से आता है।

2. रोजगार सृजन में कृषि की हिस्सेदारी

जैसा कि गांधी जी ने कहा था, भारत गांवों का एक समूह है। 1951 में, 83% जनसंख्या रहती थी गाँवों में, जबकि 17% शहरों में रहते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का 68% 32% गाँवों में और 32% शहरों में रहते थे। कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या. 1951 में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता 72% थी और यह 2010 और 2020 में क्रमशः 52% और 42% था। हालाँकि, कृषि क्षेत्र प्रदान करता है आज भी ज्यादा लोगों को रोजगार. द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र सक्षम नहीं हैं निरंतर विकास की कमी के कारण बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न होता है। अत: जनसंख्या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर दबाव अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार कम है और गरीब हैं बेरोजगारी.

3. उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना

कृषि उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध कराती है। चीनी, जूट, कपड़ा उद्योग, सिगरेट उद्योग, आटा मिलें, बाग-बगीचे और खाद्य विनिर्माण उद्योग निर्भर हैं कृषि। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग कृषि क्षेत्र पर निर्भर हैं उनके लिए आवश्यक कच्चे माल के लिए.

4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान

भारत के विदेशी व्यापार में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह निर्यात करता रहा है प्राचीन काल से भारत के कृषि उत्पाद। मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी, कोक, तम्बाकू, सूती वस्त्र, कपड़ा, कच्चा ऊन, खनिज तेल आदि सामान विदेशों में निर्यात किया जा रहा है देशों. भारत कृषि निर्यात के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्रदान करता है।

5. औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजारों का विस्तार

लोग अपनी आय का उपयोग भोजन के लिए करते हैं जबकि अतिरिक्त आय विभिन्न प्रकार की खरीदारी पर खर्च करते हैं
औद्योगिक उत्पाद जैसे कपड़े, फर्नीचर, सिलाई मशीनें, गैस स्टोव, टीवी, फ्रिज,
आदि जिससे औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार तैयार हो सके।

6. भोजन एवं चारे की आपूर्ति

मनुष्य की बुनियादी जरूरतें भोजन, कपड़ा, मकान आदि हैं। भोजन सबसे महत्वपूर्ण है
के सभी। यह कृषि क्षेत्र से उपलब्ध है। यदि हम भोजन न करें तो यह असंभव हो जाता है
हमारे जीने के लिए. यह पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराता है। इसीलिए कृषि मानी जाती है
निर्वाह क्षेत्र.

7. आर्थिक नियोजन एवं आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र की भूमिका

कृषि क्षेत्र भारत में बैंकिंग प्रणाली का समर्थन करता है। आंतरिक व्यापार मुख्यतः किसके कारण होता है?
कृषि उत्पादों। की भूमिका के बारे में 10वीं पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कृषि क्षेत्र आर्थिक हितों को बढ़ावा देने में "कृषि का एक स्रोत है।"
देश में तेजी से आर्थिक विकास ”।

21.2 कृषि में कम उत्पादकता

1950-51 से 2012-13 की अवधि के दौरान कई फसलों की पैदावार धीरे-धीरे बढ़ी है
और धीरे-धीरे. कृषि क्षेत्र में वास्तविक उत्पादकता का स्तर बहुत कम है
अन्य देशों की तुलना में या संभावित उपज की तुलना में। गेहूं की उत्पादकता
यूके की तुलना में भारत की हिस्सेदारी 48% और चीन की तुलना में 64% है। भारत में चावल की उत्पादकता 53% है
चीन का और अमेरिका का 43% उत्पादन। इसी का परिणाम है कि भारत की उत्पादकता बहुत अधिक है
कम।

कृषि में कम उत्पादकता के कारण

भारत में कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के कई कारण हैं।

वे हैं 1. सामान्य कारण 2. संगठनात्मक कारण 3. तकनीकी कारण।

1.सामान्य कारण

i) सामाजिक वातावरण: ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक वातावरण एक बाधा है
कृषि का विकास. भारतीय किसान अनपढ़ हैं. वे अंधविश्वासों का पालन करते हैं और
पुरानी परंपराएँ. वे नई कृषि पद्धतियों को शीघ्रता से नहीं देखते और उनका पालन नहीं करते।

ii) भूमि पर जनसंख्या का दबाव: जनसंख्या का भारी दबाव निम्न का मुख्य कारण है
भारतीय कृषि की उत्पादकता. भूमि जोतों का विभाजन एवं विघटन हो सकता है
इसका कुछ हद तक ज़मीनी स्तर पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी जिम्मेदार है। यह है
कम लाभदायक लेकिन भूमि जोत की उत्पादकता कम है।

iii) मिट्टी की उर्वरता में गिरावट: देश में 329 मिलियन हेक्टेयर भूमि में से आधी
मिट्टी की उर्वरता कम हो गई, जिससे कृषि में उत्पादकता कम हो गई।

2. संगठनात्मक कारण

i) भूमि स्वामित्व प्रणाली: क्षमता और इच्छा का दोहन करने की प्रणाली
किसानों को उत्पादन बढ़ाने की तथा उत्पादकता कम करने की व्यवस्था की गई है
शोषण. किरायेदारी कानून, किरायेदारी की सुरक्षा, और भूमि के अधिकार
किरायेदारों ने किरायेदारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं किया है, और में
ऐसी स्थिति में उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकती।

ii) भूमि जोत का आकार: भारत में भूमि जोत का औसत आकार बहुत छोटा है। 2010 में-
11. 85% भूमि जोत 2 एकड़ से कम थी। खेती की वैज्ञानिक विधि
इन जोतों में उन्नत औजार, बीज आदि की व्यवस्था संभव नहीं है। कृषि उपज है
गैर-लाभकारी भूमि जोत के कारण भी कम है।

iii) पूंजी की कमी: यह कृषि क्षेत्र की एक और समस्या है। पर्याप्त का अभाव
किसानों के लिए ऋण सुविधाएं भी कम उत्पादकता का कारण बनती हैं। किरायेदारों के पास कोई नहीं है
भूमि उधार लेने और गिरवी रखने के लिए है और इसलिए किरायेदार ऋण का लाभ नहीं उठा सकता है।

3. तकनीकी कारण

i) पारंपरिक कृषि उपकरण: भारत में किसान पारंपरिक तरीकों और उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं
खेती में और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग करने में कोई जागरूकता नहीं। प्राप्यता
आधुनिक उत्पादों की मात्रा न केवल सीमित है बल्कि उनकी लागत भी अधिक है। किसान नहीं
उन्हें खरीदने की शक्ति है और इसलिए उत्पादकता कम है।

ii) सिंचाई सुविधाओं की कमी: उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई
सुविधा। 2010-11 में, भारत में कुल फसल क्षेत्र 199 मिलियन हेक्टेयर था और केवल 89 मिलियन हेक्टेयर
मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित की गई। यानी फसलों के अंतर्गत आने वाले 45% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है
सुविधा। इसलिए, उन सभी क्षेत्रों में उत्पादकता कम है जो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं
या सिंचाई सुविधा.

iii) पर्यावरणीय समस्याएँ: बाढ़, जंगलों की कमी, भूजल की कमी,

सूखा, ग्लोबल वार्मिंग, खुराक से अधिक उर्वरकों का उपयोग, भूमि, जल और वायु प्रदूषण हैं

कृषि में कम उत्पादकता में भी योगदान दे रहा है।

21.2.1 भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपाय

कम उत्पादकता की समस्या से संस्थागत, तकनीकी, सामाजिक और सामाजिक तौर पर निपटना होगा

आर्थिक रूप से.

i) संस्थागत उपाय: भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, सीमित सुविधाएं प्रदान करना,

कृषि अवसंरचना, विपणन, भंडारण गोदाम, संचार, आदि चाहिए

किया जाए.

ii) बेहतर उपकरण: बीज, उर्वरक, कीट नियंत्रण दवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

सिंचाई, विद्युत ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति आदि उत्पादकता में योगदान देंगे।

iii) किसानों के लिए रिटर्न में सुधार: समर्थन मूल्य बढ़ाना, आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना

सब्सिडी, फसलों के लिए बीमा सुविधाएं प्रदान करना, भूमि पर जनसंख्या दबाव को कम करना

गैर-कृषि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। स्वामित्व अवधारणाओं को प्रस्तुत करने जैसे उपाय

कृषि में भी पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता है।

iv) कुशल प्रबंधन: भूमि और जल का व्यापक और कुशल प्रबंधन

मिट्टी की उर्वरता में गिरावट को रोकने और क्षति को कम करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है

भूमि। किसानों को अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

मृदा परीक्षण, मृदा संरक्षण एवं निराकरण के लिए बेहतर कृषि अनुसंधान की आवश्यकता है

कृषि में हुई क्षति। क्षेत्रवार कृषि-जलवायु योजनाएँ उचित तरीके से होनी चाहिए।

21.3 भारत में भूमि सुधार

भारत की स्वतंत्रता के समय भूमि कुछ ही लोगों के हाथों में केन्द्रित थी।

जमींदारों को भूमि की उत्पादकता बढ़ाने में कोई रुचि नहीं थी। कृषि

उत्पादकता उत्पादों को उगाने की क्षमता से कम थी और इसकी अनुमति भी नहीं थी

सामाजिक न्याय। "भूमि सुधार" वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सीधे हस्तक्षेप करती है

कृषि क्षेत्र में और कृषि संरचना में परिवर्तन लाता है। अनुसार

यूएनओ की परिभाषा के अनुसार, "भूमि सुधार एक भूमि पुनर्वितरण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है

छोटे, सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करना।

भूमि सुधार के उद्देश्य: 1951 में योजना आयोग ने लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की
भूमि सुधार इस प्रकार हैं।

1. किरायेदारों को मकान मालिकों के शोषण से बचाना।

3. कृषि के विकास में बाधक सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करना।

4. जोतने वालों को भूमि का अधिकार प्रदान करना।

5. भूमि सुधार कार्यक्रम चलाकर कृषि उत्पादकता बढ़ाना।

6. सीमित भूमि संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग।

7. वास्तव में सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना
भूमि पर खेती करना.

8. सामाजिक एवं सभी प्रकार के शोषण को दूर कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना
कृषि क्षेत्र में अन्याय.

21.3.1 भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी उपाय

भारत सरकार ने आजादी के बाद कई कदम उठाए हैं
नये समाज की स्थापना और कृषि उपज की वृद्धि। प्रमुख घटक
भूमि सुधारों में शामिल हैं 1. बिचौलियों को हटाना 2. किरायेदारी सुधार 3. भूमि पर सीमाबंदी
जोत.

1. बिचौलियों को हटाना: ब्रिटिश काल में बड़ी मात्रा में बिचौलियों को हटाया गया
जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारों जैसे बिचौलियों के नियंत्रण में भूमि जोत
आदि जो कृषकों से लगान वसूल करते थे। आजादी के बाद बिचौलिए
कानून द्वारा हटा दिए गए और भूमि कृषकों को सौंप दी गई। इस प्रकार, कृषक
शोषण से बचाया गया। इनामदार व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। का निष्कासन
बिचौलियों ने अपने कब्जे वाली भूमि को कृषकों को हस्तांतरित करने में मदद की।

2. किरायेदारी सुधार: भूमि को एक निश्चित अवधि के लिए भूस्वामी से किराये पर लिया जाता है
इस शर्त पर कि किरायेदार किराया चुकाएगा। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं
किरायेदारों को मकान मालिकों से बचाने के लिए कदम।

क) किराए की मात्रा को विनियमित करना: किरायेदारों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए,
सरकार ने किरायेदारी की मात्रा को विनियमित किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक
लगान की सीमा कुल उत्पादन का केवल 1/4 अथवा 1/5 थी। "किरायेदार संरक्षण अधिनियम"
हैदराबाद राज्य में बल ने किरायेदारों की बेदखली की संभावना को समाप्त कर दिया
उन्हें मालिक से जमीन खरीदने का अधिकार।

ख) किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान करना: विभिन्न राज्य सरकारों ने किरायेदारों को सुरक्षा प्रदान की है किरायेदारों की बार-बार बर्खास्तगी के बिना कानून।

i) मकान मालिक अपने किरायेदारों को नहीं हटा सकते।

ii) जमींदार केवल स्वयं खेती के उद्देश्य से किरायेदार से जमीन ले सकते हैं।

iii) मकान मालिक को जमीन का एक हिस्सा किरायेदार के कब्जे में रखना होगा
स्वयं की कृषि हेतु भूमि लेने का समय।

ग) स्वामित्व अधिकार: कुछ राज्य सरकारों ने अधिकार देने के लिए कानून बनाए हैं किरायेदार. यह उपाय सराहनीय है लेकिन प्राप्त परिणाम बहुत संतोषजनक नहीं हैं।

3. भूमि जोत की अधिकतम सीमा

"भूमि की अधिकतम सीमा" वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक परिवार कानून के अनुसार निर्णय लेता है किसी परिवार के स्वामित्व या कब्जे में कितनी जमीन हो सकती है।
सरकार सीमा से अधिक भूमि का अधिग्रहण करती है और उसे भूमिहीन किसान परिवारों को वितरित करती है और सीमांत किसान। 1960 के दशक से विभिन्न क्षेत्रों में भूमि हदबंदी कानून लागू किये गये हैं राज्य. रिश्तेदारों के नाम पर जमीन के हस्तांतरण पर नियंत्रण में सरकार विफल रही (बेनामी) और अन्य।

4. जोतों का एकीकरण: भारत में छोटी जोतों का विखंडन सबसे अधिक है सामान्य। ये अलाभकारी जोतें बेहतर कृषि पद्धतियों के पक्ष में नहीं थीं। में छोटी जोतों के विखंडन की समस्या को हल करने के लिए पंजाब सरकार, हरियाणा और महाराष्ट्र ने जोत समेकन में कुछ राहत दी। कई में राज्यों का कहना है, लामबंदी धीमी थी क्योंकि किसानों ने सहयोग नहीं किया कार्यक्रम.

5. सहकारी कृषि: किसी क्षेत्र में किसान अपनी छोटी-छोटी जोतों को मिलाकर एक कृषि क्षेत्र बनाते हैं सहकारी फार्म. बड़े पैमाने पर क्षेत्र प्रबंधन की बचत समर्थन के साथ उपलब्ध है सरकार के। की कमी के कारण बड़े किसानों की भूमिका काफी हद तक असफल रही है अप्रभावी प्रशासनिक मशीनरी और वितरण के संतुलित तरीके का अभाव उत्पादन, क्योंकि "सभी का काम किसी का काम नहीं है"।

भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत आशाजनक ढंग से शुरू किये गये हैं। हालांकि व्याप्त निराशा के कारण हुई प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। निम्नलिखित कार्यान्वयन में विफलताओं के मुख्य कारण हैं।

1. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव.

2. न्यायालयों का हस्तक्षेप

3. सटीक, संशोधित भूमि रिकॉर्ड का अभाव।

4. भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक मशीनरी की कमी और उदासीनता।

5. हाशिए पर रहने वाले वर्गों को वितरित भूमि का हस्तांतरण।

6. जमींदारों के विरोध के कारण जमींदार अपनी जमीनों को बेनामी नामों से बचा रहे हैं और कानूनों के कार्यान्वयन में देरी।

7. भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में वित्तीय सहायता का अभाव है भूमि का वितरण.

8. निचले स्तर (जमीनी स्तर) वर्गों से दबाव का अभाव।

इस प्रकार, उपरोक्त कारणों से भारत में भूमि सुधार आशा के अनुरूप सफल नहीं हो पाये हैं।

21.4 भारत में हरित क्रांति

1960 के दशक के मध्य में, वैश्विक कृषि क्षेत्र ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी थी। उच्च पैदावार चावल और गेहूं की फसलों की उच्च उपज देने वाली किस्मों के विश्वव्यापी उपयोग से यह संभव हुआ मेक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और उनके अनुयायियों द्वारा विकसित। नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में वर्णित। 1966 के ख़रीफ़ सीज़न से, हमारे देश में पहली बार हरित क्रांति लागू हुई। प्राप्ति की प्रक्रिया रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग से खाद्यान्नों में अधिक पैदावार (HYVs) और जल सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना "हरित क्रांति" के रूप में जाना जाता है।

हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम एस. गैंड ने किया था। एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत की हरित क्रांति के जनक.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति का प्रभाव: हरित क्रांति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है भारत का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ। खाद्यान्न की खेती के अंतर्गत भूमि का आकार है बढ़ा हुआ। हमारे देश के कृषि क्षेत्र पर हरित क्रांति का प्रभाव बताया जा सकता है निम्नलिखित नुसार।

1. खाद्यान्न उत्पादों में वृद्धि: चावल, गेहूं, में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। HYV प्रौद्योगिकी को अपनाकर मक्का और ज्वार उत्पाद। चावल का उत्पादन 106.29 तक पहुंच गया 1960-61 में 35 मिलियन टन से बढ़कर 2013-14 में मिलियन टन। गेहूँ का उत्पादन भी पहुँच गया 1960-61 में 11.1 मिलियन टन से बढ़कर 2013-14 में 95.85 मिलियन टन हो गया।

2. रोजगार: हरित क्रांति ने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है

कृषि क्षेत्र में बहुफसलों को बढ़ावा देना। रोजगार के अवसर हैं

खाद्य प्रसंस्करण, HYV बीज, रासायनिक पैकेजों के कारण वृद्धि हुई।

3. आय में वृद्धि: हरित क्रांति के प्रभाव से आय में वृद्धि हुई है

पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात और हिमाचल राज्यों में किसान महत्वपूर्ण हैं

प्रदेश. कृषि-सहयोगी एवं कृषि-आधारित उद्योगों के विस्तार से रोजगार में वृद्धि हुई है

अवसर और साथ ही लोगों की आय।

4. निर्यात में वृद्धि: कृषि और उससे जुड़े उत्पादों का लगभग रु. का निर्यात किया गया

1960-61 में 284 करोड़ रु. 2013-14 तक इन निर्यातों का मूल्य 2,57,590 रुपये तक पहुंच गया था

करोड़, जिससे विदेशी मुद्रा उत्पन्न होती है। निर्यात और आयात नीति में परिवर्तन

(EXIM POLICY) ने WTO नियमों के अनुरूप महत्वपूर्ण योगदान दिया है

हमारे देश के कृषि क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि।

5. व्यावसायिक फसलों में वृद्धि: खाद्य फसलों के उत्पादन के साथ-साथ का प्रभाव

हरित क्रांति से गन्ने और कपास जैसी फसलों की पैदावार में वृद्धि हुई, जिससे बदलाव आया

फसलों का पैटर्न.

21.4.1 हरित क्रांति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1. आय असमानताएं बढ़ी हैं।
2. क्षेत्रीय मतभेद बढ़ गए हैं.
3. हरित क्रांति खाद्य फसलों तक ही सीमित थी। में कोई बदलाव नहीं आया है
   तिलहन का उत्पादन.
4. यह कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित था।
5. आधुनिक तरीकों का प्रयोग बढ़ा और श्रमिकों की नौकरियाँ चली गईं।
6. रसायन और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग का प्रभाव केवल मनुष्य पर ही नहीं पड़ा है
   स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण भी.
7. हरित क्रांति के कारण छोटे और सीमांत किसानों को गंभीर नुकसान हुआ है।
8. कृषि ने कॉरपोरेट कंपनियों का दामन पकड़ लिया है.

21.5 कृषि ऋण एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता

किसान कृषि कार्यों, उर्वरकों, कीटनाशकों, मजदूरों, भूमि के लिए ऋण लेते हैं विकास कार्य, बीज, चारा और मवेशियों की खरीद। कृषि ऋण मुख्यत: का है तीन प्रकार.

अल्पावधि ऋण: ये ऋण बीज, मवेशी और चारा खरीदने के लिए दिए जाते हैं और इनकी अवधि होती है 15 महीने से कम.

मध्यावधि ऋण: कृषि भूमि को समतल करने, मवेशियों की खरीद, खरीद के लिए ऋण कृषि उपकरण. इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है।

दीर्घकालिक ऋण: कृषि भूमि की अतिरिक्त खरीद, महंगी मशीनरी की खरीद, पुराने बकाया की अदायगी के लिए दिए गए ऋण। कार्यकाल 5 वर्ष से 20 वर्ष तक है।

कृषि ऋण के स्रोत: किसानों के लिए उपलब्ध कृषि ऋण स्रोत भारत को दो भागों में बाँटा जा सकता है। 1. संस्थागत ऋण स्रोत 2. गैर-संस्थागत क्रेडिट स्रोत.

1. संस्थागत ऋण स्रोत

एक। सरकार: सूखे और बाढ़ की स्थिति में सरकार मामूली दर पर ऋण देती है ब्याज की दर। इन्हें "तक्कवी" ऋण कहा जाता है।

बी। सहकारी ऋण समितियाँ: हमारे देश में इस प्रणाली की स्थापना 1904 में की गई थी किसानों को कम ब्याज दर पर समय पर आवश्यक ऋण प्रदान करें। प्राथमिक ग्राम स्तर पर कृषि ऋण समितियाँ, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCEB) जिला स्तर पर और राज्य सहकारी बैंक (SCB) राज्य स्तर पर थे स्थापित। वे अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।

सी। वाणिज्यिक बैंक: ये किसानों को ऋण देने के मामले में चरम पर हैं। सरकार और निजी बैंकों ने मिलकर 2013 तक 71.2% संस्थागत ऋण प्रदान किए।

डी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक: श्री एम. नरसिम्हा समिति की सिफारिशों के अनुसार, 2 अक्टूबर, 1975 को 05 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई, जो 10.5% प्रदान करते थे। वर्ष 2012-13 तक कुल ऋण

इ। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड): यह था

राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष दर्जा प्राप्त शिखर बैंक के रूप में जुलाई, 1982 में स्थापित किया गया,

ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए संस्थाएँ और पंचायती राज संस्थाएँ।

2. गैर-संस्थागत ऋण

किसान बिना गारंटी के ऋण के लिए जल्दी और निकट के ऋण स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं
दस्तावेज़. 1. साहूकार 2. व्यवसायी और कमीशन एजेंट 3. जमींदार 4.
रिश्तेदार और दोस्त अहम भूमिका निभाते हैं. इन ऋणों पर ब्याज दर अधिक होती है।
किसान इस ऋण प्रणाली में धोखाधड़ी, शोषण के कारण पीड़ित होते हैं।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता के कारण: इसमें वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वे हैं

1. खेती की लागत बहुत बढ़ गई है.
2. फसलों का समर्थन मूल्य अपर्याप्त है।
3. माता-पिता से विरासत में मिला ऋण।
4. अनुत्पादक कार्यों पर खर्च करना।
5. ऋण लेने और भूमि विकास कार्य करने की खोज।
6. गरीबी, बचत का निम्न स्तर, फसल का नुकसान।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के कदम: भारी निर्भरता से इसे कुछ हद तक रोका जा सकता है
असंगठित ऋणों पर, फसलों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाना, संस्थागत ऋण का विस्तार,
साहूकारों के खतरे पर अंकुश लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में सुधार करना,
और कुटीर एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देना।

21.6 भारत में कृषि विपणन

कृषि विपणन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संयोजन, भंडारण, प्रसंस्करण,
विभिन्न कृषि वस्तुओं का परिवहन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और वितरण
देश भर में।

भारत में कृषि विपणन के दोष: गोदाम सुविधाओं की कमी के कारण, 10%
कृषि उत्पादन का 20% उत्पादित कृन्तकों और कीड़ों द्वारा खाया जाता है। नियत के अभाव
पर्याप्त परिवहन सुविधाओं के कारण, किसानों को बेचने पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है

उनकी उपज स्थानीय बाजारों, कमीशन एजेंटों और साहूकारों के पास जाती है। किसानों को मिल रहा है

बिचौलियों के कारण बहुत कम आय और फसलों का समर्थन मूल्य न मिलना।

सही माप-तौल नहीं होने से किसान ठगे जा रहे हैं। तौलना

शुल्क, माल उतारने का शुल्क, उपज को परिष्कृत करने का शुल्क, कटौती

किसानों को देय धनराशि आदि में कटौती कर धोखाधड़ी की जा रही है

किसान. सुधार के कारण, वे अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने में सक्षम नहीं हैं

बाजार में सभी किसानों के लिए कीमत की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

2.1.6.1 भारत में कृषि विपणन में दोषों को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय

विनियमित बाज़ार: किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए विनियमित बाज़ारों की स्थापना की गई है

कृषि विपणन में अस्वास्थ्यकर स्थितियों को दूर करना। इनके कार्य ये हैं

किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, कीमतों में अंतर को कम करना

उत्पादक से उपभोक्ता तक माल, व्यापारियों की धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और

बिचौलिए.

वर्गीकरण और मानकीकरण: सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं

कृषि उपज की ग्रेडिंग और मानकीकरण। इसने कई ग्रेडिंग स्टेशन स्थापित किए हैं

कृषि उपज श्रेणीकरण विपणन अधिनियम, 1937 के अनुसार एगमार्क मुद्रित किया जा रहा है

बाज़ार का और विस्तार करने के लिए कृषि विपणन विभाग द्वारा वर्गीकृत वस्तुओं पर

सामान के लिये।

भंडारण सुविधाएं: गांवों और कस्बों में गोदाम सुविधाओं का विस्तार किया गया है

ताकि किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकें और समर्थन मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके भाग के रूप में,

सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 1957 में हुई थी। भारतीय खाद्य निगम

राष्ट्रीय स्तर पर (FCI) की स्थापना वर्ष 1965 में वेयरहाउस कॉर्पोरेशन थे

विभिन्न राज्यों में भी स्थापित।

बाज़ार सूचना: सरकार ने सूचना प्रसारित करने के लिए कई कदम उठाए हैं

किसानों को विभिन्न बाजारों में कृषि वस्तुओं की कीमतों पर। सूचना

आकाशवाणी अभियानों के माध्यम से प्रतिदिन किसानों तक इन कीमतों से संबंधित जानकारी पहुंचाई जाती है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन बाजार मूल्यों पर साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने 26.05.2015 को किसान चैनल लॉन्च किया।

समर्थन मूल्य: सरकार विभिन्न के लिए "न्यूनतम समर्थन मूल्य" की घोषणा करती है वस्तुओं को ताकि किसानों को कृषि विपणन में लाभकारी मूल्य मिल सके। इन कीमतों की घोषणा सरकार द्वारा लागत और कीमतों की सिफारिशों के अनुसार की जाती है कृषि वस्तु आयोग।

अन्य कार्रवाइयां: बैंकों और बीज कंपनियों के साथ जुड़ना, रायथू बाज़ारों को बढ़ावा देना इस तरह से कदम उठाएं कि बाजारों में वजन और माप का उपयोग विनियमित हो, ताकि वृद्धि हो सके ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भण्डारण की सुविधा।

21.7भारत में कृषि मूल्य नीति

कीमतें एक ओर मांग की शक्तियों और दूसरी ओर आपूर्ति के कार्य द्वारा निर्धारित होती हैं दूसरे पर बल डालता है. आजादी से पहले भी, कृषि मूल्य निर्धारण नीतियां और संबद्ध नीतियां भारत में तैयार किए गए और प्रमुख खाद्यान्नों का वितरण और खरीद शुरू की गई और वैधानिक अधिकतम कीमतें भी तय की गईं। 1960 के दशक के मध्य में, कृषि मूल्य निर्धारण नीति भारत में कीमतों में कमी के कारण भोजन की कमी को देखते हुए इसे पेश किया गया था सूखा और कृषि मूल्य निर्धारण नीति तीन कारकों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी।

मैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

द्वितीय. नई प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

iii. कृषि उपज का स्वीकार्य मूल्य देना।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई वर्ष 1965 और एसोसिएशन को "कृषि लागत और मूल्य" के रूप में जाना जाता है समिति” मार्च 1985 से। सरकार ने इसे लागू करने के लिए दो संस्थान स्थापित किए हैं मूल्य निर्धारण नीतियां।

1. कृषि मूल्य संघ (1965), 2. भारतीय खाद्य निगम (1965) (एफसीआई)।

न्यूनतम समर्थन मूल्य: सरकार प्रमुख न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कृषि व्यय के आधार पर गेहूं, चावल और मक्का जैसे कृषि उत्पाद और हर साल मूल्य समिति द्वारा सुझाव दिए जाते हैं, जिससे किसानों को यह सुनिश्चित होता है सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया।

खरीद मूल्य: सरकार कुछ कृषि वस्तुओं के लिए बढ़िया कीमतें तय करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे अनाज, चीनी, चावल, आदि को उचित मूल्य पर सरकारों द्वारा उठाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्य निर्धारण प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

बफ़र स्टॉक: बफ़र स्टॉक एक रिज़र्व है जिसका उपयोग मूल्य में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए किया जाता है

अप्रत्याशित आपातस्थितियाँ. खाद्य निगम द्वारा भण्डारित कुछ खाद्यान्न

भारत सरकार द्वारा भारत को "बफर स्टॉक" कहा जाता है।

कृषि मूल्य नीति में सुधार हेतु सुझाव:

1. कृषि मूल्य निर्धारण नीति किसानों के लिए लाभकारी होनी चाहिए।
2. बिचौलियों एवं दलालों की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सुधार
   कृषि विपणन पद्धतियों को प्राप्त किया जा सकता है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उच्च दक्षता एवं पारदर्शिता होनी चाहिए।
4. कपास निगम, जूट निगम आदि उच्च एजेंसियाँ स्थापित की जानी चाहिए
   ऊपर।
5. मूल्य निर्धारण नीति को सभी कृषि उत्पादों तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

खाद्य सुरक्षा: अंग्रेजों के समय पड़े अकाल के कारण बहुत से लोग भूख से मर गये

अवधि। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने 1965 में FCI की स्थापना की

राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उद्देश्य। यह प्रदान करेगा

लोगों को खाद्य सुरक्षा. बफर स्टॉक से सूखे पर काबू पाया और भुखमरी को रोका

मौतें।

21.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दीजिए।

1. हरित क्रांति
2. कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य
4. खाद्य सुरक्षा

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. भारत में कृषि ऋण स्रोतों के बारे में लिखें।
2. कृषि मूल्य नीति के बारे में लिखें।
3. कृषि में कम उत्पादकता के कारणों की व्याख्या करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को स्पष्ट कीजिए।
2. कृषि में कम उत्पादकता के कारण क्या हैं और बढ़ाने के उपाय क्या हैं?

   उत्पादकता?
3. हरित क्रांति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें।
4. कृषि विपणन में क्या खामियाँ हैं और दोषों को कम करने के उपाय क्या हैं?

21.9. शब्दकोष

भूमि सुधार: भूमि सुधार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार सीधे हस्तक्षेप करती है
कृषि क्षेत्रों में और कृषि संरचना में परिवर्तन लाता है।

हरित क्रांति: रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग करके और जल संरक्षण सुविधाएं प्रदान करके खाद्यान्नों में उच्च पैदावार प्राप्त करने की प्रक्रिया है
"हरित क्रांति" के नाम से जाना जाता है।

विनियमित बाज़ार: किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए विनियमित बाज़ारों की स्थापना की गई है
कृषि विपणन में अस्वास्थ्यकर स्थितियों को दूर करना।

न्यूनतम समर्थन मूल्य: यह निश्चित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है
कृषि उत्पाद, जिस पर उत्पाद सीधे किसानों से खरीदे जाएंगे
खुले बाज़ार की कीमतें लागत से कम हैं। किसानों को पूर्व घोषित भुगतान किया जाता है
उनकी फसलों की कीमत.

बफ़र स्टॉक: बफ़र स्टॉक समाप्त करने के उद्देश्य से स्टॉक, बिक्री और खरीद को संदर्भित करता है
कीमत में उतार-चढ़ाव. भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारित खाद्यान्नों में से कुछ हैं
"बफर स्टॉक" कहा जाता है।

21.10 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था: वीके मिश्रा और एसके पुरी
2. भारतीय अर्थव्यवस्था: दत्त और सुंदरम
3. भारत आर्थिकव्यवस्थ समास्यालु मारियु सावल्लु: तेलुगु अकादमी
4. भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण।

अध्याय

22

औद्योगिक क्षेत्र

22.0 परिचय

22.1 औद्योगिक क्षेत्र

22.2 उद्योगों की संरचना अथवा उद्योगों के प्रकार

22.3 भारत में औद्योगिक विकास

22.4 औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियाँ

22.5 भारत में औद्योगिक नीति संकल्प

22.5.1 औद्योगिक नीति संकल्प 1948

22.5.2 औद्योगिक नीति संकल्प 1956

22.5.3 औद्योगिक नीति संकल्प 1977

22.5.4 औद्योगिक नीति संकल्प 1980

22.5.5 औद्योगिक नीति वक्तव्य 1991

22.6 लघु उद्योग

22.6.1 भारत में लघु उद्योगों की भूमिका और महत्व

22.6.2 लघु उद्योगों के सामने आने वाली समस्याएँ

22.6.3 लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान के उपाय

22.7 औद्योगिक वित्त

22.7.1 भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक वित्त संस्थान

22.8 सारांश

22.9 मॉडल परीक्षा प्रश्न

22.10 शब्दावली

22.11 सन्दर्भ

22.0 परिचय

भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योगदान दिया

इसकी समग्र वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण रूप से। भारत में औद्योगिक क्षेत्र विविध है

और इसमें विनिर्माण, खनन, निर्माण, ऊर्जा, सहित विभिन्न उद्योग शामिल हैं।

और बुनियादी ढाँचा। इस अध्याय में हम भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे

विशेषताएँ, वृद्धि और विकास।

22.1 औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में फर्में शामिल हैं

और पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के निर्माण में काम करने वाली कंपनियां जिनका उपयोग किया जाता है

अन्य वस्तुओं का उत्पादन करना। उद्योग का तात्पर्य उत्पादन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों से है

माल की। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिए, कृषि आधारित उद्योग एक भूमिका निभाते हैं

हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका।

22.2 उद्योगों की संरचना अथवा उद्योगों के प्रकार

1) बड़े उद्योग: इनमें निवेश 10 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच होता है
उद्योग.

2) मेगा इंडस्ट्रीज: निवेश सीमा 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

3) कुटीर उद्योग: ये असंगठित घरेलू उद्योग हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं
लघु उद्योग की श्रेणी.

4) सहायक उद्योग: ये उद्योग बड़े उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट का निर्माण करते हैं। उनका
निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक न हो.

5) छोटे उद्योग: संयंत्र और मशीनरी में निवेश की सीमा 25 लाख रुपये है।

6) घरेलू उद्योग: ये उद्योग कारीगरों, कुशल कारीगरों और तकनीशियनों द्वारा चलाए जाते हैं
3000 वर्ग फुट से कम जगह, 1 किलोवाट से कम बिजली और 5 से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता नहीं है।
ये उद्योग कोई प्रदूषण नहीं फैलाते।

भारत सरकार ने जून, 2020 में सूक्ष्म, लघु और की परिभाषाओं को संशोधित किया

निवेश और टर्नओवर के आधार पर मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।

1) सूक्ष्म उद्यम: इन उद्योगों में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है
और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक न हो.

2) लघु उद्यम: छोटे संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश
उद्यम 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

3) मध्यम उद्यम: संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश नहीं होता है
50 करोड़ रुपये से अधिक और टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

उद्योगों को प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है:

कृषि आधारित: कपास, ऊनी, जूट, रेशमी वस्त्र, रबर और चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य
तेल आदि

खनिज आधारित: लोहा और इस्पात, सीमेंट, एल्यूमीनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल।

उनकी मुख्य भूमिका के अनुसार उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

बुनियादी या प्रमुख उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में अपने उत्पादों की आपूर्ति करते हैं
अन्य वस्तुओं का निर्माण करना जैसे लोहा और इस्पात, तांबा, एल्युमीनियम गलाना, आदि।

उपभोक्ता उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए सामान का उत्पादन करते हैं - चीनी,
टूथपेस्ट, कागज, सौंदर्य प्रसाधन आदि।

मध्यवर्ती वस्तुएँ: मध्यवर्ती वस्तुएँ वे उत्पाद हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं या सेवाओं की उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है।
वे अंतिम उपभोक्ता उत्पाद नहीं हैं बल्कि आगे की प्रक्रिया से गुजरते हैं जैसे रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद, प्लास्टिक आदि।

22.3 भारत में औद्योगिक विकास

भारत में पहले आधुनिक उद्योग कपास, जूट, कोयला खदानें और रेलवे थे। पाने के बाद से
1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के बाद, भारत ने महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुभव का अनुभव किया
विकास। जबकि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी
सरकार ने औद्योगीकरण और आर्थिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियां अपनाईं
विकास। इसमें रक्षा, परिवहन और संचार, बिजली, खनन और अन्य शामिल थे

ऐसी परियोजनाएँ जिन्हें करने की शक्ति केवल सरकार के पास थी और जो आवश्यक भी थी
निजी उद्योग फले-फूले। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था नीति में कुछ क्षेत्रों को आरक्षित रखा गया
सरकार के लिए, जबकि अन्य निजी क्षेत्र के लिए खुले थे। लेकिन उसके भीतर, सरकार
अपनी लाइसेंसिंग नीति के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हों।

भारत में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय औद्योगिक वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में मंदी के बावजूद भी।
आर्थिक चुनौतियाँ और उतार-चढ़ाव। औद्योगिक विकास भारत का एक महत्वपूर्ण घटक है
आर्थिक विकास और देश को इनमें से एक में बदलने में योगदान दिया है
विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ।

हालाँकि, 1990 के दशक से सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। निजी
कंपनियों, विशेषकर विदेशी फर्मों को पहले से आरक्षित क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है
दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बिजली आदि सहित सरकार के लिए अब लाइसेंस नहीं हैं
उद्योगों को खोलने की आवश्यकता है।

भारत का विनिर्माण क्षेत्र दुनिया में सबसे प्रमुख में से एक है। इसमें एक विस्तृत शामिल है
कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना जैसे उद्योगों की श्रृंखला
प्रौद्योगिकी, इस्पात, रसायन और मशीनरी। सरकार ने कई लागू किये हैं
व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए सुधार
क्षेत्र।

भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में भारी निवेश कर रही है
सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली उत्पादन। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है
पूरे देश में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में सुधार करके। भारत ने SEZ की स्थापना की है
कर प्रोत्साहन, बेहतर बुनियादी ढाँचा और सरलीकरण प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना
इन क्षेत्रों के भीतर काम करने वाले व्यवसायों के लिए नियम। ये संकल्प अक्सर
यह एक रणनीतिक रोडमैप के रूप में कार्य करता है, जो औद्योगिक विकास, निवेश और नियामक का मार्गदर्शन करता है
कार्रवाई.

मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू की गई है, इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक में बदलना है
घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करके वैश्विक विनिर्माण केंद्र
देश के भीतर विनिर्माण परिचालन। स्टार्ट-अप इंडिया पहल 2016, पहल पर ध्यान केंद्रित
उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और विभिन्न प्रोत्साहनों के साथ स्टार्ट-अप को सरल बनाने पर
विनियम, और फंडिंग और मेंटरशिप तक पहुंच प्रदान करना।

22.4 औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतियाँ

बुनियादी ढाँचे की कमी: भारत का औद्योगिक विकास अपर्याप्तता के कारण बाधित है
आधारभूत संरचना।

कुशल श्रमिकों की कमी: बड़ी आबादी होने के बावजूद भी काफी कमी है
भारत की श्रम शक्ति में कौशल अंतर। कई उद्योग कुशल श्रमिकों को खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

वित्त तक पहुंच: औद्योगिक क्षेत्र में छोटे और मध्यम आकार के उद्यम (एसएमई)।
इस क्षेत्र को अक्सर पर्याप्त और किफायती वित्तपोषण विकल्पों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अकुशल कराधान प्रणाली: भारत की कर संरचना जटिल और बार-बार होने वाली हो सकती है
कर नीतियों में बदलाव व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकता है।

वैश्विक बाज़ारों से प्रतिस्पर्धा: बढ़ते वैश्वीकरण के साथ, भारतीय उद्योग
न केवल घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा
बाज़ार.

डिजिटल परिवर्तन: कई भारतीय उद्योग अभी भी डिजिटल को अपनाने में पीछे हैं
प्रौद्योगिकियों का पूर्ण उपयोग किया है।

22.5 भारत में औद्योगिक नीति संकल्प:

उद्योग नीति संकल्प सरकारों या संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज या घोषणाएं हैं जो किसी देश या क्षेत्र के भीतर विशिष्ट उद्योगों के विकास के लिए रूपरेखा और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करते हैं।

22.5.1 औद्योगिक नीति संकल्प 1948

आज़ादी के बाद यह भारत की पहली व्यापक औद्योगिक नीति थी। इस पर जोर दिया गया
औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व और इसकी नींव रखी
अर्थव्यवस्था का नियोजित विकास.

1948 की औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं:

इस नीति ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी, जिसमें निम्नलिखित तत्व सम्मिलित थे
सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र।

नीति में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया
और आर्थिक आत्मनिर्भरता. प्रमुख उद्योग, जैसे लोहा और इस्पात, भारी मशीनरी,
बिजली उत्पादन और परिवहन राज्य के स्वामित्व के लिए आरक्षित थे।

सरकार ने निजी उद्योगों को विनियमित करने के लिए एक लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की।

नीति ने कुटीर और लघु उद्योगों के महत्व को पहचाना

ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास.

इस नीति में श्रमिक कल्याण और श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान शामिल थे।

22.5.2 औद्योगिक नीति संकल्प 1956

इस प्रस्ताव का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास पर ध्यान केंद्रित करके समाजवाद को बढ़ावा देना और आर्थिक असमानताओं को कम करना था। सरकार ने प्रमुख उद्योगों की पहचान की जो विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित होंगे।

संकल्प में इस पर जोर दिया गया:

भारी और मशीन-निर्माण उद्योगों का विकास;

सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार;

एक बड़े और बढ़ते सहकारी क्षेत्र की स्थापना; और

निजी क्षेत्र में स्वामित्व एवं प्रबंधन के प्रसार को प्रोत्साहन।

22.5.3 औद्योगिक नीति संकल्प 1977

इस नीति ने संख्या को कम करते हुए अधिक मिश्रित अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिह्नित किया
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

22.5.4 औद्योगिक नीति संकल्प 1980

1980 का प्रस्ताव विशेषकर लघु उद्योगों के विकास पर केंद्रित था
ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और क्षेत्रीयता को कम करने के लिए
असंतुलन.

22.5.5 औद्योगिक नीति वक्तव्य 1991

यह नीति भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर में से एक है। एलपीजी
भारत में सुधारों का तात्पर्य आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण से है
1991 में लागू किए गए उपाय। ये सुधार भारत सरकार द्वारा किए गए थे
तत्कालीन प्रधान मंत्री पीवी नरसिम्हाराव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में,
गंभीर भुगतान संतुलन संकट को दूर करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, जो
ठहराव और उच्च राजकोषीय घाटे का सामना कर रहा था। इसने उदारीकरण के लिए सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की
अर्थव्यवस्था, व्यापार बाधाओं को दूर करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और विभिन्न क्षेत्रों को खोलना
निजी खिलाड़ियों के लिए.

1991 की नई औद्योगिक नीति की मुख्य विशेषताएं:

उदारीकरण: इस नीति का उद्देश्य सरकारी नियंत्रण और हस्तक्षेप को कम करना है
औद्योगिक क्षेत्र में अधिक बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

डी-लाइसेंसिंग: सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं से संबंधित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता को दूर करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली में काफी ढील दी गई थी।

एमआरटीपी अधिनियम का उन्मूलन: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएँ
(एमआरटीपी) अधिनियम, जिसने बड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया था, निरस्त कर दिया गया।

विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन: इस नीति का उद्देश्य उन्नत लोगों को आकर्षित करना है
प्रौद्योगिकी और घरेलू उद्योगों में तकनीकी उन्नयन को बढ़ावा देना
विदेशी प्रौद्योगिकी समझौतों की अनुमति देना।

लघु उद्योगों पर ध्यान: नीति ने रोजगार पैदा करने और संतुलित क्षेत्रीय विकास में लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता दी।

एफडीआई: नीति ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित किया और अनुमति दी
बहुराष्ट्रीय निगम विशिष्ट क्षेत्रों के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करेंगे
कुछ क्षेत्रों में नियम और प्रतिबंध।

1991 की नई औद्योगिक नीति या "नई आर्थिक नीति" या "उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण" (एलपीजी) सुधारों का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

नई आर्थिक नीति के कुछ सकारात्मक प्रभाव:

इसने त्वरित आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार किया।

विदेशी निवेश बढ़ा.

नए उद्योगों का उदय और मौजूदा उद्योगों का विस्तार, रोजगार सृजन
अवसर और बेरोजगारी दर कम करना।

निर्यात-उन्मुख उद्योगों में जबरदस्त वृद्धि देखी गई

आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों में वृद्धि से गरीबी कम करने में मदद मिली
दरें।

जीवन स्तर में वृद्धि हुई है

कुछ नकारात्मक प्रभाव:

उन क्षेत्रों में बेरोज़गारी और नौकरी की हानि जो परिवर्तन के अनुकूल नहीं बन सके

आर्थिक परिदृश्य.

बढ़ी हुई आय असमानता

क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ीं।

पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि

22.6 लघु उद्योग

भारत में लघु उद्योग की विशेषताएँ

स्वामित्व: आम तौर पर, ऐसे व्यवसाय एकल स्वामित्व वाले होते हैं या, कुछ मामलों में,

साझेदारी.

प्रबंधन: आम तौर पर, प्रबंधन और नियंत्रण दोनों मालिक के पास होते हैं/

मालिक. इसलिए मालिक दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होता है

व्यापार।

श्रम गहन: प्रौद्योगिकी पर निर्भरता सीमित है। इसलिए वे अधिक उपयोग करते हैं

उनकी उत्पादन गतिविधियों के लिए श्रम और जनशक्ति।

लचीलापन और अनुकूलनशीलता: बड़े पैमाने के उद्योगों, लघु उद्योगों की तुलना में

आम तौर पर अधिक लचीले होते हैं और बदलती बाजार स्थितियों के लिए जल्दी से अनुकूल हो सकते हैं

ग्राहक की मांग.

स्थानीयकृत संचालन: ये उद्योग आम तौर पर स्थानीयकृत होते हैं और संचालित होते हैं

विशिष्ट क्षेत्र या समुदाय.

कम पूंजी निवेश: उन्हें आम तौर पर कम पूंजी की आवश्यकता होती है

बड़े उद्योगों की तुलना में.

22.6.1 भारत में लघु उद्योगों की भूमिका और महत्व

भारत एक जीवंत और विविध लघु उद्योग क्षेत्र का घर है। ये उद्योग एक भूमिका निभाते हैं

क्षेत्रीय रोजगार सृजन में योगदान देकर देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

विकास, और निर्यात आय। यहां लघु-स्तरीय उद्योगों की कुछ प्रमुख भूमिकाएँ दी गई हैं

भारत:

रोजगार सृजन: लघु उद्योग श्रम प्रधान और रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं

विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर।

क्षेत्रीय विकास: लघु उद्योग प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं

पिछड़े क्षेत्र, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

सकल घरेलू उत्पाद में योगदान: लघु उद्योग महत्वपूर्ण योगदान देते हैं

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)।

नवाचार और उद्यमिता: लघु उद्योग नवाचार को बढ़ावा देते हैं और

उद्यमिता की भावना।

गरीबी उन्मूलन: लघु उद्योग गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

जमीनी स्तर पर लोगों के लिए आय-सृजन गतिविधियाँ बनाकर।

निर्यात प्रोत्साहन: भारत में कुछ लघु उद्योग, विशेष रूप से हस्तशिल्प, कपड़ा और अन्य पारंपरिक शिल्प में लगे उद्योगों में निर्यात क्षमता है।

स्थानीय संसाधनों का उपयोग: लघु उद्योग स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं

संसाधन और कच्चे माल, जो सतत विकास में योगदान दे सकते हैं।

बड़े उद्योगों को सहायता: लघु उद्योग अक्सर सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं,

बड़े उद्योगों को कच्चे माल, घटकों और सेवाओं की आपूर्ति करना।

22.6.2 लघु उद्योगों के सामने आने वाली समस्याएँ

वित्त तक पहुंच का अभाव: छोटे पैमाने के उद्योग अक्सर पर्याप्त धन जुटाने के लिए संघर्ष करते हैं

बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन और ऋण सुविधाएं।

बुनियादी ढाँचे में रुकावटें: अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जैसे कि ख़राब

परिवहन, अविश्वसनीय बिजली आपूर्ति और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच बाधा उत्पन्न कर सकती है

लघु उद्योगों की वृद्धि और उत्पादकता।

बाज़ार में प्रतिस्पर्धा: बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है

छोटे पैमाने के उद्योगों को बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए।

कच्चा माल: इन इकाइयों को उपलब्धता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है

अपर्याप्त मात्रा, खराब गुणवत्ता और यहां तक कि कच्चे माल की आपूर्ति भी नियमित नहीं है
आधार.

समग्र प्रबंधन: अपर्याप्त प्रबंधन कौशल व्यवसाय के विस्तार में बाधा डालते हैं

और अक्सर लघु उद्योगों की गैर-प्रतिस्पर्धीता का कारण बनता है।

22.6.3 लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान के उपाय

वित्तीय सहायता: सरकार ने कई वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है

लघु एवं कुटीर उद्योगों को उचित दर पर ऋण देने के लिए संस्थाएँ

ब्याज की दर।

कच्चे माल तक पहुंच: उचित मूल्य पर कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करें

कीमतें.

कौशल विकास और प्रशिक्षण: कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करें और

कार्यबल की तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।

कच्चे माल का समान आवंटन: छोटी, बुनियादी औद्योगिक इकाइयों को होना चाहिए

आवश्यक, लेकिन दुर्लभ, कच्चे के आवंटन की विधि में प्राथमिकता की पर्याप्त डिग्री

सामग्री, आयातित घटक और उपकरण।

बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ: सरकार को उचित बुनियादी सुविधाओं, यानी परिवहन, बिजली, जल आपूर्ति, वित्त, आदि के साथ

लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक संपदा विकसित करनी चाहिए।

निर्यात प्रोत्साहन: लघु उद्योगों को निर्यात में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें

निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रशिक्षण, और प्रदान करके गतिविधियाँ

वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच को सुगम बनाना।

इन उपायों को लागू करके भारत सरकार और विभिन्न हितधारक मदद कर सकते हैं
लघु उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करना, उनके विकास को बढ़ावा देना और
देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देना।

22.7 औद्योगिक वित्त

भारत में औद्योगिक वित्त का तात्पर्य देश में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि और विकास को समर्थन देने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और तंत्रों से है। यह निवेश को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में औद्योगिक वित्त के कुछ प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

बैंक वित्तपोषण: बैंक भारत में औद्योगिक वित्त का प्राथमिक स्रोत हैं।
वे उद्योगों को ऋण, कार्यशील पूंजी और सावधि वित्त प्रदान करते हैं। औद्योगिक
उधारकर्ता विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी बैंकों आदि से ऋण प्राप्त कर सकते हैं
भारत में कार्यरत विदेशी बैंक।

अनौपचारिक ऋण: एक स्रोत, मात्रात्मक रूप से बड़ा महत्व, की बचत है
इकाई ही. यह घर, व्यवसाय या सरकार हो सकता है।

शेयर बाज़ार: इक्विटी पूंजी बाज़ार भी वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
भारत में उद्योग.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) वित्तपोषण: एमएसएमई
भारत के औद्योगिक परिदृश्य में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार
और वित्तीय संस्थान विशेष वित्तपोषण योजनाएँ और ऋण सुविधाएँ प्रदान करते हैं
एमएसएमई वृद्धि और विकास का समर्थन करना।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई): भारत सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करता है
अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश। विदेशी कंपनियाँ भारत में निवेश कर सकती हैं
स्वचालित या सरकारी मार्ग के माध्यम से, क्षेत्र-विशिष्ट नियमों के अधीन।

सार्वजनिक जमा: इस प्रणाली के तहत, लोग अपना पैसा जमा के रूप में रखते हैं
इन कंपनियों या प्रबंध प्राधिकारियों को छह महीने, एक वर्ष, दो की अवधि के लिए
वर्ष, तीन वर्ष या उससे अधिक।

22.7.1 भारत में महत्वपूर्ण औद्योगिक वित्त संस्थान

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई)

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई)

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM बैंक)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

22.8 सारांश

भारत में द्वितीयक क्षेत्र का तात्पर्य औद्योगिक और विनिर्माण गतिविधियों से है
देश की अर्थव्यवस्था. यह समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार सृजन और निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। द्वितीयक
इस क्षेत्र को पुरानी प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे की बाधाओं, नौकरशाही जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है
बाधाएँ, और श्रम संबंधी मुद्दे।

22.9 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4-5 वाक्यों में दीजिए।

1) प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें

2) औद्योगिक नीति संकल्प 1948:

3) एलपीजी मॉडल को परिभाषित करें

4) एमआरटीपी अधिनियम की व्याख्या करें।

5) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

द्वितीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 8-10 वाक्यों में दीजिए।

1) औद्योगिक वित्त से क्या तात्पर्य है?

2) एमएसएमई को समझाइये।

3) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

4) भारतीय अर्थव्यवस्था पर नई आर्थिक नीति 1991 के प्रभाव का वर्णन करें।

5) भारत में लघु उद्योगों की विशेषताओं की व्याख्या करें

6) लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान के उपाय सुझायें

तृतीय. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 16-20 वाक्यों में दीजिए।

1) भारतीय उद्योगों की संरचना की व्याख्या करें

2) नई औद्योगिक नीति संकल्प, 1991 का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

3) भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की भूमिका का वर्णन करें।

4) भारत में औद्योगिक वित्त की व्याख्या करें।

22.10 शब्दावली

औद्योगिक क्षेत्र: उद्योग द्वितीयक गतिविधि का हिस्सा हैं।

एमएसएमई: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

उदारीकरण: उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई राज्य कुछ पर से प्रतिबंध हटा देता है निजी व्यक्तिगत गतिविधियाँ

निजीकरण: सरकार से स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसाय का हस्तांतरण

निजी क्षेत्र को निजीकरण कहा जाता है

वैश्वीकरण: वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने पर केंद्रित है

वैश्विक अर्थव्यवस्था।

एमआरटीपी अधिनियम: एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं (एमआरटीपी) अधिनियम, जिसने बड़े व्यवसायों पर प्रतिबंध लगाया था, निरस्त कर दिया गया

22.11 सन्दर्भ

1. तेलुगु अकादमी से इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक।
2. तेलुगु अकादमी से इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक।
3. वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रम अर्थशास्त्र (318), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान।
4. तेलुगु अकादमी से बीए भारतीय अर्थव्यवस्था
5. https://commerce.gov.in/

अध्याय 23 तृतीयक क्षेत्र (सेवा क्षेत्र)

23.0 उद्देश्य

23.1 परिचय

23.2 भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका

23.3 हमारे देश में तृतीयक क्षेत्र की प्राथमिकता

23.4 भारत में बुनियादी ढाँचा क्षेत्र का विकास

23.5 भारत में परिवहन क्षेत्र

23.6 ऊर्जा क्षेत्र

23.7 सूचना क्षेत्र

23.8 सूचना प्रौद्योगिकी

23.9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

23.10 बैंकिंग क्षेत्र

23.11 पर्यटन

23.12 सारांश

23.13 मॉडल परीक्षा प्रश्न

23.14 शब्दावली

23.15 सन्दर्भ

23.0 उद्देश्य

जानिए आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व.

सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी का विश्लेषण करें।

भारत में परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में जानें।

आर्थिक विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को जानें।

आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों का आकलन करें।

23.1 परिचय

अर्थव्यवस्थाओं में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तीसरा क्षेत्र या सेवा क्षेत्र है। यह क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और अधिकतम कार्यबल के एक बड़े प्रतिशत को रोजगार देता है सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का हिस्सा। तृतीयक क्षेत्र आवश्यक प्रदान करता है प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के उत्पादन के लिए बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ। कृषि, संबद्ध क्षेत्र, उद्योग, खनन, परिवहन, सूचना और भंडारण विपणन, ऋण, बैंकिंग और बीमा सुविधाओं की आवश्यकता है। ये सभी सुविधाएं और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं तृतीयक क्षेत्र द्वारा. इसलिए तृतीयक क्षेत्र को "सेवा क्षेत्र" भी कहा जाता है।

प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों का विकास किसके विकास पर निर्भर करता है? सेवा क्षेत्र. सेवा क्षेत्र विकास के लिए अनेक सुविधाएँ एवं सेवाएँ प्रदान करता है कृषि और औद्योगिक क्षेत्र जैसे: 1. व्यवसाय 2. आतिथ्य सेवाएँ 3. परिवहन (रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन) 4. सूचना, भंडारण, रियल एस्टेट व्यवसाय 5. बैंकिंग, और बीमा सेवाएँ 6. वाणिज्यिक सेवाएँ, आईटी सेवाएँ, परामर्श सेवाएँ 7. सार्वजनिक प्रशासन, पुलिस, रक्षा और न्यायपालिका 8. स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता 9. एनएसएसओ 63वें दौर 2006-07 के सर्वेक्षण में व्यक्तिगत, घरेलू सेवाओं, वित्तीय के उपयोग का उल्लेख किया गया संस्थान, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), माइक्रोफाइनेंस संस्थान और वाणिज्यिक वाहन सेवा क्षेत्र में वस्तुओं के रूप में।

23.2 भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका

विकसित तृतीयक क्षेत्र तीव्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। की आपूर्ति बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे से विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी पूंजी सृजन की दर में वृद्धि. यदि अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ता है, तो

जीडीपी रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। सेवाओं का हिस्सा

2020-21 तक अमेरिका में सेक्टर 53.89%, यूके में 72%, जर्मनी में 71% और भारत में 72% है।

जापान. 2020-21 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 80.1% है। 2020-21 में,

भारत में सेवा क्षेत्र विकसित देशों से भी अधिक है। हालाँकि, सेवाएँ

यह क्षेत्र हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ी हिस्सेदारी रखता है।

हमारे देश में तृतीयक क्षेत्र के विकास ने हरित क्रांति में योगदान दिया है,

औद्योगीकरण और शहरीकरण.

23.3 भारत में तृतीयक क्षेत्र की प्राथमिकता

निम्नलिखित आर्थिक आंकड़े सेवा क्षेत्र के महत्व को दर्शाते हैं, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है। वे हैं: 1. सेवा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत, और 2. राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा, 3. सेवा क्षेत्र में निवेश, 4. सेवा क्षेत्र का निर्यात।

1. सेवा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत: श्रमिकों की संख्या

सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या 1991 में 179 लाख से बढ़कर 193 लाख हो गई है

2020. कुल कार्यबल में सेवा क्षेत्र के श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है

1950-51 में 17.3% से 2020 में 32.3% हो गया।

2. राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा: राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का हिस्सा

आय 1950-51 में 29% से बढ़कर 2020-21 में 61% हो गई। की औसत वृद्धि दर

1950-51 से 1990-91 तक चार दशकों में सेवा क्षेत्र 4.9% से बढ़ गया

2004-05 से 2020-21 तक 10.6%।

3. सेवा क्षेत्र में निवेश: पंचवर्षीय योजनाओं में सेवा क्षेत्र के विकास को अधिकतम प्राथमिकता दी गई। ऊर्जा, परिवहन और सूचना क्षेत्रों को कुल योजना आवंटन का 55% से 65% आवंटित किया गया था। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सेवा क्षेत्र में सार्वजनिक, निजी और निवेश में 9% की वृद्धि हुई।

4. सेवा क्षेत्र निर्यात: हमारे निर्यात के कारण आर्थिक क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन

विकास। निर्यात में कृषि उत्पादों और खनिजों की हिस्सेदारी में कमी आई है और

सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। तकनीकी परामर्श का निर्यात

सेवाएँ, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, परियोजना मूल्यांकन (अवलोकन) और विज्ञान अनुसंधान हैं

की बढ़ती। इन सेवाओं के आयात से लेकर निर्यात तक के स्तर पर यह क्षेत्र विकसित हुआ है

उन्हें विकसित देशों के लिए. देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। तीसरा क्षेत्र निर्यात आय

2004-05 में 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2020-2021 में 497.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

21.4 भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास

प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों का विकास किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है?

बुनियादी सुविधाएं. बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और विस्तार होगा

अधिकतम आर्थिक विकास दर को सक्षम करना और तीव्र आर्थिक विकास में योगदान देना।

बुनियादी ढाँचा दो प्रकार के होते हैं: 1. वित्तीय बुनियादी ढाँचा 2. सामाजिक बुनियादी ढाँचा।

1. आर्थिक बुनियादी ढांचे में शामिल हैं (ए) सिंचाई और बाढ़ की रोकथाम, (बी) ऊर्जा क्षेत्र, कोयला, तेल, बिजली, (सी) परिवहन क्षेत्र - सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन, (डी) संचार - फ़ोन, टेलीग्राम, दूरसंचार, (ई) वित्तीय सेवाएँ- बैंकिंग, बीमा, (एफ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र.

2. सामाजिक बुनियादी ढांचे में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि शामिल हैं जो इसकी रीढ़ हैं अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढाँचा। बुनियादी ढांचे का विकास एक सतत प्रक्रिया है भारी निवेश और श्रम। में अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता एवं विस्तार हमारा देश शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं हो रहा है. इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत धीमा है। रोजगार के अवसर इन क्षेत्रों में उत्पादन बहुत धीमा और कम होता है।

तालिका: बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता (मिलियन टन में)

आधारभूत संरचना	1950-51 1999-2000 2020-21		
1. कोयला	32	322	598
2. बिजली	5	481	886
3. पेट्रोल और तेल	0.4	32	20
4. स्टील	1.0	27	78
5. सीमेंट	3	100	235
6. रेलवे का माल	73	456	1021
7. समुद्र तटीय परिवहन	19	272	576
8. टेलीफोन कनेक्शन NA		5	1036

स्रोत: भारत का आर्थिक सर्वेक्षण: 2021; # अरब टन को दर्शाता है

तालिका के अनुसार, कोयला उत्पादन 1950-51 में 32 मिलियन टन से बढ़कर 598 मिलियन टन हो गया।
1999-2000 में सीमेंट उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 235 मिलियन टन हो गया
2020-21. इसी प्रकार, रेलवे का माल 1950-51 में 73 मिलियन टन से बढ़कर 1021 हो गया।
2020-21 में मिलियन टन। भारत देश में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ
प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे।

23.5 भारत में परिवहन क्षेत्र

परिवहन क्षेत्र एक बुनियादी ढांचागत सुविधा है जो आर्थिक गतिविधियों के उपयोग और उत्पादन के वितरण को सुविधाजनक बनाती है। परिवहन सुविधाएं लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। परिवहन प्रणाली कृषि क्षेत्र और उद्योग इनपुट प्रदान करते हैं और निर्मित उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाते हैं। परिवहन क्षेत्र देश के पहाड़ी क्षेत्र, जंगल और पिछड़े क्षेत्र हैं। यह क्षेत्रों, नदी तटों और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है। दुनिया के सभी देशों के बीच जल और वायु परिवहन लोगों के प्रवास, वस्तुओं के निर्यात और आयात, व्यापार, ज्ञान के आदान-प्रदान, अच्छे संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देता है।

परिवहन के विभिन्न साधन

परिवहन सुविधाएं चार प्रकार की होती हैं, 1. सड़क परिवहन 2. रेल परिवहन
3. वायु परिवहन 4. जल परिवहन।

1. सड़क परिवहन: यह हमारे देश में परिवहन का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। सड़कें दूरदराज के इलाकों और बस्तियों को भी जोड़ती हैं। आज सड़कें सार्वजनिक-निजी भागीदारी से विकसित की जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों को गोल्डन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है और उनके उपयोगकर्ताओं से टोल वसूला जा रहा है। शुल्क के रूप में एकत्रित राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत में किया जा रहा है। राष्ट्रीय और राज्य सड़कों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजेएसवाई) योजनाएं शुरू की गई हैं।

2. रेल परिवहन: ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की
भारत में। 1950 में देश में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारतीय रेलवे सबसे बड़ी है
दुनिया में परिवहन प्रणाली जो देश के दूरदराज के इलाकों को जोड़ती है। भारत 19 से मिलकर बना है
रेलवे प्रभाग. रेलवे इंजन, कोच और वैगनों के स्थान पर नये इंजनों का आगमन,
पंचवर्षीय योजनाओं में रेलवे के नियमितीकरण और आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी गई।
फोन और वाई-फाई जैसे आधुनिक उपकरणों की शुरूआत जैसी चर्चाएं हुईं
रेलगाड़ियाँ. चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में मेट्रो ट्रेनें शुरू की गईं।

3. जल परिवहन: जल परिवहन दो प्रकार के होते हैं: 1. अंतर्देशीय जल परिवहन

2. समुद्री जल परिवहन। अंतर्देशीय जल परिवहन के स्रोत: नदियाँ, जलाशय, नहरें, समुद्र, बैक वॉटर) छोटी नावें, मोटरबोट - लोगों और सामानों का परिवहन करती हैं।

समुद्री जल परिवहन में छोटे जहाज, भारी जहाज और भारी सामान (कोयला, तेल) शामिल होते हैं। घरेलू बंदरगाहों और विदेशी बंदरगाहों तक पहुंचाया गया। यह परिवहन की कम लागत और गैर-परिवहन का स्थिर साधन. इस परिवहन व्यवस्था के विकास से रोजगार मिलता है तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए अवसर और आय और व्यापार में वृद्धि। हमारे देश का समुद्रतट 7,156 कि.मी. हमारे देश में 12 बड़े और 187 छोटे बंदरगाह हैं। जल परिवहन कुल परिवहन क्षेत्र का 29% हिस्सा है।

4. वायु परिवहन: भारत में वर्ष 1950 में विमानन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कर भारतीयकरण कर दिया गया एयरलाइंस और एयर इंडिया की स्थापना हुई। इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ान सेवाएँ प्रदान करती है और एयर इंडिया अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाएँ प्रदान करता है। आर्थिक सुधारों के भाग के रूप में, निजी क्षेत्र को विमानन क्षेत्र में प्रवेश दिया गया है। प्राइवेट एयरलाइंस को एंट्री दे दी गई है विमानन क्षेत्र में. वर्तमान में, भारत में 103 घरेलू और 24 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। हवाई परिवहन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के नियंत्रण में संचालित होता है।

हमारे देश में परिवहन क्षेत्र की समस्याएँ निम्नलिखित हैं:

1. रखरखाव की लागत में वृद्धि.
2. उचित योजनाओं का अभाव
3. यात्री यातायात और जनसंख्या वृद्धि
4. पुराने इंजन, वैगन, सिग्नलिंग
5. प्रौद्योगिकी और निवेश का अभाव
6. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का अभाव
7. राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव

23.6 ऊर्जा क्षेत्र

आर्थिक विकास की दर ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उच्चतर प्रति व्यक्ति आय जितनी होगी, ईंधन की खपत उतनी ही कम होगी। प्रति व्यक्ति आय और प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत, जर्मनी और जापान बहुत ऊँचे हैं। चीन, हमारा प्रतिस्पर्धी, प्रति से दोगुना से भी अधिक है हमारी प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत।

ऊर्जा स्रोतों के प्रकार:

ऊर्जा स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। 1. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत 2. गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत.

1. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत: ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में कोयला, तेल, प्राकृतिक शामिल हैं गैस, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि, जिनका एक बार सेवन करने के बाद दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता।

i) कोयला- कोयला और लिग्नाइट नाशवान खनिज हैं। दुनिया का 7% हिस्सा भारत का है कोयला भंडार और ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% कोयले से पूरा होता है। कोयला और लिग्नाइट 2018-19 में उत्पादन 583 मिलियन टन था। यदि समान स्तर पर उपयोग किया जाए तो ये खनिज होंगे अगले 13 वर्षों में पूरी तरह नष्ट हो जायेंगे। लिग्नाइट केवल खनन में ही उपलब्ध है तमिलनाडु राज्य के नेवेली और आर्कोट क्षेत्र।

ii) तेल एवं प्राकृतिक गैस- हमारे देश में उपलब्ध तेल की मात्रा 550 अरब है टन. प्राकृतिक गैस 550 अरब मीटर है। यदि उत्पादन उसी स्तर पर होता है स्तर पर, ये खनिज 20 से 25 वर्षों की अवधि में विलुप्त हो जायेंगे।

iii) परमाणु ऊर्जा: परमाणु बिजली का आधार यूरेनियम, थोरियम और अयस्क हैं, जो कुल बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 4% है।

2. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत: ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों में सौर ऊर्जा शामिल है ऊर्जा, समुद्री लहर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, आदि, जिनका पुनरुत्पादन किया जा सकता है। वे नहीं प्रदूषण करता है। विकसित देशों में इनकी खपत अधिक है। इन्हें छोड़कर, इथेनॉल का उत्पादन गन्ने और जेट्रोफा पौधे आदि से किया जाता है। इसे इससे समझा जा सकता है निम्न तालिका.

तालिका: भारत में बिजली उत्पादन, प्रतिशत में
क्षेत्रीय बिजली खपत (1950-2019)

वर्ष शक्ति	पीढ़ी (गीगा वाट)	घरेलू वाणिज्य उद्योग कृषि अन्य उपयोग क्षेत्र				
1950 510		9	6	72	10	3
1979 84005		9	5	65	14	4
1997 315294		18	6	44	27	4
2007 525672		21	18	46	19	4
2013 85292		22	8	45	18	4
2019 87145		21	9	47	17	6

स्रोत: वाणिज्यिक ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार-2019

उपरोक्त तालिका पर नजर डालें तो उद्योगों एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों की खपत है
बढ़ रही है, जबकि घरेलू क्षेत्र भी उपभोग दर में सबसे आगे है।
1950 से 2019 तक लगभग सभी क्षेत्रों की खपत बढ़ी है।

23.7 सूचना क्षेत्र

सूचना क्षेत्र व्यक्तियों और क्षेत्रों को आवश्यक जानकारी प्रदान करता है
बाज़ारों का विकास. प्रभावी संचार व्यापार के विकास में मदद करता है और
आर्थिक विकास दर. सूचना क्षेत्र i) डाक (पोस्ट) ii) टेलीग्राफ (टेलीग्राफ)
दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करता है।

i) डाक सेवाएँ: हमारे देश में डाक सेवाएँ 1776 से वर्तमान में उपलब्ध हैं
हमारे देश में 1.5 लाख डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर एक से सेवाएं प्रदान करता है
औसतन 7000. 500 से ज्यादा आबादी वाले हर गांव में एक पोस्ट होती है
कार्यालय। हमारा डाक विभाग दुनिया में नंबर एक है। पारंपरिक सेवाओं के अलावा
जैसे पोस्टकार्ड, कवर, टिकट, पत्र और पार्सल की बिक्री, नई सेवाएँ भी हैं
की पेशकश की जा रही है। 21वीं सदी के 'स्पीड युग' के अलावा, स्पीड पोस्ट, मेट्रो पोस्ट,
राजधानी सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय पार्सल केंद्र, इंडिया पोस्ट वैश्विक पोर्टल, प्राप्त करने में आसानी
त्वरित मनी ऑर्डर, वेस्टर्न मनी ट्रांसफर की शुरुआत की गई है।

डाक विभाग को कर्मचारियों की कमी, भारी राजकोषीय घाटा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
निजी कूरियर प्रतियोगिता, आदि।

ii) भारतीय टेलीग्राफ सेवाएँ: दुनिया की पहली टेलीग्राफ सेवाएँ हमारे देश में शुरू हुईं।
टेलीग्राम, फैक्स संदेश आदि को त्वरित वितरण की सुविधा प्रदान की गई है। विस्तार के साथ
टेलीफोन लाइनों, टेलीग्राफ सेवाओं का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार हुआ है।

iii) दूरसंचार: दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास में योगदान देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन्स लिमिटेड (एमटीएनएल) एशिया में सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता हैं। कर्मचारियों की कमी, टावरों की कमी आदि जैसे मुद्दे हैं। वर्ष 1999 में, दूरसंचार नीति का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन का विस्तार करना और टेलीफोन टैरिफ को ठीक करने और विनियमित करने के लिए भारतीय टेलीफोन नियामक प्राधिकरण (TRAI) की स्थापना करना था। (आरोप)। टेलीकॉम सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है.

2010 की राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का उद्देश्य टैरिफ को विनियमित करना और प्रदान करना था
दूरसंचार सेवाओं को सभी वर्गों के लोगों तक पहुँचाने के लिए कुशल सेवाएँ प्रदान करना।
लक्ष्य यह भी था कि आकर्षित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाकर नौकरी के अवसरों में सुधार किया जाए
दूरसंचार क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश।

23.8 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) 21वीं सदी के नवाचार और ज्ञान-संचालित समाज में क्रांति ला रही है। सूचना प्रौद्योगिकी दुनिया के सभी देशों में क्रांति ला रही है
आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना। वैश्विक गांव की अवधारणा आईटी के विकास के साथ आई। यह
दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में आईटी आधारित सेवाओं का उपयोग करता है। आईटी क्षेत्र सॉफ्टवेयर प्रदान करता है,
हार्डवेयर, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, अनुसंधान, विकास ज़ूम सेवाएँ। सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ सूचना आधारित सेवा, बैंक, बीमा कंपनियाँ,
वित्तीय संस्थान, दूरसंचार क्षेत्र इन सेवाओं का उपयोग करते हैं। आईटी मुहैया कराने वाली 5 बड़ी कंपनियां
हमारे देश में सेवाएँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस (टीसीएस), कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, इंफोसिस,
विप्रो, एचसीएल।

आईटी क्षेत्र के विकास ने हमारे देश को "सुस्त" क्षेत्र से अलग पहचान दिलाई है
देश'' को ''नवाचार का देश'' कहा जाता है। भारत उपलब्ध कराने में विश्व का सबसे बड़ा देश है
सूचान प्रौद्योगिकी सेवाएं। भारत सरकार की क्लाउडिंग आईटी क्षेत्र में एक और उभरती हुई सेवा है
जहां इस तकनीक का उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों और क्षेत्रीय सरकारों द्वारा किया जाता है।
इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग सार्वजनिक प्रशासन, कार्यों और सेवाओं के लिए किया जाता है
सरकारें. सभी सरकारी सेवाओं, ई-सेवा, मी-सेवा को कम्प्यूटरीकृत करने के बाद,
नगर पालिकाओं, ऑनलाइन भुगतान, कर भुगतान, रसीदें, प्रमाणपत्र सभी द्वारा उपयोग किए जाते हैं।
सरकारी सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण। यह पारदर्शिता, दक्षता और को संभव बनाता है
शासन प्रणाली में सामुदायिक स्वामित्व, और देरी और भ्रष्टाचार को कम करता है
कर्तव्यों का निर्वहन.

आईटी को निर्यातोन्मुख उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेवाओं में आईटी निर्यात 77% है। यह
यह क्षेत्र दस लाख आबादी में से 4.4% को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान कर रहा है
वर्ष 2020-21 में 12 करोड़ आबादी को रोजगार। हमारे निर्यात के साथ विकास
हमारे देश को ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर पहुंचाया है।

सोशल मीडिया नेटवर्किंग (गूगल, फेसबुक, ट्विटर) विकास में योगदान दे रही है
का A) ऑनलाइन शॉपिंग B) सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय सेवाएँ D) कंप्यूटर क्यूरेटिव आईटी क्षेत्र। सामान्य
सेवाओं ने इंटरनेट और अत्याधुनिक दूरसंचार उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है।

23.9 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इन क्षेत्रों के विकास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है बाज़ार. सभी विकसित देश हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। देश को अनुसंधान और विकास के प्रचुर अवसरों वाले देश के रूप में पहचाना जाता है। आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है। इन सेक्टर आर्थिक विकास दर को निचले स्तर से शिखर तक ले जाने की ताकत रखते हैं। नया अनुसंधान और नवाचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान करते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और विस्तार में योगदान देगी रोजगार के अवसरों की.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लाभ

1. उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाता है।
2. पूंजीगत वस्तुओं का कुशल उपयोग संभव है।
3. नई मशीनों तथा उन्नत उपकरणों के प्रयोग से कार्यकुशलता में वृद्धि होगी कर्मचारियों की संख्या।
4. उत्पादन की बर्बादी और लागत को कम करता है।
5. उत्पादन और वितरण प्रक्रियाओं में तेजी लाता है।
6. इससे कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा।
7. आंतरिक और बाह्य बचत से बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि होगी उद्योगों का मुनाफा.
8. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास से इसका उपयोग संभव हो सकेगा वांछनीय संसाधन और अधिकतम उत्पादन प्रदान करना। भारत को स्थान दिया गया है दुनिया के वैज्ञानिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में शीर्ष पर है। हालाँकि, तथ्य यह है कि केवल 6% हमारे देश की जनसंख्या अनुसंधान के क्षेत्र में विकसित होना भारत की मुख्य कमजोरी है। इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका में 32% आबादी शोध में काम कर रही है मैदान। प्रति 10,000 जनसंख्या पर इंजीनियरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, केवल हैं भारत में 22. संयुक्त राज्य अमेरिका में 456 लोग हैं। हालाँकि, संरचनात्मक परिवर्तन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े हैं सेवा क्षेत्र और राष्ट्रीय आय का हिस्सा बढ़ रहा है।

23.10 बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग प्रणाली वित्तीय बाजार का एक अभिन्न अंग है। भारत का अभिन्न अंग उद्यमशील बैंकिंग प्रणाली. i) रिजर्व बैंक ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक iii) अनुसूचित सहकारी बैंक। बैंकिंग प्रणाली या शीर्ष बैंक का प्रमुख रिजर्व बैंक है भारत या सेंट्रल बैंक का. अनुसूचित बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं बैंक वे बैंक हैं जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं जो बैंकिंग का सामान्य व्यवसाय जैसे जमा स्वीकार करना, ऋण देना आदि करते हैं और अन्य बैंकिंग सेवाएँ। वाणिज्यिक बैंक लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय करते हैं। जमा राशि की भलाई को परेशान किए बिना निवेश किया जाएगा। सहकारी बैंक सदस्यों की सहायता से गैर-लाभकारी सेवा प्रदान करते हैं। लोगों और संस्थाओं की बचत वाणिज्यिक बैंक जमा के रूप में एकत्र किया जाता है और एकत्रित धन को संक्षिप्त रूप से स्वीकृत किया जाता है-सावधि ऋण. 1969 में, भारत में पहली बार 14 निजी बैंकों और 6 अन्य का राष्ट्रीयकरण किया गया सामाजिक कल्याण के लिए वर्ष 1980 में बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।

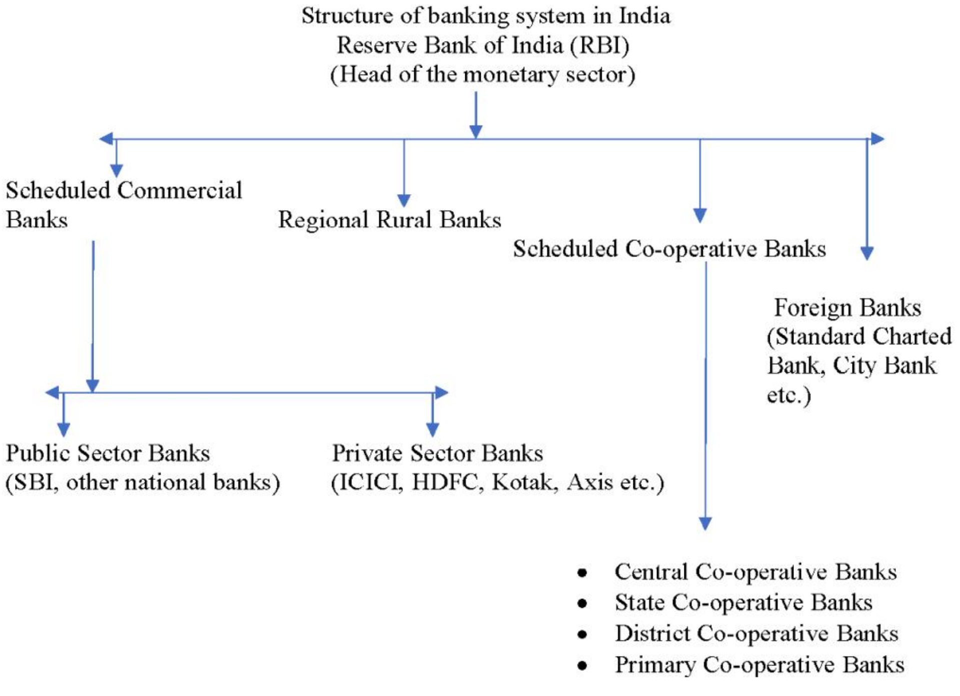

रिज़र्व बैंक (RBI): इसकी स्थापना 1935 में हुई और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और यह मुंबई में स्थित है। भारतीय रिज़र्व बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है। इसे शीर्ष बैंक मौद्रिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। रिज़र्व बैंकों का कार्य करेंसी नोट जारी करना है

बैंकर, एजेंट और सरकार के सलाहकार, विदेशी मुद्रा कोष और स्वर्ण भंडार की सुरक्षा, बैंकों के बैंकर के रूप में बैंकों की नकदी भंडारण गतिविधियों को देखना, चेक समाशोधन सेवाएं प्रदान करना, क्रेडिट नियंत्रण, विनिमय दर पर नियंत्रण आदि।

यह कई अन्य कार्य भी करता है जो आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं कल्याण। रिजर्व बैंक महंगाई पर काबू पाने के लिए कदम उठाता है.

वाणिज्यिक बैंक

वाणिज्यिक बैंकों का मूल कार्य जनता से ऐसी बचत स्वीकार करना है संस्थाएँ जमा के रूप में और प्राप्त जमा का एक बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में स्वीकृत करती हैं। बैंक ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को 'साख निर्माण' के रूप में जाना जाता है। में केवल 12 बैंक हैं वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 27 बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंकिंग प्रणाली में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सबसे बड़ी बैंकिंग मानी जा सकती है प्रणाली।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना वर्ष 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। ये बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निष्पादित सभी कार्य करना। लेकिन कार्रवाई का दायरा ये बैंक केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बचत जुटाते हैं क्षेत्रों और विभिन्न और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीणों को ऋण प्रदान करते हैं कुटीर उद्योगों।

सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों की संरचना इस प्रकार तीन स्तरों पर होगी।

1) राज्य सहकारी बैंक (एससीओबी) जो आरबीआई और संबंधित राज्य द्वारा विनियमित होते हैं सरकारें. ये बैंक ग्रामीण और कम आय वाली आबादी को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं देश भर में। वे अक्सर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए ऋण का प्राथमिक स्रोत होते हैं गतिविधियाँ, लघु उद्योग और अन्य छोटे व्यवसाय। यह एक शीर्ष बैंक है सहकारी ऋण प्रणाली के लिए राज्य स्तर.

2) केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी), ये राज्य में जिला स्तर पर हैं। सीसीबी हैं राज्य सहकारी विभाग द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है और रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है भारत। सीसीबी अपने सदस्यों को ऋण और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और ले रहे हैं आम जनता से जमा राशि भी वाणिज्यिक बैंकों की तरह होती है।

3) प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस), सहकारिता की तीसरी परत हैं प्रणाली। आम तौर पर, PACS का संचालन ग्रामीण स्तर पर किया जाता है और उनका स्वामित्व और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है उनके सदस्य, जो सहकारी के लाभ के लिए पूंजी और श्रम दोनों का योगदान करते हैं। 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंकिंग सेवाएं विकसित हो रही हैं। नई सेवाएँ बैंकों द्वारा प्रस्तावित हैं: i) वाणिज्यिक विकास के लिए मर्चेंट बैंकिंग, शेयर, डिबेंचर

ii) म्यूचुअल फंड iii) उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए खुदरा बैंकिंग iv) स्वचालित टेलर मिशन (एटीएम) v) किसी भी शाखा से बैंकिंग सुविधा, vi) इंटरनेट बैंकिंग, vii) तत्काल नकदी स्थानांतरण सुविधा viii) योनो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आदि।

23.11 पर्यटन

पिछली दो शताब्दियों से पर्यटन क्षेत्र सबसे बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है सेवा क्षेत्र में. भारत के योजना आयोग ने पर्यटन की पहचान की है हमारे देश में सर्वाधिक विकास दर वाला दूसरा प्रमुख क्षेत्र। यह सेक्टर, जिसके पास है उच्चतम विकास, राजस्व और रोजगार के अवसर, चौथा क्षेत्र माना जाता है अर्थव्यवस्था का. विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार "पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक विषय है और आर्थिक घटना जिसमें देशों या स्थानों पर लोगों की आवाजाही शामिल है व्यक्तिगत या व्यावसायिक/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपने सामान्य वातावरण से बाहर"। इन लोगों को आगंतुक कहा जाता है। एक वर्ष से भी कम समय के लिए एक दिन से अधिक समय के लिए हमारे देश का दौरा करना है इसे "भ्रमण" कहा जाता है। आगरा, दिल्ली, जयपुर, कश्मीर, हैदराबाद, गोवा, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई आदि हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं।

भारत में पर्यटन का महत्व: आर्थिक विकास में पर्यटन का महत्व वृद्धि होगी। पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, आदान-प्रदान में योगदान देता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पर्यटन की वृद्धि दर व्यापार को बढ़ावा देती है। यह मजबूत होगा संबद्ध क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला में कनेक्टिविटी। बागवानी, भूदृश्य, की मांग हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ बढ़ोतरी होगी परिवहन, सूचना, बैंकिंग, बीमा, होटल, रेस्तरां आदि में वृद्धि होगी सुविधा क्षेत्रों की आय. पर्यटकों की खपत बढ़ेगी तो राजस्व पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी.

पर्यटन के विकास से अर्थव्यवस्था को लाभ:

1. यह अर्थव्यवस्था में राजस्व और रोजगार बढ़ाता है और विदेशी मुद्रा प्रदान करता है।
2. पर्यटन क्षेत्र में निवेश का गुणांक किसके विस्तार में योगदान देता है चक्रीय आय प्रवाह के लिए रोजगार।
3. होटल जो बागवानी, भूदृश्य, हस्तशिल्प उद्योग, फास्ट फूड, प्रदान करते हैं पर्यटकों को आकर्षित करने वाले विशिष्ट स्वदेशी व्यंजन फल-फूलेंगे।
4. नई सेवाएँ जैसे टिकट बुकिंग, मौद्रिक विनिमय, पर्यटक सुविधाएँ, भोजन सुविधाएं एवं सुविधाएं, पार्किंग, भ्रमण स्थलों का विकास किया जाएगा।

5. केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय सरकारों का राजस्व बढ़ेगा.

6. स्वच्छता, संरक्षित पेयजल एवं प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं सतत आर्थिक विकास जैसे उपाय संभव हो सकेंगे।

7. पर्यटन क्षेत्र विभिन्न स्तरों के कुशल श्रमिकों के साथ-साथ अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम (STDC) की स्थापना की। संगठन के कार्य हैं: i) इसने परिवहन, मनोरंजन, खरीदारी, सेमिनार, सम्मेलन और सम्मेलन आयोजित करने के लिए कन्वेंशन कैंटर बनाए हैं ii) परामर्श और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना iii) नई सेवाएं प्रदान करना जो पर्यटकों को उनके खर्च किए गए पैसे के लिए संतोषजनक हैं iv) सार्वजनिक-निजी भागीदारी में नई सेवाएँ शुरू करना। वर्ष 2020 में कुल 2.74 मिलियन की आबादी वाले भारत में विदेशी पर्यटकों ने स्थानों का दौरा किया। इसके परिणामस्वरूप 6.958 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई, जिससे 80 मिलियन लोगों को रोजगार मिला।

23.12 सारांश

विकसित तृतीयक क्षेत्र तीव्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की आपूर्ति पूंजी उत्पादन की दर को बढ़ाकर विकास प्रक्रिया को गति देगी। परिवहन क्षेत्र एक बुनियादी ढांचागत सुविधा है जो आर्थिक गतिविधियों के उपयोग और उत्पादन के वितरण की सुविधा प्रदान करती है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) 21वीं सदी के नवाचार और ज्ञान-संचालित समाज में क्रांति ला रही है। सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक उपकरणों का उपयोग करके दुनिया के सभी देशों में क्रांति ला रही है। इसे निर्यातोन्मुख उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेवाओं में इसका निर्यात 77% है। आईटी सेक्टर वर्ष 2020-21 में 4.4% मिलियन आबादी को प्रत्यक्ष रोजगार और 12 मिलियन आबादी को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान कर रहा है। बैंकिंग प्रणाली वित्त बाजार का एक अभिन्न अंग है। भारत की उद्यमशील बैंकिंग प्रणाली का अभिन्न अंग।

आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है. पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सद्भावना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान में योगदान देता है। पर्यटन की वृद्धि दर व्यापार को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा।

23.13 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. तृतीयक क्षेत्र को परिभाषित करें
2. बुनियादी ढांचे के प्रकार
3. विमानन क्षेत्र

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. हमारे देश में बैंकिंग संरचना बताइये।

2. सहकारी बैंकों का महत्व लिखिए।

3. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के बीच क्या अंतर है?

ऊर्जा?

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के लाभ बताइये।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. रिजर्व बैंक के कार्यों की व्याख्या करें।

2. सेवा क्षेत्र का महत्व बताइये।

3. आइये जानते हैं कि हमारे देश में परिवहन क्षेत्र किन समस्याओं का सामना कर रहा है।

4. हमारे देश के विकास में सूचना क्षेत्र के महत्व को समझाइये।

5. पर्यटन के विकास से अर्थव्यवस्था को होने वाले लाभों का उल्लेख करें।

23.14 शब्दावली

भारतीय रिज़र्व बैंक: यह भारत का एक शीर्ष बैंक है; इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
इसके पास बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने,
सरकार और बैंकों को सहायता करना। इसकी स्थापना 1935 में भारत सरकार द्वारा की गई थी
1969 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक: अनुसूचित बैंक वे बैंक हैं जो दूसरे में सूचीबद्ध हैं
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की अनुसूची। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय है
वह संस्था जो आम जनता से जमा स्वीकार करने का कार्य करती है
लाभ कमाने के उद्देश्य से निवेश के लिए अग्रिम और ऋण देना। ये बैंक ऑफर करते हैं
अन्य वित्तीय सेवाएँ जैसे एटीएम, डिमांड ड्राफ्ट, जमा प्रमाणपत्र आदि भी।

23.15 सन्दर्भ

1. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22

2. तेलुगु अकादमी बीए अंतिम वर्ष की पुस्तक

3. दत्त और सुंदरम द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था

4. रिजर्व बैंक इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट

अध्याय 24

विदेशी क्षेत्र

24.0 उद्देश्य

24.1 परिचय

24.2 व्यापार संतुलन

24.3 भुगतान संतुलन

24.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

24.5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

24.6 गैट

24.7 विश्व व्यापार संगठन

24.8 सारांश

24.9 मॉडल परीक्षा प्रश्न

24.10 शब्दावली

24.11 सन्दर्भ

24.0. उद्देश्य

- व्यापार संतुलन (बीओटी) और भुगतान संतुलन (बीओपी) की अवधारणाओं को समझाएं
- भारत के भुगतान संतुलन के रुझान का विश्लेषण करें
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अवधारणा को समझाइये
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के गुण और दोषों का वर्णन करें
- GATT और WTO में अंतर बताएं।

24.1 परिचय

प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में माहिर होता है जिनका वह समर्थन कर सकता है- कम लागत पर उपज. प्रत्येक देश उन वस्तुओं का आयात करता है जिनका वह केवल उत्पादन कर सकता है अधिक लागत. प्रत्येक देश को कुछ वस्तुओं के उत्पादन में लाभ होता है। यह विशेषज्ञता या कारक बंदोबस्ती के कारण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आदान-प्रदान है राष्ट्रीय सीमाओं के पार देशों के बीच सामान और सेवाएँ। देशों को व्यापार करने की आवश्यकता है ऐसी वस्तुएं प्राप्त करें जिनका वे स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते या जिन्हें वे अन्यत्र खरीद सकते हैं- जहां कम कीमत पर.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी है यदि यह क्षेत्रीय स्तर पर ले जाता है विशेषज्ञता, उत्पादन का उच्च स्तर, बेहतर जीवन स्तर, विश्वव्यापी उपलब्धता वस्तुओं और सेवाओं का, कीमतों और मजदूरी का बराबर होना और ज्ञान का प्रसार और संस्कृति.

विदेशी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जिसके साथ लेन-देन होता है विदेशी देश. विदेशी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात शामिल है साथ ही निवेश और बैंकिंग लेनदेन के संबंध में पूंजी की आवाजाही, और घरेलू आर्थिक गतिविधि के स्तर और संरचना और स्थिति को प्रभावित करता है देश का व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन।

24.2 व्यापार संतुलन (बीओटी)

व्यापार संतुलन आयातित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी रिकॉर्ड करता है

एक देश द्वारा दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। व्यापार संतुलन (बीओटी) कुल मूल्य को संदर्भित करता है

किसी देश के वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात के कुल मूल्य का। केवल

वस्तुओं के निर्यात और आयात को व्यापार संतुलन के विवरण में शामिल किया जाता है

देश। वस्तुओं की आवाजाही (वस्तुओं का निर्यात और आयात) को भी कहा जाता है

दृश्यमान व्यापार, क्योंकि देशों के बीच वस्तुओं की आवाजाही देखी जा सकती है

आंखों और हाथों से महसूस किया जा सकता है और किसी देश के कस्टम अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

अनुकूल बीओटी: जब किसी देश के वस्तु निर्यात का कुल मूल्य उस देश के वस्तु आयात के कुल मूल्य से अधिक हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि देश के

पास अनुकूल बीओटी है।
व्यापार का संतुलन।

प्रतिकूल बीओटी: यदि किसी देश के वस्तु निर्यात का कुल मूल्य कुल से कम है

उस देश के वस्तु आयात का मूल्य प्रतिकूल कहा जाता है
व्यापार का संतुलन।

व्यापार संतुलन का संतुलन: किसी देश के व्यापार संतुलन में संतुलन हो सकता है

जब उसके द्वारा निर्यात किए गए माल का कुल मूल्य आयातित माल के कुल मूल्य के बराबर हो

इसके द्वारा।

24.3 भुगतान संतुलन (बीओपी)

भुगतान संतुलन (बीओपी) एक वर्ष के दौरान सभी आर्थिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाली प्राप्तियों और भुगतान का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार "किसी देश का भुगतान संतुलन एक व्यवस्थित होता है

किसी देश के निवासियों और शेष के बीच सभी आर्थिक लेनदेन का रिकॉर्ड

दुनिया। यह निर्यातित वस्तुओं, सेवाओं के कारण सभी प्राप्तियों का वर्गीकृत रिकॉर्ड प्रस्तुत करता है

निवासियों द्वारा प्रदान की गई पूंजी और माल के कारण उनके द्वारा किया गया भुगतान

आयातित और पूंजी से प्राप्त सेवाएँ गैर-निवासियों या विदेशियों को हस्तांतरित की गईं।

भुगतान संतुलन एक समयावधि से संबंधित एक रिकॉर्ड है; आमतौर पर यह सब वार्षिक विवरण होता है।

भुगतान संतुलन में प्रवेश करने वाले सभी लेनदेन को तीन व्यापक के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है

खाते हैं (1) चालू खाता; (2) पूंजी खाता; और (3) आधिकारिक आरक्षित संपत्ति

खाता (4) त्रुटियाँ और चूक।

24.3.1 भुगतान संतुलन का महत्व

बीओपी उन सभी लेनदेन को रिकॉर्ड करता है जो मुद्रा की मांग और आपूर्ति पैदा करते हैं।

अल्पावधि में किसी देश की आर्थिक और वित्तीय स्थिति का आकलन करता है।

बीओपी अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय दर में रुझान की पुष्टि कर सकता है

मुद्रा। यह प्रवृत्ति में बदलाव या उलटफेर का संकेत भी दे सकता है।

यह देश के मौद्रिक प्राधिकरण (आरबीआई) की नीति में बदलाव का संकेत हो सकता है।

बीओपी अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय दर में रुझान की पुष्टि कर सकता है

मुद्रा। यह प्रवृत्ति में बदलाव या उलटफेर का संकेत भी दे सकता है

24.3.2 व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बीच अंतर

व्यापार का संतुलन	भुगतान संतुलन
1. यह एक संकीर्ण शब्द है	1. यह एक व्यापक शब्द है
2. इसमें केवल दृश्यमान वस्तुएं और पूंजी हस्तांतरण शामिल हैं	2. इसमें सभी लेनदेन से संबंधित शामिल हैं
3. यह अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है	3. यह सदैव स्वयं को संतुलित रखता है
4. बीओटी = निर्यात पर शुद्ध कमाई - आयात के लिए शुद्ध भुगतान	4. बीओपी = चालू खाता + पूंजी खाता + या - शेष मद - (त्रुटियां और चूक)
5. बीओटी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं ए) उत्पादन की लागत बी) कच्चे माल की उपलब्धता सी) विनिमय दर डी) घर पर निर्मित वस्तुओं की कीमतें	5. बीओपी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं ए) विदेशी ऋणदाताओं की स्थितियां बी) सरकार की आर्थिक नीति सी) बीओटी के सभी कारक

24.3.3 भारत का भुगतान संतुलन

किसी देश के भुगतान संतुलन (बीओपी) को आमतौर पर एक वर्ष की विशिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व के साथ किसी देश के सभी आर्थिक लेनदेन के व्यवस्थित विवरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह इंगित करता है कि देश के पास व्यापार पर अधिशेष है या घाटा। जब निर्यात, आयात से अधिक हो जाता है, तो व्यापार अधिशेष होता है और जब आयात, निर्यात से अधिक हो जाता है, तो व्यापार अधिशेष होता है

व्यापार घाटा.

बीओपी की गणना के उद्देश्य

किसी देश की वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है।

यह निर्धारित करने के लिए एक संकेतक के रूप में उपयोग किया जा सकता है कि देश की मुद्रा का मूल्य क्या है सराहना या अवमूल्यन करना।

सरकार को राजकोषीय और व्यापार नीतियों पर निर्णय लेने में मदद करता है।

आर्थिक लेन-देन का विश्लेषण और समझने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है एक देश का दूसरे देशों के साथ।

बीओपी के घटक

बीओपी खाते तैयार करने के लिए, एक देश और बाकी देशों के बीच आर्थिक लेनदेन विश्व को चालू खाता, पूंजी खाता और त्रुटियां और चूक के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। यह विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव को भी दर्शाता है।

चालू खाता: यह दृश्यमान (माल या माल) के निर्यात और आयात को दर्शाता है अदृश्य (गैर-व्यापार)। अदृश्य में सेवाएँ, स्थानान्तरण और आय शामिल हैं।

पूंजी खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है। यह एक देता है किसी अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के शुद्ध प्रवाह का सारांश।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), एफडीआई, एफपीआई आदि पूंजी खाते का एक हिस्सा बनते हैं।

24.4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान या व्यापार के रूप में जाना जाता है विभिन्न राष्ट्रों के बीच.

आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका

यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रीय व्यापार की ओर ले जाए तो यह राष्ट्रों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद है दुनिया भर में विशेषज्ञता, उत्पादन का उच्च स्तर, बेहतर जीवन स्तर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, कीमतों और मजदूरी का बराबर होना, और का प्रसार ज्ञान और संस्कृति.

1. श्रम विभाजन और विशेषज्ञता: विदेशी व्यापार से श्रम विभाजन होता है और

विश्व स्तर पर विशेषज्ञता। कुछ देशों के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा है। वे चाहिए

कच्चे माल का वितरण और तैयार माल का आयात उन गणराज्यों से करना जो प्रगतिशील हैं

कुशल जनशक्ति. इससे सभी राज्यों को लाभ मिलता है और इस प्रकार श्रम का पृथक्करण होता है

और विशेषज्ञता.

2. संसाधनों का इष्टतम आवंटन और उपयोग: विशेषज्ञता के कारण, गैर-रचनात्मक

लाइनों को हटाया जा सकता है और संसाधनों की बर्बादी को किनारे किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, संसाधन हैं

केवल उन्हीं संपत्तियों के निर्माण के लिए चैनलाइज़ किया गया जो अधिकतम नोट्स दे सकें

रिटर्न. इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का संतुलित वितरण और उपयोग होता है

विदेशी व्यापार के कारण स्तर।

3. कीमतों की समानता: विदेशी व्यापार द्वारा कीमतों को स्थिर किया जा सकता है: यह बनाए रखने में सहायता करता है

अनुरोध और आपूर्ति स्थान स्थिर है, जो बदले में कीमतों को स्थिर करता है, जिसके लिए भुगतान किया जाता है

परिवहन और अन्य विपणन व्यय।

4. एकाधिक विकल्पों की उपलब्धता: बेहतर विकल्प प्रदान करने में विदेशी व्यापार को लाभ होता है

उपभोक्ताओं को. यह दुनिया भर के उपभोक्ताओं के लिए प्राप्य नए परिवर्तन करने में सहायता करता है

दुनिया।

5. गुणवत्ता और मानक सामान सुनिश्चित करता है: विदेशी व्यापार अत्यधिक मामूली है। संरक्षित करने के लिए

और माल के लिए अनुरोध बढ़ाएं, निर्यातक राज्यों को माल की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी।

इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

6. लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाता है: आयात लोगों के जीवन स्तर को सक्षम कर सकता है

लोग। क्योंकि लोगों के पास वस्तुओं और सेवाओं के नए और बेहतर बदलाव का विकल्प हो सकता है। द्वारा

वस्तुओं की नई और बेहतर विविधताओं को मात देकर लोग अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं।

7. रोजगार के अवसर पैदा करता है: विदेशी व्यापार रोजगार का समर्थन करता है

श्रम और संसाधनों की गतिशीलता बढ़ाकर अवसर। यह सीधे सेवा प्रदान करता है

आयात क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार। जैसे उद्योग,

सेवा क्षेत्र (बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार), आदि।

8. आर्थिक विकास को सुगम बनाना: आयात किसी के आर्थिक विकास में सहायता करता है

राष्ट्र। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं और ज्ञान के आयात से कोई देश कमा सकता है

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, यानी कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि।

9. प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता: उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भूकंप, बाढ़, अकाल आदि अतिरंजित देशों को अभाव की समस्या का सामना करना पड़ता है आवश्यक वस्तुओं का. विदेशी व्यापार किसी देश को खाद्यान्न और दवाइयाँ आयात करने की अनुमति देता है प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अन्य देशों से।

10. भुगतान संतुलन की स्थिति बनाए रखता है: प्रत्येक देश को अपना संतुलन जारी रखना होता है भुगतान की स्थिति का. तब से, हर देश को आयात करना पड़ता है, जो कि निर्वहन का प्रतीक है विदेशी मुद्रा, यह विदेशी मुद्रा के प्रवाह के लिए व्यापार भी करता है।

11. प्रतिष्ठा लाता है और सद्भावना अर्जित करने में मदद करता है: एक ऐसा देश जो जटिल है स्प्रेड वैश्विक बाजार में दयालुता अर्जित करता है। उदाहरण: जापान को बहुत सद्भावना प्राप्त हुई है फीचर इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात के कारण वैश्विक बाजारों में।

12. विश्व शांति को बढ़ावा देता है: विदेशी व्यापार देशों को करीब लाता है। यह सौंपने में सक्षम बनाता है स्थापित देशों से उभरते देशों को प्रौद्योगिकी और अन्य सहायता। यह लाता है व्यापार समझौतों से उत्पन्न होने वाले आर्थिक संबंधों के कारण विभिन्न देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
इस प्रकार, विदेशी व्यापार युद्धों और संघर्षों को दरकिनार करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण माहौल उत्पन्न करता है। यह विश्व शांति का समर्थन करता है क्योंकि ऐसे देश आपस में मैत्रीपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं खुद।

24.5 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी देश में उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश है किसी अन्य देश में स्थित कंपनी, या तो लक्ष्य देश में किसी कंपनी को खरीदकर या उसके द्वारा उस देश में मौजूदा व्यवसाय के परिचालन का विस्तार करना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है देश में विशेष रूप से सस्ती मजदूरी का लाभ उठाने सहित कई कारणों से किया गया लाभ के लिए प्रोत्साहन के रूप में देश द्वारा दी जाने वाली कर छूट जैसे निवेश विशेषाधिकार देश या क्षेत्र के बाजारों तक टैरिफ-मुक्त पहुंच। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है पोर्टफोलियो निवेश के विपरीत जो दूसरे की प्रतिभूतियों में एक निष्क्रिय निवेश है देश जैसे स्टॉक और बांड।

24.5.1 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभ

1. देश में प्रतिस्पर्धी माहौल: विदेशी उद्यमों के प्रवेश से आम तौर पर बढ़ावा मिलता है

प्रतिस्पर्धा और मेज़बान देश में प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करता है। घरेलू

उद्यमों को घरेलू स्तर पर खुलने वाले विदेशी उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है

बाज़ार। सेवा देने में सक्षम होने के लिए घरेलू उद्यमों को कुशल होना होगा। (पूर्व:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के खुलने के बाद भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का तेजी से विकास हुआ

ऑटोमोबाइल में निवेश)।

2. उत्पादन में वृद्धि: एफडीआई से भारी पूंजी आती है। इस बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग किया जा सकता है

उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम और अन्य संसाधनों को नियोजित करें

3. आर्थिक वृद्धि और विकास: चूंकि एफडीआई वृद्धि में योगदान देता है

उत्पादन, एफडीआई बहुत कुछ प्रदान करके विकास और आर्थिक विकास को गति दे सकता है

आवश्यक पूंजी, प्रौद्योगिकी, जानकारी कौशल आदि।

4. रोजगार: चूंकि एफडीआई में कारखानों, इमारतों जैसी वास्तविक संपत्तियों में निवेश शामिल है

पौधे आदि यह प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करते हैं। एक बार जब किसी विशेष क्षेत्र में एफडीआई होता है, तो यह

उन क्षेत्रों में घरेलू निवेश बढ़ता है जो निवेश क्षेत्र से जुड़े हैं

5. विदेशी संबंधों में सुधार: एफडीआई में लोगों से लोगों के संबंध शामिल हैं और हैं

आमतौर पर द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। अधिक खुलापन

विदेशी पूंजी के कारण अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पर राष्ट्रीय निर्भरता बढ़ जाती है। निर्भरता

देशों के बीच हमेशा मित्रता और सद्भावना उत्पन्न होती है

6. घरेलू एकाधिकार में कमी: एफडीआई से घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है

और घरेलू एकाधिकार की शक्ति को कमजोर करता है।

7. जीवन स्तर में वृद्धि: एफडीआई से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं की उपलब्धता होती है

घरेलू बाज़ार में मानक जो मेज़बान देश में बनाये जाते हैं। इससे अधिक विकल्प उपलब्ध होते हैं

उपभोक्ताओं और देश के लोगों के लिए उच्च जीवन स्तर

8. भुगतान संतुलन: चूंकि एफडीआई से विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है

मेजबान देश के भुगतान संतुलन पर अनुकूल प्रभाव। एफडीआई के माध्यम से प्रवाह बहुत अधिक है

बाहरी उधार से अधिक लाभप्रद।

24.5.2 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की समस्याएँ

1. पूंजी गहन उद्योगों पर अधिक ध्यान: पूंजी में एफडीआई की संभावना अधिक है

गहन उद्योग जिससे अपेक्षाकृत कम संख्या में श्रमिकों को रोजगार मिलता है। ऐसा

प्रौद्योगिकी श्रम प्रचुर देश के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह पीढ़ी का समर्थन नहीं करती है

नौकरियों की, जो गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

2. क्षेत्रीय असमानता: एफडीआई उन क्षेत्रों या राज्यों की ओर प्रवाहित होने की संभावना है जो अच्छे हैं

प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के मामले में संपन्न और क्षमतावान है

क्षेत्रीय असमानता को बढ़ाना।

3. विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह: एफडीआई अधिक विदेशी मुद्रा लाता है, सुधार करता है

प्रारंभिक चरण में भुगतान संतुलन। हालाँकि एक बार निवेश हो जाने के बाद

एफडीआई के साथ लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के लिए आयातित कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है

ब्याज और लाभांश भुगतान के कारण विदेशी मुद्रा में भुगतान किया गया। इस तरह का बहिर्वाह

विदेशी मुद्रा भुगतान संतुलन पर दबाव डालती है।

4. घरेलू उत्पादकों को कम कीमत पर कटौती: एफडीआई कंपनियों के पास भारी धन शक्ति होती है; वे अपनाते हैं

घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को ख़त्म करने के लिए प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाएँ। कुछ क्षेत्रों में घरेलू

उत्पादक विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

5. प्राकृतिक संसाधनों का शोषण: निर्मम शोषण के लिए एफडीआई बहुत बड़ा जिम्मेदार है

प्राकृतिक संसाधनों और संभावित पर्यावरणीय क्षति।

6. दोहरी अर्थव्यवस्था: एफडीआई के कुछ पसंदीदा क्षेत्र हैं; कुछ क्षेत्रों में एफडीआई है

एक विकसित विदेशी क्षेत्र और एक के साथ दोहरी अर्थव्यवस्था के उभरने की प्रबल संभावना

अविकसित घरेलू क्षेत्र।

7. पर्यावरण मानकों का कमजोर होना: कम श्रम या पर्यावरण की निरंतरता

लाभ चाहने वाले विदेशी उद्यमों द्वारा मेजबान देशों में मानकों की अत्यधिक सराहना की जाती है। यह

यह बहुत चिंता का विषय है क्योंकि ऐसे मानकों को संरक्षित करने के प्रयास अक्सर समर्थन प्राप्त करने में विफल रहते हैं

इच्छुक पार्टियों से.

24.6 टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी)

टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी) किसके बाद बनी एक संधि है

द्वितीय विश्व युद्ध का समापन. टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) था

युद्ध के बाद आर्थिक पुनर्प्राप्ति में सहायता के लिए विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए इसे क्रियान्वित किया गया। गैट इसका मुख्य उद्देश्य टैरिफ में कमी पर वैश्विक व्यापार की बाधाओं को कम करना था, कोटा और सब्सिडी.

GATT के उद्देश्य

टैरिफ अवरोधों को कम करके और वैश्विक व्यापार में भेदभाव को दूर करके, GATT लक्ष्य है:

1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार;
2. योगदान में पूर्ण रोजगार प्रमाणित करके विश्व उत्पादन को गहन बनाना राष्ट्र का;
3. विश्व संसाधनों का विकास एवं पूर्ण दोहन; और
4. संपूर्ण विश्व में सामुदायिक जीवन स्तर में वृद्धि। दूसरी ओर,
   GATT के लेख इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश नहीं देते हैं। इन मुक्त की उन्नति के माध्यम से GATT द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जाना है (अबाधित) और बहुआयामी वैश्विक व्यापार।

इस प्रकार, GATT द्वारा स्वीकृत नियम निम्नलिखित मौलिक पर बनाए गए हैं सिद्धांतों:

1. व्यापार को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से निर्देशित किया जाना चाहिए;
2. मात्रात्मक सीमाओं का उपयोग पूर्वनिर्धारित होना चाहिए
3. असहमतियों का निर्णय विचार-विमर्श के माध्यम से किया जाना चाहिए

संक्षेप में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि GATT के सदस्य व्यापार ब्लॉकों को कम करने पर सहमत हैं और नोट्स के लिए वैश्विक व्यापार में भेदभाव को मिटाना, बहुआयामी और मुक्त बनाना व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे विश्व व्यापार और समृद्धि का दायरा व्यापक होगा।

24.7 विश्व व्यापार संगठन

डब्ल्यूटीओ ने 1 जनवरी 1995 को कार्य करना शुरू किया, लेकिन इसकी व्यापार प्रणाली आधी-अधूरी है सदी पुराना. 1948 से, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (जीएटीटी) दिया गया था सिस्टम के लिए नियम. डब्ल्यूटीओ की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक मई में जिनेवा में आयोजित हुई

1998 में इस प्रणाली की 50वीं वर्षगांठ का उत्सव शामिल था। इसे के नाम से जाना जाता था
उरुग्वे दौर और इससे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का निर्माण हुआ
GATT ज्यादातर वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, WTO और इसके समझौते केवल इसे ही कवर नहीं कर सकते थे
वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं और अन्य बौद्धिक संपदाओं जैसे व्यापार निर्माण, डिजाइन, का भी व्यापार करते हैं।
और आविष्कार.

डब्ल्यूटीओ में 164 सदस्य और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। अफगानिस्तान बन गया
जुलाई 2016 में 164वां सदस्य। राज्यों के अलावा, यूरोपीय संघ और प्रत्येक यूरोपीय संघ देश
अपने आप में एक सदस्य है.

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटना। इसके केंद्र में विश्व व्यापार संगठन के समझौते हैं, जिन पर दुनिया के अधिकांश व्यापारिक देशों ने बातचीत की और हस्ताक्षर किए और अपने देशों में इसकी पुष्टि की।
संसदों. लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार सुचारू रूप से, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो
संभव। डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों की एक वैश्विक प्रणाली संचालित करता है, यह बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है
व्यापार समझौते, यह अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है और जरूरतों का समर्थन करता है
विकासशील देशों का.

सभी प्रमुख निर्णय डब्ल्यूटीओ की सदस्य सरकारों द्वारा लिए जाते हैं: या तो मंत्रियों द्वारा (जो आमतौर पर कम से कम हर दो साल में मिलते हैं) या उनके राजदूतों या प्रतिनिधियों द्वारा (जो जिनेवा में नियमित रूप से मिलते हैं)। कई सरल, मौलिक सिद्धांत इसकी नींव बनाते हैं

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का. डब्ल्यूटीओ का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार को खोलना है
सभी का लाभ. डब्ल्यूटीओ का शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है। नीचे
यह सामान्य परिषद और विभिन्न अन्य परिषदें और समितियाँ हैं।

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आमतौर पर हर दो साल में होते हैं।

सामान्य परिषद दैनिक निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह एक संख्या से मिलता है
जिनेवा में साल में कई बार।

डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के लिए सरकार को अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों को एक अनुरूप लाना होगा
डब्ल्यूटीओ नियमों के साथ और डब्ल्यूटीओ सदस्यता के साथ प्रवेश की शर्तों पर बातचीत करें।

डब्ल्यूटीओ अपने वार्षिक बजट के लिए अधिकांश आय किसके योगदान से प्राप्त करता है?
इसके सदस्य. ये योगदान एक फ़ॉर्मूले पर आधारित हैं जिसे ध्यान में रखा जाता है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक सदस्य का हिस्सा।

न्गोजी ओकोन्जो-इवेला डब्ल्यूटीओ के सातवें महानिदेशक हैं। उसने पदभार ग्रहण किया
1 मार्च 2021 को, निदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनीं-
सामान्य। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 को समाप्त होगा।

विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य

समझौते में दर्शाई गई नई विश्व व्यापार प्रणाली को लागू करना;

विश्व व्यापार को इस तरह से बढ़ावा देना जिससे हर देश को लाभ हो;

यह सुनिश्चित करना कि विकासशील देश साझाकरण में बेहतर संतुलन सुरक्षित रखें
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से होने वाले लाभ
उनकी विकासात्मक आवश्यकताएँ;

एक खुली विश्व व्यापार प्रणाली की सभी बाधाओं को ध्वस्त करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश करना
आर्थिक पुनर्जागरण क्योंकि विश्व व्यापार को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन है
आर्थिक विकास;

उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सभी व्यापारिक साझेदारों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना
और वैश्विक एकीकरण में सहायता;

उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से वृद्धि करना
दुनिया में रोजगार;

विश्व संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और विस्तार करना;

वैश्विक आबादी के जीवन स्तर में सुधार करना और आर्थिक गति को गति देना
सदस्य राष्ट्रों का विकास.

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

1. समझौते का प्रशासन: यह 29 समझौतों के प्रशासन की देखभाल करता है
(1994 में उरुग्वे दौर के समापन पर हस्ताक्षरित), साथ ही कई अन्य समझौते,
उरुग्वे दौर के बाद प्रवेश किया।

2. व्यापार बाधाओं को कम करने का कार्यान्वयन: यह के कार्यान्वयन की जाँच करता है
टैरिफ में कटौती और गैर-टैरिफ उपायों में कमी पर सदस्य राष्ट्रों द्वारा सहमति व्यक्त की गई
उरुग्वे दौर का समापन.

3. सदस्यों की व्यापार नीतियों की जांच: यह नियमित रूप से विदेशी व्यापार की जांच करता है
सदस्य राष्ट्रों की नीतियां, यह देखना कि ऐसी नीतियां डब्ल्यूटीओ दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

4. विदेशी व्यापार सूचना का संग्रहण: यह निर्यात के संबंध में सूचना एकत्रित करता है-

आयात व्यापार, विभिन्न व्यापार उपाय और सदस्य देशों के अन्य व्यापार आँकड़े।

5. विवादों का निपटान: यह सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए सुलह तंत्र प्रदान करता है

सदस्य राष्ट्रों के बीच व्यापार संघर्षों का समाधान। डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय

यह उन व्यापार विवादों पर निर्णय देता है जिन्हें सदस्यों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है

राष्ट्र का।

6. परामर्श सेवाएँ: यह विश्व अर्थव्यवस्था में विकास पर नजर रखती है

यह अपने सदस्य देशों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

7. बातचीत का मंच: डब्ल्यूटीओ एक ऐसा मंच है जहां सदस्य देश लगातार बातचीत करते रहते हैं

व्यापार रियायतों का आदान-प्रदान। सदस्य राष्ट्र व्यापार प्रतिबंधों पर भी चर्चा करते हैं

वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि के क्षेत्र।

8. आईएमएफ और आईबीआरडी की सहायता: यह आईएमएफ और आईबीआरडी को सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है।

सार्वभौमिक आर्थिक नीति प्रशासन।

भारत और विश्व व्यापार संगठन

भारत जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और सदस्य भी रह चुका है

जुलाई 1948 से टैरिफ और व्यापार पर डब्ल्यूटीओ के पूर्ववर्ती सामान्य समझौते (जीएटीटी) का।

एक विकासशील देश के रूप में भारत ने विश्व व्यापार संगठन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विशेष रूप से अपनी और संपूर्ण विकासशील दुनिया की चिंताओं को व्यक्त करने में।

2001 में हुए दोहा WTO सम्मेलन में भारत सबसे आगे निकल कर उभरा

विकासशील गुट के समर्थकों का मुखर होना। इसके बाद से बैठक को सफल घोषित कर दिया गया

142 देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार वार्ता के एक नए दौर पर सहमति व्यक्त की, जिसमें ये विषय भी शामिल हैं

पर्यावरण, प्रतिस्पर्धा और निवेश के रूप में।

इसके परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव पड़ रहे हैं

डब्ल्यूटीओ के हिस्से के रूप में हस्ताक्षरित समझौते।

हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी के लिए विवाद समाधान

भारत ने वैश्विक समझौते में एक स्पष्ट विवाद निपटान तंत्र की मांग की है

हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी समाप्त करें।

डब्ल्यूटीओ के सदस्य सब्सिडी खत्म करने के लिए विषयों को अंतिम रूप देने पर बातचीत कर रहे हैं अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ना, और मत्स्य पालन के कुछ रूपों पर प्रतिबंध लगाना सब्सिडी जो अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मछली पकड़ने में योगदान करती है।

भारत अनावश्यक जल्दबाजी से बचना चाहता है और अगली मंत्रिस्तरीय बैठक तक वार्ता समाप्त करना चाहता है जून 2021 में सम्मेलन।

GATT और WTO के बीच अंतर

क्र.सं. नहीं।	गैट	विश्व व्यापार संगठन
1	GATT तदर्थ और अनंतिम था	डब्ल्यूटीओ और उसके समझौते हैं स्थायी
2	GATT में अनुबंधित पार्टियाँ थीं	विश्व व्यापार संगठन के सदस्य
3	GATT ने मौजूदा घरेलू की अनुमति दी भले ही कानून जारी रहे GATT समझौते का उल्लंघन किया	डब्ल्यूटीओ इसकी इजाजत नहीं देता.
4	GATT कम शक्तिशाली था, विवाद निपटान प्रणाली धीमी थी और कम कुशल, इसका शासन हो सकता है आसानी से अवरुद्ध.	WTO GATT से अधिक शक्तिशाली है, विवाद निपटान तंत्र है तेज़ और अधिक कुशल, बहुत फैसले को रोकना मुश्किल.

24.8 सारांश

विदेशी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो विदेशों के साथ लेनदेन से संबंधित है विदेशी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के साथ-साथ निवेश और बैंकिंग लेनदेन और प्रभावों के संबंध में पूंजी आंदोलन घरेलू आर्थिक गतिविधि का स्तर और संरचना और देश की स्थिति व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन। व्यापार संतुलन (बीओटी) कुल को संदर्भित करता है किसी देश के वस्तुओं के निर्यात का मूल्य और वस्तुओं के आयात का कुल मूल्य।

भुगतान संतुलन (बीओपी) प्राप्तियों और भुगतानों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है

और एक वर्ष के दौरान सभी आर्थिक लेनदेन से उत्पन्न होने वाले अन्य देशों के लिए।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी कंपनी द्वारा किसी देश में उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश है

दूसरे देश में स्थित, या तो लक्ष्य देश में एक कंपनी खरीदकर या विस्तार करके

उस देश में मौजूदा व्यवसाय का संचालन। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

यह एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है।

डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों की एक वैश्विक प्रणाली संचालित करता है, व्यापार पर बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है

समझौते करता है, अपने सदस्यों के बीच व्यापार विवादों का निपटारा करता है और की जरूरतों का समर्थन करता है

विकासशील देश।

24.9 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. GATT पर एक नोट लिखें।
2. व्यापार संतुलन को परिभाषित करें।
3. डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य क्या हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन के बीच अंतर बताएं।
2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लाभों पर चर्चा करें।
3. विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का वर्णन करें।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका स्पष्ट करें।
2. GATT और WTO के बीच अंतर बताएं।
3. भारत और विश्व व्यापार संगठन में नवीनतम विकास का वर्णन करें।

24.10 शब्दावली

बीओटी: व्यापार संतुलन (बीओटी) किसी देश के निर्यात के कुल मूल्य को संदर्भित करता है

वस्तुएं और वस्तुओं के आयात का कुल मूल्य

बीओपी: भुगतान संतुलन (बीओपी) प्राप्तियों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है

अन्य देशों से भुगतान

एफडीआई: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रत्यक्ष निवेश है

किसी दूसरे देश में स्थित कंपनी द्वारा किसी देश में उत्पादन करना,

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनिमय या व्यापार कहा जाता है

विभिन्न राष्ट्रों के बीच वस्तुएँ और सेवाएँ।

विदेशी भंडार: इसे आम तौर पर आरक्षित मुद्राओं में रखा जाता है, आमतौर पर अमेरिकी डॉलर

और कुछ हद तक यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग। इसका उपयोग बैक करने के लिए किया जाता है

इसकी देनदारियां - जैसे जारी की गई देशी मुद्रा और आरबीआई द्वारा जमा किया गया भंडार भी।

डब्ल्यूटीओ: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है

राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला संगठन।

24.11 सन्दर्भ

1. इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र के लिए पाठ्यपुस्तक। टीएसबीआईई तेलंगाना।

2. एनसीईआरटी कक्षा 11, 12 अर्थशास्त्र

3. ब्रौ, बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र

4. इग्नू बीए अर्थशास्त्र

5. एनआईओएस अर्थशास्त्र

अध्याय पर्यावरण - आर्थिक विकास

25

25.0. उद्देश्य
25.1. परिचय
25.2. चेतन और निर्जीव पर्यावरण
25.3. पर्यावरण - महत्वपूर्ण अवधारणाएँ
25.4. पर्यावरण अनुभाग
25.5. पर्यावरणीय कर्तव्य
25.6. पर्यावरण-अर्थव्यवस्था संबंध 25.7. पर्यावरण की अवधारणाएँ
25.7.1. इको सिस्टम 25.7.2. इको सिस्टम के प्रकार
25.8. पर्यावरण प्रदूषण
25.8.1. प्रदूषक - प्रकार 25.8.2. प्रदूषण के प्रकार 25.9. पर्यावरणीय क्षरण 25.9.1. भूमि का निम्नीकरण
25.9.2. जंगलों
25.9.3. मिट्टी का कटाव
25.10. पर्यावरण की सुरक्षा
25.11. सतत विकास 25.11.1 सतत विकास - अवधारणाएँ 25.11.2. सतत विकास के लिए
25.12. सारांश 25.13. मॉडल परीक्षा प्रश्न 25.14. शब्दकोष
25.15. संदर्भ

25.0. उद्देश्य

पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंध स्पष्ट करें।

पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों को वर्गीकृत करें।

प्रदूषण के दुष्परिणामों का विश्लेषण कीजिए।

प्रदूषण की रोकथाम के उपाय बताए जाएंगे।

पर्यावरणीय संकट से बचने के उपाय बताएं।

सतत विकास की आवश्यकता बताइए।

25.1. परिचय

अंग्रेजी शब्द एनवायरनमेंट फ्रेंच शब्द एनवायरनर से लिया गया है। पर्यावरण मतलब घेरना. हमारे आस-पास की हर चीज़ को पर्यावरण कहा जाता है।

(हमारे आसपास क्या है? कोई अनुमान।)

हम सजीव और निर्जीव वस्तुओं से घिरे हुए हैं। सजीव वस्तुएँ कहलाती हैं सजीव वस्तुएँ और निर्जीव वस्तुएँ निर्जीव पर्यावरण वस्तुएँ कहलाती हैं। पर आधारित इस वर्णन को दो भागों में बाँटा गया है- सजीव एवं निर्जीव पर्यावरण।

"पर्यावरण एक जीवित जीव को प्रभावित करने वाले जीवित और भौतिक तत्वों का संयोजन है"

25.2. चेतन और निर्जीव पर्यावरण

सभी चेतन वस्तुएँ मिलकर सजीव वस्तुएँ कहलाती हैं। पौधे, पेड़, जानवर और मनुष्य सभी प्राणियों को एक साथ जैविक तत्व कहा जाता है। चट्टानें, पहाड़ियाँ, टीले, पहाड़, रेगिस्तान, घास के मैदान, पानी, गैसें, धूल के कण आदि सभी निर्जीव पदार्थ कहलाते हैं।

ये सभी निर्जीव और चेतन संरचनाएँ एक दूसरे पर निर्भर हैं। वे प्रत्येक को प्रभावित करते हैं पर्यावरण में अन्य. अतः इन तत्वों के बीच दो प्रकार के संबंध हैं।

वे हैं...

1. किसी भी ऊर्जा या पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
2. पदार्थ और ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होते हैं।

निर्जीव और सजीव वस्तुएँ परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं। एक कारक में परिवर्तन दूसरे कारक को प्रभावित करेगा. इस प्रकार मनुष्य इनके बीच एक केंद्रक के रूप में जी रहा है चेतन और निर्जीव तत्व और व्यापक संरचना। के ऊपर आश्रित,
इन्हीं कारकों से प्रभावित व प्रभावित होकर मनुष्य अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है।

25.3. पर्यावरणमहत्वपूर्ण अवधारणाएँ

जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे आमतौर पर पर्यावरण कहा जाता है। आधुनिक में पर्यावरण समय को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

पर्यावरण एक निश्चित स्थान पर मनुष्य के आसपास की स्थितियों की समग्रता है,
एक निश्चित समय पर।

जल, वायु, भूमि, मनुष्य, अन्य जीवित जीव, पौधे, सूक्ष्मजीव।

इन दोनों के बीच के संबंध को पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

आस-पास की परिस्थितियाँ, वस्तुएँ, नियम मिलकर पर्यावरण कहला सकते हैं।

पर्यावरण को उन सभी नियमों एवं प्रभावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विकास को प्रभावित करते हैं मनुष्य के साथ-साथ सभी प्रकार के जीवित प्राणियों का भी। इसमें सभी अच्छे और भी शामिल हैं मानवीय हस्तक्षेप और संपत्तियों के निर्माण से उत्पन्न होने वाले बुरे प्रभाव।

उपरोक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को सामूहिक रूप से सभी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है वे गतिविधियाँ और चीज़ें जो किसी जीवित जीव या जीवों को उसके जीवन चक्र के दौरान बदल देती हैं। मोटे तौर पर कहें तो उपरोक्त के साथ-साथ मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मनुष्य की बौद्धिक गतिविधियों को पर्यावरण कहा जा सकता है। इन मानवीय गतिविधियों के कारण, भौतिक वातावरण बदल जाता है।

इन परिभाषाओं को देखकर हमें एक और बात समझ में आती है। ये तो समझ आ गया यार जानवरों (जीवित चीजों) में से एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपने परिवेश को बदलने में सक्षम नहीं है उसके अनुकूल करने के लिए. यह भी ज्ञात है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है।

पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. जैविक कारक: पशु, पौधे, पौधे
2. भौतिक कारक: जल, जंगल, पहाड़, भूमि, वायु।
3. ऊर्जा कारक: पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा

4. सामाजिक कारक: शहरीकरण, मानवीय संबंध, रीति-रिवाज

5. मानसिक कारक: मानसिक परिपक्वता, ज्ञान, बुद्धि

6. सांस्कृतिक कारक: राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, धार्मिक कारक।

ये कारक एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सभी अलग-अलग हैं.

25.4. पर्यावरण अनुभाग

पर्यावरण को मुख्यतः चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

1. स्थलमंडल: स्थलमंडल पृथ्वी की सतह पर एक मोटी जमी हुई परत है। यह होते हैं मैदान, पठार, पहाड़ियाँ, घाटियाँ और जलीय क्षेत्र। इसमें जो चट्टानें, मिट्टी और अन्य सामग्रियां हैं परत जीवित जीवों के लिए उपयोगी है।

2. जलमंडल: पृथ्वी पर संपूर्ण जलराशि को जलमंडल कहा जाता है। तालाब, झीलें, नदियाँ और महासागर जलमंडल के सभी भाग हैं। भूजल भी इसका एक हिस्सा है।

3. वायुमंडल : पृथ्वी के चारों ओर फैली गैसों की परत को वायुमंडल कहते हैं। गैसें पसंद हैं इस वातावरण में धूल के साथ-साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हैं।

4. जीवमंडल: पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजों को सामूहिक रूप से जीवमंडल कहा जाता है। साथ में इसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्मजीव, पशु, पक्षी, पौधे और समुद्री जल शामिल हैं पारिस्थितिकी तंत्र। जीवमंडल तब तक जारी रहता है जब तक स्थलमंडल, वायुमंडल आदि मौजूद है जलमंडल. पर्यावरण इन सभी क्षेत्रों का संयोजन है। सब चेतन और चेतन चीजें इस पर निर्भर करती हैं। अर्थात् पर्यावरण का सम्बन्ध सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड से है। यह है कोई सीमा नहीं। मनुष्य इस पर्यावरण का केंद्र है, जो उन्हें बदल रहा है और प्रभावित कर रहा है सजीव और निर्जीव तत्वों के साथ संरचनाएं और सह-अस्तित्व।

25.5. पर्यावरणीय कर्तव्य

पर्यावरण चार प्रकार के कार्य करता है। वे हैं:

1. प्रजनन संसाधनों और गैर-प्रजनन संसाधनों की आपूर्ति करता है।
2. पर्यावरण में ठोस, तरल और गैसीय अपशिष्ट शामिल हैं। इसका मतलब है पर्यावरण अवशोषक के रूप में कार्य करता है।

3. पर्यावरण जैव विविधता, आनुवंशिक विविधता और जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है पारिस्थितिकी संतुलन। ये महत्वपूर्ण सेवाएँ अब तक उपयोग करने और परिवर्तित करने में मदद करती हैं अप्रयुक्त सामग्री और ऊर्जा को उपयोग में लाना।

4. पर्यावरण मानसिक परमानंद को प्रेरित करने, अनुभव करने के लिए प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करता है प्रकृति की सुंदरता।

पर्यावरण द्वारा किये जाने वाले उपरोक्त चार प्रकार के कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं. प्रत्येक कार्य दूसरे कार्य को प्रभावित करता है। यदि एक फ़ंक्शन अपने कार्य में विफल हो जाता है, अन्य फ़ंक्शन भी ठीक से काम नहीं करता है। ये कार्य अर्थव्यवस्था की दिशा तय करें.

25.6. पर्यावरण-अर्थव्यवस्था संबंध

पर्यावरण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। यह अवशोषित भी कर लेता है अर्थव्यवस्था से बर्बादी. आर्थिक दृष्टि से, द्वारा आपूर्ति किये गये सभी संसाधन पर्यावरण पर्यावरणीय संसाधन हैं। सभी जीवित वस्तुएँ पर्यावरणीय सामग्रियों का उपयोग करती हैं। इनसे निर्जीव प्राणी प्रभावित होते हैं।

मानवीय आर्थिक गतिविधियाँ, शोषण और उपेक्षा आपूर्ति पर सीमाएँ लगाती हैं पर्यावरणीय संसाधनों का. इससे सफाई क्षमता भी कम हो रही है पर्यावरण। ब्रिटिश अर्थशास्त्री केनेथ बॉल्डिंग ने 1966 में परिणामों की चेतावनी दी थी पर्यावरण के व्यर्थ उपयोग का. मानव जाति को इसका सेवन उतना ही कम करने की सलाह दी जाती है यथासंभव। उन्होंने कहा कि संतुलन होने पर ही पर्यावरण संतुलित रहता है उत्पाद.

25.7. पर्यावरण की अवधारणाएँ

पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। वायु, जल, पृथ्वी, हम अंतर्संबंध का अनुभव करते हैं हमारे बीच। यहाँ तक कि निर्जीव वस्तुएँ भी एक दूसरे के ऊपर हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनकी स्थिरता को विनियमित करें. पारिस्थितिकी ऐसी चीजों का अध्ययन करती है। यह के बीच संबंध का वर्णन करता है सजीव और निर्जीव वस्तुएँ। पर्यावरण को पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्ति को इसके बारे में जानना चाहिए पारिस्थितिकी.

25.7.1. पारिस्थितिकी तंत्र

एनक्लोजर सिस्टम में जीवित और निर्जीव चीजें शामिल होती हैं। वे अधीन हैं तापमान, धूप, हवा और वर्षा जैसी स्थितियाँ। जानवर और पौधे भी हैं उनके पर्यावरण से प्रभावित। इन सभी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का संयोजन एनक्लोजर है प्रणाली। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन शामिल होते हैं चक्र, ऊर्जा प्रवाह और खाद्य श्रृंखलाएँ। इनके माध्यम से परिक्षेत्र प्रणाली अपना कार्य करती है कार्य. इस प्रणाली में एक दूसरे को प्रभावित करता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी परिवर्तन करेगा पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व कठिन है।

25.7.2. इको सिस्टम के प्रकार

पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र।

1. प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र: एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक है। यह अपना कार्य स्वयं करता है। यह मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह मानव के बिना प्राकृतिक परिस्थितियों में काम करता है हस्तक्षेप। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। वे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र. उदाहरण: जंगल, घास के मैदान, झीलें, नदियाँ।

2. कृत्रिम घेरा प्रणाली: इस प्रणाली में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। मनुष्य बनाते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप रहित परिवर्तन। मनुष्य नियंत्रित और संशोधित करने का प्रयास करता है जीवित जीवों की विशेषताएं. परिवर्तन प्रौद्योगिकी और मानव के आधार पर होते हैं परिप्रेक्ष्य। शहरों का निर्माण, भूमिगत या पानी के नीचे संरचनाएँ, बीजों की क्लोनिंग, फसलें, मनुष्यों और जानवरों में आनुवंशिक संशोधन कृत्रिम पर्यावरण के उदाहरण हैं। इसके अलावा, वे मानव विचारों को व्यावहारिक रूप और परिणाम देते हैं। इसलिए ये प्रणालियाँ अत्यधिक संवेदनशील हैं. विविधता की कमी के कारण वे अक्सर असफल हो जाते हैं। उनमें स्वत्व नहीं है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विनियमन तंत्र। वे सीमाओं के अधीन हैं. जैसे हौड्रो पोनिक्स। मिट्टी या धूप की आवश्यकता के बिना पौधों की खेती करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है भोजन की कमी को हल करें. इसमें मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं शामिल हैं।

25.8. पर्यावरण प्रदूषण

प्रदूषण

प्रदूषण तब होता है जब किसी पदार्थ की मात्रा आवश्यकता से अधिक या कम होती है

पर्यावरण। उदाहरण के लिए, यदि वायुमंडल में पर्याप्त ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है,

यह प्रदूषण है. अच्छी फसल की पैदावार के लिए हम मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए फॉस्फेट और नाइट्रेट का उपयोग करते हैं।

इस मात्रा से अधिक होना प्रदूषण है। इस प्रदूषण से पर्यावरण प्रभावित होता है।

इन हानिकारक कारकों से पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा जाता है।

प्रदूषण कभी-कभी प्रकृति के कारण होता है। और कभी-कभी यह इंसान के कारण भी होता है।

मृदा अपरदन और ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक हैं। लेकिन प्रकृति सही कर देगी

यह। वायु प्रदूषण कई उद्योगों की स्थापना, उनकी पूर्ति के लिए वनों की कटाई के कारण होता है

जनसंख्या में वृद्धि और कंक्रीट निर्माण के कारण प्रदूषण के कारण आवश्यकताएँ। इंसान

प्रदूषण आज विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है।

25.8.1. प्रदूषक - प्रकार

प्रदूषण को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं...

क) गैर-निम्नीकरणीय प्रदूषक: प्रदूषक जो प्रवेश करने के बाद विघटित नहीं होते हैं

पर्यावरण को अविघटनीय प्रदूषक कहा जाता है। इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता. जैसे परमाणु

बरबाद करना।

ख) निम्नीकरणीय प्रदूषक: जो पर्यावरण में आसानी से घुल जाते हैं, कहलाते हैं

निम्नीकरणीय प्रदूषक. उदाहरण के लिए घरेलू कचरा और सब्जियां आसानी से अवशोषित हो जाती हैं

पर्यावरण।

ग) प्रदूषक जो धीरे-धीरे विघटित होते हैं...: ये अपनी स्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं

कई वर्ष और फिर पर्यावरण में विलीन हो जाते हैं। जैसे डीडीटी और प्लास्टिक आइटम। लेकिन अगर यह

शुद्धिकरण की मात्रा से अधिक होने पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है।

25.8.2. प्रदूषण के प्रकार

प्रदूषण तब होता है जब पर्यावरण में ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ अपना अस्तित्व खो देते हैं

पवित्रता.

1. जल प्रदूषण

जल विश्व की जीवित चीजों के लिए आवश्यक है। यदि इसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाएं जल में अधिकता होने पर वह अपनी शुद्धता खो देता है।

जल प्रदूषण के कारण:

उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण

खनन से निकले अपशिष्ट पदार्थ

कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक

कचरा

घरेलू अपशिष्ट उत्पाद

मानव अपशिष्ट

जल प्रदूषण के परिणाम:

1. साफ पानी नहीं मिलता.
2. दूषित पानी पीने से कई बीमारियाँ फैलती हैं।
3. जलाशयों के प्रदूषण से मछलियाँ जहरीली हो रही हैं।
4. पानी दुर्गन्धयुक्त हो जाता है।

जल प्रदूषण की रोकथाम:

1. खेती के लिए केवल जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए।
2. जल के पुनः उपयोग के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग यथासंभव कम करना चाहिए।
4. वर्षा जल को रोककर उसका उपयोग करना चाहिए।

2. वायु प्रदूषण

वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी कई गैसें हैं जो जीवित चीजों के लिए आवश्यक हैं। इन गैसों के मिश्रण को वायु कहते हैं। बिना हवा के, मनुष्य और अन्य प्राणी थोड़े समय के लिए भी जीवित नहीं रह सकते। वायु प्रदूषण यह तब होता है जब हवा में अन्य पदार्थों की अधिकता हो जाती है।

वायु प्रदूषण - कारण:

उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, खाना पकाने वाले गन्ने को जलाना, वाहनों से निकलने वाली ख़राब गैसें, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, परमाणु परीक्षण, बिजली उत्पादन और रेफ्रिजरेटर का उपयोग वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।

वायु प्रदूषण के परिणाम:

1. यह मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य को ख़राब करता है।
2. पौधों के प्रकाश संश्लेषण को रोकता है।
3. प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य को नष्ट कर देता है।
4. जलवायु को प्रभावित करता है जिससे अत्यधिक तापमान, अम्लीय वर्षा और सूखा होता है।

वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

1. वायु प्रदूषण के कारणों को पहचानें।
2. वैकल्पिक ईंधन स्रोत ढूँढना
3. उद्योगों में प्रदूषण कम करने वाले उपकरण लगाये जायें।
4. वायु कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन।
5. दोहराव वाले संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।

3. ध्वनि प्रदूषण

ध्वनि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के वाहनों, उद्योगों तथा लाउडस्पीकरों से होता है। मिट्टी के अनुचित उपयोग और कीटनाशकों के उपयोग के कारण मिट्टी प्रदूषित हो रही है।

25.9. वातावरण संबंधी मान भंग

प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। सभी मिट्टी, पानी, हवा, जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधन संकट में हैं।

25.9.1. भूमि का निम्नीकरण

सबसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि है। हम आश्रय, भोजन और हर चीज के लिए जमीन पर निर्भर हैं ज़रूरत। मानवीय स्वार्थ, वनों की कटाई, औद्योगीकरण और रसायनों के उपयोग के कारण पृथ्वी अपनी प्राकृतिक ऊर्जा खो रही है।

25.9.2. जंगलों

वन मनुष्य के लिए कई प्रकार से उपयोगी हैं। वनों से ऑक्सीजन, लकड़ी, जैसे कई फायदे हैं।

जंगली जानवरों और औषधियों के लिए आवास। जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी में वनों की भूमिका

संतुलन अथाह है. लेकिन मनुष्य लाखों वर्ग किलोमीटर जंगल काट रहा है

हर साल कृषि, उद्योग, लकड़ी, गन्ना पकाने के लिए।

वनों की कटाई के कारण:

1. गन्ना और लकड़ी का कोयला पकाने के लिए वनों पर निर्भरता
2. कागज के लिए लकड़ी का उपयोग करना
3. बढ़ी हुई जनसंख्या को समायोजित करने के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रावधान
4. जनसंख्या के अनुरूप उद्योगों एवं परिवहन मार्गों की स्थापना
5. खाद्य उत्पादन के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण
6. मवेशियों की नियमित चराई

वन संरक्षण के उपाय:

1. वन भूमि को उद्योगों के लिए आरक्षित न करें।
2. केवल बंजर भूमि को ही कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाना चाहिए।
3. बढ़ती जनसंख्या के लिए वन भूमि को मकान निर्माण के लिए आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।
4. वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसाय एवं उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. वनों की अवैध कटाई एवं पशुचारण पर सख्त कार्यवाही की जाये।

25.9.3. मिट्टी का कटाव

मिट्टी कंकड़, रेत और मिट्टी के खनिज कणों से बनी होती है। ऐसी मिट्टी हो रही है

मानवीय गतिविधियों के कारण अपमानित।

मृदा अपरदन-कारण:

कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, प्रथागत मवेशी चराई, बाढ़

तूफानों के दौरान पानी और हवा से मिट्टी का कटाव होता है और फसलों की खेती, खनन,

निर्माण गतिविधियाँ मृदा अपरदन का मुख्य कारण हैं।

मृदा अपरदन की रोकथाम:

1. वनरोपण
2. चेक डैम का निर्माण
3. कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और जैविक उर्वरकों का उपयोग करें
4. मवेशियों को चराने में सावधानी बरतनी चाहिए।
5. जल प्रवाह की गति को कम करने के लिए जमीन पर बांध और खाईयां बनानी चाहिए।

25.10. पर्यावरण की सुरक्षा

पर्यावरण इस पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजों से बना है। यह का नहीं है कोई भी। यह सभी जलीय जंतुओं, पक्षियों, जानवरों, मनुष्यों आदि के लिए उपयोगी है, लेकिन अकेले मनुष्य के लिए अपने लालच से पर्यावरण का अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग कर रहा है। परिणामस्वरूप, पर्यावरण नहीं है अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करने में सक्षम है।

माल्थस जैसे अर्थशास्त्रियों ने पर्यावरण संकट के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन मनुष्य ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मिशान द्वारा 'द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ', राचेल कारसेल द्वारा 'द साइलेंट स्प्रिंग' और 'लिमिट्स' मीडोज द्वारा 'टू ग्रोथ' ने दुनिया को पर्यावरण संकट के बारे में आगाह किया।

इस संकट के तीन कारण पहचाने गए हैं. वे हैं:

1. जनसंख्या
2. प्रति व्यक्ति उत्पादन (उपभोग)
3. किसी आर्थिक वस्तु द्वारा उत्पन्न औसत प्रदूषण

इन कारणों से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है और कृषि उत्पादन कम हो रहा है इस ग्रह पर घट रही है. खाद्य सुरक्षा खतरे में है. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्रीन हाउस गैसों का असर हो रहा है. महाद्वीपीय क्षेत्रों और समुद्र तल पर बर्फ पिघलती है उठना। इस प्रकार पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, जलीय जीव-जंतु प्रभावित होते हैं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, देश संगठनों, परिषदों और कानूनों के माध्यम से काम कर रहे हैं प्रदूषण को रोकें. अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं. इन सबका कारण मनुष्य ही है। यह मानव है जिसे भविष्य में परिणाम भुगतने होंगे।

25.11. सतत विकास

सतत विकास का अर्थ वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है

भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता। धारित्रि सम्मेलन 1992 में आयोजित हुआ

स्थिरता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें भविष्य में मानव कल्याण समाप्त नहीं होगा।

अमीर देश सोचते हैं कि विकास का मतलब आर्थिक विकास है। विकास है

मनुष्य में मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन माने जाते हैं। लेकिन पर्यावरण,

जो मानव कल्याण के लिए उत्तरदायी है, उसकी पवित्रता को भुला दिया गया है। सतत विकास

इसे तभी प्राप्त किया जा सकता है जब संसाधनों के उपयोग और उनके पुनरुत्पादन के बीच संतुलन हो।

सतत विकास शब्द को भी महत्व मिला है।

25.11.1 सतत विकास - अवधारणाएँ

स्थिरता में तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएँ शामिल हैं। वे पर्यावरणीय, सामाजिक हैं

और आर्थिक अवधारणाएँ। सतत विकास तभी संभव है जब संतुलन हासिल किया जाए

इन तीनों के बीच.

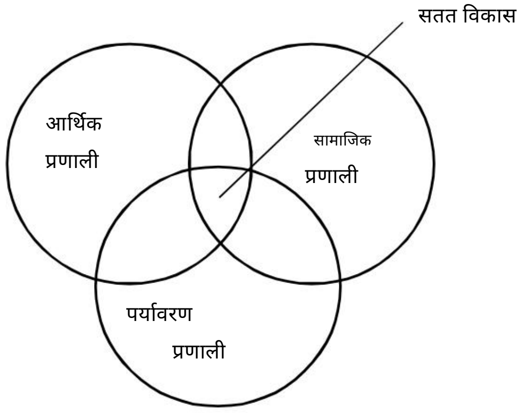

चित्र-1: सतत विकास

उपरोक्त तीन अवधारणाओं के संतुलन के लिए.. भविष्य के संसाधन

हमें जो संसाधन मिल रहे हैं, उनसे पीढ़ियाँ कम नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण एवं मानव-

अर्जित संपत्तियां भी भावी पीढ़ियों को विरासत में मिलनी चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और

पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मानव कल्याण टिकाऊ हो

आने वाली पीढ़ियों के लिए भी.

25.11.2. सतत विकास के लिए

1. हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम पृथ्वी से संबंधित हैं। और ये धरती हमारी नहीं है.
2. मानवीय कार्यों से किसी एक प्रजाति का विनाश नहीं होना चाहिए।

3. प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए।

4. यह मानना चाहिए कि इस धरती पर हर जीव को जीने का समान अधिकार है
मनुष्य के रूप में.

5. भौतिक, रासायनिक। जैविक संसाधन ख़त्म नहीं हुए हैं.

25.12. सारांश

जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह सबका है पर्यावरण को महत्व देना और यह सुनिश्चित करना कि इसका दुरुपयोग न हो, जिम्मेदारी है। प्राथमिकता होनी चाहिए सतत विकास को दिया गया जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है और कोई कमी नहीं छोड़ता है भावी पीढ़ियों के लिए.

25.13. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. वायु प्रदूषण से होने वाली हानियाँ लिखिए
2. वनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये जाने चाहिए?
3. पर्यावरण के तत्वों का वर्णन करें।
4. कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है?
5. जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को समझाइये।
2. पर्यावरण के कार्यों को समझाइये।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. वनों की कटाई के कारणों के बारे में लिखिए।
2. प्रदूषण को परिभाषित करें
3. पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इसके भागों का उल्लेख करें।
4. वायु प्रदूषण को समझाइये।
5. सतत विकास क्या है?

25.14. शब्दकोष

पर्यावरण: पर्यावरण मनुष्य के चारों ओर मौजूद स्थितियों की समग्रता है

किसी निश्चित समय का स्थान दिया गया।

प्रदूषण: प्रदूषण तब होता है जब कोई पदार्थ पर्यावरण में जितना होना चाहिए उससे अधिक या कम होता है।

सतत विकास: सतत विकास का तात्पर्य लोगों की जरूरतों को पूरा करना है

भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान।

25.15. संदर्भ

1. डॉ.बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय- डिग्री अर्थशास्त्र

2. तेलुगु अकादमी इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र, द्वितीय वर्ष

3. अनिल मार्कंड्य और अन्य (2004): सतत विकास के लिए पर्यावरण अर्थशास्त्र, एडगर एलन, न्यूयॉर्क।

4. चन्द्रशेखर एम, शंकर राव ई (2004) पर्यावरण विज्ञान, द हाईटेक प्रकाशक, हैदराबाद।

अध्याय

26

गठन के बाद तेलंगाना अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास

26.0. उद्देश्य

26.1. परिचय

26.2. अलग तेलंगाना राज्य के लिए छह दशक का संघर्ष

26.3. तेलंगाना राज्य का विकास

26.4. जीएसडीपी, जीएसवीए, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान

26.5. राज्य गठन के वर्ष से तेलंगाना का सफर बढ़ता जा रहा है

26.6. प्रति व्यक्ति आय

26.7. क्षेत्रीय रचना

26.8. सारांश

26.9. शब्दकोष

26.10. संदर्भ

26.0. उद्देश्य

इस पाठ का मूल उद्देश्य संरचना, विकास, पर वैचारिक ज्ञान प्रदान करना है।

और तेलंगाना अर्थव्यवस्था के रुझान और यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर भी ध्यान केंद्रित करता है

(जीएसडीपी), सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए), प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) और क्षेत्रीय

तेलंगाना अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों की संरचना।

- गठन के बाद तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की संरचना और विकास।
- वर्तमान और स्थिर कीमतों में जीएसडीपी, जीएसवीए और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान।
- तेलंगाना में जीएसडीपी और जीएसवीए की क्षेत्रीय संरचना।
- सकल जिला घरेलू उत्पाद और जिलेवार प्रति व्यक्ति आय में रुझान
  तेलंगाना.

26.1. परिचय

आंध्र राज्य 1 अक्टूबर 1953 को अस्तित्व में आया, जो तत्कालीन का एक हिस्सा था

मद्रास के समग्र राज्य के लिए लंबे समय तक तेलुगु भाषी लोगों ने संघर्ष किया

एक अलग राज्य के गठन में एक दशक लग गया क्योंकि उन्हें लगा कि राज्य में उनके साथ भेदभाव किया जाता है

तमिलों द्वारा और संघर्ष जारी रहा, जब पोट्टी श्री रामुलु ने एक हिंसक मोड़ ले लिया

दिसंबर 1952 में गांधीवादी अनुयायी की मृत्यु हो गई। तब भारत सरकार बनाने का निर्णय लिया गया

1953 में आंध्र प्रदेश राज्य।

26.2. अलग तेलंगाना राज्य के लिए छह दशक का संघर्ष

- 1956 का जेंटलमैन समझौता।
- जय तेलंगाना आंदोलन 1969 में शुरू हुआ।
- पांच सूत्री फॉर्मूला 1970 का आठ सूत्री फॉर्मूला 1969।
- 1972 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय।
- छह सूत्री फॉर्मूला 1973.
- 1985 का जीओ नंबर 610 और गिरगलानी आयोग की रिपोर्ट

भारतीय गणराज्य के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का जन्म एक शुरुआत का प्रतीक है

एक सिरा। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था और यह चारों ओर से चारों ओर से घिरा हुआ राज्य है

यह राज्य दक्षिणी भारत प्रायद्वीप और दक्कन पठार में स्थित है, जिसका केंद्र हैदराबाद है

पूंजी। यह क्षेत्र 15''500N से 19''510N अक्षांश और 77''150E से 89''160E के बीच स्थित है।

देशांतर. इसकी सीमा उत्तर में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में कर्नाटक से लगती है

पश्चिम और दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश। तेलंगाना 12वें स्थान पर है

जनसंख्या की दृष्टि से यह देश भौगोलिक दृष्टि से 11वें स्थान पर है। क्षेत्र है

79% और 69% जलग्रहण क्षेत्रों के साथ मुख्य रूप से गोदावरी और कृष्णा नदियों द्वारा जल निकासी होती है

क्रमश। राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। अन्य भाषाएँ

उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी, तमिल, मराठी, बंगाली, कन्नड़ आदि का उपयोग किया जाता है।

राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है। 33 जिले हैं

तेलंगाना में. 74 राजस्व प्रभाग, 612 राजस्व मंडल और 10909 राजस्व हैं

राज्य के गाँव. स्थानीय निकाय, राज्य में 12769 ग्राम पंचायतें, 129 नगर पालिकाएँ हैं

और 13 नगर निगम। विधायी प्रभाग 119 विधानसभा क्षेत्र हैं

और 2022 में तेलंगाना राज्य में 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

26.3. तेलंगाना राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

तेलंगाना के जन्म की पृष्ठभूमि के रूप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर यहां चर्चा की गई है।

यह 1 नवंबर 1956 को पूर्व एपी राज्य (1 जून 2014 तक अस्तित्व में) था

हैदराबाद राज्य को पूर्व आंध्र राज्य के साथ विलय करके गठित किया गया।

पूर्व हैदराबाद राज्य

224 वर्षों तक निज़ामों (आसा-जही वंश) द्वारा शासित हैदराबाद राज्य को विभाजित किया जा सकता है

दो चरण, (ए) चरण- I: 1724-1857 और (बी) चरण- II: 1857-1948। पहला चरण हो सकता है

इसे अधिकतर कृषि पर निर्भर अवधि के रूप में माना जाता है। दूसरे चरण को इस प्रकार माना जा सकता है

वह काल जिसमें औद्योगिक विकास की नींव रखी गई।

इसकी अपनी मुद्रा और प्रशासनिक व्यवस्था थी। उर्दू वहाँ की राजभाषा थी

साम्राज्य। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम भी उर्दू में ही था।

15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ , तो हैदराबाद राज्य के तत्कालीन शासक,

मीर उस्मान अली खान (सातवें निज़ाम) ने राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में बनाए रखना पसंद किया।

भारत सरकार ने निज़ाम को हैदराबाद राज्य के विलय के लिए बाध्य किया

भारतीय संघ ने एक सशस्त्र हस्तक्षेप के माध्यम से जो इतिहास में पुलिस कार्रवाई के रूप में दर्ज किया गया।

यह विलय 17 सितम्बर 1948 को हुआ। वर्ष 1952 में आम चुनाव हुए।

राज्य विधानसभा में आयोजित किए गए और डॉ. बर्गुला के साथ एक लोकप्रिय सरकार ने सत्ता संभाली

राम कृष्ण राव आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में।

26.4. जीएसडीपी, जीएसवीए और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अंतिम वस्तुओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है

राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सेवाएँ। जीएसडीपी सबसे अधिक है

किसी राज्य की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक। जीएसडीपी दोनों को मापा जाता है

मौजूदा और स्थिर कीमतों पर.

चालू वर्ष की प्रचलित कीमतों के अनुमान को "वर्तमान में" कहा जाता है

कीमतें" जबकि आधार वर्ष की कीमतों पर तैयार की गई कीमतों को "स्थिर कीमतों पर" कहा जाता है

स्थिर कीमतों पर अनुमानों की तुलना, जिसका अर्थ वर्षों में वास्तविक अर्थों में है

वास्तविक वृद्धि का माप देता है। स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति के लिए समायोजन करती हैं

आधार वर्ष मूल्य स्तर का आधार जिसे "डिफ्लेटर" कहा जाता है।

तेलंगाना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में वृद्धि और रुझान

2021-22 में मौजूदा कीमतों पर तेलंगाना का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)।

(एई) 11.55 लाख करोड़ रुपये है। तेलंगाना का जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2018-19 में बढ़कर 19.1% हो गया।

2021-22.

जबकि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था इससे उत्पन्न उथल-पुथल से पूरी तरह अछूती नहीं थी

COVID-19 महामारी के बावजूद, राज्य अभी भी GDSP में वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहा

2020-21 में मौजूदा कीमतें।

26.5. राज्य गठन के वर्ष से तेलंगाना की विकास यात्रा

2014-15 में तेलंगाना की नाममात्र विकास दर भारत की तुलना में 1% अंक अधिक हो गई। 2020-21 तक लक्ष्य बढ़कर 3.6% अंक हो गया था, उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर गिरावट आई 2021-22 में महामारी से उबरी अर्थव्यवस्था, तेलंगाना की नॉमिनल जीएसडीपी 21.8% 2021-22 में उच्चतर, जबकि भारतीय नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में दो वर्षों में केवल 17.8% की वृद्धि हुई है साल। तेलंगाना ने 2020-21 में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 4.1% का योगदान दिया। राज्य बन गया 14 सामान्य श्रेणी के बीच राष्ट्रीय नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद में छठा सबसे बड़ा योगदानकर्ता डेटा उपलब्धता वाले राज्य। 2014-15 से 2021-22 के बीच राज्य का योगदान भारत की नॉमिनल जीडीपी 4.1% से बढ़कर 4.9% हो गई।

स्थिर (2011-22) कीमतों पर जीएसडीपी

वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान (एई) आंकड़ों के आधार पर, तेलंगाना के स्थिर (2011-12) कीमतों पर जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 11.2% बढ़ गई। राज्य प्रदर्शन भारत की तुलना में काफी बेहतर था जिसमें वृद्धि का अनुभव हुआ 2021-22 में वास्तविक जीडीपी 8.9%।

मौजूदा कीमतों पर भारत की जीडीपी में तेलंगाना की जीएसडीपी का योगदान (2014-15 से) 2021-22)

तालिका: तेलंगाना (जीएसडीपी) और भारत (जीडीपी) स्थिर कीमतों पर

(लाख करोड़ रुपये और जीडीपी वृद्धि%)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17 2017-18		2018-19 2019-20 2020-21			2021-22
तेलंगाना 4.2 6.8% 4.711.6% 5.19.3% 5.69.7%					6.19.1% 6.45.0% 6.2-3.5% 6.911.2%			
भारत	10.53 7.4% 113.78.0% 123.18.3% 131.56.8% 139.96.5% 145.23.7% 135.6-6.6% 1478.9%							

26.6. प्रति व्यक्ति आय

जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाता है, किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आर्थिक विकास का बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय है (पीसीआई) वर्ष 2020-21 में।

वर्ष 2021-22 में, तेलंगाना का नाममात्र पीसीआई (एई) बढ़कर 2.7 लाख रुपये हो गया था। तेलंगाना का पीसीआई वर्ष से लगातार औसत राष्ट्रीय पीसीआई से अधिक रहा है राज्य गठन का. 2014-15 में, तेलंगाना का पीसीआई राष्ट्रीय पीसीआई से 1.43 गुना था (तेलंगाना का पीसीआई राष्ट्रीय पीसीआई से 37,457 रुपये अधिक था)। 2021-22 तक, गुणक बढ़कर 1.86 हो गया था (तेलंगाना का पीसीआई राष्ट्रीय पीसीआई से 1,28,985 रुपये अधिक था)।

$$\text{प्रति व्यक्ति आय} = \frac{\text{कुल राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल राष्ट्रीय जनसंख्या}}$$

राज्यों के गठन के बाद प्रत्येक वर्ष तेलंगाना का पीसीआई न केवल भारत से अधिक रहा है, लेकिन यह उन सभी वर्षों में भारत की तुलना में अधिक दर से बढ़ा है।

2020-21 में तेलंगाना और भारत के लिए पीसीआई की विकास दर की तुलना, जबकि भारत COVID-19 महामारी के कारण इसके नाममात्र पीसीआई में भारी गिरावट का अनुभव हुआ (-4.0%), 2021-22 में तेलंगाना पीसीआई उस वर्ष भी (1.6%) बढ़ी। राज्य ने देखा नाममात्र पीसीआई में 18.8% की उच्चतम वृद्धि, जो राष्ट्रीय नाममात्र से लगभग 0.7% अधिक है पीसीआई विकास दर.

26.7. क्षेत्रीय रचना

किसी भी राज्य की जीएसडीपी को तीन आर्थिक योगदानकर्ताओं के आधार पर मापा जाता है प्रमुख क्षेत्र। वे कृषि और संबद्ध क्षेत्र, खनन और उत्खनन सहित उद्योग हैं। और सेवाएँ। 2201-22 में तेलंगाना के लिए जीएसवीए के अग्रिम अनुमान (एई) के आधार पर, मौजूदा कीमतों पर तेलंगाना जीएसवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 61.3% है औद्योगिक क्षेत्र (20.4%) और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (18.3%)।

राज्य के कुल जीएसवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ गई 2014-15 में 16.3% से 2021-22 में 18.3% हो गया। जबकि राष्ट्रीय जीवीए में इसकी हिस्सेदारी बनी रही मोटे तौर पर (दोनों वर्षों में लगातार 18.5% के करीब), इसके योगदान में वृद्धि हुई है तेलंगाना में यह क्षेत्र इसकी नाममात्र विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित था 2014-15 में नकारात्मक 0.6% से 2021-22 में 9.09%।

चूंकि औद्योगिक विकास रोजगार सृजन और दूसरी ओर उत्पादकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है क्षेत्रों में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने कई उपाय किए हैं औद्योगिक क्षेत्र का विकास. इनमें TS-IPASS, T-IDEAand जैसे बिजनेस सुधार शामिल हैं टी-प्राइड और एमएसएमई क्षेत्र के लिए कई पहल।

2021-22 में राज्य के मूल्यवर्धित मूल्य में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 61.3% था, और इसलिए यह तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। राज्य में इसकी हिस्सेदारी नाममात्र जीएसवीए (61.3%) भारत के नाममात्र जीवीए (52.8%) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी से बड़ा है।

क्षेत्रीय विकास दर

तेलंगाना का कृषि और संबद्ध क्षेत्र पिछले 7 वर्षों से उन्नति पथ पर है वर्ष 2014-15 के बीच इसकी वर्तमान मूल्य वृद्धि दर में 9.75% अंक की वृद्धि हुई है 2021-22. शिखर के दौरान भी इस क्षेत्र की विकास दर भारत की तुलना में अधिक थी 2020-21 में महामारी की। जबकि देश के कृषि और संबद्ध क्षेत्र में वृद्धि हुई 2020-21 में 7.48%, तेलंगाना के कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 12.24% की वृद्धि का अनुभव उस वर्ष के दौरान मौजूदा कीमतों पर। यह कई कारकों के माध्यम से हासिल किया गया है इसमें कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जैसी नई सिंचाई योजनाएं शामिल हैं मिशन काकतीय और रायथु बंधु योजना जैसी नवीन कृषि सहायता नीतियां और रायथु भीमा और कृषि क्षेत्र को 24x7 मुफ्त बिजली आपूर्ति और न्यूनतम भी समान फसलों में समर्थन मूल्य लागू किया गया।

तेलंगाना में औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 में महामारी से मजबूत सुधार देखा गया पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय 20.23% की दर से बढ़ रहा है। उद्योग और विनिर्माण उप-क्षेत्र जो किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है, तेलंगाना में सबसे तेज सुधार देखा गया। तेलंगाना ने 2021-22 में 28.59% की वार्षिक वृद्धि दर देखी। इसकी तुलना में, वृद्धि भारत में इस उप-क्षेत्र की दर तेलंगाना से 22.78% (5.81% अंक) कम थी। खनन और उत्खनन उप-क्षेत्र में 13.24% की वृद्धि देखी गई, इसके बाद निर्माण, उप-क्षेत्र का स्थान रहा। क्षेत्र जिसमें 10.38% की वृद्धि हुई और बिजली और उपयोगिता उप-क्षेत्र, जिसमें वृद्धि हुई 7.38%।

26.8. सारांश

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) सभी अंतिम वस्तुओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है
राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सेवाओं को बाहर गिना जाता है
एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान नकल, आमतौर पर एक वर्ष। कुल मिलाकर विकास दर
तेलंगाना में जीएसडीपी की वृद्धि दर भारत की जीडीपी वृद्धि दर से अधिक थी। 2011-12 के दौरान
2018-19, वर्तमान और स्थिर दोनों कीमतों पर अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में तेलंगाना की हिस्सेदारी
4.11% और 4.5% के बीच था। जीएसडीपी और वार्षिक के क्षेत्रीय वितरण के संबंध में
औसत विकास दर, कुल मिलाकर 2012-13 के दौरान तेलंगाना में मिश्रित रुझान रहा
2018-19 चालू और स्थिर दोनों कीमतों में।

तेलंगाना अर्थव्यवस्था में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के क्षेत्रीय योगदान के मामले में,
इसके विपरीत, कृषि और उद्योग दोनों के शेयरों के विकास पैटर्न में अस्थिरता है
इस दौरान सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी में क्रमिक और स्थिर वृद्धि हुई है
2011-12 से 2021-22. 2011-12 से 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई)
मौजूदा कीमतों पर अखिल भारतीय पीसीआई की तुलना में तेलंगाना राज्य में बहुत तेजी से वृद्धि हुई।

26.9. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. टीएस आई-पास
2. प्रति व्यक्ति आय
3. विकास दर

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. तेलंगाना के एसजीडीपी के विकास पैटर्न के बारे में संक्षेप में लिखें।
2. तेलंगाना अर्थव्यवस्था की क्षेत्रीय विकास दर प्रवृत्तियों के बारे में बताएं।

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. जीएसडीपी क्या है? तेलंगाना में जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय के रुझान की व्याख्या करें।
2. तेलंगाना के सकल राज्य मूल्य वर्धित के क्षेत्रीय योगदान पर एक निबंध लिखें
   अर्थव्यवस्था।

26.9. शब्दकोष

1. जीएसडीपी: राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) सभी अंतिम के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है

राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बाहर गिना जाता है

समय की एक विशेष अवधि के दौरान नकल, आमतौर पर एक वर्ष।

2. वार्षिक वृद्धि दर AGR= $\frac{\text{चालू वर्ष का मूल्य - पिछले वर्ष का मूल्य x 100}}{\text{पिछले वर्ष का मूल्य}}$

3. वर्तमान और स्थिर कीमतें: चालू वर्ष की प्रचलित कीमत पर अनुमान हैं

वर्तमान कीमतों पर तैयार की गई कीमतों को स्थिर कहा जाता है, जबकि आधार वर्ष की कीमतों पर तैयार की गई कीमतों को स्थिर कहा जाता है

कीमतें.

4. क्षेत्रीय योगदान: यह कुल में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक का हिस्सा दर्शाता है

सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए)।

26.10. संदर्भ

1. तेलंगाना योजना विभाग, सामाजिक आर्थिक आउटलुक 2021-22।
2. अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार, सांख्यिकीय वर्ष पुस्तक 2021।
3. तेलुगु अकादमी (2020) इंटरमीडिएट द्वितीय वर्ष की पाठ्यपुस्तक।
4. तेलुगु अकादमी (2016) तेलंगाना अर्थव्यवस्था।
5. डॉ. बीआर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, तेलंगाना अर्थव्यवस्था बीए सेमेस्टर-VI पुस्तक

Annexure 9

Gross Domestic Product and Per Capita Income of All India at Current Prices from 2014-15 to 2020-21

(Rs. in crore)

Sl. No.	Sector	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (TRE)	2019-20 (SRE)	2020-21 (FRE)	2021-22 (SAE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agriculture, Livestock, Forestry and Fishing	20,93,612	22,27,533	25,18,662	28,29,826	30,29,925	33,58,364	36,09,494	
1.1	Crops	12,92,874	13,27,992	14,86,044	16,33,264	16,80,777	18,91,966	19,97,147	
1.2	Livestock	5,10,411	5,82,410	6,72,611	7,85,683	8,82,009	9,77,730	11,14,249	
1.3	Forestry and Logging	1,73,760	1,84,411	2,05,364	2,17,603	2,55,053	2,60,603	2,65,479	
1.4	Fishing and Aquaculture	1,16,567	1,32,720	1,54,643	1,93,275	2,12,087	2,28,065	2,32,620	39,64,312
2	Mining and Quarrying	3,08,476	2,94,011	3,26,808	3,36,109	3,77,661	3,58,517	3,24,980	5,18,170
	Primary	**24,02,088**	**25,21,544**	**28,45,470**	**31,65,935**	**34,07,586**	**37,16,881**	**39,34,474**	**44,82,482**
3	Manufacturing	18,78,369	21,46,189	23,33,721	25,66,623	28,12,560	27,04,809	27,09,435	33,26,746
4	Electricity, Gas, Water supply and Other Utility Services	2,82,258	3,34,965	3,55,709	4,25,718	4,49,459	5,01,618	5,07,352	5,70,125
5	Construction	9,79,086	9,91,084	10,80,870	12,00,414	13,52,118	13,72,759	13,15,608	17,02,055
	Secondary	**31,39,713**	**34,72,238**	**37,70,300**	**41,92,755**	**46,14,137**	**45,79,186**	**45,32,395**	**55,98,926**
6	Trade, Repair, Hotels and Restaurants	13,20,833	14,33,969	16,09,001	18,81,395	21,36,707	23,25,812	18,18,981	
6.1	Trade and Repair Services	12,06,474	13,07,323	14,68,583	17,22,671	19,55,798	21,29,686	17,32,821	
6.2	Hotels and Restaurants	1,14,359	1,26,646	1,40,418	1,58,723	1,80,909	1,96,127	86,160	
7	Transport, Storage, Communication & Services related to Broadcasting	7,86,763	8,60,544	9,30,155	9,97,528	10,66,055	11,52,680	10,47,412	35,43,624
7.1	Railways	92,459	1,00,451	1,06,786	1,16,584	1,23,596	1,35,477	1,36,807	
7.2	Road Transport	3,70,364	3,99,902	4,34,947	4,84,134	5,36,552	5,65,438	4,47,164	
7.3	Water Transport	7,590	7,298	9,206	13,021	13,059	13,350	13,418	
7.4	Air Transport	11,820	20,344	21,496	22,444	12,730	22,508	10,323	
7.5	Services incidental to Transport	91,681	88,246	1,02,468	97,602	1,03,341	1,03,301	98,170	
7.6	Storage	6,407	7,021	7,442	16,194	18,597	19,513	19,628	
7.7	Communication & Services related to Broadcasting	2,06,442	2,37,282	2,47,809	2,47,549	2,58,179	2,93,094	3,21,902	
8	Financial Services	6,61,411	7,26,286	7,50,201	8,46,194	9,41,778	10,27,359	10,88,222	45,67,241
9	Real Estate, Ownership of Dwellings and Professional Services	17,01,935	18,99,852	21,61,236	22,81,018	25,87,720	28,51,979	29,57,538	
10	Public Administration and Defence	6,76,818	7,31,578	8,27,438	9,45,082	10,45,488	11,47,741	12,38,383	
11	Other Services	8,14,718	9,28,489	10,71,399	11,95,759	13,75,658	15,53,471	14,40,404	31,65,000
	Tertiary	**59,62,478**	**65,80,718**	**73,49,430**	**81,46,976**	**91,53,406**	**1,00,59,042**	**95,90,940**	**1,12,75,865**
12	**Total GSVA at Basic Prices**	**1,15,04,279**	**1,25,74,499**	**1,39,65,200**	**1,55,05,665**	**1,71,75,128**	**1,83,55,109**	**1,80,57,810**	**2,13,57,273**
13	Taxes on Products	12,91,662	15,18,496	17,46,288	18,98,896	20,43,568	20,76,662	22,55,495	
14	Subsidies on Products	3,27,982	3,21,121	3,19,819	3,14,518	3,19,028	3,56,916	5,12,391	22,86,602
15	**Gross Domestic Product**	**1,24,67,959**	**1,37,71,874**	**1,53,91,669**	**1,70,90,042**	**1,88,99,668**	**2,00,74,856**	**1,98,00,914**	**2,36,43,875**
16	**Per Capita Income (Rs.)**	**86,647**	**94,797**	**1,04,880**	**1,15,224**	**1,25,946**	**1,32,115**	**1,26,855**	**1,49,848**

SAE-Second Advance Estimates, FRE- First Revised Estimates, SRE- Second Revised Estimates, TRE- Third Revised Estimates

Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India

Annexure 10

Sectoral Growth Rates (%) of Gross Domestic Product and Per Capita Income of all India at Current Prices

(Percent)

Sl. No.	Sector	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (TRE)	2019-20 (SRE)	2020-21 (FRE)	2021-22 (SAE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Agriculture, Livestock, Forestry and Fishing	6.4	13.1	12.4	7.1	10.8	7.5	
1.1	Crops	2.7	11.9	9.9	2.9	12.6	5.6	
1.2	Livestock	14.1	15.5	16.8	12.3	10.9	14.0	
1.3	Forestry and Logging	6.1	11.4	6.0	17.2	2.2	1.9	
1.4	Fishing and Aquaculture	13.9	16.5	25.0	9.7	7.5	2.0	9.8
2	Mining and Quarrying	-4.7	11.2	2.8	12.4	-5.1	-9.4	59.4
	Primary	**5.0**	**12.8**	**11.3**	**7.6**	**9.1**	**5.9**	
3	Manufacturing	14.3	8.7	10.0	9.6	-3.8	0.2	22.8
4	Electricity, Gas, Water supply and Other Utility Services	18.7	6.2	19.7	5.6	11.6	1.1	12.4
5	Construction	1.2	9.1	11.1	12.6	1.5	-4.2	29.4
	Secondary	**10.6**	**8.6**	**11.2**	**10.1**	**-0.8**	**-1.0**	
6	Trade, Repair, Hotels and Restaurants	8.6	12.2	16.9	13.6	8.9	-21.8	
6.1	Trade and Repair Services	8.4	12.3	17.3	13.5	8.9	-18.6	
6.2	Hotels and Restaurants	10.7	10.9	13.0	14.0	8.4	-56.1	
7	Transport, Storage, Communication & Services related to Broadcasting	9.4	8.1	7.2	6.9	8.1	-9.1	
7.1	Railways	8.6	6.3	9.2	6.0	9.6	1.0	
7.2	Road Transport	8.0	8.8	11.3	10.8	5.4	-20.9	
7.3	Water Transport	-3.8	26.1	41.4	0.3	2.2	0.5	
7.4	Air Transport	72.1	5.7	4.4	-43.3	76.8	-54.1	
7.5	Services incidental to Transport	-3.7	16.1	-4.7	5.9	0.0	-5.0	
7.6	Storage	9.6	6.0	117.6	14.8	4.9	0.6	
7.7	Communication & Services related to Broadcasting	14.9	4.4	-0.1	4.3	13.5	9.8	23.6
8	Financial Services	9.8	3.3	12.8	11.3	9.1	5.9	
9	Real Estate, Ownership of Dwellings and Professional Services	11.6	13.8	5.5	13.4	10.2	3.7	12.9
10	Public Administration and Defence	8.1	13.1	14.2	10.6	9.8	7.9	
11	Other Services	14.0	15.4	11.6	15.0	12.9	-7.3	18.2
	Tertiary	**10.4**	**11.7**	**10.9**	**12.4**	**9.9**	**-4.7**	
12	**Total GSVA at Basic Prices**	**9.3**	**11.1**	**11.0**	**10.8**	**6.9**	**-1.6**	**18.3**
13	Taxes on Products	17.6	15.0	8.7	7.6	1.6	8.6	
14	Subsidies on Products	-2.1	-0.4	-1.7	1.4	11.9	43.6	
15	**Gross Domestic Product**	**10.5**	**11.8**	**11.0**	**10.6**	**6.2**	**-1.4**	**19.4**
16	**Per Capita Income (Rs.)**	**9.4**	**10.6**	**9.9**	**9.3**	**4.9**	**-4.0**	**18.1**

SAE-Second Advance Estimates, FRE- First Revised Estimates, SRE- Second Revised Estimates, TRE- Third Revised Estimates
Source: Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India

अध्याय 27

मानव संसाधन

27.0. उद्देश्य

27.1. परिचय

27.2. तेलंगाना की जनसांख्यिकीय विशेषताएं

27.2.1. तेलंगाना में जनसंख्या का आकार

27.2.2. तेलंगाना में जनसंख्या का घनत्व

27.2.3. जनसंख्या की साक्षरता दर

27.3. जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

27.4. तेलंगाना में मानव संसाधन विकास

27.5. शिक्षा क्षेत्र में सरकार की भूमिका

27.5.1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009

27.5.2. अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान

27.5.3. गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना

27.5.4. मन ऊरु - मन बड़ी / मन बस्ती- मन बड़ी योजना

27.5.5. सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार

27.5.6. सीखने के अवसरों का विस्तार:

27.5.7. उद्योग-शिक्षा साझेदारी का निर्माण:

27.5.8. 2021- 26 की तेलंगाना आईसीटी नीति

27.6. स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका

27.7. सारांश

27.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

27.9. शब्दकोष

27.10. संदर्भ

27.0. उद्देश्य

- तेलंगाना की जनसांख्यिकीय विशेषताओं का वर्णन करें।
- जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण को समझाइये।
- तेलंगाना में मानव संसाधन विकास का विश्लेषण करता है।
- तेलंगाना में स्वास्थ्य और शिक्षा की भूमिका स्पष्ट करें।

27.1 परिचय

तेलंगाना भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तक यह आंध्र प्रदेश का हिस्सा था जून 2014. एक अलग राज्य के लिए दशकों के आंदोलन के बाद, तेलंगाना का गठन किया गया था- एपी राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया। तेलंगाना घिरा हुआ है उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश द्वारा दक्षिण और पूर्व दिशा. तेलंगाना राज्य को 33 जिलों में विभाजित किया गया है। कवर 112,077 किमी वर्ग क्षेत्रफल वाला तेलंगाना भारत का बारहवां सबसे बड़ा राज्य है।

27.2. तेलंगाना की जनसांख्यिकीय विशेषताएं

किसी राज्य का आर्थिक विकास वहां उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है राज्य। संसाधनों को मुख्य रूप से तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, (1) मानव संसाधन (2) भौतिक प्राकृतिक संसाधन एवं (3) मानव निर्मित संसाधन। भौतिक प्राकृतिक संसाधन हैं सूर्य का प्रकाश, भूमि, हवा, पानी, वनस्पति आदि। मानव संसाधन मुख्य रूप से जनसंख्या हैं। अगर गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन हैं, वे प्राकृतिक संसाधनों का वांछनीय उपयोग कर सकते हैं कुशल तरीके। मानव निर्मित संसाधन (मशीनें, कारखाने, जहाज आदि) भी निर्भर करते हैं मानव संसाधन की दक्षता. जनसंख्या का आकार, जनसंख्या संरचना, जैसे कारक शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य, पोषण उपलब्धता, आय वितरण प्रणाली, पर्यावरण अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता आदि मानव संसाधन की गुणवत्ता और दक्षता निर्धारित करते हैं।

27.2.1. तेलंगाना में जनसंख्या का आकार

2011 की जनगणना के अनुसार, तेलंगाना राज्य भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है जनसंख्या 35,003,674। यानी यह हमारी कुल जनसंख्या का 2.89 प्रतिशत है देश। लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 988 है और यह देश के लिंगानुपात से अधिक है अनुपात। संबंधित जिलों के संबंध में, निर्मल ने पहले स्थान पर कब्जा किया और उसके बाद निज़ामाबाद, जगितियाल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके विपरीत जयशंकर भूपालपल्ली, संगारेड्डी जिलों में लिंगानुपात सबसे कम है। का जनसांख्यिकीय विवरण तेलंगाना को तालिका 1 में दिखाया गया है।

2001-2021 दशक के दौरान हमारे राज्य में जनसंख्या में 11.47% की वृद्धि हुई, जबकि 1991-2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 15.07% दर्ज की गई थी। साथ ही, पूरे देश की जनसंख्या वृद्धि दर 21.34% है। उपरोक्त सांख्यिकीय विवरण बनाते हैं दो बातें स्पष्ट हैं, (1) 1991-2001 के दशक में तेलंगाना की जनसंख्या वृद्धि कम है 1981-91 के दशक की तुलना में और (2) हमारे राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर कम है 1991-2001 के दशक के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर (17.71%)। हालाँकि, से 1961 से 2011 तक, 50 वर्षों के भीतर, हमारे राज्य में जनसंख्या का आकार 63.68% बढ़ गया जो देश की विकास दर यानी 63.72 फीसदी के बराबर थी.

27.2.2. तेलंगाना में जनसंख्या का घनत्व

जनसंख्या घनत्व किसी राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या है। तालिका.2 इससे पता चलता है कि 1960 में राज्य का जनसंख्या घनत्व 111 व्यक्ति प्रति वर्ग था किलोमीटर, और यह 2011 तक बढ़कर 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। यह इससे कम था 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व। हैदराबाद सबसे सघन है 39,43,323 की आबादी वाला जिला और मुलुगु सबसे कम आबादी वाला जिला है तेलंगाना में 29,4671 के साथ।

27.2.3. जनसंख्या की साक्षरता दर

साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत से परिभाषित होती है पढ़ें और लिखें। 1961 से 2011 तक तेलंगाना में साक्षरता दर तालिका:4 में प्रस्तुत की गई है स्पष्ट है कि तेलंगाना में पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच साक्षरता दर बढ़ रही है

पिछले चार दशकों में. वर्ष 1961 में कुल साक्षरता दर 17.34% तथा भारत में 58% थी।

2001, उसके बाद यह और बढ़कर 66.46 प्रतिशत हो गया। हालाँकि यह देश की तुलना में कम है

साक्षरता दर 74.04. 2011 की जनगणना के अनुसार, हैदराबाद में तेलंगाना की साक्षरता दर सबसे अधिक है

और उसके बाद क्रमशः मेडचल मल्काजगिरि, हनुमाकोंडा हैं। हालाँकि, लिंग अंतर है

साक्षरता दर में बहुत अधिक. पुरुष साक्षरता दर 75.04 है जो महिला साक्षरता से अधिक है
रेट यानी 57.99.

तालिका-1: 1961 से 2011 तक तेलंगाना राज्य की जनसंख्या

वर्ष	1961	1981	1991	2001	2011
तेलंगाना 1,27,11,785		2,01,81,085	2,60,89,074	3,09,87,271	3,50,03,674
भारत	43,92,34,771 68,33,29,097	84,64,21,039 1,02,86,10,328	1,21,08,54,977		

स्रोत: तेलंगाना सामाजिक आर्थिक आउटलुक 2022

तालिका-2: 1961 से 2011 तक जनसंख्या का घनत्व

वर्ष	1961	1971	1981	1991	2001	2011
तेलंगाना	111	138	176	227	270	312
भारत	144	177	216	273	325	382

स्रोत: तेलंगाना सामाजिक आर्थिक आउटलुक

तालिका-3: 1961 से 2011 तक जनसंख्या का लिंगानुपात

वर्ष	1961	1971	1981	1991	2001	2011
तेलंगाना	975	969	971	967	971	988
भारत	941	930	934	927	933	943

स्रोत: तेलंगाना सामाजिक आर्थिक आउटलुक

27.3. जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण

जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण कुल कामकाजी लोगों के अनुपात को दर्शाता है जनसंख्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न व्यापक क्षेत्रों में लगी हुई है। वे प्राथमिक क्षेत्र हैं, द्वितीयक, और सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र।

प्राथमिक क्षेत्र: इसमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि शामिल हैं

द्वितीयक क्षेत्र: इसमें उद्योग, गैस, जल आपूर्ति, बिजली, निर्माण आदि शामिल हैं।

तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र: इसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की सेवाएँ शामिल होती हैं। परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, बीमा, सामाजिक और आर्थिक सेवाएँ, वगैरह।

यदि श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है सेवा क्षेत्र में आर्थिक प्रगति में परिवर्तन आता है। में तकनीकी उन्नति कृषि क्षेत्र अधिशेष श्रमिकों की कृषि क्षेत्र से तेजी से गतिशीलता की ओर ले जाता है क्षेत्र। इस प्रकार का व्यावसायिक परिवर्तन अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाता है।

27.4. तेलंगाना में मानव संसाधन विकास

मानव विकास, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास अविभाज्य हैं और आपस में जुड़ा हुआ। आम तौर पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन, संरक्षित ताज़ा पानी, आवास (पर्यावास) सामाजिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। ये सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव विकास को संदर्भित करते हैं। अर्थात् सामाजिक क्षेत्र का विकास ही मानव विकास है। आइये अब चर्चा करते हैं तेलंगाना राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र निम्नलिखित तरीके से।

27.5. शिक्षा क्षेत्र में सरकार की भूमिका

शिक्षा वर्तमान पीढ़ी को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भविष्य के कार्यबल को सक्षम बनाने और उनकी कमाई की क्षमता को बढ़ाने में। शिक्षा में निवेश अंतर-पीढ़ीगत गरीबी को तोड़ सकता है और मानव विकास को बढ़ावा दे सकता है। तेलंगाना सरकार ने मानव संसाधन विकसित करने के लिए निम्नलिखित पहल की है।

27.5.1. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009

भारतीय संविधान में 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21ए शामिल किया गया जिसमें कहा गया है "द

राज्य ऐसे 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा

जैसा कि राज्य, कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है।" निःशुल्क एवं अनिवार्य बच्चों का अधिकार

शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आदेश देता है

उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो गई। तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए

शिक्षा, सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया

राज्य भर में.

27.5.2. अनुसंधान शैक्षणिक संस्थान

उपरोक्त संस्थागत सुविधाओं के अलावा, अकेले हैदराबाद में 40 प्रमुख शोध हैं

फार्मा, रक्षा अनुसंधान, ग्रामीण विकास जैसे विविध क्षेत्रों के शैक्षणिक संस्थान

आदि। ये संस्थान न केवल विभिन्न क्षेत्रों की अनुसंधान आवश्यकताओं में योगदान देते हैं, बल्कि

संबंधित क्षेत्रों के लिए उच्च प्रभाव वाले पेशेवर भी विकसित करें।

27.5.3. गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना

गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढाँचा समग्र शिक्षण वातावरण में सुधार में योगदान देता है

और सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है, जिसका छात्रों के ठहराव और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है

परिणाम. जैसे संकेतकों पर तेलंगाना अखिल भारतीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है

कार्यात्मक बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक शौचालय सुविधा, पुस्तकालय और रैंप वाले स्कूल

वर्ष 2019-20 के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। राज्य में 2020-21 के दौरान स्कूलों

कार्यात्मक पेयजल सुविधा, कंप्यूटर सुविधाओं वाले स्कूल और स्कूल

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यात्मक शौचालय (सीडब्ल्यूएसएन) के साथ 95.6%, 34.3% तक सुधार हुआ।

और 6.25%, जो 2019-20 में क्रमशः 92.45%, 20.81% और 2.44% था।

27.5.4. मन ऊरु - मन बड़ी / मन बस्ती- मन बड़ी योजना

सरकार ने अपनी प्रमुख पहल "माना ऊरु - मन बड़ी / मन बस्ती-" शुरू की।

सरकार में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए जनवरी 2022 में मन बाड़ी” का आयोजन किया जाएगा

7,289.54 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट के साथ तीन साल की अवधि के लिए स्कूल। 26,067

सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूल और 19,84,167 छात्र इसके अंतर्गत आते हैं

कार्यक्रम.

27.5.5. सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार

सरकारी स्कूलों में नामांकन में सुधार के लिए, राज्य ने कई पहल की हैं,

जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, एक माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरूआत शामिल है

सरकारी स्कूलों में शिक्षा, संचार जैसे सॉफ्ट-कौशल की शुरूआत

वगैरह।

सरकारी प्रयासों से राज्य में स्कूलों की कुल संख्या में वृद्धि हुई

2019-20 में 40,900 से 2020-21 में 41,220। 2021-22 के दौरान कुल संख्या 60.47 लाख

राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में बच्चों का नामांकन होता है। इनमें से 53.71% नामांकित हैं

निजी स्कूलों में और 46.29% सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं।

27.5.6. सीखने के अवसरों का विस्तार करना

शैक्षणिक अवधि के दौरान कक्षाओं से परे बच्चों के लिए सीखने के अवसरों का विस्तार करना

वर्ष 2020-21 में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (SIET) द्वारा विकसित किया गया था

तेलुगु, अंग्रेजी और टी-सैट और डीडी चैनलों के माध्यम से 2180 डिजिटल पाठ प्रसारित किए गए

उर्दू मीडिया तीसरी से दसवीं कक्षा के छात्रों को कवर कर रहा है। औसतन 85% छात्रों ने इसे देखा

ये डिजिटल पाठ।

27.5.7. उद्योग-शिक्षा साझेदारी का निर्माण

सरकार राज्य भर में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के साथ-साथ काम कर रही है

कुशल प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए उद्योग-शिक्षा साझेदारी बनाने में सबसे आगे

प्रतिभाशाली रोजगार योग्य युवा और उद्यमी। तेलंगाना जैसे विभिन्न कौशल संस्थान

कौशल और ज्ञान केंद्र (TSKC), तेलंगाना कौशल और ज्ञान अकादमी (TASK)

और उद्योग प्रासंगिक कौशल विकसित करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं।

27.5.8. 2021- 26 की तेलंगाना आईसीटी नीति

यह 80% हासिल करने के लक्ष्य के साथ तेलंगाना के नागरिकों को कौशल बढ़ाने, पुनः कौशल प्रदान करने और प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है।

कार्यबल की आवश्यकता को स्थानीय प्रतिभाओं के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इसके लिए सरकार

हर साल 5 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहता है। की इंडिया स्किल्स रिपोर्ट के मुताबिक

2022, तेलंगाना में सबसे अधिक महिला रोजगार योग्य प्रतिभा है। तेलंगाना ने भी तीसरा स्थान हासिल किया

कंप्यूटर कौशल उपलब्धता के संबंध में देश में। यह सकारात्मक नियुक्ति को दर्शाता है

राज्य में ऐसी प्रवृत्ति जो नौकरी के अवसरों में समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करती है।

राज्य में कौशल विकास के प्रमुख अवसरों में व्यावसायिक शिक्षा शामिल है,

व्यावसायिक महाविद्यालयों में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण।

27.6. स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) 'स्वास्थ्य' को पूर्ण शारीरिक स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, मानसिक और सामाजिक कल्याण, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। यह इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद इनमें से एक है प्रत्येक मनुष्य के मौलिक अधिकार। तेलंगाना सरकार ने मान्यता दे दी है राज्य के गठन से ही जनसंख्या को स्वस्थ रखने में राज्य के हस्तक्षेप की भूमिका 2014 में।

1. राज्य में विशेष रूप से संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो ध्यान केंद्रित करती हैं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य में सुधार करना। मे आगे सरकार के "आरोग्य तेलंगाना" के उद्देश्य के साथ संरेखण, और नए स्थापित करना सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास, सरकार ने बजटीय बनाया 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए 6,295 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें से रु. 1,010 करोड़ रुपये आवंटित किये गये स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर।

2. राज्य गठन के बाद से ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है तेलंगाना की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की दिशा में। उसके प्रयासों का परिणाम परिलक्षित होता है हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक, 2019 में राज्य का उल्लेखनीय प्रदर्शन- 20. 19 बड़े राज्यों में तेलंगाना राज्य तीसरे स्थान पर है, जबकि केरल और तमिल नाडु क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है।

3. स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को अक्सर "स्वास्थ्य प्रणाली का तंत्रिका केंद्र" कहा जाता है। मोटे तौर पर, इसमें एक सक्षम और योग्य कार्यबल, अद्यतन डेटा और जानकारी शामिल है सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं का आकलन करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम प्रणालियाँ, और एजेंसियां, और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। तेलंगाना सरकार सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण निवेश कर रही है 2014-15 से राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना।

4. 2021 में, तेलंगाना सरकार ने चार तेलंगाना स्थापित करने की योजना की घोषणा की

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च (टीआईएमएस) के अस्पतालों में समान बुनियादी ढांचा है

गाचीबोवली, सनथ नगर, अलवाल और दिलसुखनगर में कॉर्पोरेट अस्पताल। 2021 में

सरकार ने शिलान्यास किया और निर्माण के लिए 1,100 करोड़ रुपये मंजूर किये

वारंगल को एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की अपनी योजना के हिस्से के रूप में

स्वास्थ्य शहर और एक चिकित्सा पर्यटन स्थल।

5. प्रबंधन के लिए 2014-15 में तेलंगाना वैद्य विधान परिषद (टीवीवीपी) की स्थापना की गई थी

माध्यमिक स्तर के अस्पताल (जिसमें चुनिंदा जिला अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल शामिल हैं)

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अस्पताल, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य

राज्य में केंद्र, और सिविल औषधालय)। वर्तमान में 122 टीवीवीपी अस्पताल हैं

बिस्तरों की संख्या 9,320। ये अस्पताल अधिकतर मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं,

सामान्य चिकित्सा के अलावा, सामान्य सर्जरी, बाल रोग, आर्थोपेडिक्स, ईएनटी, आदि सेवाएं।

6. तेलंगाना सरकार ने एक अभिनव पहल योजना 'बस्ती' शुरू की

स्वास्थ्य सेवाओं को शहरी गरीबों के करीब लाने के लिए 2018 में दावाखाना। 256 बस्ती

राज्य द्वारा अब तक शहरी मलिन बस्तियों में दवाखानों की स्थापना की गई है, जिनमें एक बस्ती दवाखाना भी शामिल है

5,000 से 10,000 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना। ये केंद्र विभिन्न प्रकार की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं

जिसमें बाह्य रोगी परामर्श, दवाएँ, बुनियादी प्रयोगशाला निदान और गैर-के लिए स्क्रीनिंग शामिल है

संचारी रोग। बस्ती दवाखानों में विशेषज्ञ परामर्श भी प्रदान किया जाता है

टेलीमेडिसिन. बस्ती दवाखाना मरीजों के लिए यात्रा और प्रतीक्षा समय को कम करता है, आउट-आउट को कम करता है।

मरीजों के लिए अपनी जेब से खर्च।

7. बाद में सरकार ने लोगों के रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 'पल्ले दवाखाना' शुरू किया

ग्रामीण क्षेत्रों में उनके शहरी समकक्षों के समान ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं,

जिसमें डॉक्टरों तक चौबीसों घंटे पहुंच शामिल है। पल्ले दवाखाना वितरित करेगा

स्थानीय आबादी के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ।

8. आरोग्यश्री योजना (एएस) एक अद्वितीय राज्य सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा है

तेलंगाना में आरोग्यश्री हेल्थ केयर ट्रस्ट द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजना। लक्ष्य

इस योजना का उद्देश्य राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) 87.5 लाख परिवारों की मदद करना है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक कैशलेस और न्यायसंगत पहुंच के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय को कम करना।

यह योजना लाभार्थियों को रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। 5 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष, और रुपये तक का अतिरिक्त वित्तीय कवरेज। उच्च-स्तरीय प्रक्रियाओं के लिए 10 लाख। मई में 2021, तेलंगाना सरकार ने इस योजना को भारत सरकार से जोड़ा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई)।

27.7. सारांश

मानव संसाधन विकास में विभिन्न स्तरों पर विकास शामिल है समुदाय। सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण और संगठन जैसे मानव संसाधन विकास प्रयासों की आवश्यकता होती है विकास। सामुदायिक विकास शिक्षा और प्रशिक्षण का एक वैकल्पिक मार्ग है सामुदायिक परिवेश के नागरिकों, विशेषकर विकासशील देशों में, को उस मानव संसाधन विकास की आवश्यकता होती है अभ्यासकर्ता सांस्कृतिक चर, विश्वास, परंपराओं जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हैं और परिवर्तन लाने से पहले लिंग भूमिकाएँ। इसका स्वभाव सामुदायिक विकास है बहुविषयक और इस प्रकार, समुदाय को समझने के लिए एक संकीर्ण फोकस वाले सिद्धांतों का उपयोग करना समुचित विकास.

27.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. जनसंख्या का घनत्व क्या है?

2. प्राथमिक क्षेत्र क्या है?

3. बस्ती दवाखाना क्या हैं?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण की व्याख्या करें?

2. तेलंगाना राज्य में आईसीटी नीति 2021-26 की व्याख्या करें?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या भूमिका है?

2. स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या भूमिका है?

27.9. शब्दकोष

1. साक्षरता दर: साक्षरता दर 7 वर्ष और आयु वर्ग की साक्षर जनसंख्या है
उपरोक्त को समान आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से विभाजित किया गया है।

2. जनसंख्या घनत्व: क्षेत्र के आकार से विभाजित व्यक्तियों की संख्या। की गणना करना
जनसंख्या घनत्व, आप जनसंख्या को क्षेत्र के आकार से विभाजित करेंगे। इस प्रकार, जनसंख्या
घनत्व = लोगों की संख्या/भूमि क्षेत्र।

3. टीएसकेसी: नए राज्य तेलंगाना के गठन के बाद कार्यक्रम का पालन किया जा रहा है
एक ताज़ा जोश के साथ. पिछले जेकेसी केंद्रों को अब तेलंगाना कौशल और ज्ञान कहा जा रहा है
केन्द्रों ने अपने दायरे और दक्षताओं का विस्तार किया है।

4. ABPM-JAY: 2018 में, भारत सरकार ने 'आयुष्मान भारत' योजना शुरू की
नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाना और देश की सहायता करना
2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। मई 2021 में,
तेलंगाना सरकार ने आरोग्यश्री योजना (एएस) को भारत सरकार से जोड़ा
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई)।

27.10. संदर्भ

1. वीके मिश्रा और एसके पुरी द्वारा भारत अर्थव्यवस्था
2. तेलंगाना सामाजिक-आर्थिक आउटलुक 2022
3. तेलुगु अकादमी से तेलंगाना अर्थव्यवस्था

अध्याय 28

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र - तेलंगाना

28.0 उद्देश्य

28.1 परिचय

28.2 तेलंगाना में अर्थव्यवस्था के अभिनेता

28.3 कृषि क्षेत्र

28.3.1 तेलंगाना की कृषि क्षमता

28.3.2 कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

28.3.3 कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकारी कार्यक्रम।

28.3.4 राज्य का कृषि विजन

28.4 औद्योगिक क्षेत्र

28.4.1 तेलंगाना औद्योगिक नीति और दृष्टिकोण

28.4.2 औद्योगिक नीति का दृष्टिकोण

28.4.3 तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व-प्रमाणन प्रणाली (टीएस-आईपीएएसएस) अधिनियम.2014

28.4.4 रैपिड इनक्यूबेशन दलित उद्यमियों के लिए तेलंगाना राज्य कार्यक्रम (टी-प्राइड)

28.4.5 महिला उद्यमी हब (वी-हब)

28.4.6 टेक्नोलॉजी-हब (टी-हब)

28.4.7 तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास और उद्यमी उन्नति (टी-आईडीईए)

28.5 सेवा क्षेत्र

28.5.1 सेवाओं के प्रमुख उपक्षेत्र

28.5.2 सेवा क्षेत्र पर सरकार का दृष्टिकोण

28.6 सारांश

28.7 मॉडल परीक्षा प्रश्न

28.8 शब्दकोष

28.9 संदर्भ

28.0. उद्देश्य

तेलंगाना अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की विशेषताओं का वर्णन करना।

तेलंगाना अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के महत्व की पहचान करना।

कृषि को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रमों की व्याख्या करना

उत्पाद

औद्योगिक विकास के लिए सरकारों के प्रोत्साहनों की व्याख्या करना

सेवा क्षेत्रों के उप क्षेत्रों का वर्गीकरण करना

28.1 परिचय

राज्य की आय या राज्य का घरेलू उत्पाद मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है किसी राज्य की आर्थिक वृद्धि. समय के साथ अर्थव्यवस्था के ये अनुमान बताते हैं आर्थिक विकास के स्तरों में परिवर्तन की सीमा और दिशा। इस में अध्याय में हम तेलंगाना राज्य में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।

28.2 तेलंगाना में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

राज्य घरेलू उत्पाद मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है जिसे आर्थिक कहा जाता है गतिविधियाँ। इन आर्थिक गतिविधियों को तीन व्यापक क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहलाते हैं।

ये सेक्टर हैं

1. कृषि क्षेत्र
2. औद्योगिक क्षेत्र
3. तृतीयक क्षेत्र (सेवा)

तेलंगाना में, निम्नलिखित ग्राफ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र की हिस्सेदारी दर्शाता है।

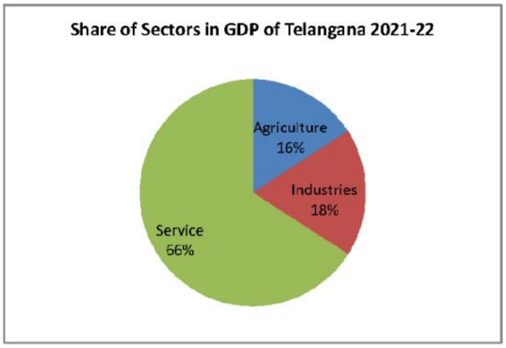

28.3 कृषि क्षेत्र

तेलंगाना की अर्थव्यवस्था और बेहतर प्रदर्शन में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है समावेशी विकास के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तेलंगाना राज्य प्रचुर संसाधनों से संपन्न है अच्छी मिट्टी, विविध फसल पैटर्न और नदियों द्वारा पोषित प्रमुख सिंचाई प्रणालियाँ गोदावरी और कृष्णा की तरह. कृषि जीवन जीने का एक तरीका है, एक परंपरा है जिसने संस्कृति को आकार दिया है और तेलंगाना के लोगों का आर्थिक जीवन। तेलंगाना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में साल-दर-साल वृद्धि हासिल की।

28.3.1 तेलंगाना की कृषि क्षमता

तेलंगाना राज्य 276.96 से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ भारत का 11वां सबसे बड़ा राज्य है लाख एकड़. कुल क्षेत्रफल में से 49.07 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोये गये क्षेत्र के अंतर्गत आता है लगभग 24.07 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत है। गैर-कृषि उपयोग हेतु उपयोग की जाने वाली भूमि चारों ओर है 7.46 प्रतिशत, परती भूमि (9.02 प्रतिशत), बंजर एवं अनुपयोगी भूमि (5.42 प्रतिशत) तथा शेष स्थायी चरागाहों और अन्य चारागाहों के अंतर्गत हैं। की कुल संख्या राज्य में परिचालन जोत 59.48 लाख है जो 59.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है।

राज्य के गठन के बाद खेती के क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है बढ़ा हुआ। सकल बोया गया क्षेत्र (जीएसए) 2014-15 में 131 लाख एकड़ से बढ़कर 2021-22 में 198 लाख एकड़ (51% की वृद्धि)। क्षेत्रफल में यह वृद्धि मुख्यतः के कारण है नई सिंचाई परियोजनाओं में नियोजित निवेश, मौजूदा सिंचाई प्रणालियों का पुनरुद्धार और सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यवस्थित खरीद तंत्र।

तेलंगाना की मिट्टी अच्छे जल निकास से लेकर मध्यम जल निकास वाली है और मिट्टी की उर्वरता प्रबंधन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। मिट्टी विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त है जिसमें खाद्यान्न, तिलहन, दालें, फल फसलें, चारागाह, वानिकी आदि शामिल हैं।

28.3.2 कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ -मैक्रो ट्रेंड्स कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियाँ हैं

यह राज्य के अधिकांश लोगों के जीवन और आजीविका का अभिन्न अंग है। इस तथ्य के अलावा कि

यह क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है, यह आधे से अधिक लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है

राज्य का कार्यबल.

28.3.3 कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकारी कार्यक्रम

तेलंगाना तेजी से आत्महत्या, भारी कर्ज़ आदि जैसे अतीत की छाया से बाहर आ गया है

सिंचाई सुविधाओं की कमी और कृषि में कई नए कार्यक्रम लागू किए हैं

किसानों के लिए आदर्श बनने का लक्ष्य। सरकार के कुछ निम्नलिखित हैं

दीक्षा.

एक। भूमि अभिलेख अद्यतनीकरण कार्यक्रम - धरणी

के शुद्धिकरण के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम

राज्य के सभी मंडलों के सभी गांवों के भूमि रिकॉर्ड।

बी। बीज उत्पादन

कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बीज एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। इसलिए, उत्पादन

और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है

योजना बजट के तहत जिसके लिए राशि रु. सुदृढ़ीकरण के लिए 50.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं

बीज उत्पादन. तेलंगाना सरकार राज्य को ऐसा बनाने की रणनीति विकसित कर रही है

देश का "बीज का कटोरा", अनुकूल जलवायु परिस्थितियों से संपन्न है

विभिन्न फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी।

सी। मृदा परीक्षण

किसानों को जागरूक करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलायी जा रही है

मृदा परीक्षण के महत्व और उर्वरकों के विवेकपूर्ण और एकीकृत उपयोग के संबंध में

मृदा परीक्षण डेटा पर, जिससे खेती की लागत कम हो जाती है।

डी। कृषि विपणन

अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक व्यापक आंध्र प्रदेश (कृषि उपज और पशुधन) बाजार अधिनियम 18.11.1996 से लागू हुआ है, और इसे इसके लिए अपनाया गया है तेलंगाना राज्य. बाजार अधिनियम का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना है कृषि उपज की बिक्री और उनके लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना तथा सुरक्षा प्रदान करना उन्हें बेईमान व्यापारियों के चंगुल से बचाया जाए।

इ। सिंचाई परियोजनाएँ

तेलंगाना राज्य में शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएँ इस प्रकार हैं:

1) कालेश्वरम परियोजना (18.25 लाख एकड़),

2) सीता राम लिफ्ट सिंचाई योजना (3.87 लाख एकड़),

3) जे.चोक्का राव देवदुला लिफ्ट सिंचाई योजना (5.58 लाख एकड़),

4) राजीव भीम लिफ्ट सिंचाई योजना (2.03 लाख एकड़),

5) महात्मा गांधी कलवाकुर्थी लिफ्ट सिंचाई योजना (4.24 लाख एकड़),

6) जवाहर नेट्टमपाडु लिफ्ट सिंचाई योजना (2.00 लाख एकड़)।

एफ। रायथु बंधु (निवेश सहायता)

बुनियादी इनपुट लागत के लिए किसानों को वित्तीय सहायता के महत्व को पहचानना खेती के लिए, सरकार ने 2018 में रायथु बंधु योजना शुरू की रुपये की वित्तीय सहायता. राज्य में भूमि मालिक किसानों को प्रति वर्ष 10,000/- प्रति एकड़ दो किश्तों में. सरकार ने इस योजना को सभी भूमि मालिक किसानों तक बढ़ा दिया है भूमि स्वामित्व की परवाह किए बिना.

जी। जोखिम शमन-रयथु बीमा: तेलंगाना सरकार ने एक प्रमुख समूह की शुरुआत की वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 2018 से जीवन बीमा योजना- रायथु बीमा किसान की जान जाने की स्थिति में परिवार के सदस्यों/आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा किसी भी कारण से, नामांकित किसान की मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक मृत्यु पर बीमित राशि 5.00 लाख रुपये खाते में जमा की जाएगी 10 दिनों के भीतर नामांकित व्यक्ति नामित करें।

एच। खेती के लिए मुफ्त बिजली

1 जनवरी 2018 से सरकार 24 घंटे निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति कर रही है
राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान बिजली की खपत बढ़ गई है
राज्य गठन से पहले 1,500 मेगावाट की तुलना में 3,500 मेगावाट।

28.3.4 राज्य का कृषि विजन

तेलंगाना के लिए एक दृष्टिकोण तेलंगाना सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं
दृष्टि हैं:

- किसानों को बीज के क्षेत्र में सशक्त बनाना
- खेती को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य प्रयास बनाना
- इनपुट, वित्त, प्रौद्योगिकी और आईटी तक आसान पहुंच प्रदान करना
- उपलब्ध सतही और भूजल क्षमता का उपयोग करके सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना
- कुशल मृदा एवं जल प्रबंधन के लिए भूमि विकास के साधन उपलब्ध कराना
- किसानों के दरवाजे पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रशिक्षित विस्तार कर्मचारी उपलब्ध कराना

28.4. औद्योगिक क्षेत्र

तेलंगाना राज्य बड़े विनिर्माण उद्योगों का घर है। थोक औषधियाँ,
फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-प्रसंस्करण, सीमेंट और खनिज-आधारित उद्योग, कपड़ा और परिधान,
बागवानी और मुर्गीपालन वर्तमान में तेलंगाना में मौजूद मुख्य उद्योग हैं। राज्य
देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक है और मामले में इसका स्थान छठा है
उद्योग और उद्योगों से सकल मूल्यवर्धन के मामले में 8वें स्थान पर हैं। तेलंगाना में भी,
उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
महत्वपूर्ण आजीविका के अवसर.

28.4.1. तेलंगाना औद्योगिक नीति और दृष्टिकोण

तेलंगाना राज्य औद्योगिक नीति कुछ मूल मूल्यों में निहित है:

1. सरकारी नियामक ढांचा औद्योगिक विकास को सुविधाजनक बनाएगा
2. उद्यमी एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित और प्रगतिशील व्यापार नियामक में फलेंगे-फूलेंगे पर्यावरण

3. औद्योगिक विकास से बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन होगा जिससे स्थानीय युवाओं को लाभ होगा

4. औद्योगीकरण समावेशी होगा और सामाजिक समानता को सुगम बनाएगा

5. औद्योगीकरण का लाभ सीमांत और सामाजिक रूप से वंचितों तक पहुंचना चाहिए

राज्य के अनुभाग

6. पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और किसी भी संभावित प्रभाव को कम किया जाएगा

औद्योगिक नीति का

28.4.2 औद्योगिक नीति का दृष्टिकोण

तेलंगाना के औद्योगीकरण का दृष्टिकोण "नवाचार के लिए अनुसंधान" है; नवप्रवर्तन को उद्योग; उद्योग से समृद्धि'' औद्योगिक नीति ढांचे को इसके द्वारा संचालित किया जाएगा नारा "तेलंगाना में-इनोवेट, इनक्यूबेट, इनकॉर्पोरेट"। नीतिगत ढाँचे का इरादा है एक व्यवसाय विनियामक वातावरण प्रदान करें जहां व्यवसाय करना हिलाने जितना आसान हो हाथ. नवाचार और प्रौद्योगिकी राज्य के उद्योगों को आगे बढ़ाएगी।

28.4.3 तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन और स्व-प्रमाणन प्रणाली

(टीएस-आईपीएएसएस) अधिनियम 2014

तेलंगाना सरकार ने "तेलंगाना राज्य औद्योगिक परियोजना अनुमोदन" अधिनियमित किया है और आवेदनों के त्वरित प्रसंस्करण के लिए स्व-प्रमाणन प्रणाली (TS-iPASS) अधिनियम, 2014" एक ही बिंदु पर उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न मंजूरी जारी करने के लिए उद्यमी द्वारा प्रदान किए गए स्व-प्रमाण पत्र पर और निवेशक अनुकूल बनाने के लिए भी तेलंगाना राज्य में पर्यावरण

टीएस-आईपास की मुख्य विशेषताएं:

• किसी उद्यम की स्थापना और संचालन के लिए जुड़े सभी विभाग लाए गए TS-iPASS के दायरे में।

• प्रत्येक अनुमोदन के लिए निर्धारित समय सीमा 1 दिन से लेकर अधिकतम 30 दिन तक होती है अनुमोदन की जटिलता पर निर्भर करता है।

• सहायता के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर आवेदनों की पूर्व-जांच उद्यमियों को आवेदन सही ढंग से जमा करने और देरी से बचने के लिए विभागों द्वारा फाइलों का प्रसंस्करण।

• सक्षम प्राधिकारियों के लिए कमी/अतिरिक्त की तलाश करना अनिवार्य बनाना
आवश्यक जानकारी, यदि कोई हो, केवल एक बार, प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर
आवेदन पत्र।

• टीएस-आईपास के तहत मंजूरी के अधिकार के साथ उद्यमियों को सशक्त बनाना, जानना
समय सीमा के भीतर मंजूरी मिलने में देरी के कारण और जुर्माना
देरी के लिए अधिकारी जिम्मेदार

28.4.4 रैपिड इनक्यूबेशन दलित उद्यमियों के लिए तेलंगाना राज्य कार्यक्रम (टी-प्राइड)

टी-प्राइड का लक्ष्य विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्र को अधिक न्यायसंगत बनाना है
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना,
महिलाएं और विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति (एसएपी)।

28.4.5. महिला उद्यमी हब (वी-हब)

वी-हब एक राज्य-नेतृत्व वाला इनक्यूबेटर है जिसकी स्थापना 2017 में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद के लिए की गई थी
तेलंगाना में. यह ऊष्मायन सुविधाएं, सरकार तक पहुंच और एक वैश्विक नेटवर्क प्रदान करता है
राज्य में नई महिला उद्यमियों के लिए सहयोगी।

28.4.6. टेक्नोलॉजी-हब (टी-हब)

नवाचार और प्रौद्योगिकी को औद्योगिक विकास का प्रमुख चालक माना जाता है
तेलंगाना. वर्तमान में, राज्य में 78 इन्क्यूबेटर, एक्सेलेरेटर और सह-कार्यशील स्थान हैं
जीवन विज्ञान, फिनटेक, एग्री टेक, डिजिटल इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।
राज्य की नवाचार नीति और स्टार्ट-अप को दिए गए प्रोत्साहन ने इसे बनाया है
कई उभरते स्टार्टअप के लिए एक उपजाऊ जमीन बताएं और उनमें से कुछ को लाभ हुआ है
राष्ट्रीय प्रमुखता.

28.4.7 तेलंगाना राज्य औद्योगिक विकास और उद्यमी उन्नति

(टी-आइडिया)

टी-आईडीईए के तहत, राज्य उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है
स्टांप शुल्क, बिजली लागत की प्रतिपूर्ति, ब्याज और निवेश सब्सिडी, पूंजी की पेशकश
गुणवत्ता नियंत्रण और पेटेंट पंजीकरण में सहायता और अन्य सहायता।

28.5 सेवा क्षेत्र

यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र का बोलबाला रहा तेलंगाना अर्थव्यवस्था में क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल आदि शामिल हैं रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण, परिवहन, वित्तीय सेवाएँ, अचल संपत्ति, और अन्य। सेवा क्षेत्र भी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है विद्युतीकरण, संचार, में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए परिवहन, बैंकिंग आदि सेवाएं बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र ने रोजगार प्रदान किया कुल कार्यबल के एक तिहाई से अधिक तक। सेवा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है राज्य में उत्पादन, विकास और नौकरियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है राज्य की अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी। पिछले सात वर्षों में, ज्ञान में निवेश और डेटा, और तीव्र तकनीकी प्रगति ने सेवाओं के तीव्र विकास को बढ़ावा दिया है तेलंगाना में क्षेत्र के साथ-साथ अन्य संबंधित क्षेत्र।

28.5.1. सेवाओं के प्रमुख उपक्षेत्र

1. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी): तेलंगाना राज्य आईटी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे यह भी कहा जाता है आईटी क्षेत्र में भारी दबाव के कारण भारत का साइबराबाद। प्रमुख आईटी कंपनियां और आईटी पार्क हैदराबाद में स्थित हैं। आईटी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकास, आईटी परामर्श, आउटसोर्सिंग शामिल हैं सेवाओं और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ), हैदराबाद को आईटी हब कहा जाता है।

2. आतिथ्य और पर्यटन: तेलंगाना में समृद्ध सांस्कृतिक परिवर्तन और ऐतिहासिक विरासत है। राज्य में चारमीनार, गोलकुंडा, रामजोरी फिल्म सिटी जैसी अच्छी साइट देखने लायक जगहें हैं रामप्पा मंदिर जिनकी पहचान यूनेस्को द्वारा की गई है। राज्य प्रचार-प्रसार में निवेश कर रहा है पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए पर्यटन और बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसमें शामिल है होटल, रिसॉर्ट, ट्रैवल एजेंसियां आदि।

3. स्वास्थ्य देखभाल: तेलंगाना कई अस्पतालों के साथ स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और चिकित्सा संस्थान। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के विकास में निवेश किया है देखभाल, मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों सहित बुनियादी ढाँचा। यह उपक्षेत्र इसमें फार्मास्युटिकल कंपनियां और चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता शामिल हैं।

4. परिवहन: तेलंगाना में सड़क सहित एक अच्छी तरह से विकसित परिवहन नेटवर्क है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी. इस उपक्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन, रसद सेवाएं शामिल हैं और कूरियर सेवाएं, वेयर हाउसिंग और नई अच्छी संख्या में रोजगार का समर्थन करना।

5. वित्तीय सेवाएँ: कई बैंक, बीमा कंपनियाँ और अन्य वित्तीय संस्थान तेलंगाना में स्थित हैं। इस उपक्षेत्र में स्टॉक ब्रोकिंग, निवेश सलाहकार सेवाएँ और वित्तीय परामर्श शामिल हैं।

28.5.2 सेवा क्षेत्र पर सरकार का दृष्टिकोण

सरकार सेवा क्षेत्र में नवाचारों को कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत करने की इच्छुक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख हैं, और वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में केंद्रित आईटी/आईटीईएस में नवाचारों से लाभ उठा रही है।

सभी क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार सृजन होता है। सेवा-क्षेत्र के विकास में प्रौद्योगिकी की केंद्रीय भूमिका को पहचानते हुए, सरकार टी-हब, वाई-हब, वी-हब, टीएसआईसी जैसी पहलों के माध्यम से फर्मों, विशेष रूप से स्टार्ट-अप को संस्थागत समर्थन के माध्यम से मौजूदा क्षमता को पूरक करने का प्रयास कर रही है। , और टी-वर्क्स। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी और के उपयोग को भी सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है

ड्रोन प्रौद्योगिकियाँ। अधिक अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकार टी-फाइबर और उच्च गुणवत्ता वाले सड़क नेटवर्क जैसे सक्षम बुनियादी ढांचे प्रदान कर रही है। कुल मिलाकर, ये पहल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी

क्षेत्र, और मजबूत रोजगार पैदा करते हैं।

28.6 सारांश

कृषि जीवन जीने का एक तरीका है, एक परंपरा है जिसने तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और आर्थिक जीवन को आकार दिया है। तेलंगाना की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इस क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तेलंगाना राज्य बड़े विनिर्माण उद्योगों का घर है। राज्य देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक है और यह उद्योगों के मामले में 6वें स्थान पर है और उद्योगों से सकल मूल्यवर्धन के मामले में 8वें स्थान पर है। तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जिसने औद्योगिक मंजूरी प्राप्त करने का अधिकार बना लिया है। राज्य आईटी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) में उत्पादन और निर्यात के मामले में देश में अग्रणी स्थान रखता है। आईटी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव ने नए अवसरों को जन्म दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद अब विश्व स्तर पर अग्रणी आईटी केंद्रों में से एक के रूप में पहचानी जाती है।

28.7 मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का उल्लेख करें और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक उदाहरण दें।

2. धरणी कार्यक्रम क्या है?

3. टी-प्राइड के बारे में लिखें।

4. सेवा क्षेत्र के उपक्षेत्र लिखिए।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. कृषि को बढ़ावा देने के लिए कोई दो सरकारी कार्यक्रम लिखिए।

2. तेलंगाना औद्योगिक नीति और उसके दृष्टिकोण का वर्णन करें

3. TS-iPASS की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. कृषि को बढ़ावा देने हेतु सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन करें।

2. तेलंगाना की औद्योगिक नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की व्याख्या करें।

3. तेलंगाना में सेवा क्षेत्र का महत्व स्पष्ट करें।

28.8 शब्दावली

प्राथमिक क्षेत्र: इसे कृषि क्षेत्र कहा जाता है जिसमें फसलें उगाना, मछली पकड़ना, वानिकी और खनन शामिल हैं।

तृतीयक क्षेत्र: सेवा क्षेत्र, जिसे तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, तीन-क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में तीसरा स्तर है

रायथु बंधु: बुनियादी इनपुट के लिए तेलंगाना में किसानों को वित्तीय सहायता कृषि।

टीएस-आईपास: सिंगल विंडो प्रमाणन सेवा।

टी-हब: इसका लक्ष्य तेलंगाना को स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में बनाने में उत्प्रेरक बनना है दुनिया।

28.9 सन्दर्भ

1. टीएसबीआईई, अर्थशास्त्र पाठ्यपुस्तक द्वितीय वर्ष।

2. तेलंगाना सामाजिक आर्थिक आउटलुक।

अध्याय 29

तेलंगाना बजट

29.0. उद्देश्य

29.1. परिचय

29.2. बजट: अर्थ और परिभाषा

29.3. बजट का वर्गीकरण

29.4. तेलंगाना बजट 2023-24 पर एक नज़र

29.5. राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय

29.6. राजस्व प्राप्तियाँ

29.7. सारांश

29.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

29.9. शब्दकोष

29.10. संदर्भ

29.0. उद्देश्य

- बजट की परिभाषा एवं बजट की विशेषताएँ
- बजट का वर्गीकरण करें
- 2023-24 में तेलंगाना बजट को एक नजर में समझें
- बजट की राजस्व लेखा प्राप्तियों को जानें
- बजट के राजस्व, व्यय और ऋण में अंतर करें

29.1. परिचय

बजट महज एक तकनीकी वित्तीय दस्तावेज नहीं है. यह आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली उपकरण है अर्थशास्त्रियों और आम नागरिकों के लिए सशक्तिकरण। 'बजट' शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ़्रेंच शब्द 'बौगेट', जिसका अर्थ है चमड़े का छोटा थैला या 'थैली'। इसका प्रयोग सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था उस सफेद चमड़े के थैले का वर्णन करने के लिए जिसमें राजकोष के मध्यकालीन दरबार की मुहर लगी हुई थी।

29.2. बजट का अर्थ और परिभाषा

सरकारी बजट एक वित्तीय योजना है जो आमतौर पर एक अवधि के लिए परिव्यय और प्राप्तियों को कवर करती है एक वर्ष का. यह आम तौर पर सरकार की आर्थिक स्थिति को स्पष्ट करने का भी एक अवसर है सामाजिक लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के तरीके। बजट आय पर आधारित एक व्यय योजना है एक साल का खर्च.

बजट की प्रमुख विशेषताएँ हैं

- यह भविष्य के लिए एक योजना या कार्यक्रम है
- बजट में शामिल मदें महज अनुमान हैं।
- यह एक व्यापक योजना है.
- यह सामान्यतः एक वार्षिक योजना है।
- यह हमेशा कार्यपालिका की ओर से तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।
- इसे मतदान के लिए विधायिका के समक्ष रखा जाता है।

29.3. बजट का वर्गीकरण

कार्यों की प्रकृति के आधार पर सार्वजनिक बजट को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है

संतुलित बजट: एक बजट तब संतुलित कहा जाता है जब प्रस्तावित व्यय और व्यय दोनों प्रस्तावित हों
प्रत्याशित राजस्व बराबर है. संतुलित बजट में न तो कोई घाटा होता है और न ही कोई अधिशेष।
बजट बनाते समय संतुलित बजट बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।

असंतुलित बजट: जब कोई बजट दिखाता है कि सरकार ने व्यय प्रस्तावित किया है और
प्रत्याशित राजस्व समान नहीं होने पर इसे असंतुलित बजट कहा जाता है। असंतुलन आय से अधिक व्यय या व्यय से अधिक आय के कारण हो सकता है।

राजस्व बजट: राजस्व बजट में सरकार से राजस्व प्राप्ति शामिल होती है, और व्यय इन राजस्व से पूरा किया जाता है। कर राजस्व में केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों और अन्य शुल्कों की आय शामिल होती है। सरकार की अन्य प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और लाभांश, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।

पूंजीगत बजट: पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता से लिये गये ऋण हैं। पूंजीगत व्यय है
पूंजीगत प्राप्तियों या परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों, सरकारी कंपनियों, निगमों और अन्य पक्षों को दिए गए ऋण अग्रिम भी पूंजीगत व्यय में शामिल किए जाते हैं।

अधिशेष बजट: जब सार्वजनिक राजस्व सार्वजनिक व्यय से अधिक हो जाता है तो इसे अधिशेष बजट कहा जाता है
अधिशेष बजट. अधिशेष बजट से सरकार की देनदारियाँ कम हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं
इसका राजस्व

अंतरिम बजट: यह वह होता है जो अंतरिम अवधि यानी उससे भी कम समय के लिए तैयार किया जाता है
बारह महीने। यदि पूरे वर्ष के लिए नियमित बजट तैयार करने में देरी होती है तो a
अंतरिम बजट इसलिए तैयार किया जाता है ताकि बीच के खर्चों को पूरा किया जा सके.

साधारण बजट: साधारण बजट वह होता है जो सामान्य परिस्थितियों में तैयार किया जाता है
एक वर्ष। इसे सामान्य समय के दौरान तैयार किया जाता है।

घाटे का बजट: जब प्रस्तावित व्यय प्रत्याशित आय से अधिक हो जाता है
घाटे का बजट कहा जाता है. नियोजित अर्थव्यवस्था में, सरकार आमतौर पर विकास व्यय को पूरा करने के लिए घाटे का बजट तैयार करती है। घाटे का बजट देनदारी बढ़ाता है
सरकार या उसका राजस्व घट जाता है।

अनुपूरक बजट: यदि नियमित बजट के दौरान व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है या सरकार को कुछ विशिष्ट पर व्यय करने की आवश्यकता होती है
जिन परियोजनाओं के लिए नियमित बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया था, इस अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट तैयार किया जाता है। यह बजट लोगों के लिए मददगार है.

आपातकालीन बजट: आपातकालीन बजट वह होता है जो आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है परिस्थितियाँ, जैसे युद्ध, भारी अवसाद, और प्राकृतिक आपदाएँ इत्यादि।

बजट पर अधिक अवधारणाओं के लिए, अध्याय 11 पढ़ें।

29.4. तेलंगाना बजट नजर 2023-24

				करोड़ों में
विवरण	लेखा2021-22 बीई 2022-23		आरई 2022-23	बीई 2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मैं ओपनिंग बैलेंस	-5.67	-111.34	63.83	336.86
द्वितीय राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,468.59	1,93,029.40	1,75,802.18	2,16,566.97
केंद्रीय करों में 1 राज्य का हिस्सा	18,720.54	18,394.11	19,668.15	21,470.84
2 कर राजस्व	91,271.38	1,08,211.93	1,10,592.28	1,31,028.65
3 गैर कर राजस्व	8,857.42	25,421.63	15,291.53	22,808.31
4 सहायता अनुदान	8,619.26	41,001.73	30,250.22	41,259.17
तृतीय पूंजीगत प्राप्तियाँ	55,598.70	63,832.37	54,582.37	55,277.68
5 खुले बाज़ार ऋण	45,716.00	53,970.00	44,970.00	40,615.68
6 अस्थायी ऋण (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
7 भारत सरकार से ऋण	214.14	4,102.00	3,852.00	4,102.00
8 अन्य ऋण	1,278.53	1,500.00	1,500.00	1,500.00
9 जमा लेनदेन आदि (नेट)	3,772.89	4,200.37	4,200.37	4,000.00
10 ऋण और अग्रिम	47.70	60.00	60.00	5,060.00
11 अन्य रसीदें (ऋण दर्शाए गए भारत सरकार की पुस्तकों में जीएसटी मुआवजा)	4,569.49	0	0	0
12 आकस्मिकता निधि नेट	-0.05	0.00	0.00	0.00
13 अंतरराज्यीय समझौता	0.00	0.00	7,500.00	17,828.00
IV कुल प्राप्तियां(II+III+13)	1,83,067.29	2,56,861.77	2,37,884.55	2,89,672.65
V राजस्व व्यय	1,36,803.43	1,89,274.82	1,72,822.25	2,11,685.23
जिनमें से 14 ब्याज भुगतान	19,161.41	18,911.88	18,911.88	22,407.67
VI पूंजीगत व्यय	28,874.35	29,728.44	26,934.02	37,524.70
सातवीं ऋण और अग्रिम	8,469.41	26,253.36	26,253.36	28,479.98
आठवीं पूंजी संवितरण (15 से 18) 8,850.60		11,601.90	11,601.90	12,606.09
15 सार्वजनिक ऋण चुकौती	6,460.42	8,336.00	8,336.00	9,341.17
16 ऋण फॉर्म भारत सरकार	509.92	367.94	367.94	427.16
17 अन्य ऋण	1,872.09	2,897.96	2,897.96	2,837.76
18 अंतरराज्यीय समझौता	8.18	0.00	0.00	0.00
IX कुल व्यय	1,82,997.80	2,56,858.51	2,37,611.52	2,90,296.00
एक्स समग्र लेनदेन (IV-IX)	69.50	3.26	273.03	-623.35
XI समापन शेष (I+X)	63.83	-108.08	336.86	-286.49
XII राजस्व अधिशेष (II - V)	-9,334.84	3,754.58	2,979.93	4,881.74
XIII राजकोषीय घाटा (XII - VI - VII + 10 -13 -18) 46,639.09		52,167.21	42,647.44	38,234.94
XIV प्राथमिक घाटा (XIII - 14)	27,477.67	33,255.33	23,735.56	15,827.27

स्रोत:

1. तेलंगाना बजट 2023-24
2. तेलंगाना का सामाजिक आर्थिक आउटलुक 2023

29.5. राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय

वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्व खाते पर प्राप्तियां अनुमानित हैं 2,16,566.97 करोड़ और खर्च 2,11,685.23 करोड़ होने का अनुमान है. अनुमान 2023-24 के लिए 4,881.74 करोड़ के राजस्व अधिशेष (+) का खुलासा

तालिका 2			करोड़ों में
विवरण	लेखा 2021-22	संशोधित अनुमान2022-23	बजट अनुमान 2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)
राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,468.59	1,75,802.18	2,16,566.97
राजस्व व्यय	1,36,803.43	1,72,822.25	2,11,685.23
अधिशेष(+)	-9,334.84	2,979.93	4,881.74

राज्य का राजस्व एवं व्यय

टेबल तीन			करोड़ों में
प्राप्तियां		व्यय	
कर और शुल्क		विकास व्यय	1,61,467.03
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	21,470.84	ऋण सेवाएँ	22,412.67
राज्य कर और शुल्क	1,31,028.65	प्रशासनिक सेवा	12,367.44
गैर-कर राजस्व		कर संग्रहण शुल्क	1,282.17
ब्याज प्राप्तियाँ	162.79	अन्य व्यय	14,155.92
अन्य गैर-कर राजस्वI (केंद्र से सहायता अनुदान सहित)	64,067.48		
कुल	2,16,566.97	कुल	2,11,685.23
घाटा	0.00	आधिक्य	4,881.74
कुल योग	2,16,566.97	कुल योग	2,16,566.97

स्रोत: तेलंगाना बजट

29.6. राजस्व प्राप्तियाँ

टेबल-4				करोड़ों में
विवरण	हिसाब किताब 2020-21	हिसाब किताब 2021-22	दोबारा 2022-23	होना 2023-24
1 कर एवं कर्तव्य	79,341.99	1,09,991.96	1,30,260.43	1,52,499.49
मैं केंद्रीय करों और शुल्कों आदि में राज्य का हिस्सा	12,691.62	18,720.54	19,668.15	21,470.84
द्वितीय राज्य कर	66,650.37	91,271.42	1,10,592.28	1,31,028.65
एक भू-राजस्व	0.50	0.26	6.71	12.05
बी बिक्री, व्यापार पर कर	43,094.24	55,890.70	69,203.00	83,500.00
सी राज्य उत्पाद शुल्क	14,369.84	17,482.19	17,500.00	19,884.90
डी अन्य	9,185.79	17,898.27	23,882.57	27,631.70
2 गैर-कर राजस्व	6,101.24	8,857.42	15,291.53	22,808.31
3. सहायता अनुदान	15,471.13	8,619.26	30,250.22	41,259.17
कुल	1,00,914.36	1,27,468.63	1,75,802.18	2,16,566.97

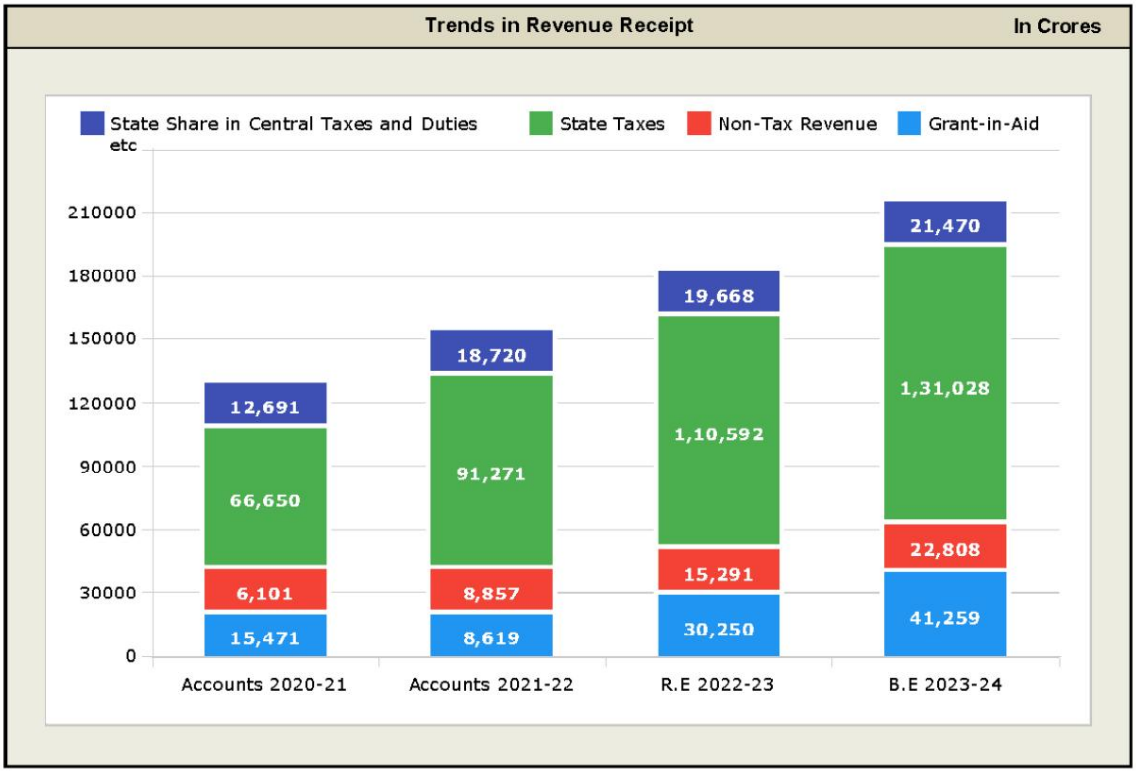

स्रोत: तेलंगाना बजट 2023-24

उपरोक्त ग्राफ राजस्व प्राप्तियों के रुझान को बताता है, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी। 2020-21 में 12691 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 21,470 करोड़ रुपये हो गया समय राज्य कर राजस्व 66,650 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1,31,029 रुपये हो गया करोड़ 2023-24. गैर कर राजस्व भी 2020-21 में 6101 करोड़ रुपये से बढ़ गया 2023-24 में 22,808 करोड़ रुपये के साथ-साथ सभी अनुदान सहायता में भी काफी वृद्धि हुई है तेलंगाना में 2020-21 से राजस्व प्राप्तियां लगातार बढ़ रही हैं।

29.7. सारांश

तेलंगाना के वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश किया 2,90,396 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 6 फरवरी 2023 को 2023-24। बाहर इसमें से राजस्व व्यय 2,11,685 करोड़ रुपये है; पूंजीगत व्यय 37,525 करोड़ रुपये है और राजकोषीय घाटा 28,224 करोड़ रुपये है. सरकार के पास कई नीतियां हैं सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना। ए रक्षा, प्रशासन एवं विकास, कल्याण, परियोजनाओं पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और कई अन्य राहत गतिविधियाँ। अत: पर्याप्त उत्पादन का प्रयास किया जाना चाहिए वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राजस्व।

29.8. मॉडल परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. बजट क्या है?
2. अधिशेष बजट की व्याख्या करें।

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. बजट के प्रकार बताइये।
2. बजट का अर्थ एवं परिभाषा बताइये

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. बजट का वर्गीकरण समझाइये।
2. तेलंगाना बजट 2023-24 पर एक नज़र डालें

29.9. शब्दकोष

संतुलन बजट: एक बजट तब संतुलित कहा जाता है जब प्रस्तावित व्यय और दोनों

प्रत्याशित राजस्व.

संतुलित बजट = राजस्व = व्यय

राजस्व बजट: राजस्व बजट में सरकार और सरकार से राजस्व प्राप्तियाँ शामिल होती हैं

व्यय इन राजस्वों से पूरा किया जाता है।

आपातकालीन बजट: आपातकालीन बजट वह होता है जो आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जाता है

युद्ध, भारी, अवसाद और प्राकृतिक आपदाएँ आदि स्थितियाँ।

29.10. संदर्भ

1. तेलंगाना बजट 2023-24 पर एक नज़र
2. तेलंगाना सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य 2022-23
3. तेलंगाना बजट 2023-24.

गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन- निर्माण एवं कल्याण कार्यक्रम

अध्याय 30

तेलंगाना राज्य

30.0. उद्देश्य

30.1. परिचय

30.2. तेलंगाना में गरीबी - जागरूकता

30.2.1. गरीबी के प्रकार

30.2.2. तेलंगाना में गरीबी का अनुमान

30.3. तेलंगाना राज्य में बेरोजगारी

30.4. तेलंगाना में बेरोज़गारी के आँकड़े

30.5. तेलंगाना में कल्याण और विकासात्मक योजनाएं

30.5.1. किसान कल्याण योजनाएँ

30.5.1.1. किसान निवेश सहायता योजना (रायथु बंधु)

30.5.1.2. किसान समूह जीवन बीमा योजना (रयथु बीमा)

30.5.1.3 मिशन काकतीय

30.5.2. महिला विकास एवं बाल कल्याण योजनाएँ

30.5.2.1. कल्याण लक्ष्मी - शादी मुबारक

30.5.2.2. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

30.5.2.3. केसीआर किट योजना

30.5.2.4. अम्मा ओडी

30.5.2.5. आरोग्य लक्ष्मी

30.5.3. समाज के कमज़ोर और असुरक्षित वर्गों के लिए योजनाएँ

30.5.3.1. आसरा पेंशन

30.5.3.2. आरोग्य श्री (आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना)

30.5.3.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

30.5.4. अन्य कल्याण एवं विकासात्मक योजनाएँ

30.5.4.1. दलित बंधु

30.5.4.2. मिशन भगीरथ

30.5.4.3. डबल बेडरूम मकानों का निर्माण

30.5.4.4. छात्रवृत्ति

30.5.4.5. तेलंगाना भेड़ वितरण योजना

30.5.4.6. शिक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

30.6. सारांश

30.7. मॉडल परीक्षा प्रश्न

30.8. शब्दकोष

30.9. संदर्भ

30.0.उद्देश्य

गरीबी और उसके प्रकारों को परिभाषित करें

तेलंगाना में गरीबी का अनुमान स्पष्ट करें

आंकड़ों के आधार पर तेलंगाना राज्य की बेरोजगारी पर चर्चा करें

की विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की व्याख्या करें

तेलंगाना राज्य

तेलंगाना सरकार के कार्यक्रम कैसे हैं, इसे समझें और चर्चा करें

गरीबी उन्मूलन

30.1. परिचय

सत्ता का एकमात्र कर्तव्य लोगों के सामाजिक कल्याण को सुरक्षित करना है।

-बेंजामिन डिज़रायली

गरीबी एक सतत सामाजिक और आर्थिक समस्या है। गरीबी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है वह राज्य या स्थिति जहां समाज के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं या भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी आवश्यक चीजें। जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं हम गरीब कहे जाने वाले लोगों को वास्तविकता तक पहुंचाकर उनकी गरीबी को दूर कर सकेंगे लाभार्थी. रोजगार को लागू कर हम गरीबी को दूर कर सकेंगे सृजन, गरीबी उन्मूलन और कल्याण योजनाएं। यदि केवल वे ही पहुंच रहे हैं वास्तविक लाभार्थी. संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य सतत विकास है 2030 के अंत तक गरीबी उन्मूलन। किसी भी सरकार का मुख्य एजेंडा सुरक्षित करना होता है लोगों का सामाजिक कल्याण.

कोई राज्य कैसे विकास कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर आसानी से देखकर दिया जा सकता है उस विशेष राज्य के गरीबी आँकड़े। गरीबी, आर्थिक असमानता, बेरोजगारी एक विकासशील राष्ट्र में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक समस्याएं हैं। ये सब हैं परस्पर संबंधित। ये समस्याएँ किसी भी देश के विकास में बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती हैं या एक राज्य. तेलंगाना राज्य जिसका गठन दशकों के अंतहीन संघर्ष के बाद हुआ था

नीलू, निधुलु और नियमाकलु पर आधारित फिल्म भी गरीबी की समस्या का सामना कर रही है। राज्य के पास है कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजनाएँ तैयार कर उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। पहचानने की जरूरत है जिस राज्य में गरीबों के लिए कल्याण कार्यक्रम क्रियान्वित हैं।

भले ही अन्य राज्यों की तुलना में तेलंगाना भारत का एक नवगठित राज्य है देश के कुछ हिस्सों में राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है, खासकर तेलंगाना में सरकार अपने प्रतिष्ठित कल्याणकारी सुधारों को लागू करने का प्रयास कर रही है और हर दरवाजे तक रोजगार सृजन कार्यक्रम। के गठन के बाद से तेलंगाना राज्य में गरीबों और पीढ़ी के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए रोजगार का।

30.2. तेलंगाना में गरीबी जागरूकता

30.2.1. गरीबी के प्रकार

अर्थशास्त्र के अनुसार गरीबी दो प्रकार की होती है, वे हैं 1. पूर्ण गरीबी और 2. सापेक्ष गरीबी.

पूर्ण गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति या परिवार ऐसा करता है उनकी सबसे बुनियादी जरूरतों, जैसे भोजन, को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय की आवश्यकता नहीं है आश्रय और वस्त्र. इस प्रकार की गरीबी मुख्यतः भारत जैसे विकासशील देशों में देखी जा सकती है। पूर्ण गरीबी की गणना करते समय, बाजार मूल्य के आधार पर जीवनयापन की मूल लागत को ध्यान में रखा जाता है।

सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य समाज में असमानताओं से है। इस हिसाब से गरीबी निम्न जीवन स्तर वाले लोगों के आय स्तर की तुलना निम्न जीवन स्तर वाले लोगों से की जाती है उच्च जीवन स्तर और फिर जिन लोगों की आय कम है उन्हें अपेक्षाकृत कहा जाता है गरीब। सापेक्ष गरीबी का प्रयोग मुख्यतः अमीर या अमीर देशों में किया जाता है

30.2.2. तेलंगाना में गरीबी का अनुमान

की गणना के लिए 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी भारत में गरीबी. यह संस्था प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार गरीबी की गणना करती है।

गरीबी अनुमान - सुरेश तेंदुलकर समिति

1993-94 में, तेलंगाना में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए, ग्रामीण और प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 11,244/- रुपये और 11,282/- रुपये लिया जाता है। वैसे ही गरीबी

वर्ष 2011-12 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 860/- रूपये मानी गयी है।
क्रमशः रु.1009/-. सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुमान के अनुसार, में
2011-12 में तेलंगाना में ग्रामीण गरीबी का स्तर 11.5% था जबकि ग्रामीण गरीबी का स्तर
भारत 25.7% था। उसी वर्ष, तेलंगाना में ग्रामीण और शहरी गरीबी का स्तर समग्र रूप से कम हो गया
8.77% था इस बीच भारत में ग्रामीण और शहरी गरीबी का स्तर कुल मिलाकर 21.9% था। में
1993-94 से 2011-12 तक तेलंगाना में ग्रामीण गरीबी का स्तर 49% से कम हो गया है
11.5%. इस बीच शहरी गरीबी का स्तर 30.5% से घटकर 5% हो गया है। तेलंगाना में
1993-94 से 2011-12 तक गरीबों की आबादी 12 मिलियन से घटकर 3 मिलियन हो गई है।
इसे गरीबी के स्तर में कमी का एक कारण कहा जा सकता है।

1990 के दशक में सामाजिक रूप से वंचितों में गरीबी का स्तर ऊँचा था
समुदाय जबकि 2011-12 में इसे कम कर दिया गया था। 2011-12 में तेलंगाना में, ग्रामीण और शहरी
अनुसूचित जनजाति की गरीबी का स्तर अनुसूचित जाति की तुलना में अधिक है। 1993-94 में तत्कालीन तेलंगाना में
हैदराबाद में गरीबी का स्तर 16.5% था, पूर्ववर्ती महबूबनगर में यह 50% था। लेकिन में
2011-12 में यह स्थिति बदल गई है। हैदराबाद में यह 2.4% थी और निजामाबाद में यह 2.4% थी।
11.6%.

गरीबी अनुमान - रंगराजन समिति रिपोर्ट।

2011-12 में रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना में गरीबी का स्तर
भारत के गरीबी स्तर से कम है। 2011-12 में, तेलंगाना में ग्रामीण गरीबी का स्तर 9.3% था
जबकि भारत में यह 30.9% था. इसी प्रकार तेलंगाना में शहरी गरीबी का स्तर था
11.1% जबकि भारत में यह 26.4% थी। यदि हम ग्रामीण गरीबी के स्तर पर विचार करें
और शहरी क्षेत्रों में कुल मिलाकर तेलंगाना में यह 10% था और भारत में यह 29.5% था। अगर हम गौर करें
तेलंगाना में गरीबों की आबादी ग्रामीण और शहरी इलाकों में 20.1 लाख और 15.2 लाख थी
क्रमश। रंगराजन समिति के अनुमान के अनुसार कुल गरीब
तेलंगाना में 35.3 लाख थे.

गरीबी उन्मूलन के लिए तेलंगाना सरकार ने कई पहल की हैं
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) पर आधारित कार्यक्रम। 2021 के अनुसार
नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बेसलाइन रिपोर्ट, तीन प्रमुख पर आधारित
भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे संकेतकों में हर चार में से एक गरीब है, लेकिन
तेलंगाना में यह अनुपात हर सात में से केवल एक है। राज्य गठन के बाद से

सरकार ने स्वास्थ्य में गरीबी उन्मूलन के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं (केसीआर किट,
आरोग्य लक्ष्मी, गिरिपोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार),
शिक्षा (मन ऊरु - मनबाड़ी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने और बहाल करने के लिए एक पहल
स्कूल में बुनियादी ढाँचा) और जीवन स्तर (मकान, कौशल विकास, मुफ़्त)।
बिजली, संपत्ति निर्माण) अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए।

30.3.तेलंगाना राज्य में बेरोजगारी

राज्य गठन के बाद सबसे अधिक निर्भरता कृषि क्षेत्र पर है
वर्षा का होना, ऋतु का अनुकूल तथा प्रतिकूल होना | फिर भी कृषि क्षेत्र है
राज्य में प्राथमिक क्षेत्र बना हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण रोजगार है
इस क्षेत्र द्वारा निर्मित उत्पादन और खाद्य सुरक्षा। यह वह क्षेत्र है जो मदद करता है
सबसे गरीब राज्य के विकास में भूमिका निभाएं। लगभग 55.7% श्रमिक या
कर्मचारियों को कृषि क्षेत्र और उसके सहायक क्षेत्रों के तहत रोजगार दिया जाता है। ए
संपत्ति विकास, रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र में त्वरित वृद्धि महत्वपूर्ण है
और अंततः यह राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसलिए, कृषि में सुधार करना महत्वपूर्ण है
गरीबी कम करने और राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि के लिए आय। पर प्रमुख फोकस है
इस कार्यबल को गैर-कृषि क्षेत्रों की ओर मोड़ने के लिए उनका कौशल विकास करना
ग्रामीण उद्योगों की तरह. और इसलिए तेलंगाना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी जाती है
इस क्षेत्र में अधिकांश कार्यबल मौजूद है।

उपजाऊ भूमि, विविध फसलें, विशाल सिंचाई प्रणाली जैसे प्रचुर संसाधन
कृष्णा और गोदावरी जल संचयन आदि तेलंगाना के लिए वरदान हैं। कृषि जो
तेलंगाना के लोगों का सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन एक परंपरा है और यही जीवन है
लोगों की शैली. अतः, नियोजित सामाजिक-आर्थिक की सभी रणनीतियों का केंद्र बिंदु
राज्य का विकास कृषि है। इसी प्रकार सहायक क्षेत्र को
मत्स्य पालन, पशुपालन आदि जैसे कृषि क्षेत्र भी सुनिश्चित करने में सक्षम हैं
रोज़गार। लेकिन उद्योग हैदराबाद और रंगारेड्डी में और उसके आसपास केंद्रीकृत हैं
अकेला। यद्यपि हम देखते हैं कि अन्य जिलों में उद्योगों की संख्या कम है
ऐसे कर्मचारी जो कम योग्य हैं या जिनके पास ऐसे कौशल हैं जिनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है।
अब सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन कर्मचारी
इस क्षेत्र में काम करने वालों को कुशल होना चाहिए। अधिकांश लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर रहे हैं
रोज़गार की तलाश में शहरी क्षेत्र अधिकतर अकुशल हैं।

30.4. तेलंगाना राज्य में बेरोजगारी के आँकड़े

रोज़गार को किसी भी व्यक्ति के लिए बुनियादी तौर पर आय के स्रोत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की जरूरतें। रोजगार की कमी को बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसी स्थिति या स्थिति जब कोई व्यक्ति काम करने में सक्षम हो और सक्रिय रूप से खोज कर रहा हो एक नौकरी लेकिन उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाने को बेरोजगारी कहा जाता है। इसे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति दी गई मजदूरी पर काम करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो लेकिन करने में असमर्थ हो काम ढूंढो.

बेरोजगारी को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है- a) ग्रामीण बेरोजगारी और बी) शहरी बेरोजगारी।

जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि गतिविधियों पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ गई है जितने लोगों की आवश्यकता है उससे अधिक रोजगार बढ़ गया है। बेरोजगारी कहां किसी भी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होना कहलाता है गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो मजदूर काम करते हैं कृषि क्षेत्र में साल में केवल सात से आठ महीने ही काम मिलता है और शेष महीनों में वे निष्क्रिय रहते हैं। ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अल्परोज़गार एक अन्य प्रकार है जहां एक उच्च कुशल व्यक्ति अनिच्छा से काम करता है कम कौशल वाली कम वेतन वाली नौकरियों में।

2004-05 में वर्ष के दौरान, तेलंगाना में ग्रामीण बेरोजगारी दर 11.3% थी वहीं भारत में यह 8.2% थी. 2011-12 के दौरान, तेलंगाना में ग्रामीण बेरोजगारी दर 4% वहीं भारत में यह 5.7% थी. यह आँकड़े इस बात का स्पष्ट अंदाज़ा देते हैं कि ग्रामीण कैसे हैं इन वर्षों में बेरोजगारी दर कम हुई है। यदि हम शहरी बेरोजगारी पर विचार करें 2004-05 के दौरान तेलंगाना और भारत की दर क्रमशः 7.5% और 8.3% थी। इस बीच 2011-12 के दौरान तेलंगाना में शहरी बेरोजगारी दर 6% और भारत में थी यह 5.5% था. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बेरोजगारी दर काफी कम है बेरोजगारी की दर।

तेलंगाना में गरीबी कम करने के लिए औद्योगिक विकेंद्रीकरण लागू किया जा सकता है। अगर विकेंद्रीकरण होने से क्षेत्रीय असमानताओं के साथ-साथ आय को भी कम करने में मदद मिलती है मतभेद. इससे क्षेत्रीय मानव संसाधनों का उपयोग होता है जिसके परिणामस्वरूप परिणाम मिलता है

बेरोजगारी में कमी. कृषि में श्रम गहन तरीकों के उपयोग के साथ क्षेत्र, इस क्षेत्र में भारी विकास और रोजगार सृजन होगा परिणामस्वरुप बेरोजगारी कम होगी. हम आपूर्ति करके बेरोजगारी को रोकते हैं कृषि क्षेत्र और उस पर निर्भर क्षेत्रों के लिए आवश्यक ढांचागत सुविधाएं छोटे और सीमांत किसानों को गहन और व्यापक आय लाभ प्रदान करना कृषि। ग्रामीण साक्षरों को वित्त पोषण के साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी होगा बेरोजगारी रोकने में पूरी मदद करें. केवल रोजगार ही गरीबी के लिए पर्याप्त नहीं है उन्मूलन, लेकिन उनके कौशल और क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है।

30.5. तेलंगाना राज्य में विकासात्मक और कल्याण योजनाएं

राज्य के गठन के बाद से ही तेलंगाना सरकार इसे लागू कर रही है गरीबों के लिए कई विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना, स्वास्थ्य प्रदान करना और अमीर और गरीब की परवाह किए बिना सभी को शिक्षा की सुविधाएं, समान बनाना महिलाओं के लिए हर पहलू में अवसर और आत्मनिर्भरता। इनके साथ ही एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र को महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि हमारा राज्य इस पर निर्भर है। अर्थशास्त्रियों अनुमान है कि अगर तेलंगाना कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा तो वह सक्षम होगा गरीबी को दो गुना से खत्म करना। ऐसा इसलिए क्योंकि कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा इसके सहायक क्षेत्रों का विकास। उद्योग स्थापित होने से बेरोजगारी कम होगी। तेलंगाना सरकार ने नई औद्योगिक नीति और विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं बेरोजगारी कम करने के लिए कौशल विकास. इन पहलों को युद्ध की संज्ञा दी जा सकती है गरीबी के खिलाफ सरकार.

तेलंगाना सरकार कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू कर रही है गरीबों के जीवन स्तर में सुधार, कमजोर और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और किसानों के कल्याण के लिए। ये बंटे हुए हैं चार प्रकार में.

1. किसान कल्याण योजनाएँ
2. महिला एवं बाल कल्याण योजनाएँ
3. समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लिए योजनाएं
4. अन्य कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाएँ

30.5.1. किसान कल्याण योजनाएँ

30.5.1.1. रायथु बंधु (FISS)

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल सुविधा, बिजली, बीज, उर्वरक, श्रम और मशीनरी किसानों के लिए आवश्यक इनपुट हैं। ये उपज सुनिश्चित करते हैं और उत्पादकता. एक ग्रामीण किसान आम तौर पर उन आदानों के लिए कर्ज पर निर्भर रहता है। के लिए यह सुनिश्चित करें कि किसान फिर से ग्रामीण ऋण जाल के दुष्चक्र में न फंसें ऋणग्रस्तता, एक नई योजना जिसे रायथु बंधु (किसान निवेश सहायता योजना) कहा जाता है तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित है और वर्ष 2018-19 से लागू किया गया है ख़रीफ़ सीज़न आगे। रायथु बंधु योजना 5000/- रुपये की निवेश सहायता प्रदान कर रही है - बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे इनपुट की खरीद के लिए प्रत्येक मौसम में प्रति किसान प्रति एकड़ फसल मौसम के लिए किसान की पसंद के क्षेत्र संचालन में श्रम और अन्य निवेश। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जाती है।

30.5.1.2. रायथु बीमा (एफजीएलआईएस)

रायथु बीमा एक प्रतिष्ठित योजना है जिसकी संकल्पना और कार्यान्वयन किया गया है तेलंगाना सरकार. इस योजना का मुख्य उद्देश्य वित्तीय और प्रदान करना है किसान के परिवार के सदस्यों/आश्रितों को सामाजिक सुरक्षा। बहुसंख्यक किसान छोटे, सीमांत और साधनहीन हैं, अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। में किसानों की जान जाने की घटना से उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहां तक कि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी। इसी को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने 2018 में रायथु बीमा योजना लेकर आएं। 18 से 59 आयु वर्ग के किसान वर्ष योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र हैं। नामांकित की मृत्यु की स्थिति में किसान की प्राकृतिक मृत्यु सहित किसी भी कारण से मृत्यु होने पर बीमित राशि 5 लाख रूपये जमा करायी जाती है (10) दिनों के भीतर नामित नामांकित खाते में। सरकार मासिक भुगतान करती है किसानों की ओर से एलआईसी को प्रीमियम। इस योजना का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है शोक संतप्त परिवारों के जीवन और उनकी आजीविका में मदद करना, क्योंकि उनमें से अधिकांश संसाधन हैं गरीब छोटे किसान और समाज के कमजोर वर्गों से आते हैं। यह योजना रही है ऑनलाइन पोर्टल के विकास के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। इस योजना की विशिष्टता है कि, नामांकित व्यक्ति को दावे के निपटान के लिए किसी भी कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है मात्रा।

30.5.1.3. मिशन काकतीय

मिशन काकतीय का उद्देश्य कृषि के विकास को बढ़ाना है छोटे और सीमांत किसानों के लिए आय आधारित, लघु विकास में तेजी लाना सिंचाई के बुनियादी ढांचे, समुदाय आधारित सिंचाई प्रबंधन को मजबूत करना और टैंकों की बहाली के लिए एक व्यापक कार्यक्रम अपनाना। मिशन काकतीय प्रथम था यह कार्यक्रम 2014 में नवगठित तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किया जाना था 12 मार्च 2015 को कामारेड्डी के सदाशिवनगर गांव के पाथा चेरुवु में उद्घाटन किया गया ज़िला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 46,000 टैंकों (चेरुवुलु) को बहाल करना है। प्रोजेक्ट है पाँच चरणों में किया गया। पुनर्स्थापना के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाता है।

1. टैंकों की मूल जल भंडारण क्षमता को बहाल करने के लिए टैंक बिस्तरों से गाद निकालना।
2. जीर्ण-शीर्ण नालों, बांधों आदि की मरम्मत करके।
3. टैंक बंधों को उनके मूल मानकों के अनुरूप मजबूत करके।
4. टैंकों में पानी को निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए फीडर चैनलों को मानकों के अनुरूप मरम्मत करना।
   (टैंकों की श्रृंखला का हिस्सा)।
5. लघु सिंचाई टैंकों को पूरक/भरने के लिए आवश्यक कार्य शुरू करके
   कृष्णा दोनों पर प्रमुख, मध्यम और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के नहर नेटवर्क शुरू किए गए
   और गोदावरी नदियाँ।
6. सिंचाई चैनलों को मानकों के अनुसार पुनः विभाजित करके और सीएम और सीडी कार्यों की मरम्मत करके
   खेतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पानी के सुचारू वितरण के लिए।

मिशन काकतीय को केंद्रीय बोर्ड से सर्वश्रेष्ठ सिंचाई अभ्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2018 में सिंचाई और बिजली। इस परियोजना को 2021 में स्वर्ण के लिए SKOCH पुरस्कार भी मिला। सिंचाई में श्रेणी.

30.5.2. महिला विकास एवं बाल कल्याण योजना

2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाना की पुरुष और महिला जनसंख्या 1.76 है क्रमशः करोड़ और 1.74 करोड़। पुरुष, महिला जनसंख्या 50.31% और 49.6% है क्रमश।

सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यान्वित कर रही है

ऐसे कार्यक्रम जिनका लक्ष्य महिलाओं का उत्थान करना, उन्हें सशक्त बनाना और उनकी गरिमा को बढ़ाना है। इस ओर अंत में तेलंगाना ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक जैसी कई योजनाएं शुरू कीं।

केसीआर किट्स, अम्मा ओडी, आरोग्य लखमी आदि। आइए अब इन योजनाओं पर चर्चा करते हैं।

30.5.2.1. कल्याण लक्ष्मी - शादी मुबारक

तेलंगाना सरकार ने कल्याण लक्ष्मी/शादी नामक एक कल्याणकारी योजना शुरू की

मुबारक 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है आयु बीसी, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक से संबंधित है। यह योजना 2 तारीख से लागू हो गई अक्टूबर, 2014. तेलंगाना निवासी एक लड़की, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसकी वार्षिक आय है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1.5 लाख और 2 लाख लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। ए विवाह के समय दुल्हन के परिवार को 1,00,166/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है शादी का खर्च पूरा करने के लिए. इसे दुल्हन के खाते में जमा किया जाता है।

30.5.2.2. स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर समुदाय में संगठित करना है ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और समग्र विकास के लिए आधारित संगठनों का नेतृत्व करना गरिमापूर्ण जीवन. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी) बनाने के लिए सोसायटी का गठन किया गया एसएचजी को मजबूत करने के लिए संघ। के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं महिलाओं की वित्तीय वृद्धि. बैंक लिंकेज कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत एसएचजी को सहायता प्रदान की जा रही है बैंकों द्वारा ऋण दिए जाने से तेलंगाना एसएचजी में अग्रणी राज्य बन गया है। हमारे राज्य में कुल 47.53 लाख महिलाएं और 4.39 एसएचजी 17,883 ग्राम संगठनों में गठित हैं। उन्मूलन करना शहरी क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए एमईपीएमए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही है।

30.5.2.3. केसीआर किट योजना

KCR किट योजना 3 जून 2017 को शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य है गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना। एक वित्तीय रुपये की सहायता इस योजना के तहत 12,000/- रुपये दिए जाते हैं (और यदि बच्चा पैदा होता है तो 13,000/- रुपये दिए जाते हैं) एक लड़की) यह वित्तीय सहायता माँ और बच्चे की देखभाल के लिए दी जाती है। एक केसीआर किट इसमें मां और बच्चे के उपयोग के लिए 15 वस्तुएं शामिल हैं। यह किट बच्चे को रखने में काम आएगी 3 महीने तक गर्म और स्वच्छ। 2020-21 में लगभग 2.1 लाख किट और 2021-22 में

(2021 अप्रैल से नवंबर के बीच) लगभग 1.5 लाख किट वितरित किये गये। इस योजना का नेतृत्व

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी और संख्या में कमी

सिजेरियन ऑपरेशन किया गया. इसके परिणामस्वरूप प्रसवोत्तर खर्च कम हो गया और महिलाओं को होने लगा

कम स्वास्थ्य समस्याएं. 2015-16 में इस योजना की एक और उपलब्धि यह है कि संख्या

सरकारी अस्पतालों में प्रसव 30.5% से बढ़कर 49.7% हो गया है। हम कर सकते हैं

इसे दो गुना सुधार कहें।

30.5.2.4. अम्मा ओडी

अम्मा ओडी योजना 18 जनवरी 2018 को राज्य भर में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी।

यह योजना एम्बुलेंस से डायग्नोस्टिक सेवाओं तक मुफ्त परिवहन सुविधा प्रदान करती है

नियमित जांच, परीक्षण और नवजात शिशुओं के टीकाकरण के लिए। वाहन गर्भवती महिला को ले जाएगा

डिलीवरी के लिए और डिलीवरी के बाद उसे वापस उसके घर तक छोड़ें। लगभग 300 गाड़ियाँ हैं

तेलंगाना के 33 जिलों में काम कर रहा है। 2020-21 में, लगभग 10.85 लाख लाभार्थी और तक

नवंबर 2021, लगभग 7.95 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए।

30.5.2.5. आरोग्य लक्ष्मी

आरोग्य लक्ष्मी योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन प्रदान करती है

आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से माताओं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। इस योजना के लिए धन राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात में इकट्ठा किया जाता है। तेलंगाना सरकार अतिरिक्त रुपये दे रही है। 14/- महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए। के लाभार्थी

योजना के तहत महीने में 25 दिन 200 मिलीलीटर दूध और भोजन के साथ हर दिन एक अंडा मिलता है।

इनके साथ ही गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाती हैं।

30.5.3. समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्गों के लिए योजनाएं

30.5.3.1. आसरा पेंशन योजना

अपने कल्याणकारी उपायों के एक भाग के रूप में, तेलंगाना सरकार ने सभी गरीबों के लिए सम्मान के साथ सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसरा पेंशन योजना शुरू की है। आसरा

पेंशन योजना विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए है

बूढ़े और अशक्त, एचआईवी-एड्स से पीड़ित लोग, विधवाएँ, अक्षम बुनकर और ताड़ी निकालने वाले, जो बढ़ती उम्र के साथ अपनी आजीविका के साधन खो चुके हैं, फाइलेरिया से पीड़ित लोग, बीड़ी श्रमिक।

क्रियान्वयन के दिन से लेकर आज तक इसके तहत 39 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं

योजना। 2019 से पीएच श्रेणी की पेंशन में 1500 रुपये से 3016 रुपये की बढ़ोतरी हुई।

इसी तरह बाकी वर्गों के लिए पेंशन 1000 रुपये से बढ़ा दी गई है

रु. 016. नवंबर 2014 से जनवरी 2022 तक लगभग 45,882 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

30.5.3.2. आरोग्य श्री (आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY)

आरोग्य श्री राज्य में क्रियान्वित की जा रही एक अनूठी सामुदायिक स्वास्थ्य योजना है। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। आरोग्य श्री योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, सरकार ने आरोग्य श्री स्वास्थ्य देखभाल ट्रस्ट की स्थापना की है। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। कवर की गई प्रक्रियाओं के लिए सभी लेनदेन कैशलेस हैं। यह योजना रुपये तक की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। एक वर्ष में 5 लाख रुपये तक। बीमारियों के लिए 10 लाख रु.

मई 2021 में, तेलंगाना सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) से जोड़ा। वर्तमान में आरोग्य श्री लाभार्थी भी AB PM-JAY के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, एबी पीएम-जेएवाई के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में लगभग 646 प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। 2014-15 और 2019-20 के बीच लगभग 42.3% लाभार्थी बढ़े। योजना की लागत भी है

बढ़कर 48.6% हो गया।

30.5.3.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली

तेलंगाना सरकार पूरे राज्य में गरीबों को अनाज वितरित करती है
17,013 उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से रियायती दरें। तेलंगाना सरकार ने बढ़ा दिया है
इस योजना से 1.96 करोड़ लोगों के अलावा 96 लाख और लाभार्थियों को लाभ मिलेगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किया गया। दिसंबर 2021 तक 2.87 करोड़ लाभार्थी
योजना से लाभान्वित हुए। हमारे राज्य में एक व्यक्ति को 6 रुपये प्रति किलो चावल दिया जाता है. 1\- प्रति
परिवार में सभी के लिए किलो।

30.5.4. अन्य कल्याण एवं विकासात्मक योजनाएँ

सरकार ने कमजोर और असुरक्षित लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं
समाज के सभी वर्ग आत्मनिर्भर। मुख्य उद्देश्य संपत्ति में सुधार करना है
सक्षम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना
लोगों को स्व-रोज़गार बनाना, सामाजिक-आर्थिक रूप से कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना
समाज में असमानताएं. आइए उनमें से कुछ योजनाओं पर एक नजर डालते हैं।

30.5.4.1. दलित बंधु

यह योजना वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी। यह योजना 1 अगस्त को यदाद्री भुवनागिरी जिले के अलेरू विधानसभा क्षेत्र के वसाला मैरी गांव में शुरू की गई थी।
2021. यह पहल अनुसूचित जाति के परिवारों को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।

रुपये की एकमुश्त पूंजी सहायता। सभी को 100% अनुदान के रूप में प्रति अनुसूचित जाति परिवार को 1.लाख रुपये प्रदान किये जाते हैं
या उनकी पसंद के अनुसार उपयुक्त आय सृजन योजना स्थापित करने के लिए सब्सिडी जैसे
वाहन, दुकानें, मशीनरी आदि, बिना बैंक ऋण लिंकेज के। इसका उद्देश्य एक रास्ता उपलब्ध कराना है
ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

30.5.4.2. मिशन भगीरथ

संयुक्त राष्ट्र ने संरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता को मौलिक या घोषित किया है
प्राथमिक अधिकार. यूएनओ के स्थायी लक्ष्यों में ये छठे स्थान पर हैं । एक नारा "शराब पीना।"
सभी के लिए जल-सभी के लिए स्वच्छता'' भी दिया गया। जल की उपलब्धता मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है
और आर्थिक विकास. तेलंगाना सरकार ने प्रदान करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की है
तेलंगाना राज्य के सभी लोगों को पाइप से संरक्षित, शुद्ध, पर्याप्त पानी। यह कार्यक्रम
17 अगस्त 2016 को अपराह्न 3 बजे प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। में इसका उद्घाटन किया गया
गजवेल निर्वाचन क्षेत्र के कोमाटी बांदा। मिशन भागीरथ के 26 खंडों के माध्यम से शुद्ध किया गया
घरों में नल कनेक्शन द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। भारी मात्रा में पानी की आपूर्ति की जाती है
शहरी इलाका. यह परियोजना 135 ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लीटर (एलपीसीडी) शुद्ध पानी की आपूर्ति करती है
नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों को एलपीसीडी और नगर निगमों को 150 एलपीसीडी।
औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इस परियोजना से 10% पानी का उपयोग किया जाता है। यह परियोजना जल आपूर्ति करती है
22.882 स्कूलों, 27,310 आंगनबाड़ियों और सभी सरकारी संगठनों को नल के माध्यम से
सम्बन्ध। नल कनेक्शन के माध्यम से 100% पानी की आपूर्ति की जाती है, यानि 24,028 ग्रामीण इलाकों में
2021 तक बस्तियां केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, तेलंगाना पहले स्थान पर है
हरियाणा और गोवा के साथ 100% नल कनेक्शन और जल आपूर्ति प्रदान करना। जब तक
दिसंबर 2021, लगभग रु. मिशन भागीरथ के लिए 35,836 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

30.5.4.3. डबल बेडरूम मकानों का निर्माण

घर विभिन्न भौगोलिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाता है और सभी को सामाजिक रूप से सम्मानजनक
जीवन देता है। हर मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग
समाज के लोगों का अपने खुद के घर का सपना है। घर परिवार के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उचित जल सुविधा, स्वच्छता
और स्वच्छ वातावरण वाला अपना घर आवश्यक है।

तेलंगाना सरकार ने डबल बेडरूम हाउसिंग योजना तैयार की है
अक्टूबर, 2015 माह में गरीबों को शत-प्रतिशत लाभ देकर सम्मान प्रदान किया गया।
सब्सिडी वाले घर। इस योजना के तहत 2016 के बीच 2,91,057 घरों को मंजूरी दी गई
और 2021. नवंबर 2021 तक स्वीकृत घरों में से 1,07,612 घर थे
निर्मित. कार्यान्वयन के दिन से आज तक (नवंबर 2021) रु. 10,455 करोड़

योजना में निवेश किया गया था। तेलंगाना राज्य आवास निगम (टीएसएचसी) कार्यान्वयन कर रहा है

यह योजना हैदराबाद को छोड़कर पूरे राज्य में। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम

हैदराबाद में यह योजना शुरू कर रही है। इस 2BHK परियोजना को PMAY-U (प्रधान) प्राप्त हुआ

वर्ष 2018-19 में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

30.5.4.4. तेलंगाना छात्रवृत्ति योजना

तेलंगाना सरकार एससी, एसटी, बीसी की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है

और अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति देकर। प्रत्येक

सरकार प्रत्येक वर्ष प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति प्रदान कर रही है

एससी, एसटी और बीसी छात्रों के लिए। तेलंगाना सरकार विदेशी छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है

आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए। जिन विद्यार्थियों के परिवार के

वार्षिक आय 5 लाख से कम है, वे इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। जो स्कॉलरशिप हैं

एससी, एसटी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को डॉ.बी.आर.आंबेडकर, बीसी और ईबीसी को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का नाम दिया गया है

महात्मा ज्योतिबा फुले और अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को प्रमुख नाम दिया गया है

मंत्री विदेशी छात्रवृत्ति। इस स्कॉलरशिप के तहत हर छात्र को 20 लाख तक मिलते हैं।

30.5.4.5. भेड़ वितरण

यह योजना यादव/गोल्ला/कुरुमा परिवारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। इन परिवारों को 75% सब्सिडी पर भेड़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत लगभग 3.81 लाख लाभार्थियों को 79.38 लाख भेड़ें दी गईं।

30.5.4.6. शिक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

कमजोर वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना की गई है

समाज के वर्ग. गुरुकुल शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाई गई है

2014 में 298 से बढ़कर 2022 में 978 हो गई। सरकार ने 2022 में 7,283.54 करोड़ रुपये के बजट के साथ मन ऊरु-मन बड़ी/ मन बस्ती-मन बड़ी कार्यक्रम शुरू किया है।

30.6. सारांश

अब तक हमने गरीबी, बेरोजगारी और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की है

जिन्हें सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तेलंगाना सरकार ने हर जाति के कमजोर लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

लिंग और समाज के अन्य सभी वर्ग। योजनाओं की सफलता निर्भर नहीं करती

सिर्फ सरकार के नजरिए पर नहीं बल्कि योजनाओं के सही क्रियान्वयन पर भी.

30.7. मॉडलपरीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 4-5 पंक्तियों में दें।

1. गरीबी क्या है?
2. गरीबी के प्रकार क्या हैं?
3. गरीबी उन्मूलन कल्याण योजनाओं को हम कितने प्रकारों में बाँट सकते हैं तेलंगाना? व्याख्या करना।
4. तेलंगाना सरकार कौन सी किसान कल्याण योजनाएं लागू कर रही है?

द्वितीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 8-10 पंक्तियों में दीजिए।

1. रायथु बंधु योजना की कार्यान्वयन प्रक्रिया की व्याख्या करें।
2. रायथु बीमा योजना किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है?
3. महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं तेलंगाना के विकास के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? व्याख्या करना।
4. तेलंगाना की छात्र कल्याण योजनाएं क्या हैं?
5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर तेलंगाना सरकार की नीति क्या है?

तृतीय. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 16-20 पंक्तियों में दें।

1. तेलंगाना द्वारा शुरू की गई किसान कल्याण योजनाओं पर अपनी राय बताएं?
2. तेलंगाना सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के उद्देश्य पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखें?

30.8.शब्दावली

- संपूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी व्यक्ति या परिवार के पास अपनी सबसे बुनियादी जरूरतों, जैसे भोजन, आश्रय और कपड़े को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की गरीबी मुख्यतः भारत जैसे विकासशील देशों में देखी जा सकती है।

- तुलनात्मक गरीबी। सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य समाज में असमानताओं से है। इस गरीबी के अनुसार लोगों का आय स्तर निम्न स्तर का होता है रहन-सहन की तुलना उच्च जीवन स्तर वाले लोगों से की जाती है और फिर लोगों से जिनकी आय कम है उन्हें अपेक्षाकृत गरीब कहा जाता है।
- प्रच्छन्न बेरोजगारी. किसी भी सेक्टर में यदि कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है आवश्यकता से अधिक बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है।

30.9.संदर्भ

1. तेलंगाना राज्य सांख्यिकीय सार, 2021।
2. राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट नीति आयोग, 2021।
3. तेलंगाना सामाजिक आर्थिक आउटलुक, 2022।